



अल्पमोलीय संस्करण

# भारत-विभाजन की कहानी

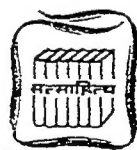
भारत के बंटवारे तथा सत्ता-हस्तांतरण की आंतरिक कहानी

लेखक

एलन कैम्पबेल जॉन्सन

अनुवादक

रनवीर सक्सेना



सरिता साहित्य मण्डल

सरिता साहित्य मण्डल-प्रकाशन

१९६०

प्रकाशक  
मार्तण्ड उपाध्याय,  
मन्त्री, सस्ता साहित्य मण्डल,  
नई दिल्ली-१

---

दूसरी बार १९६०  
अल्पमोली-सस्करण  
मूल्य डेढ रुपया

---

मुद्रक  
श्री जैनेन्द्र प्रेस,  
दिल्ली-६

## प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक श्री एलन कैम्पबेल जान्सन की 'मिशन विद माउण्टबेटन' नामक सुविख्यात पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। इसमें लार्ड माउण्टबेटन के एक महान् मिशन को लेकर भारत में आने, भारतीय स्वतन्त्रता का व्यावहारिक एवं सर्वमान्य हल उपलब्ध कराने, शासन-सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंपने, भारत के टुकड़े होने और दो स्वतन्त्र राष्ट्रों के बनने की बड़ी ही सूक्ष्म, रोचक तथा आंतरिक कहानी है। लेखक लार्ड माउण्टबेटन के प्रेस अटैची थे। इस नाते त्येक घटना से उनकी जानकारी रहना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, लार्ड माउण्टबेटन हर मुलाकात के बाद पन्द्रह मिनट में उसके नोट लिखा देते थे। साथ ही विचार-परिवर्तन करने की दृष्टि से अपने उच्च कर्मचारियों की वह प्रतिदिन नियमित रूप से बैठक भी किया करते थे। इसके परिणामस्वरूप लेखक हर घटना से न केवल अवगत ही रहते थे, अपितु उसकी आवश्यक एवं प्रामाणिक सामग्री भी उन्हें प्राप्त होती रहती थी।

बड़े हर्ष की बात है कि इस विषय की इतनी ऐतिहासिक एवं उपादेय सामग्री लेखक के परिश्रम तथा दूरदर्शिता के कारण प्राप्त हो सकी। उन्होंने प्रत्येक दिन की घटनाओं का वर्णन तिथि-क्रम से किया है और छोटे-बड़े सभी विवरण प्रस्तुत किये हैं। उन्हें पढ़ पर पता चलता है कि भारत के हाथ में सत्ता सौंपने की पृष्ठ-भूमि क्या थी, ब्रिटिश सरकार को किन-किन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ा, भारतीयों को किस लाचारी की अवस्था में विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, मुस्लिम लीग ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए रास्ते में क्या-क्या अड़चने पैदा की, पाकिस्तान स्वीकार होने पर किस प्रकार भारत का अंग-भंग हुआ, विभाजन से क्या-क्या समस्याएँ उत्पन्न हुईं, किस तरह दो पृथक् राष्ट्रों का निर्माण हुआ और किस प्रकार भारत से अपनी सत्ता हटा लेने पर भी भारत और ब्रिटेन के संबंध मधुर बन रहे।

पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखक ने उसे निष्पक्ष भाव से लिखा है। दैनिक घटनाओं को ज्यों-का-त्यों उन्होंने उपस्थित कर दिया है। जहाँ कहीं अपनी बात कहने का अवसर आया है, वहाँ उन्होंने किसी के साथ भी पक्षपात से काम नहीं लिया। भारत-विभाजन व सत्ता-हस्तांतरण-संबंधी साहित्य में, जो कि पुस्तक के रूप में बहुत ही कम उपलब्ध है, इस ऐतिहासिक पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है।

पुस्तक की कुछ घटनाएँ तो इतनी मनोरंजक हैं कि पाठक पढ़कर आनन्द-



विभोर हो उठता है। १५ अगस्त की रात को सत्ता-हस्तांतरण की विधि के पश्चात् विधान-सभा के अध्यक्ष राजेन्द्रबाबू जब लार्ड माउन्टबेटन से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल बनने का अनुरोध करने जाते हैं तो उन्हें जो कहना चाहिए, कहना भूल जाते हैं और उनके मुह से शब्द ही नहीं निकल पाते। उसी अवसर पर नेहरूजी अपने मन्त्रिमंडल के नामों की सूची एकवद लिफाफे में माउन्टबेटन को देकर चले जाते हैं, पर जब माउन्टबेटन उसे खोलते हैं तो देखते क्या है कि अन्दर कुछ भी नहीं है। पहली मुलाकात होने के समय जिन्ना, लार्ड और लेडी माउन्टबेटन का फोटो खिंचता है। अपनी बहादुरी की डींग मारने के लिए विनोद भरे स्वर में जिन्ना लेडी माउन्टबेटन से कहते हैं कि दो काटो के बीच एक गुलाब है, पर मजे की बात यह कि माउन्टबेटन-दपति के बीच वह स्वयं खड़े थे। ऐसी मनोरंजक घटनाएँ बहुत-सी मिलती हैं, जो पुस्तक को बड़ी सरसता और सजीवता प्रदान करती हैं।

मूल पुस्तक काफी बड़ी है और उसमें विभाजन तथा सत्ता-हस्तांतरण के अतिरिक्त और बहुत-सी बातें आ गई हैं। भारतीय पाठकों की दृष्टि से मूलभूत घटनाओं को लक्ष्य में रख कर पुस्तक का सक्षिप्तीकरण एवं सम्पादन कर दिया गया है।

हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सग्रहणीय पुस्तक पाठकों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

## दूसरा संस्करण

हमें प्रसन्नता है कि पुस्तक का दूसरा संस्करण पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है। पुस्तक की उपयोगिता को देखकर इसे अपनी 'अल्पमौली प्रकाशन'-माला में निकाला जा रहा है और सामग्री को ज्यों-का-त्यों रख कर भी इसका मूल्य बेहद कम कर दिया गया है।

—मन्त्री

## दो शब्द

जुलाई १९४२ में मुझे माउन्टबेटन के कर्मचारी-मडल में संयुक्त कमाण्ड हेडक्वार्टर्स में एयर पब्लिक रिलेशंस आफिसर का स्थान सौंपा गया था। १५ महीने के बाद माउन्टबेटन को दक्षिण-पूर्व एशिया की मित्र-राष्ट्र सेनाओं के सर्वोच्च कमाण्डर के पद पर नियुक्त किया गया तो उन्होंने मुझे केवल सरकारी आधारों में सूचना प्राप्त कर लेने का काम नहीं सौंपा, बल्कि वह मुझे अपनी साप्ताहिक मुलाकातों एवं महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल कर लेते थे। अतः वाइसराय के रूप में जब उन्हें भारत जाने के लिए आमंत्रित किया गया तबतक मैं माउन्टबेटन-तन्त्र का इतना अभिन्न अंग बन चुका था कि मुझे प्रेस अटैची के रूप में उनके साथ भारत आना पड़ा। उनके पूर्व के वाइसरायों के समय में यह पद नहीं होता था।

इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य अपने 'निक नोटो, पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर, जोकि मैंने उस समय लिखे थे, इस कहानी को कहना है। अधिकांशतः मैंने इतिहास देने की अपेक्षा इतिहास की साधन-सामग्री इस पुस्तक में उपस्थित की है। इसकी घटनाओं और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मेरा संपर्क इतना घनिष्ठ था कि मैं उनके विश्लेषण का प्रयत्न नहीं कर सका।

यदि इस पुस्तक का घटना-क्रम तीव्र है तो इसका कारण यह है कि हम सबको बड़ी तेजी और रफ्तार से काम करना पड़ा और हम लोगों के मामले बेहद जल्दी थी। यदि वे विवरण कुछ असम्बद्ध से प्रणीत होते हैं, तो इसका कारण यह है कि समय-समय पर अनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती थीं और उनके तात्कालिक समाधान भी करने पड़ते थे, जिनसे हमारी दिनचर्या का तारतम्य टूट जाता था।

तेजी और बाधाओं के बावजूद विभाजन द्वारा सत्ता-हस्तांतरण निश्चित रूप से अनवरत चला। हमारे भारत में आने के ७३ दिन में विभाजन-योजना का ऐलान कर दिया गया और उसके ७२ दिन के बाद स्वतः वाइसराय पद का अंत हो गया। माउन्टबेटन के गवर्नर-जनरल पद के १० महीनों में घटनाओं की रफ्तार कभी भी मंद नहीं पड़ी।

# विषय-सूची

प्रकाशकीय	३
दो शब्द	५
१ नये वाइसराय की नियुक्ति	७
२ महत्वपूर्ण बहस और सलाह-मशविरे	१०
३ भारत में पहला सप्ताह	२०
४ गांधी और जिन्ना	२९
५ नई योजना पर गवर्नरो के विचार	४०
६ मीमाप्रान्त की यात्रा	४६
७ शिमला में सकट	५२
८ योजना में परिवर्तन	५८
९ ऐतिहासिक समझौता	६३
१० प्रशासन-संबंधी नतीजे	७६
११ नये गवर्नर-जनरल का प्रश्न	८२
१२ सघ-प्रवेश-पत्र पर राजाओ के हस्ताक्षर	८७
१३ पाक-भारत में स्वाधीनता-दिवस	१०३
१४ उत्तराधिकार का युद्ध	११३
१५ विषम परिस्थिति	११९
१६ जूनागढ़ का सकट	१२३
१७ विस्थापितों के काफिले और जूनागढ़	१२९
१८ काश्मीर का झमेला	१३३
१९ प्रगति और अवगति	१४८
२० प्रायश्चित्त	१५७
२१ गांधी का बलिदान	१६३
२२ अन्तिम श्रद्धाजलि	१७१
२३ फिर वही सघर्ष	१७२
२४ परिभाषा और अनुसंधान	१७८
२५ गतिरोध	१८५
२६ निजाम से भेट	१९१
२७ विदाई के दिन	१९९
परिनिष्ठ	
१ ३ जून १९४६ की योजना	२१२
२ प्रमुख व्यक्तियों के परिचय	२१८
अनुक्रमणिका	२२१

# भारत-विभाजन की कहानी

: १ :

## नये वाइसराय की नियुक्ति

लदन, बृहस्पतिवार, १९ दिसम्बर १९४६

मैं सबरे ही चेस्टर स्ट्रीट में माउटबेटन के घर पहुँचा। नाश्ते का समय था। माउटबेटन ने मुझे आदेश दिया कि मैं जाऊँ और पश्चिमी-पूर्वी एशिया की कमान-सबवी आदेशों के बारे में उनसे मिलूँ। प्रधान सेनापति की हैसियत से उन्होंने जो भ्रमण किया था, उस सारे भ्रमण में मैं उनकी युद्ध की डायरी लिखता और रखता था, इस नाते उन आदेशों में पदेन-सदस्य के तौर पर मेरी रुचि थी। इस काम में कुछ भारी कठिनाइयाँ भी थीं और सबसे बड़ी कठिनाई उनके व्यस्त कार्यक्रम के साथ इस काम का मेल बिठाना था। हम लोगों का काम पूरा नहीं हुआ था और समय की कमी थी, इसलिए अगले कार्यक्रम के लिए उनके साथ जाने के सिवा और कोई चारा न रहा। अगला कार्यक्रम था अपना सरकारी चित्र बनवाने के लिए आस्वाल्ड बर्ले चित्रकार के यहाँ जाना।

जब हम कार में बैठ गए तो माउटबेटन ने सब खिडकियाँ बंद कर दी, एकदम गुप्त रखने की मुझे सौगंध दिलाई और धीरे से कहा, “जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, वह मेरे निजी परिवार के बाहर किसी को भी मालूम नहीं।” उन्होंने बताया कि मि एटली ने मुझे कल शाम बुलाया था और लार्ड वेवल की जगह भारत का वाइसराय बनने को आमंत्रण दिया। यद्यपि मैं उनकी अचरज-भरी बातों में शामिल होने का आदी हो गया हूँ, तथापि जो रहस्य उन्होंने प्रकट किया, उसकी मुझे बिल्कुल आशा न थी। अपने जीवन की चिरकालीन असफल आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह फिर नौसेना में जानेवाले थे और बड़े जोरों से उनका अभ्यास भी चल रहा था। उन्हें प्रथम क्रूजर स्क्वेड्रन की कमान के लिए रियर एडमिरल बनना था। इसके अलावा, भारतीय नेताओं, लार्ड वेवल और ब्रिटिश सरकार के बीच अभी-अभी लदन में जो बातचीत हुई थी, उसमें सहज आशा की कोई झलक न होते हुए भी, लगता था कि मंत्रिमंडल-मिशन योजना अभी जीवित है।

लेकिन अब जो मैंने सुना, उससे जान पड़ा कि प्रधानमंत्री भारत और माउटबेटन दोनों के भविष्य के बारे में कुछ और ही सोच रहे हैं। मि एटली ने

माउटवेटन से जो मुलाकात की थी उसकी शुरुआत यह पूछते हुए की थी कि क्या दरअसल उनका दिल नौसेना में जाने को करता है ? उन्होंने जवाब दिया कि निश्चय ही यह बात सही है ।

एटली ने इसके बाद भारतीय संकट की बात छेड़ दी । उन्होंने कहा कि वेवल तो सेनाएँ हटाने की योजना से अधिक कुछ भी नहीं कर पाए । इसपर सरकार उन राजनैतिक विचारधाराओं से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट है, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पर असर कर रही है । अगर हम सावधान न रहे तो हम भारत को न केवल घरेलू युद्ध में ही, बल्कि तानाशाही राजनैतिक दलों के हाथों में सौंपने को लाचार हो जायेंगे । प्रस्तुत गतिरोध का अंत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है, और मन्त्रिमंडल के प्रमुख सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नये सिरे से व्यक्तिगत संपर्क से ही संभवतः आशाजनक परिणाम निकल सकता है । इस काम को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त आदमी की तलाश में उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा व्यक्तित्व और आवश्यक योग्यता केवल माउटवेटन में ही थी ।

लंदन, बुधवार, १५ जनवरी १९४७

आखिर माउटवेटन ने वाइसराय पद संभालने की स्वीकृति दे ही दी । प्रधान-मंत्री के साथ उनकी पहले की बातचीत अपूर्ण रही थी । सरकारी नीति में समय-अवधि के सिद्धान्त को मान लिया गया, लेकिन बिल्कुल निश्चित तारीख अभी तय नहीं हो पाई । १९४८ की वाद की छमाही की तजवीज की गई थी, लेकिन माउटवेटन का दृढ़ मत था कि राजनैतिक सफलता इस बात पर निर्भर है कि सरकार अंग्रेजों के भारत छोड़ने के लिए निकटतम तारीख मंजूर करने को तैयार है या नहीं, और तुरंत ही उन्होंने सुझाव दिया कि छमाही का अर्थ दिसंबर नहीं, जून होना चाहिए । बड़े दिन के सप्ताह के निकट होने के कारण आखिरी निर्णय स्थगित कर दिये गए और माउटवेटन थोड़े दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार को लेकर डेवोस चले गए । वहां गये अभी अड़तालीस घंटे ही हुए होंगे कि लंदन से उनके लिए जरूरी बुलावा आ गया और एक खास हवाई जहाज उन्हें लाने को भेजा गया । इस घटना से अखबारों में बड़े-बड़े अनुमान लगाये जाने लगे, लेकिन असली मतलब कोई नहीं समझ पाया । मिसाल के तौर पर 'डेलीमेल' के संपादक फ्रैंक ओवन ने मुझे अपना निजी अनुमान बताया कि माउटवेटन फिलस्तीन भेजे जा रहे हैं ।

माउटवेटन को इस तरह वापस बुलाने का कारण यह था कि भारत से आने-समाचार अधिकाधिक गंभीर थे । सांप्रदायिक गतिरोध और हिंसा का दौर

## नये वाइसराय की नियुक्ति

जारी था। सरकार जितना जल्दी हो सके, नई नीति और नये वाइसराय की घोषणा करना चाहती थी। इस घोषणा के मसविदे की शर्तों पर गभीरतापूर्वक विचार करने के बाद माउटबेटन ने अतत् सिद्धान्त रूप में इस पद को ग्रहण करना स्वीकार किया। सरकार के साथ उनका जो विचार-विनिमय हुआ, उसमें उन्होंने सरकार को इस आशय का कोई भाव प्रकट करने के खतरे से सावधान कर दिया कि उनकी नियुक्ति वाइसराय-प्रथा को स्थिर रखने या ब्रिटिश मध्यस्थता लागू करने के लिए की गई है। इसीलिए शुरू की चर्चा में उन्होंने यह शर्त रखी कि वह वाइसराय-पद तभी स्वीकार करेंगे जब भारतीय दल स्वतः अपनी शर्तों के साथ उन्हें भारत आने का निमन्त्रण दे। जो हो, मि एटली ने विस्तार के साथ समझाया कि यह आखिरी शर्त मुनासिब नहीं है, लेकिन इस सिद्धान्त को पूरी तरह स्वीकार किया कि अगर भारतीय दल एक सविधान और एक सरकार के रूप पर एकमत हो जाय तो समझौते के बावजूद वह किसी निश्चित तारीख अथवा उससे पहले भी ब्रिटिश राज्य की समाप्ति कर देंगे।

माउटबेटन को राजी करने के लिए सरकार अधिक-से-अधिक सीमा तक बढ़ने को तैयार थी। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कहा कि भारतीय नेताओं और नये वाइसराय के बीच वह पहले से ही आवश्यक संपर्क की व्यवस्था कर देंगे, और सरकारी घोषणा में पूर्व ही इस नियुक्ति के बारे में वह उनकी सहमति प्राप्त कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रिप्स ने तो यहाँ तक कह डाला कि वह माउटबेटन के साथ भारत भी जाने को तैयार है। इस सुझाव को दवा देना स्वाभाविक था, क्योंकि भारतीय मामलों में क्रिप्स की स्थिति और अनुभवों से माउटबेटन की स्थिति विगड़ जाती और नये वाइसराय के लिए आवश्यक अधिकार या प्रतिष्ठा के साथ वातचीत करना प्रायः असंभव हो जाता।

लंदन, सोमवार, १७ फरवरी १९४७

माउटबेटन ने आग्रह किया कि उन्हें वाइसराय के सामान्य कर्मचारी-मंडल में वृद्धि करने की अनुमति दी जाय। उनका कहना था कि उनको पूर्व वाइसरायों को दिये जानेवाले चायार्ड में भी कम समय में अभूतपूर्व राजनैतिक और सैनिक महत्व के निर्णय लेने का भार सौंपा गया है। लॉर्ड वेवेल के सामान्य सिविल सर्विस स्टाफ के लोग हालाँकि बहुत प्रतिभाशाली और अनुभवी थे, फिर भी उनमें बिना अन्य सहायता के काम पूरा कर ले जाने की उम्मीद करना असंभव था। मि एटली ने तुरन्त वादा किया कि माउटबेटन जिन कर्मचारियों की नियुक्ति चाहेंगे सरकार उसे पूरा करेगी।

माउटबेटन चार नये पदों का निर्माण कर रहे थे, जो वाइसराय-भवन के

इतिहास में नये थे। वाइसराय के नीचे एक चीफ ऑफ स्टाफ, एक प्रमुख सेक्रेटरी, एक कान्फ्रेंस सेक्रेटरी और एक प्रेस अटची। इनके अलावा उनका व्यक्तिगत मंत्रालय भी होगा, जिसके प्रमुख होंगे दो वयस्क नौसेना अधिकारी। अपनी पटाने की योग्यता के बल पर, जो माउटबेटन के व्यक्तित्व की एक खासियत है, उन्होंने अपने दो पुराने मित्रों को, अपने कामों को छोड़ कर, उनके दल को अपने महान् अनुभव का लाभ देने के लिए राजी कर लिया।

यही कारण है कि लार्ड इस्मे ने अपनी समाधि भग करना स्वीकार कर लिया था और वह चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभाल रहे थे। सर एरिक मिएविल नगर में महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्तरदायित्व को छोड़ कर प्रमुख सेक्रेटरी बने थे।

माउटबेटन के विशेष दल के अन्य सदस्य कैप्टन रोनाल्ड ब्रोकमेन (शाही नौसेना), कमांडर जार्ज निकोल्स (शाही नौसेना), लेफ्टिनेंट कर्नल वरनोन अर्नकिन क्रम (स्काट्स गार्ड्स) और मैं—हम सब लोग कहीं-न-कहीं पहले भी माउटबेटन के नीचे काम कर चुके थे।

: २ :

## महत्त्वपूर्ण बहस और सलाह-मशविरे

लंदन, बुधवार, २६ फरवरी १९४७

लार्ड सभा में गत दो दिन से सरकार की २० फरवरी वाली घोषणा पर जो सनसनीपूर्ण बहस चल रही थी, वह लार्ड टैम्पलवुड के अपने निदा-प्रस्ताव को वापस लेने के साथ समाप्त हो गई। यह एक ऐसा मौका था, जब बहुत से लोगों का यह मानना गलत नहीं था कि लार्ड सभा के मत कामन्स सभा की अपेक्षा अधिक राजनैतिक वजन वाले हैं। पहली बात तो यह कि लार्ड सभा वाले नई परिस्थिति पर कामन्स सभा से पूर्व ही से विचार कर रहे थे। इसलिए यह खयाल किया जाता था कि अनुदार विरोधी दल का अन्तिम रुख संभवतः लार्डों द्वारा अपनाये गए स्वर पर ही निर्भर करेगा। इसके अलावा, ये वयोवृद्ध राजनीतिज्ञों और विशेषज्ञों के रूप में अपनी वशगत क्षमता के आधार पर बहस नहीं कर रहे थे।

भारतीय शासन के इतिहास में जिनके नाम चौयाई सदी से भी अधिक समय तक चमक चुके थे, ऐसे बहुत से लोगों ने लार्ड टैम्पलवुड के कड़े मत पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि समय-अवधि का निश्चय वचन-भग है, जिससे भारत की शांति और समृद्धि खतरे में पड़ जायगी।

## महत्वपूर्ण बहस और सलाह-मशविरे

जब लार्ड टैम्पलवुड भारत-सचिव के पद पर आसीन थे और सर सेमुअल होर के नाम से प्रख्यात थे, तब उन्होंने लगभग सात वर्ष भारत सरकार के १९३५ के विधान को मि० चर्चिल और अनुदार दल के दक्षिणपथियों के तीव्र और सतत विरोध के विपरीत स्वीकार करवाने में लगाए थे। इसलिए उनके द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव सरकार के लिए निश्चय ही बड़ी भारी चुनौती थी। यदि इसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो जाता तो भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न पर पूरे राष्ट्र द्वारा कोई संयुक्त प्रयास करना असंभव हो जाता। जब लार्ड लिस्टोवेल ने सरकार की ओर से पहले दिन की बहस का जवाब दिया, उस समय तक इस बात की बहुत कम संभावना थी कि इस प्रश्न पर मतदान और पराजय को टाला जा सकेगा।

यह खतरा आज और भी बढ़ गया जब साइमन कमीशन ख्यातिवाले लार्ड साइमन ने विरोधी दल की तरफ से बोलना शुरू किया। वह एक घटे से जरा ही ऊपर बोले। उनका भाषण तर्कपूर्ण नकारात्मकता और निषेधों का आदर्श नमूना था।

इसके बाद लार्ड ट्रेन्चार्ड ने बहुत ही तीखी आलोचना करते हुए भाषण दिया और फिर लार्ड हैलीफक्स भारतीय मामलों में आखिरी बार निर्णायक हस्तक्षेप करने खड़े हुए। बहस में भाग लेने वाले एकमात्र भूतपूर्व वाइसराय वही थे। पार्टी की मान्यताओं और अनुशासन को छोड़ कर उन्होंने कहा

“अपनी जानकारी के आधार पर मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि और कोई चीज चाहे गलत रही हो या सही, लेकिन यह कदम तो हर हालत में गलत है ही। क्योंकि सच तो यह है कि भारत की समस्या का कोई ऐसा हल नहीं है जो गंभीरतम आपत्ति और गहनतम खतरे से भरा न हो। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ—इसके दोषों के बावजूद—कि मैं तब तक सम्राट की सरकार के निर्णयों की निन्दा करने को तैयार नहीं हूँ जब तक कि मैं ईमानदारी और विश्वास के साथ इससे अच्छा हल न सुझा सकूँ। मुझे खेद होगा यदि इस क्षण इस सभा की ओर से भारत को जो सन्देशा भेजा जा रहा है, उसमें केवल निन्दा ही भरी हो; हालाँकि मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि यह निन्दा असफलता, निराशा और आशकाओं की स्वाभाविक भावनाओं पर आधारित है।”

लार्ड सेमुअल ने बाद में मुझसे कहा कि लार्ड सभा में उन्होंने जितने भाषण सुने, उनमें यह सबसे अधिक प्रभावशाली था और इसका इतना अधिक असर पड़ा कि बहुत से अनुदारदली लार्डों ने, जिन्होंने उनके खड़े होने से पूर्व सरकार के खिलाफ मत देने का फैसला कर लिया था, उनके भाषण के दौरान में अपने विचार बदल



डाले। वे टैम्पलवुड से की गई उनकी इस अपील से सहमत हो गए कि “सभा को मतदान लेने की आवश्यकता से बचाए।” शेष बहस में दम नहीं था। जनमत का ज्वार पलट गया था। लार्ड टैम्पलवुड ने अपनी आलोचना कायम रखते हुए अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

लंदन, बुधवार, ५ मार्च १९४७

हालाकि कामन्स सभा में दो दिन की बहस का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण सप्ताह की अवसर था, फिर भी जब मैंने क्रिप्स को अपने स्वाभाविक समय और सुस्पष्टता के साथ सरकारी पक्ष की वकालत करने खड़े होते देखा, तो मैं यह सोचने बिना न रह सका कि नई नीति की मुख्य लड़ाई तो पहले ही लार्ड सभा में जीती जा चुकी है। क्रिप्स के भाषण हमेशा इतने तर्कयुक्त और इतने सुयोजित होते हैं कि जब वह बोलते हैं तो भावनाओं का पारा तुरन्त गिर जाता है। आपके दिमाग को अनुकूल करने का प्रयास करने के पहले वह आपके दिल को अपील करने की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन इस बार उनके भाषण में मुझे हमेशा से अधिक गहरे आत्मविश्वास का आभास मिला।

भारत की भावी स्वाधीनता में क्रिप्स ने जो योग दिया, उसका स्थान पहले ही इतिहास में सुरक्षित हो चुका था। जैसा कि लार्ड हैलीफेक्स ने कहा था, १९४२ की क्रिप्स-मिशन योजना एक ऐसा निर्णायक कदम था, जिससे वापस नहीं लौटा जा सकता था। १९४६ के मन्निमडलीय मिशन की वह सबसे बड़ी हस्ती थी। दोनों बार की चर्चाओं में वह पूरी सहमति और निर्दोष सफलता के बहुत नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी क्षण में उनके प्रयासों को निष्फल होना पड़ा था।

वह यह समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि प्रशासकीय और सैनिक दृष्टि से १९४८ के बाद भारत में रुके रहना असंभव है। इसके अलावा उन्होंने समय की मर्यादा पर कोई विशेष जोर नहीं दिया और न लार्ड वेवल की ही कोई चर्चा की। लार्ड वेवल के सम्बन्ध में कुछ न कहना निःसंदेह एक खेदजनक बात थी, जिससे इन दुर्भाग्यपूर्ण अफवाहों को बल मिला कि सरकार और लौटनेवाले वाइसराय के बीच गंभीर मतभेद है। क्रिप्स ने सारे भाषण में सशोधित मन्निमडलीय मिशन-योजना के लिए दरवाजा खुला छोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है, जब सारे भारत के, जिसमें दोनों सम्प्रदायवाले सब जगह फैले हुए हैं, व्यापक हितों को अलग-अलग सम्प्रदायों, अथवा उस महादेश के इस या उस भाग के सकीर्ण हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाय।”



लार्ड वेवल को क्यों एक तरफ हटा फेंका गया है। उन्होंने जोर दिया कि जब वह वापस आवे तो उनसे व्यक्तिगत वक्तव्य देने को कहा जाय।

जहाँ तक नये वाइसराय का सम्बन्ध है, "क्या वह परिस्थिति को सभालने का नया प्रयत्न करेगा, या उन्हें तथा दूसरे प्रतिष्ठित अधिकारियों को डेरा-डडा उठाने के लिए भेजा जा रहा है?" मुझे कहना पड़ता है कि सारी कार्यवाही ऐसी दिखलाई देती है कि सरकार एक विपादपूर्ण और विनाशकारी सौदे को छिपाने के लिए युद्धकाल के हमारे तेजस्वी नेताओं का उपयोग कर रही है।"

इसके पश्चात् चर्चिल भविष्यवाणी के क्षेत्र में उतर आये. "भारत का न केवल विभाजन किया जायगा, वरन् उसको अनेक खंडों और वह भी बेतरतीब खंडों में बांट दिया जायगा। समय की मर्यादा बाधने से भारतीय दल होश में न आयेंगे, वरन् अपनी मांगें बढ़ा देंगे। इन दलों के भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने के दावे झूठे हैं। इन तथाकथित राजनैतिक वर्गों के हाथ में भारत का शासन सौंप कर हम मिट्टी की मूरतों के हाथ में सत्ता सौंप रहे हैं। कुछ ही वर्षों के बाद इनका नाम-निशान भी न रहेगा। सरकार अपने नये काम से यह पन्द्रह महीने की मर्यादा बाध कर नये वाइसराय को अपाहिज किये दे रही है।"

भारत के लिए समय की मर्यादा का निश्चित किया जाना उन्हें अनावश्यक लगा, जबकि फिलस्तीन के लिए उसका अभाव उन्हें खटक रहा था। क्या सभा विश्वास करेगी कि आज विशाल भारत में जितनी ब्रिटिश सेना है, उससे तीन या चार गुना नन्हे से फिलस्तीन में है? हमारी सेना के इस बटवारे में उन्हें कोई तर्क नजर नहीं आता था। उनका एकमात्र रचनात्मक सुझाव यह था कि सेना के बटवारे का यह अनुपात उलटा कर दिया जाय-और विल्कुल चर्चिलवादी ढंग से उन्होंने यह चर्चित करनेवाला सुझाव रखा कि जिलियाकस के सुझाव को स्वीकार कर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या को संयुक्त राष्ट्र-संघ के सामने रख दिया जाय। अन्त में वह इस दुःखद निष्कर्ष पर पहुँचे, "ब्रिटेन को उसके शत्रुओं से तो बहुतो ने बचाया है, लेकिन खुद के खिलाफ उसे कोई नहीं बचा सकता, किन्तु कम-से-कम एक बात तो हम जरूर कर सकते हैं। ऐसी शर्मनाक भागदौड़ मचाकर और ऐसी जल्दबाजी के साथ कुसमय अपना डेरा-डडा उखाड़कर अपने दुःख के चुभते गूलों पर शर्म की कालिख तो न पोते।"

जब एटली सरकारी पक्ष की ओर से बोलने को खड़े हुए उस समय वायुमंडल में प्रतीक्षा व्याप्त थी, जो पहले दिखलाई नहीं पड़ती थी, बल्कि कल जब क्रिप्स बोल रहे थे, उस समय मजदूर दल के सदस्यों की कमी से मुझे आश्चर्य हुआ था। प्रश्नों के बाद वे सभी उठ कर बाहर चल दिये थे और तबतक सामूहिक रूप में नहीं लौटे जबतक कि दूसरे दिन शाम को प्रधान मंत्री ने वहस का अन्त नहीं किया।

एटली ने लोगों को निराश नहीं किया। मैंने विविध विषयों पर एटली के

अनेक भाषण सुने हैं, परन्तु भारत पर, जो उनका विशेष विषय है, उनका भाषण सुनने का मेरे लिए यह पहला ही अवसर था। साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में उनका दो वर्ष काम करना स्पष्टतः उनके जीवन का बहुत ही प्रभावकारी अनुभव था। इतिहास की दृष्टि से साइमन कमीशन के बारे में यही सबसे खास बात थी। जो लोग चर्चिल तथा एटली के बीच का अन्तर समझने में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें भारतीय पहलू की प्रधानता को नहीं भूलना चाहिए।

इस अवसर पर एटली ने अपने मशहूर प्रतिद्वन्द्वी पर तर्क के इतने शक्तिशाली शस्त्र चलाए, जिनकी मैं उनसे अपेक्षा नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने नोट अलग रख दिए और सीधे हृदय से बोलना आरम्भ किया, जिसके फलस्वरूप प्रभावशाली शब्दों का प्रवाह फूट पड़ा। इससे उनकी गैली में तो अन्तर नहीं पड़ा, किन्तु उनका भाषण असाधारण हो गया। इस व्यक्ति के अन्तः में एक आग छिपी हुई थी और एक आध्यात्मिक ईमानदारी इसको बल पहुँचाती थी। जब कभी कोई महान अवसर आ उपस्थित होता, वही ईमानदारी इसे ऊँचे उठने में सहायक होती।

चर्चिल को उन्होंने नाजुक व्यंग्यों से भेद डाला। यह एक ऐसी भिडन्त थी, जिसे कभी-कभी साधारण जनता नहीं समझ पाती, परन्तु जो निर्णायकों की दृष्टि में विजय सूचक होती है और सदन के अखाड़े में बाजी मार लेती है।

एटली ने इस सिद्धांत का प्रतिवाद किया कि वेवल के व्यक्तिगत वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “यदि गेद फेंकनेवाले को बदलना हो तो सदैव लम्बे-चौड़े स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती।” जहाँ तक इस बात की आलोचना का सवाल था कि भारतीय नेताओं को सरकार में शामिल क्यों किया गया और कामचलाऊ शासन क्यों चालू रखा जाता है, उन्होंने कहा, “भारतीय समस्या का सार ही यह है कि वहाँ के राजनीतिज्ञों को यह समझने दिया जाय कि वे समस्याएँ क्या हैं, जिनका सामना उन्हें आगे चलकर करना पड़ेगा। बीते जमाने में हमने जो सुधार किये उनमें सबसे बड़ा दोष यही था कि हमने जिम्मेदारी की बजाय गैर-जिम्मेदारी सिखाई है। सारे भारतीय नेता विरोधी पक्ष में रहते चले आ रहे थे। अपने लंबे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमेशा विरोध में बने रहना कोई अच्छी चीज नहीं है।” इसके बाद उन्होंने अल्प सख्यको के प्रति हमारी जिम्मेदारी का विषय छोड़ा। इस बारे में उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि चूँकि परिगणित जातियाँ हिन्दू समाज-व्यवस्था का अंग हैं, इसलिए ब्रिटिश राज इच्छा रहते हुए भी उनका उत्थान नहीं कर सका। एक-दो अपवादों को छोड़कर हमारी नीति मौजूदा आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को स्वीकार कर लेने की थी।

“फिर अब, जब कि हम अपनी सत्ता समेट रहे हैं, हममें यह क्यों कहा जाता है कि हम इन सब बुराइयों को साफ करके जायँ, नहीं तो हम जिम्मेदारी से भागने

के अपराधी होंगे ? यदि कोई जिम्मेदारी थी तो उसे बहुत पहले पूर्ण किया जाना चाहिए था। मल बात यह है कि विलम्ब करने और लटके रहने में उतना ही बड़ा खतरा है, जितना कि आग बढ़ते जान में।” उन्होंने यह कह कर अपने भाषण को समाप्त किया,। मुझे विश्वास है, समस्त सभा नय वाइसराय और उनके मिशन के प्रति शुभकामना प्रकट करेगी। यह विश्वासघात का नहीं, बल्कि उद्द्वेग-पूर्ति का मिशन है।”

प्रधानमंत्री के भाषण और खासकर उसके आखिरी भाग ने मौन रहनेवाले उनके समर्थकों को जगा दिया। भारत के प्रति सकीर्ण और निष्क्रिय दृष्टिकोण रखनेवाले ये सदस्य उत्साह से उफन उठ। जब मत लिये गए तो ३३७ सरकार के पक्ष में और १८५ विपक्ष में आये।

हालाकि श्री एटली की यह अपील कि सभा की ओर से भारत के नेताओं और जनता को सद्भाव का संयुक्त सन्देश भेजा जाय, दलों के आधार पर मतदान होना नहीं रोक सकी थी, फिर भी इस ऐतिहासिक बहस से यही धारणा दृढ़ होती थी कि चर्चिल की सजीदा दलीलो के बावजूद सरकार और विरोधी पक्ष के बीच की खाई बहुत ही सकरी है।

लंदन, सोमवार, १० मार्च १९४७

आमतौर पर कहा जा सकता है कि अपने-आपको आगे आनेवाले राजनैतिक काम के लिए तैयार करने में माउन्टबेटन ने बिल्कुल सिर से शुरुआत की थी। वह भारत जा चुके हैं। पहली बार प्रिंस ऑव वेल्स की १९२१ की यात्रा के समय उनके ए. डी. सा. के रूप में गये थे, फिर, अक्टूबर १९४३ और अप्रैल १९४४ के बीच सर्वोच्च मित्रराष्ट्रीय कमांडर के रूप में नई दिल्ली उनका प्रधान कार्यालय रहा था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान पर अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली मुलाकात हुई। लार्ड वेवल के सुझाव पर नेहरू प्रवासी भारतीयों को देखने मलाया गये थे। यह बहुत ही सफल और सुखद भेंट थी। मैं इस मौके पर मौजूद था और स्पष्ट था कि दोनों व्यक्तियों ने एक-दूसरे पर गहरा असर डाला था।

अपनी नियुक्ति की घोषणा होते ही माउन्टबेटन मुलाकातों और बैठकों के ताते में पड़ गये। वह सम्राट से मिल चुके थे, जिनकी वैधानिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था। मंत्रिमंडल की भारत-वर्मा-कमेटी से भी वह लगातार चर्चा कर रहे थे। इस कमेटी में एटली, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लारेस सम्मिलित थे और सरकार की भारत-सम्बन्धी नीति निश्चय करने और उसके नियंत्रण का

काम इसी के जिम्मे था। सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुखों और इंडिया आफिस के विशेषज्ञों में भी विस्तार में चर्चाएं हो चुकी थीं।

सबसे अधिक ध्यान दिया गया था गवर्नर जनरल को दिये जानेवाले आदेश-पत्र के मशौदन के प्रश्न पर। यह आदेश-पत्र सरकारी निर्देशों का लेखा होता था, जिनपर अमल करना गवर्नर-जनरल का कर्तव्य था। अगले लिए नया आदेश-पत्र जारी करवाने में माउन्टबेटन का काफी हाथ था। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री एटली की ओर से उनको लिखे गये एक पत्र के रूप में यह आदेश-पत्र दिया जाय।

यह स्वीकार हो जाने पर उसका समविदा तैयार करने में भी उनका काफी हाथ रहा। आदेश-पत्र में नीति-सम्बन्धी निम्नलिखित लक्ष्य उनके पथ-प्रदर्शन के लिए शामिल किये गए

१ ब्रिटिश सरकार का निश्चित उद्देश्य ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिलाकर एक एकात्मक सरकार की स्थापना करना है। इस सरकार की स्थापना मंत्रिमंडल-मिशन योजना के अनुसार विधान सभा द्वारा की जायगी और जहां तक संभव होगा यह सरकार "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत" रहेगी। ये शब्द "ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत" माउन्टबेटन के विशेष आग्रह पर जोड़े गए। उनकी धारणा थी कि उन्हें ऐसा ढल निकालने का प्रयास करना चाहिए जिससे इतनी सद्भावना पैदा हो कि भारतीय दल राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत रहना पसन्द करें।

२ चूंकि मंत्रिमंडल-मिशन-योजना दोनों बड़े दलों की रजामन्दी से ही ब्रिटिश भारत में लागू होगी, इसलिए किसी भी दल पर उसके स्वीकार करने के लिए जोर डाले जाने का मवाल नहीं उठता। यदि १ अक्टूबर तक माउन्टबेटन को ऐसा लगे कि एक सरकार के आधार पर समझौता होने की कोई संभावना नहीं है तो वह ब्रिटिश सरकार के सामने सुझाव रखे कि निश्चित तिथि पर मत्ता हस्तान्तरण किये जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

एटली के पत्र में जितने महत्वपूर्ण आदेशों का उल्लेख है, उतने महत्वपूर्ण आदेश शायद ही पहले कभी किसी सरकार द्वारा किसी वाइसराय को दिये गए हों।

लंदन, मंगलवार, ११ मार्च, १९४७

मुलाकातो के ताते में माउन्टबेटन ने विरोधी नेताओं को सम्मिलित करने का विशेष ध्यान रखा है। इसमें से कुछ चर्चाएं बिल्कुल खानगी और अनौपचारिक रही। आज रात को वह लार्ड सेमुअल से पहली भेंट करने के लिए मेरे निवास-स्थान पर आये। लार्ड सेमुअल कुछ मिनट पहले आ गये, माउन्टबेटन बिल्कुल समय पर आये।

उन्होंने जोर देकर लार्ड सेमुअल को यह समझाने का प्रयत्न किया, कि जहां तक उनकी नियुक्ति का सवाल है, उसे बादशाह की हार्दिक स्वीकृति प्राप्त है। बादशाह ने उनसे व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि वह राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर इसे स्वीकार कर लें। एटली ने इस विषय में सारी आवश्यक औपचारिकता पूरी की थी और विरोधी दल का कहना बिल्कुल गलत था कि यह नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री ने ही की थी। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि समय की मर्यादा का विकल्प क्या था? जून, १९४८ भले ही लम्बी अवधि न हो, परन्तु इसकी सिफारिश स्वयं वेबल ने की थी। अपना व्यक्तिगत मत देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय सत्ता ग्रहण करना सबसे अच्छा होगा, जबकि देश में उत्तेजना सबसे कम हो। बंगाल और बिहार हाल के उपद्रवों के बाद लगभग शान्त हो गये हैं, किन्तु पंजाब में सकट अनिवार्य प्रतीत होता था।

कुछ समय से पंजाब की स्थिति में बहुत तनाव था। मिली-जुली सरकार के मुस्लिम प्रधानमंत्री मुस्लिम लीगियों के हाथों हत्या से बचने के लिए पांच महीनों से रात को इस घर से उस घर में छिपते फिरते थे। माउन्टबेटन को लगता था कि शायद सीमाप्रान्त में भी सकट पैदा होगा।

उन्होंने वह चेतावनी दुहराई, जो उन्होंने सर ह्यूबर्ट रेन्स को बर्मा के गवर्नर का पद सभालने के पूर्व दी थी। उन्होंने कहा था कि रेन्स को तबतक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जबतक कि रगून की स्थिति भयानकतम रूप धारण नहीं कर लेती। परन्तु यह कर्तव्य की भावना से जल्दी चले गए। फलतः रगून की हड़ताल के कुछ दिन पूर्व वहां पहुंचे। इससे हड़ताल का कुछ दोष उनके सिर पर भी मढ़ा गया। माउन्टबेटन ने कहा, “जहां तक मेरा सम्बन्ध है, कोई भी मुझे भारत के वर्तमान उपद्रवों के लिए जिम्मेदार नहीं समझेगा। यह मेरे लिए अगली चर्चाओं की दृष्टि से एक बड़ी सुविधा की बात है।”

उन्होंने सलाह मागी कि उन्हें भविष्य में किस दिशा का आन्दोलन करना चाहिए। बाद में अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही देते हुए और मन-ही-मन सोची बात को शब्दों में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “मे खास-खास नेताओं के साथ शिमला में एक सप्ताह तक व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना पसन्द करूंगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट और बेलाग विचार-विनिमय का अवसर मिलेगा।” सेमुअल अधिकतर सुनते रहे, परन्तु उन्होंने सत्ता-हस्तांतरण के बाद सम्राट् की सरकार के साथ वैधानिक संवध कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वाइसराय के पद को कायम रखकर भी शायद ऐसा करना अनुचित न होगा।

मुझे इस भेट की व्यवस्था करने में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उम्र और दृष्टि-कोण के स्पष्ट अन्तर के बावजूद इन दोनों व्यक्तियों में बहुत-कुछ साम्य था। लार्ड सभा में सेमुअल का प्रभाव बहुत अधिक है और आगे आनेवाले महीनों में उनकी सद्भावना लार्ड सभा में उदार दल की शक्ति की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी।

लदन, बृहस्पतिवार, १३ मार्च, १९४७

शायद माउन्टबेटन की सबसे जटिल प्रारम्भिक कठिनाई यह है कि भारत के लिए रवाना होने से पहले भारतीय सिविल और सैनिक कर्मचारियों के (जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सर्विस भी कहते हैं) मुआवजे के प्रश्न पर एक ऐसी नीति कैसे तय करे, जिसे सबका समर्थन प्राप्त हो। इस प्रश्न पर गुरु में ही उन्होंने अपने विचार अपने विशिष्ट उत्साह और दृढ़ता के साथ जाहिर किये थे। जिस हल पर वह आग्रह कर रहे थे, वह आज आखिरी तौर से स्वीकार कर लिया गया था।

जहां तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सर्विसों (कर्मचारियों) का प्रश्न है, गुरु-गुरु में उनसे तीन खास वादे किये गए थे। पहला यह कि वैधानिक परिवर्तनों के कारण उनकी नौकरी खत्म होने पर उन्हें एकमुश्त मुआवजा दिया जायगा, जिसकी दरे युद्धकालीन नौकरियों के मुआवजे से किसी हालत में कम न होगी। इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें एकमुश्त उससे कहीं बड़ी रकम मिलेगी, जितनी उन्हें स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त होती। दूसरा यह कि वे नई भारत सरकार के अन्तर्गत काम करना चाहे या न चाहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनके संवध खत्म हो जायगे। इसलिए मुआवजा उन्हें हर हालत में मिलेगा। तीसरा यह कि नई सरकार के अन्तर्गत काम करने के लिए उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जायगा और यदि नई भारत सरकार इस दृष्टि से उनके लिए नीची दरे तय करने की कोशिश करेगी तो उसका हर प्रकार से विरोध किया जायगा। इसमें यूरोपीय और भारतीय कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया जायगा।



भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने जल्दी ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुआवजा देने के सिद्धांत और शर्तों दोनों के ही बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नई सरकार को अपनी पूर्वगामी सरकार के वादों से नहीं बाधा जा सकता, क्योंकि पूर्वगामी सरकार ब्रिटिश पार्लामेंट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नियंत्रण में काम करनेवाली सरकार थी। उन्होंने कहा कि यदि मुआवजे की दर इस आधार पर ठहराई गई कि वह युद्धकालीन नौकरियों के मुआवजे से कम न होगी तो ब्रिटिश सरकार को उसका भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय मामलों के पार्लामेंटरी अण्डर-सेक्रेटरी आर्थर हेण्डरसन जनवरी में सरदार पटेल को समझाने और इस योजना के लिए राजी करने का निष्फल प्रयास करने दिल्ली गये। इस असफलता से माउन्टबेटन ने अपना विचार नहीं बदला। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि मूल योजना को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि वह सिर्फ अंग्रेजों पर लागू होगी। अगर भारत सरकार भुगतान न करे तो उन्हें यह कहने का अधिकार दिया जाय कि उसे देने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की सरकार लेगी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि अकेले ब्रिटिश सरकार को यह बोझा उठाना पड़ा तो भारतीय पौडपावने की रकम को तय करते समय इस खर्च को ध्यान में रखा जायगा।

: ३ :

## भारत में पहला सप्ताह

वाइसराय-भवन, नई दिल्ली,  
शनिवार, २२ मार्च, १९४७

ठीक १२-३० बजे दोपहर हम पालम के हवाई अड्डे पर उतरे। प्रधान सेनापति फील्ड मार्शल आर्चिबाल्ड हमारा स्वागत करने हवाई अड्डे पर मौजूद थे। यह उनका सौजन्य था, क्योंकि दो घंटे बाद ही माउन्टबेटन का स्वागत करने उन्हें फिर हवाई अड्डे पर आना था। अपने सामान की चिन्ता किये बिना हम वाइसराय-भवन की विशाल मोटरों में सवार होकर चल पड़े।

वाइसराय-भवन में पहुँचते ही हमें बतलाया गया कि हमें वेवल-परिवार के साथ भोजन करना है। वाइसराय के नाते यह उनकी अन्तिम दावत है। यह विश्वास करना कठिन है कि कल सवेरे ही वह यहाँ से प्रस्थान करनेवाले हैं। कैसा अजीब सयोग है कि पहली बार मैं १९ अक्टूबर, १९४३ को दिल्ली आया था—वेवल द्वारा लिखलियगो से पद का भार लेने के ठीक एक दिन बाद।

तीसरे पहर मुख्य सहन और वाइसराय-भवन के दरबार हाल को जानेवाली सीढ़ियों पर बड़ी चहल-पहल थी। गर्वनर जनरल के सवारों और रक्षकों के साथ माउन्टबेटन खली बग्घी में बैठकर पौने चार बजे वहाँ पहुँच गये। लाल मखमल बिछी हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वे ऊपर पहुँचे, जहाँ वेवल-दम्पती ने उनका स्वागत किया। काफी देर तक वह वहाँ खड़े बातें करते रहे, जिससे फोटोग्राफर उनके चित्र खींच सके।

रात के भोजन के पहले और बाद में वेवल और माउन्टबेटन के बीच विचार-विमर्श जारी रहा। माउन्टबेटन ने वेवल से भारतीय समस्या के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

बिना जरा भी समय नष्ट किये माउन्टबेटन ने गांधीजी और जिन्ना को दो सीधे-सादे पत्र भेजकर आशा प्रकट की कि दोनों नेता जल्दी ही उनसे मिलने आ सकेंगे। जहाँ तक गांधीजी का सम्बन्ध था वह उनके बिहार में रहने का मूल्य समझते थे। गांधीजी बिहार के दगाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे। गांधीजी इतने व्यस्त थे कि इस बात में भी शक था कि सोमवार को लाल किले की छाया में प्रारम्भ होनेवाले एशियाई सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आयेंगे।

नई दिल्ली, रविवार, २३ मार्च, १९४७

सबसे ठीक सवा आठ बजे वेवल-दम्पती ने प्रस्थान किया। आज का दिन निश्चय ही हमारे लिए चैन का दिन नहीं था। कल के शपथ विधि-समारोह के प्रचार के विषय में काफी प्रशासकीय घबराहट दृष्टिगोचर हो रही थी। माउन्टबेटन के निवास में जाकर मैंने मनोनीत वाइसराय से कल के समारोह के बारे में चर्चा की।

माउन्टबेटन को नई बात सूझी है—शपथ-विधि के समय उनका छोटा-सा भाषण। जार्ज एब्रेल का तैयार किया पहला मसविदा उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया। मेरा खयाल था कि भाषण का विचार और मौका दोनों उपयुक्त हैं। शाम के भोजन के समय स्वयं माउन्टबेटन द्वारा सुधारा गया मसविदा मेरे सामने आया। इसके एक वाक्य से मुझे चिन्ता हुई। ब्रिटिश सरकार के इस निश्चय पर टीका करने के बाद कि सत्ता हस्तांतरण का काम जून, १९४८ तक पूरा हो जायगा, उन्होंने कहा, “अगर छ महीने के पूर्व कोई हल नहीं निकलता तो उसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए काफी समय नहीं रह जायगा।” मुझे लगा कि इन शब्दों को गलत समझा जा सकता था और इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता था कि समय-मर्यादा से बचाव का यह एक तरीका है। माउन्टबेटन की पहली प्रतिक्रिया तो यह हुई कि चूँकि सरकार ने उन्हें अक्टूबर तक प्रगति की रिपोर्ट देने का अधिकार सौंपा था, इसलिए इसे अभी से कह देने में क्या हर्ज था?

अभी दिन का ठीक एक बजा था और एक ए डी सी ने आकर खबर दी कि वाइसराय महोदय ने अपना भाषण दोहरा लिया है और उसे पत्रों को देने के लिए उन्हें क्या करना होगा ? मुझे यह देख कर राहत मिली कि वह खतरनाक वाक्य उसमें से गायब था ।

नई दिल्ली, सोमवार, २४ मार्च, १९४७

शपथ-विधि के लिए तडके ही उठ बैठा । इसका स्वरूप वेवल की शपथ-विधि के समान था, जो मैं १९४३ में दरबार हाल में देख चुका था । छन से वजने-वाली वही तुरही, जो समारोह की सूचक थी, डकट्टे ए डी सी लोगों का वही जलूस, जिसके साथ चलकर 'हिज एक्सेलेसी' अपने सिंहासनो के पास पहुंचे । इस सब शान-शौकत के बीच माउन्टबेटन ऐसे फबते थे मानो इसीके लिए पैदा हुए हो । 'नाइट ऑव गार्टर' का गहरा नीले रंग का फीता और सीने पर सम्मान के अन्य तमगे और पट्टियां पहने लार्ड माउन्टबेटन बहुत प्रभावशाली लग रहे थे ।

लेडी माउन्टबेटन सुकुमारता की साकार प्रतिमा प्रतीत हो रही थी । नये ताज के अलावा वह अपने सब युद्धकालीन तमगे और अन्य सम्मानीय फीते सफेद जरी की पोशाक के ऊपर लगाये हुए थी । कीमती लाल मखमल के पर्दों के अन्दर छिपी हुई वस्तियों के हलके प्रकाश में लाल और सुनहला काम किये हुए सिंहासन बड़े भले प्रतीत हो रहे थे ।

भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने माउन्टबेटन को शपथ दिलाना शुरू किया । माउन्टबेटन उनके कहे को दोहराते गए और अपने लम्बे नाम को बोलने में एकवार भी नहीं अटके ।

पूरा समारोह चौथाई घंटे में समाप्त हो गया । माउन्टबेटन के भाषण में केवल चार मिनट लगे । सिंहासनो के दोनों ओर नये भारत के नेता खड़े थे, जिनके कंधों पर आनेवाले सप्ताहों में इतनी भारी जिम्मेदारी पड़नेवाली थी । मैंने देखा कि नेहरू और लियाकतअली दोनों ने भाषण को बड़े गौर से सुना । इस भाषण से उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ।

दो महत्वपूर्ण लोग इस समारोह से गैरहजरि थे—और गायद बिना कोई वजह बतलाये । ये थे नवाब भोपाल और महाराजा वीकानेर । नवाब भोपाल और महाराजा वीकानेर दोनों माउन्टबेटन के पुराने दोस्त थे। राजा लोग समारोहों से सम्बन्धित गिण्टाचार को, और खासकर वाइसराय से सम्बन्धित समारोह को बहुत महत्व देते थे । यह बात ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता था कि उनकी अनुपस्थिति उनके बीच पैदा हुई फूट और संघर्ष का अच्छा-खासा संकेत था ।

माउन्टबेटन ने आज तीसरे पहर तीन घंटे नेहरू और दो घंटे लियाकतअली के

साथ बिताए। उन्होंने लियाकत के बजट पर चर्चा की, जो इस समय दोनों दलों के बीच झगड़े का कारण बना हुआ था। वेवल ने माउन्टबेटन को चेतावनी दी थी कि जब वह अपनी कार्यकारिणी कौंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो उन्हें इस पेचीदा समस्या से निबटना पड़ेगा। अन्तरिम सरकार के वित्तमन्त्री के नाते सब बड़ी आमदनियों पर भारी कर लगाने का प्रस्ताव कर लियाकत ने कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अपने धनी समर्थकों को बचाने के लिए अब उसे अपनी प्रगतिशील और समतावादी घोषणाओं के प्रतिकूल उनके लिए राहत की माग करनी पड़ेगी। आम भावना यह थी कि कोई समझौते का रास्ता निकल आयेगा, क्योंकि अपने धनी समर्थकों पर कर लगाने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों ही एक सीमा के आगे नहीं जा सकेंगी।

नई दिल्ली, मंगलवार, २५ मार्च, १९४७

मैंने माउन्टबेटन के कर्मचारी-मंडल की पहली बैठक में भाग लिया, जिसमें इस्मे, मिएविल, जार्ज एब्रेल, ब्रोकमेन, अर्सेकिन क्रम और मैं सम्मिलित हुए। माउन्टबेटन का इरादा था कि प्रतिदिन ऐसी अनौपचारिक बैठक हुआ करेगी, जिससे वह अपने विचारों को बिना किसी छिपाव के सबके सामने रख सकेंगे। माउन्टबेटन ने कल नेहरू और लियाकत से हुई मुलाकातों का मजेदार विवरण सुनाया। महाराज बीकानेर और नवाब भोपाल से हुई मुलाकात की बात भी उन्होंने बतलाई, जो शपथ-समारोह के समय अपनी गैरहाजिरी की सफाई देने आये थे।

नवाब भोपाल और महाराज बीकानेर की मुलाकातों से राजाओं में फैली फूट की गम्भीरता का पता चला। इससे नवाब भोपाल बहुत दुखी थे। उन्हें लगता था कि महाराज बीकानेर तथा उनके समान अन्य विद्रोही विधान सभा में भाग लेकर कांग्रेस की कठपुतली बन रहे थे और रियासतों की सोदा करने की ताकत को क्षीण किये दे रहे थे। नवाब भोपाल का विचार था कि समय की मर्यादा का पालन करना असंभव होगा और यदि इसपर अमल किया गया तो खून-खराबी और अव्यवस्था फैलेगी। उन्होंने बड़ी चिंता से माउन्टबेटन से पूछा कि क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। माउन्टबेटन ने कहा कि इससे बचने का एक, सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह यह कि सारे भारतीय दल हमसे यही बने रहने को कहें, जिसकी बहुत ही कम आशा की जा सकती थी। नवाब भोपाल का खयाल था, जैसे-जैसे समय बीतता जायेगा, ऐसा निमंत्रण आ भी सकता है।

माउन्टबेटन ने महाराज बीकानेर से भी इस बारे में चर्चा की। महाराज बीकानेर का खयाल ऐसा नहीं था। उन्होंने तथाकथित 'विद्रोही' राजाओं का समर्थन

किया। उन्होंने फूट को दुर्भाग्यपूर्ण बतलाते हुए इस बात पर जोर दिया कि नवाब भोपाल ने ही अन्तरिम सरकार के प्रति अपने रुख से राजाओं के बीच साम्प्रदायिकता को उभाड़ा है। 'विद्रोही' राजा विधान सभा में भाग लेकर नये केन्द्रीय शासन को अपार बल पहुँचायेंगे और यह प्रयास करेंगे कि वह पूर्णतः कांग्रेसी शासन न बन जाय।

नेहरू के साथ माउन्टबेटन की पहली मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण थी। नेहरू ने मन्त्रिमंडल-मिशन के बाद की सब बड़ी घटनाओं पर अपनी राय दी। माउन्टबेटन का खयाल था कि नेहरू का दिया व्यौरा काफी सही था और उस जानकारी से मेल खाता था, जो उन्होंने लन्दन में प्राप्त की थी। नेहरू की राय में लार्ड वेवल ने एक भारी भूल की थी। उन्हें मुस्लिम लीग को अन्तरिम सरकार में शामिल होने का बुलावा न देकर थोड़ा इन्तजार करना चाहिए था। मुस्लिम लीग शामिल किये जाने की खुद मांग करती। उन्होंने मुस्लिम लीग की एक खानगी बैठक का जिक्र किया, जिसमें जिन्ना पहले ही इस प्रश्न पर घुटने टेक चुके थे।

माउन्टबेटन ने नेहरू से पूछा कि जिन्ना के बारे में उनकी क्या राय है। नेहरू ने याद दिलाई कि अपनी नई पुस्तक में वह इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। फिर भी उन्होंने जिन्ना के व्यक्तित्व के बारे में अपना मार्मिक विश्लेषण उपस्थित किया। नेहरू ने कहा कि जिन्ना के बारे में समझने की खास बात यह है कि वह एक ऐसे इंसान हैं, जिन्हें जीवन में बहुत देर में सफलता मिली—६० वर्ष के बाद। इसके पहले वह भारतीय राजनीति की कोई बड़ी हस्ती न थे। वह सफल वकील थे, लेकिन कोई खास अच्छे नहीं। उनको जो सफलता मिली थी, वह मुख्यतः उत्तेजनाजन्य थी और काफी बड़ी थी। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि उनमें स्थायी रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण पर जमे रहने की क्षमता थी। यही बात वह बड़े एकांगी दिमाग से १९३५ से करते आ रहे हैं। वह बखूबी जानते थे कि पाकिस्तान रचनात्मक आलोचना के सामने ठहर नहीं सकता और उन्होंने यह व्यवस्था कर ली थी कि उसे रचनात्मक आलोचना का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फिर माउन्टबेटन ने नेहरू से पूछा कि उनकी राय में आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। नेहरू ने तुरन्त उत्तर दिया—आर्थिक। इस पर माउन्टबेटन ने पूछा कि जिस ढंग में अन्तरिम सरकार इस समस्या से निवट रही है, क्या वह उससे सन्तुष्ट है? नेहरू ने कहा, "नहीं।" लेकिन स्थिति मुस्लिम लीग ने असंभव बना रखी थी, जो केन्द्र की ओर से की जान वाली आर्थिक योजना की हर कोशिश को नाकाम करने पर तुली हुई थी। अगर ये योजनाएँ सफल हो गईं तो वास्तव में पंजाब के बारे में पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़ जायगा। नेहरू ने सुझाव रखा, जो वह पहले भी रख चुके थे कि पंजाब का शासन साम्प्रदायिक आधारों पर तीन भागों में बांट दिया जाय। इनकी एक केन्द्रीय कमेटी भी रहे,

जो बड़े और असाम्प्रदायिक मसलों की देखरेख करे। वेवल द्वारा इस महीने के आरम्भ में पंजाब पर लागू धारा ९३<sup>१</sup> के अन्तर्गत उत्पन्न गति-अवरोध को मिटाने का उनकी राय में यही एकमात्र ढंग है।

सत्ता-हस्तांतरण के बाद भारतीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों को दिये जानेवाले मुआवजे का पेचीदा सवाल भी इस मुलाकात में उठाया गया। नेहरू का विचार था कि जिन कर्मचारियों को अपने पदों पर बने रहने का न्यौता दिया जा रहा था, उन्हें मुआवजा देने की इच्छा करना पागलपन था। नई सरकार उन्हें पहले की ही शर्तों पर काम पर रखने का वचन देगी। माउन्टबेटन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने वादों में कैसे मुकुरेगी? नेहरू ने कहा कि जहाँ तक ब्रिटिश लोगो का सवाल था, वह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी, उन्हें इतने भारी मुआवजे क्यों दिये जाने चाहिए। इससे उनको अपनी नौकरिया छोड़ने का ही प्रोत्साहन मिलेगा। और भारतीयों के बारे में नेहरू ने कहा कि यह स्थिति यह है कि वे अपने देशवासियों की सेवा ही करते रहेंगे। अभी जो योजना थी, वह वास्तव में प्रमादपूर्ण थी। फिर भी, माउन्टबेटन ने दृढ़ता से इस पर उनके समर्थन की माग की। उन्होंने कहा कि शायद नेहरू ने ब्रिटिश जनता की मन-स्थिति को गलत समझा है। मुआवजे की दर जितनी ऊँची होगी और शर्तें जितनी स्पष्ट, ब्रिटिश सिविल सर्विस कर्मचारियों द्वारा अपने पदों पर काम करते रहने की सभावना भी उतनी ही अधिक होगी।

माउन्टबेटन की राय थी कि नेहरू ने बहुत ही स्पष्टवादिता और न्याय की भावना दिखलाई, बल्कि उन्होंने एक जगह यह सुझाव देकर माउन्टबेटन को चकित कर दिया कि एक ऐसे आगल-भारतीय सभ की स्थापना हो, जिसमें नागरिक समता हो। यह सम्बन्ध वास्तव में राष्ट्रमंडल के दर्जे से कहीं निकट का था। और राष्ट्रमंडल के दर्जे को नेहरू मनोविज्ञान और भावना की दृष्टि से अमान्य समझते थे।

मुलाकात की समाप्ति पर जब नेहरू चलने को हुए तो माउन्टबेटन ने उनसे कहा, “मैं नेहरू, आप मुझे ब्रिटिश-राज का बोरिया-बिस्तर समेटनेवाला अन्तिम वाइसराय न समझकर नये भारत का मार्ग प्रशस्त करनेवाला पहला वाइसराय समझें।” नेहरू ने बड़ी भावुकता के साथ पलटकर देखा और फिर मुस्कराते हुए बोले, “अब मैं समझा कि आपके जादू को लोग इतना खतरनाक क्यों बतलाते हैं।”

<sup>१</sup> यहाँ इशारा भारत सरकार के १९३५ के विधान की धारा ९३ से है, जिसके अन्तर्गत वाइसराय और प्रान्तों के गवर्नरों को यह अधिकार था कि किसी प्रकार की सार्वजनिक गड़बड़ होने पर वे विशेषाधिकारों का उपयोग कर स्वयं शासन की बागडोर संभाल सकेंगे।

लियाकतअली ने चर्चा के समय माउन्टबेटन के शपथ-विधि के समय दिये गए भाषण के बारे में प्रश्न पूछा। वह जानना चाहते थे कि यह किसकी सूझ थी। माउन्टबेटन ने कहा कि इसका उत्तर तो वह तत्काल दे सकते हैं। यह बिल्कुल उनकी सूझ थी और इसके पीछे किसी का हाथ नहीं था, बल्कि मेरे स्टाफ के कुछ लोग इसके खिलाफ ही थे। लियाकत ने कहा, “यह सुनकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि कम-से-कम तीन बड़े ओहदेवाले और जानकार क्षेत्रों ने मुझे विश्वास दिलाया था कि आपने यह भाषण कांग्रेस के अनुरोध पर दिया था।” जिस साम्प्रदायिक सन्देह का वातावरण फैला हुआ था, यह छोटी-सी घटना उसका अच्छा उदाहरण थी। कोई भी पक्ष अपने विरोधी पक्ष को नीचे गिराने के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दे रहा था।

नेहरू के पंजाब से सम्बन्धित सुझावों के बारे में सबसे मजेदार प्रकाश पड़ा पंजाब के गवर्नर सर ईवान जेनकिन्स के तार से। जेनकिन्स ने सूचित किया था कि एक प्रभावशाली सिख नेता ज्ञानी करतारसिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस और लीग के बीच ऐसा समझौता नहीं हुआ, जो सिखों को मजूर हो, तो सिख लोग पंजाब के विभाजन की माग करेंगे। इस बीच वे अपनी सारी शक्ति लगाकर वहाँ मुस्लिम लीग का मन्त्रिमंडल बनाये जाने की हर कोशिश का विरोध करेंगे। इस भाषण का महत्त्व इस बात से और भी बढ़ जाता था कि सिखों ने पंजाब के विभाजन के बारे में एक प्रस्ताव पेश करने के लिए कांग्रेस को राजी कर लिया था। इसे केवल ने माउन्टबेटन के आने के एक सप्ताह पहले स्वीकार भी कर लिया था।

नई दिल्ली, बुधवार, २६ मार्च, १९४७

माउन्टबेटन ने कल रेलवे मंत्री डा. जान मथाई, राजनैतिक विभाग के सेक्रेटरी कोरफील्ड और सरदार पटेल से भेंट की। मथाई ईसाई हैं और किसी भी अर्थ में किसी दल के आदमी नहीं हैं। मथाई का कहना था कि आज की परिस्थिति की सबसे डरावनी बात यह है कि जो लोग बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे-धीरे उनका प्रभाव कम होता जा रहा है और दोनों दलों में उनके प्रति अविश्वास और नापसन्दगी बढ़ती जा रही है। मथाई ने कहा कि उदाहरण के लिए मैंने लियाकत के बजट का भरसक समर्थन किया, पर देखता क्या हूँ कि ‘डान’ मेरे ऊपर बुरी तरह से बरस पड़ा है।

वाडसराय यहाँ ताज के प्रतिनिधि हैं। इस नाते कोरफील्ड का काम उन्हें देशी राज्यों के बारे में हर प्रश्न पर वैधानिक सलाह देना था। कोरफील्ड ने किंचित् कटुता के साथ कहा कि महाराज वीकानेर ने विधानसभा में प्रवेश कर राजाओं की सौदा करने की ताकत बुरी तरह कमजोर कर दी है। इस विवाद में कोरफील्ड

साफ तौर से नवाब भोपाल के हामी थे। सत्ता-हस्तांतरण में वह राजाओं को एक भावी तीसरी शक्ति के रूप में देखते थे।

सरदार पटेल से अपनी मुलाकात के बारे में माउन्टबेटन जरा शक्ति थे। सरदार पटेल कांग्रेस हाई कमान्ड के लौह पुरुष के रूप में विख्यात थे। लेकिन सरदार पटेल की आंखों में हँसी की चमक देखने में उन्हें देर नहीं लगी। सारी समस्या के बारे में उनका दृष्टिकोण साफ और अटल था। भारत को मुस्लिम लीग से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। लीग वास्तव में पंजाब की घटनाओं के बारे में घमण्ड से छाती फुलाये घम रही थी। जरूर उसका दिमाग खराब था। जबतक उन्होंने मुआवजे की समस्या पर हाथ नहीं रखा तबतक तो शान्ति रही, लेकिन इसकी चर्चा छिड़ते ही पटेल ने हाथ ऊँचाकर कसम खाई कि यदि किसी भारतीय ने मुआवजा लेना मंजूर किया तो उसे फिर कभी नौकर नहीं रखा जायगा।

भारतीय सिविल सर्विस के मारिस जिनकिन के यहाँ रात के खाने पर के एम पणिकर भी मौजूद थे।

मनें उनसे पूछा, “अगर आप माउन्टबेटन की जगह होते तो क्या करते?” उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया कि नौसेना की युद्ध-नीति में निपुण माउन्टबेटन को समझना चाहिए कि ब्रिटेन का हित एक ठोस केन्द्रीय राज्य का निर्माण करने में ही है। यह भारत के विशाल समुद्रतट, तीस करोड़ से अधिक आबादी और भौगोलिक एवं धार्मिक एकता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हाथी है और पाकिस्तान उसके दो कान हैं। हाथी अपने कानों के बिना भी काम चला सकता है। बिना लाग-लगाव के उन्होंने स्वीकार किया कि जिन्ना की मांग मूलतः तर्क-संगत है। चार कमरों वाले घर में से वे केवल एक कमरा ही मांग रहे हैं। लेकिन वह चाहते हैं कि इस कमरे में किसी और का दखल न रहे। स्थानीय मुस्लिम बहुमत को वह एक केन्द्रित और मजबूत हिन्दू सरकार के हाथों नहीं सौंपना चाहते। पणिकर का विचार यही था कि भारत बुनियादी तौर से जितनी एकता चाहता है उससे बड़ी एकता हमें उसपर नहीं लादनी चाहिए। पंजाब के बारे में नेहरू के त्रि-दली सुझाव कांग्रेस द्वारा हिन्दुस्तान-पाकिस्तान विभाजन स्वीकार किये जाने का पहला संकेत है। सिखों के साथ उन्हें जो अनुभव हुआ था उससे जिन्ना समझ गये होंगे कि पंजाब की एकता बिल्कुल असंभव थी।

फिर उन्होंने राजाओं की समस्या की चर्चा छोड़ी। बीकानेर के दीवान और प्रमुख सलाहकार के नाते पणिकर का पद बड़े महत्व का था। उन्होंने और जयपुर के दीवान सर वी टी कृष्णमाचारी ने राजपूताने के राजाओं की तरफ से पहल की थी। पणिकर मानते थे कि नरेन्द्रमडल के वर्तमान चांसलर नवाब भोपाल हिन्दू रियासत के मुसलमान शासक होने के नाते बड़ी मुश्किल में पड़ गये हैं। उनका कहना था कि किसी रियासत को व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाना



चाहिए। जो कुछ भी किया जाय, वह सामूहिक रूप से और चासलर की सलाह से, किन्तु यह कहकर चासलर के नाते वह सार्वभौमता के एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे। पणिक्कर ने कहा कि सार्वभौमता की उनकी जो कल्पना है, इसमें चासलर को इस बात में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था कि कोई राजा विधानसभा में जाना चाहता है या नहीं। यह बात तो उस राज्य-विशेष और ब्रिटेन से सम्बन्ध रखती थी और इस पर सीधे ताज के प्रतिनिधि की ओर से आये आदेश का भी असर पड़ सकता था।

सोलह बड़ी रियासतों में से लगभग दस ने विधानसभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिये थे। राजाओं के बारे में ब्रिटेन द्वारा युद्धोत्तर-काल की परिस्थिति के अनुसार विचार किया जाना भी जरूरी था। जबतक राजा लोग ब्रिटेन की "फूट डालो और राज करो" नीति के मोहरे रहे, तबतक वे राज के शक्तिशाली स्तम्भ बने रहे। लेकिन ब्रिटिश राज के ढीला पड़ते ही राजाओं की शक्ति अपने-आप घटने लगी। लाचार उन्हें अब उस राजनैतिक ढाँचे के नीचे शरण लेनी पड़ेगी जो ब्रिटिश राज की जगह लेगा। उत्तरी भाग के राजाओं—जोधपुर, जयपुर, बड़ौदा, पटियाला और बीकानेर—की स्थिति ऐसी ही थी। पटियाला दिल्ली से केवल एक सौ चालीस मील है।

हालांकि राजाओं के साथ फरवरी में अपनी सात दिन की चर्चाओं में नेहरू कम-से-कम पांच बार यह बात दोहरा चुके थे कि कांग्रेस के साथ वे जो भी समझौता करेंगे वह बिल्कुल अपनी इच्छा से होगा। कांग्रेस किसी राजा को जोर या दबाव से समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगी। फिर भी राजाओं के सामने विकल्प यही था कि या तो शामिल हो या खत्म हो जाय। निजाम की ही बात लीजिए। उन्हें अपने साथ शामिल करना और उनके साथ दृढ़ता का व्यवहार करना श्रेयस्कर होगा। किन्तु पणिक्कर ने दबाव डालने की सिफारिश नहीं की। वहाँ की ८६ प्रतिशत आबादी हिन्दू है। उसका बाहर रहना असंभव था। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत काश्मीर की स्थिति बड़ी कठिन थी, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ के महाराज जिन्ना के साथ अपने भाग्य का गठबन्धन करने को लालायित होंगे। पणिक्कर ने कहा कि विधान-सभा में शामिल होने के पीछे राजाओं का खास उद्देश्य यह था कि वहाँ जाकर कांग्रेस के दक्षिण पक्ष को मजबूत वनावे।

अन्त में मैंने पणिक्कर से दोनों दलों के सामाजिक ढाँचे के बारे में उनकी राय पूछी। उन्होंने माउन्टबेटन के इस मत की पुष्टि की कि आगे चल कर कांग्रेस के कई टुकड़े हो जायेंगे। उनकी धारणा थी कि मुस्लिम लीग ज्यादा संगठित है, क्योंकि उसमें औद्योगिक अमीरी और गरीबी के चरम सिरो का अभाव था। जो इने-गिने धनी मुसलमान थे भी, वे मुख्यतः जमींदार थे। मुसलमानों का शोषण मुख्यतः हिन्दू पूजापतियों के हाथों होता था।



सुविधा प्राप्त थी, क्योंकि गांधीजी उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति मानते थे। परन्तु उन्होंने चेतावनी दी कि महात्मा गांधी के साथ बातचीत का अनुमान पहले से नहीं किया जा सकता। उसमें सदैव यह खतरा बना रहता था कि कहीं गांधीजी किसी विषय-विशेष को पकड़ कर विचाराधीन विषय को एक ओर न कर दे।”

वापस लौटा तो १० बज रहे थे और कर्मचारी-मंडल की बैठक का समय हो गया था। बैठक में माउन्टबेटन की गांधीजी के साथ तीसरे पहर होने वाली बातचीत की योजना पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया गया। इस भेंट में स्वभावतः पत्रों को बहुत दिलचस्पी थी। ३ बजे गांधीजी आये। उस समय इस महादेश का शायद प्रत्येक मान्यता-प्राप्त फोटोग्राफर ‘मुगल उद्यान’ में मौजूद था।

प्रारम्भिक अभिवादन के पश्चात् माउन्टबेटन-दम्पती उन्हें इस ‘तौपखाने’ का सामना करने के लिए ले गए। गांधीजी ने माउन्टबेटन-दम्पती से विनोद करते हुए अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक यह अग्नि-परीक्षा दी। कैमरावाले इस प्रयत्न में थे कि बहुत बढ़िया चित्र लिया जा सके और गांधीजी ने उनकी परस्पर-विरोधी मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया।

सबसे बढ़िया चित्र अमरीकी असोसिएटेड प्रेस के कुशल फोटोग्राफर मैक्स डेस्फर को मिला। वह उस समय तक प्रतीक्षा करता रहा, जबतक कि आयोजित चित्रों की धूम-धाम मिट नहीं गई। बाद में उसने सच्चे कलाकार की दृष्टि से देखा कि गांधीजी ने माउन्टबेटन के शीतल बैठकखाने में जाते समय लेडी माउन्टबेटन के कंधे पर अपना हाथ रख लिया था। यही चित्र उसने लिया। गांधीजी ने अपने इस कार्य से लेडी माउन्टबेटन के साथ ठीक वही व्यवहार किया, जो वह प्रार्थना-सभाओं में जाते समय अपनी पौत्रियों के साथ करते थे। गांधीजी के प्रत्येक सकेत में जाने-अनजाने, कुछ प्रतीकात्मक अर्थ होता था और आज तीसरे पहर की यह घटना हार्दिक मित्रता की प्रतीक थी।

आज बातचीत सवा दो घंटे चली। उसके अंत में माउन्टबेटन ने मुझे बुलाया और तुरंत प्रेस-विज्ञप्ति निकालने पर विचार-विनिमय करने के लिए गांधीजी से मेरा परिचय कराया। गांधीजी ने, जो बहुत मद और किंचित् अस्पष्ट स्वर में बोल रहे थे, कहा कि उन्हें विज्ञप्ति के मसविदे को वाइसराय पर छोड़ देने में प्रसन्नता होगी।

गांधीजी के जाने के बाद माउन्टबेटन ने मुझे बताया कि सारी भेंट जानबूझ कर मस्मरणी में बताई गई। पहले सवा घंटे लेडी माउन्टबेटन भी उपस्थित थी और वह मंत्री का वातावरण उत्पन्न करने में मदद कर रही थी। बाद का एक घंटा हम दोनों ही के बीच में व्यतीत हुआ। माउन्टबेटन ने मंत्रीभाव बढ़ाने की दृष्टि में त्राट्कालिक राजनैतिक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं छोड़ी।

गांधीजी ने इंग्लैंड तथा दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रारम्भिक जीवन तथा अन्य

वाइसरायो के साथ अपनी भेटों की चर्चा की। माउन्टबेटन के कथनानुसार, वार्ताएँ गाधीजी के दिल्ली-वास के शेष एक सप्ताह तक चलती रहेंगी। वह उनके साथ ज़ल्दबाजी न करने का पक्का सकल्प कर चुके हैं।

यह सब वैसे तो बड़ा अच्छा होता है, किन्तु सवाददाताओं को समझाना उतना सरल नहीं। उनके लिए विश्वास करना कठिन होगा कि बातचीत में महत्वपूर्ण फैसले नहीं किये गए।

जितनी जल्दी हो सका, मैंने एक विज्ञप्ति तैयार की और उसपर माउन्टबेटन की स्वीकृति लेकर बाहर गया, जहाँ सवाददाताओं की भारी भीड़ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।

मैंने पढ़ना आरम्भ किया, “वाइसराय तथा लेडी माउन्टबेटन ने आज सायंकाल गाधीजी से भेट की और उनके बीच ७५ मिनट तक अत्यन्त मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई।”

मेरे दम लेने के पहले ही एक उत्सुक सवाददाता ने विरोध किया कि यह सच नहीं हो सकता। वह जानता था कि महात्माजी वहाँ दो घंटे से अधिक रहे थे। शेष सवाददाताओं में भी कुछ कानाफूसी होने लगी। मैंने आगे के शब्द पढ़े, “इसके बाद वाइसराय तथा गाधीजी ने आत्मीयता के उसी भाव से एक घंटे तक अलग बातचीत की।” अब तो सबको मानना पड़ा कि इस विज्ञप्ति का सत्य के साथ थोड़ा सम्बन्ध होना असंभव नहीं है।

नई दिल्ली, मंगलवार, १ अप्रैल, १९४७

गाधीजी के साथ माउन्टबेटन ने आज दूसरी बार बातचीत की। वह दो घंटे तक चलती रही, लेकिन उसमें ठोस काम की बात केवल पन्द्रह मिनट ही हुई। इस बार भी काफी समय महात्माजी की जीवन-कथा में लग गया। फिर उन्होंने सम्पूर्ण समस्या को हल करने के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वह यह था कि वर्तमान मन्त्रि-मण्डल को भग कर जिन्ना को पूर्णतः मुस्लिम मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाय।

माउन्टबेटन ने पूछा, “जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया होगी?”

गाधीजी ने उत्तर दिया, “जिन्ना कहेंगे—यह धूर्त गाधी की चाल है।”

माउन्टबेटन ने मुस्करा कर प्रश्न किया, “और क्या उनका यह कहना सही न होगा?”

“नहीं”, गाधीजी ने कहा, “मे विल्कुल दिल से कह रहा हूँ।”

उन्होंने माउन्टबेटन से कहा कि आपको दृढ़ता के साथ अपने पूर्वगामियों के पापों के परिणामों का सामना करना होगा। “फूट डालो और राज्य करो”

की ब्रिटिश नीति ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसमें कानून और व्यवस्था कायम रखने के यही विकल्प शेष रह गये हैं कि या तो ब्रिटिश शासन जारी रहे या भारत में खून की होली खेली जाय। हमें खून की होली स्वीकार करके उसी का सामना करना पड़ेगा।

इन भेटों में लगनेवाले समय से वेबल चिढ़ गये थे, परन्तु माउन्टबेटन ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो मैं गांधीजी के लिए दस घंटे भी दे सकता हूँ। गांधीजी की उनपर गहरी छाप पड़ी थी और वह मानते थे कि अब भी उनका महत्त्व सर्वोपरि है।

नई दिल्ली, शुक्रवार, ४ अप्रैल, १९४७

समाचारपत्रों का ध्यान अब भी सीमाप्रान्त पर ही केन्द्रित था। इसमें न आज की कर्मचारी-मंडल की बैठक में वहाँ की स्थिति का, जिसे वह 'दोंगली स्थिति' कहते थे, वर्णन किया। वहाँ ९७ प्रतिशत आबादी मुसलमान थी, किन्तु मन्त्रि-मंडल काग्रेसी था।

त्रावणकोर का भी प्रश्न उठा। भारतीय राज्यों में केवल यही राज्य ऐसा था, जिसके पास पर्याप्त समुद्रतट था। वहाँ यूरेनियम भी मिला था, जिससे प्रभु-सत्ता के विलुप्त होने के प्रश्न को एक नया सामरिक महत्त्व प्राप्त हो गया था।

जरूरत पड़ने पर यूरोपियनों को देश से निकाल ले जाने के तरीके पर भी विस्तार से स्पष्ट चर्चा हुई। जो लोग १९४८ के जून तक भारत से चले जाने के इच्छुक थे उनका एक रजिस्टर तैयार किया जायगा। यात्री-जहाजों की इतनी कमी थी कि साधारण ब्रेडा तक जुटाने का प्रश्न नहीं उठता। माउन्टबेटन का आदेश था कि सब सम्बद्ध लोगों को समझाया जाय कि युद्ध के फलस्वरूप जहाजों की काफी कमी हो गई है। उनका यह भी आदेश था कि इस सबब में जो योजना बनाई जाय उससे ऐसा आभास न हो कि आतंक के कारण भगदड़ मचनेवाली है।

जिनकिन्स के साथ भोजन किया। जिनकिन्स ने बताया कि नेहरू तो गांधी का पश्चिमी रूप है। उन्होंने इस सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया कि पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से ईर्ष्या के योग्य होगा और यह मानना गलत होगा कि वह आर्थिक दृष्टि से जीवित न रह सकेगा। मैंने उनसे इस पर एक घोषणा-पत्र तैयार करने को कहा, क्योंकि मेरे खयाल से माउन्टबेटन को इसमें बहुत दिलचस्पी होगी। दैनिक गतिविधि की भगदड़ में दीर्घकालीन विचारों की बड़ी सरलता से उपेक्षा हो जाती है। दूसरे अतिथि थे डूंगरपुर के महाराजा के छोटे भाई, जो एक प्रतिभा-शाली व्यक्ति थे और जिन्होंने आई सी एस का जीवन अंगीकार किया था। अकबर हैदरी के समान वह भी महसूस करते थे कि १९३५ के भारत शासन-विधान के दूसरे भाग को पुनरुज्जीवित करने का एक प्रयत्न और किया जाना चाहिए।

जिनकिन्स का कहना था कि नेहरू और कांग्रेस ने फोल्ड मार्शल आर्चिनलेक का जो समर्थन किया था उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर फोल्ड मार्शल स्लिम को नियुक्ति दी जायगी, जो सही हो या गलत, अविक मुस्लिम-परस्त माने जाते थे। लियाकत और मुस्लिम लीग द्वारा आर्चिनलेक को उत्तेजित किये जाने का यह भी कारण हो सकता था कि वह उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर करना चाहते हों।

नई दिल्ली, शनिवार, ५ अप्रैल, १९४७

अब प्रथम पख्तुनारे के अंत में माउन्टबेटन की योजना की मुख्य नीति और उसको कुशलता से लागू करने का ढंग निश्चित हो गया। उन्हें बिल्कुल आदि से ही कार्य आरंभ करना पड़ा, लेकिन वक्त बरबाद नहीं हुआ। अब पहला उद्देश्य ऐसा हल निकालना था, जिससे काफी सद्भावना उत्पन्न हो जाय और जिससे भारत के विभिन्न दल राष्ट्रमंडल के अन्दर ही बने रहे। वे मन्त्रि-मंडलीय योजना को जीवित रखने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु वह मानते थे कि यदि जिन्ना की शक्ति और इरादा कायम रहा तो विभाजन की व्यवस्था करनी होगी। वह इस तर्क को स्वीकार करते थे कि यदि केन्द्रीय सत्ता का विभाजन किया जाय तो उन प्रान्तों का भी आवश्यक है, जिनमें दोनों सम्प्रदायों के लोग बराबर बराबर हैं।

योजना कोई भी रूप ग्रहण करे, माउन्टबेटन को आरम्भ से ही विश्वास हो गया था कि राजनैतिक हल की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है और जून, १९४८ की समय की मर्यादा नाकाफी होने के अलावा बहुत लची दिखलाई पड़ती थी। वह राजनैतिक स्थिति के दुःसाध्य होने का खतरा महसूस कर रहे थे। विभिन्न विरोधी दल—कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख—अपने-अपने दावों की होड़ लगाने की पर्याप्त शक्ति रखते थे। परन्तु यदि तुरन्त कोई समझौता नहीं होता तो वह भारत को चीन की जैसी स्थिति में पड़ने से रोक न सकेगे। राजनैतिक हल जल्दी निकल आने का अर्थ है कि फिर निश्चित अवधि में ही जटिल प्रशासकीय समस्या को भी सुलझाना होगा। कर्मचारी-मंडल की सुबह को बैठक जिन्ना के आने तक जारी रही। गांधीजी की पहली भेट के समय जितने फोटोग्राफर थे, उतने इस समय नहीं थे। पत्रकारों के साथ जिन्ना का व्यवहार बहुत औपचारिक और रूढ़ि रहता था। बातचीत खत्म होते ही प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा स्वीकार कराने के लिए मैं माउन्टबेटन के पास गया। उन्होंने सिर्फ एक छोटा-सा सशोधन किया।

माउन्टबेटन आज रात के बदले कल सायंकाल जिन्ना और उनकी वहन के साथ भोजन करेंगे। वह महसूस करते थे कि वह आज ही दूसरी बैठक का श्रम सहन न कर सकेंगे। जिन्ना ने कहा था कि वह अपने-आपको पूर्णतः माउन्टबेटन

की मरजी पर छोड़ देंगे। माउन्टबेटन की पहली प्रतिक्रिया यह थी—“हे भगवान, वह तो विल्कुल बर्फ के समान ठंडे थे। भेट का अधिकतर समय उन्हें पिघलाने में ही लग गया।”

यहां से मैं सीधा भोजन के लिए गया। नेहरू, उनकी पुत्री इंदिरा और इंडोनेशिया के प्रधान मंत्री डा० शहरयार अपनी सुनहरे बालों वाली प्रफुल्ल-बदना उच्च पत्नी के साथ उपस्थित थे। आस्ट्रेलिया के ‘ठिगने’ प्रधान मंत्री डालफस के बाद शहरयार शायद सबसे छोटे राजनीतिज्ञ थे। उच्च अटैची श्री विकलमैन भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे। मैं इंदिरा के पास बैठा। उन्होंने मुझे बताया कि वह लन्दन के कुछ खतरनाक हवाई हमलों का अनुभव कर चुकी थी। एक दिन जब वह पिकेडिली में एक आग लगाने वाला बम बुझाने का प्रयत्न कर रही थी, उन्हें किसी ने हवाई हमले के बार्डन का टोप दे दिया था। उसे उन्होंने अब तक यादगार के रूप में अपने पास सुरक्षित रखा था। वह शिमला जा रही थी।

भोजन के पश्चात् माउन्टबेटन के अनुरोध पर कृष्ण मेनन और इस्मैने गांधीजी के प्रस्ताव के बारे में लेखी बातचीत की। आज यह स्वीकार किया गया कि गांधीजी के कांग्रेस पर अत्यधिक जोर डालने के पूर्व ही नेहरू को स्पष्ट बता दिया जाय कि माउन्टबेटन गांधीजी की योजना से बंधे हुए नहीं थे और उसकी बारीकी से छानबीन करना आवश्यक था। जैसा कि माउन्टबेटन ने आज प्रातः काल कहा था, गांधीजी जिन्ना को मंत्रि-मंडल बनाने का आमन्त्रण देने पर तुले हुए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह इस पर कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर लेंगे।

गाम को माउन्टबेटन-दम्पती के साथ भोजन करनेवाला मैं अकेला ही था और उस समय जिन्ना की महत्वपूर्ण भेट का वर्णन सुना। जिन्ना ने विल्कुल ख़ाई के साथ बातचीत शुरू की थी, “मैं सिर्फ एक शर्त पर बात करूंगा।”

माउन्टबेटन ने बताया, “मैंने उन्हें वाक्य पूरा करने के पहले ही टोक दिया, “जिन्ना साहब, मैं किसी प्रकार की शर्तों पर विचार करने को तैयार नहीं हूँ, बल्कि जबतक आपका परिचय न पालूँ और आपके मुह से आपके बारे में कुछ और जान न लूँ, तबतक वर्तमान स्थिति पर कोई चर्चा ही नहीं करूंगा।”

माउन्टबेटन के रुख में जिन्ना विल्कुल स्तब्ध रह गए। कुछ देर तक वह गुमसुम और अकड़े हुए बैठे रहे। परन्तु अंत में उनका रुख नर्म पड़ा और उन्होंने माउन्टबेटन की इच्छा के सामने सिर झुका दिया। माउन्टबेटन मुनना चाहते थे कि उनकी कोशिशों में मुस्लिम लीग किस प्रकार शक्तिशाली हुई।

नई दिल्ली, सोमवार, ७ अप्रैल, १९४७

कल रात जिन्ना और उनकी बहन ने माउन्टबेटन-दम्पती के साथ भोजन किया।

जिन्ना ने मुसलमानों के कत्लेआम का राग अलापा और उसकी विभीषिकाओं का वर्णन किया। जल्दी ही कुछ किये जाने की आवश्यकता है। “इसके लिए शल्य-चिकित्सा ही करनी पड़ेगी”, माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, “शल्य-चिकित्सा करने के पहले ब्रेहोशी की दवा सुधानी पड़ती है।”

जिन्ना के साथ अपनी इस दूसरी मुठभेड़ से माउन्टबेटन ज्यादा आश्वस्त थे। उनका विचार था कि जिन्ना बातें चाहे जितनी कर लें, लेकिन चलेगी मेरी ही।

जिन्ना ने जोर दिया कि गांधीजी की स्थिति शरारत से भरी हुई है, क्योंकि उसमें अधिकार तो है, पर उत्तरदायित्व कोई नहीं। इसे सिद्ध करने के लिए गांधीजी के साथ हुई विभिन्न वार्ताओं का इतिहास बतलाते हुए अन्त उन्होंने किया क्रिप्स-योजना की अस्वीकृति और सन् बयालिम का आन्दोलन छेड़े जाने की घटना के साथ। व्यालीस के आन्दोलन को उन्होंने महात्माजी की “हिमालय-जैसी भूल” कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सब कुछ हथियाना चाहती है और मुझे पाकिस्तान से महरूम रखने के लिए वह औपनिवेशिक स्वराज्य तक मजूर कर लेगी।

पहली मुलाकात के समय जब माउन्टबेटन-दम्पती और जिन्ना का चित्र खींचा जा रहा था तो जिन्ना ने लेडी माउन्टबेटन के प्रति उदारता दिखलाते हुए “दो काटो के बीच कोमल कुसुम” की बात कही। अभाग्यवश पता चला कि बीच में वह खुद ही थे।

आज शाम की दूसरी बैठक के बाद माउन्टबेटन ने जिन्ना से मुलाकात करने के लिए मुझे अन्दर बुलाया। जिन्ना मेरी ओर बरछी के समान आखों से देखते रहे और बोले कुछ नहीं। फिर माउन्टबेटन के सकेत पर उन्होंने कहा कि यदि मैं उनके निवास-स्थान पर जाकर उन प्रेस-सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करूंगा तो उन्हें खुशी होगी। उनके चले जाने पर माउन्टबेटन ने कहा कि कल वह जटिल चर्चा करने वाले हैं।

नई दिल्ली, मंगलवार, ८ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मंडल की आज की बैठक में लियाकत का एक पत्र पढ़ा गया। इसमें शिकायत की गई थी कि सेना में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। वह चाहते थे कि तुरन्त इनका पुनर्गठन किया जाय, जिससे उचित समय आने पर उन्हें अविलम्ब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच बाटा जा सके। इसमें ने कहा कि लियाकत के पत्र पर कोई कार्रवाई करने का अर्थ होगा राजनैतिक प्रश्न को सकट में डालना। जबतक वाइसराय ब्रिटिश सरकार को इसके लिए तैयार नहीं देते तबतक मन्त्रि-मंडलीय योजना कायम है और योजना में एक सेना की व्यवस्था है।



माउन्टबेटन सहमत थे कि अंग्रेजों के भारत से जाने के पूर्व दो कारणों से भारतीय सेना विभाजित नहीं की जा सकती। 'पहला तो यह कि शासन-यंत्र अनुमति नहीं देगा और दूसरा यह कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।' उन्होंने कहा, "मैंने जिन्ना को यह बतला देने का निश्चय कर लिया है कि मुझे न्याय और व्यवस्था की रक्षा करनी ही होगी। मैं एक दल को नुकसान पहुंचाकर दूसरे की सहायता नहीं करूंगा। यदि विभिन्न प्रान्तों के बीच राजनैतिक सत्ता बांट देने का निश्चय हुआ तब भी प्रतिरक्षा को केन्द्र के अधीन रखना पड़ेगा।" इसमें ने कहा कि जबतक सत्ता नहीं बदलती तबतक ब्रिटिश सेना नहीं जाती। १९३५ का विधान भी तबतक लागू है।

माउन्टबेटन ने गांधी-योजना पर नेहरू के मत की चर्चा की। नेहरू का कहना था कि जबतक सत्ता लेनेवाला कोई उपयुक्त पक्ष सामने न हो तब तक दृढ़ केन्द्र को तोड़ना उचित नहीं होगा। एब्रेल ने कहा कि मुख्य प्रश्न तो यह है मंत्रि-मंडलीय योजना जीवित है या मृत? जिन्ना को जता दीजिए कि उससे इकार करने पर उन्हें क्या मिलेगा? जबतक यह स्पष्ट नहीं किया जाता तबतक वह ठीक रास्ते पर नहीं आयेगे।

नई दिल्ली, बुधवार, ९ अप्रैल, १९४७

आज की बैठक में माउन्टबेटन ने बतलाया कि कल उन्होंने जिन्ना के सामने यह प्रश्न उठाया कि दोनों प्रधान दल साम्प्रदायिक दलों को बन्द कराने के लिए एक अपील निकाले। उन्होंने जिन्ना से साफ-साफ पूछा कि क्या वह वास्तव में इन दलों को रोकवाना चाहते हैं, या ऐसी अपील निकालने से मुस्लिम लीग का राजनैतिक पक्ष कमजोर हो जायगा? आखिर जिन्ना राजी हो गए।

हमने आज फिर नीति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया। इसमें ने जिन्ना के साथ हुई अपनी एक चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना अपनी नीति से पैदा होने वाली शासकीय समस्याओं से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। ब्रिटिश लोगों का काम तो सिर्फ यहाँ से हिसाब चुकता कर चले जाना है। अगर पाकिस्तान देना स्वीकार कर लिया गया तो सब ठीक हो जायगा। लेकिन जिन्ना ने अपनी आशकां व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि उन्हें "धुन लगा पाकिस्तान" ही मिलेगा।

कर्मचारी-मंडल की बैठक के बाद मैं जिन्ना से मिलने उनके निवासस्थान पर गया। १० औरगजेब रोड पर स्थित उनकी कोठी मसजिद के समान लगती थी। उसपर लाल तथा काली पच्चीकारी हो रही थी। एक ताक पर लकड़ी के ऊपर चादी से बना भारत का नक्शा रखा हुआ था। इस में हरे रंग से पाकिस्तान की सीमाएँ दिखाई गई थी। पहली 'मुठभेड़' की अपेक्षा वह इस बार ज्यादा सौहार्द से पेश आये। हमने समाचारपत्रों की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा

कि 'ऑल इंडिया एडीटर्स कान्फ्रेंस'<sup>१</sup> पूरीतौर पर हिन्दू जमात है। मुसलमान अखबारों में से सिर्फ 'डान' पर उनकी मालिकियत है। "हालांकि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इसकी नीति पर कभी सीधा असर डालने की कोशिश नहीं की। इसे मैंने हमेशा एडीटर का काम समझा है और इसे हमेशा उसीकी मर्जी पर छोड़ा है।" फिर उन्होंने बिना मुस्कराहट के कहा, "लेकिन एडीटर हमेशा मेरे खयालों का रहा है।" नोआखाली में मुसलमानों के हाथों हिन्दुओं की हत्या के समाचारों को झूठ बतलाते हुए उन्होंने काफी देर तक उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले इसे कई हजार लोगों का कत्ले-आम कहा गया था, लेकिन बाद में सिद्ध हुआ कि सौ से ज्यादा लोग नहीं मरे और न सौ से ज्यादा घायल हुए। उन्होंने शिकायत की कि भारतीय समाचार-पत्रों के साथ खानगी चर्चा करना असंभव है। लन्दन का अपना अनुभव बतलाते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में जो बातें कही उन्हें कोई छापने नहीं दौड़ा।

आज तीसरे पहर मैंने नेहरू-परिवार के साथ चाय पी। इंदिरा और कृष्ण मेनन ने मुस्लिम लीग के उदय की कहानी बताते हुए कहा कि स्वयं जिन्ना जन्म से हिन्दू है। कृष्ण मेनन ने कहा कि लीग को तब कुछ महत्त्व मिला जब कांग्रेसी सीधी कार्रवाई करनेवाली संस्था बनी। लीग अंग्रेजों के प्रोत्साहन से बढ़ी। कृष्ण मेनन चाहते थे कि मैं 'देशी राज्य प्रजा-परिषद्' के ग्वालियर-अधिवेशन में जाऊँ, जिसमें नेहरू काश्मीर के मुसलमान कांग्रेसी नेता शेख अब्दुल्ला को, जो इस समय जेल में थे, परिषद् की अध्यक्षता सौंपेंगे। केवल राजनैतिक तापमान ही नहीं बढ़ रहा है, भौतिक तापमान भी कल १०० अंश तक पहुँच गया था। जैसा कि नेहरू ने कहा था, "कठिनाई यह है कि हम गर्मी की बात सोचकर ही गरम हो जाते हैं।"

नई दिल्ली, शनिवार, १२ अप्रैल, १९४७

माउन्टबेटन ने जिन्ना के साथ अपनी ताजा बातचीत का हाल सुनाया। जिन्ना ने बड़े नाटकीय ढंग से पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल में रखने के लिए हाथ बढ़ाया, परन्तु माउन्टबेटन पर इसकी कोई प्रतिक्रिया न होने से जिन्ना को बड़ा सदमा पहुँचा।

हमारी आज की आम चर्चा में 'खड योजना' के विरुद्ध 'अखड योजना' के सब विकल्पों पर स्पष्ट और पूर्ण विचार-विमर्श हुआ। माउन्टबेटन ने इस दुविधा के मूल में जाकर यह इरादा किया कि वह कांग्रेस से पूरी मन्त्रिमंडलीय योजना स्वीकार कराने का प्रयत्न करेंगे और फिर जिन्ना से कहेंगे कि या तो वह योजना को स्वीकार करें या कटा-फटा पाकिस्तान लेने को तैयार हो जाय। जार्ज एब्रेल को इसमें शक

<sup>१</sup> अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन।

है कि कांग्रेस अपनी नीति बदलेगी। उत्तरी भाग के प्रांतों पर दबाव डालकर वह पहले ही मुस्लिम लीग को पीछे हटने के लिए बाध्य कर चुकी है।

गांधीजी ने माउन्टबेटन को लिखा कि उनकी योजना कांग्रेस को स्वीकार नहीं है और वह भावी बातचीत का सब भार कांग्रेस कार्य-समिति को सौंप रहे हैं। माउन्टबेटन कहते हैं कि वह कोशिश करेंगे कि गांधीजी दिल्ली में रुके रहें और कांग्रेस में मंत्रि-मंडलीय योजना को स्वीकार कराने में अपने प्रभाव का उपयोग करें। वह महसूस करते हैं कि कांग्रेस में अब भी एक संध की इच्छा बहुत प्रबल है।

संयोग से गांधीजी के पत्र में 'पुनश्च' के बाद एक यह सुन्दर सुझाव भी था कि श्रीमती आसफअली को लेडी माउन्टबेटन से मिलना चाहिए। लेडी माउन्टबेटन ने तुरन्त निमंत्रण भेजा, किन्तु श्रीमती आसफअली ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरे दिन जब गांधीजी वाइसराय से मिलने आये तब श्रीमती आसफअली उनके साथ थी।

गांधीजी ने कहा, "मैंने सुना कि इसने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेता आया हूँ।"

नई दिल्ली, सोमवार, १४ अप्रैल, १९४७

समाचार-पत्रों में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज सवेरे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक लेख में उस संयुक्त 'शांति-अपील' के निकाले जाने की 'भविष्यवाणी' की गई थी, जिसके लिए माउन्टबेटन प्रयत्नशील थे। 'भविष्यवाणी' में बताया गया था कि शांति-अपील गांधीजी, जिन्ना और कृपालानी (कांग्रेस-अध्यक्ष) के हस्ताक्षरों से शीघ्र ही निकाली जायगी। एक बड़ी समस्या यह थी कि कांग्रेस-कृपालानी के हस्ताक्षरों का आग्रह कर रही थी और जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे।

अनिश्चय के कई ओकों के बाद माउन्टबेटन के धैर्य और इच्छाशक्ति की विजय हुई और आज तीसरे पहर गांधीजी तथा जिन्ना के हस्ताक्षरों की अपील की मूल प्रति लेकर मैं सूचना-विभाग में गया। कृपालानी के हस्ताक्षर के बारे में जिन्ना की विजय हुई और उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए नहीं बुलाया गया। गांधीजी ने अपना नाम दो बार, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा।

इस अपील की ध्वनि और सामयिकता में माउन्टबेटन की एक भारी व्यक्तिगत विजय निहित थी। इससे उनके उन प्रयासों को बल मिला जो वह सर्वसम्मत राजनैतिक योजना तैयार करने के लिए कर रहे थे। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके आसपास फैले सद्भाव का पूरा लाभ उन्हें मिल गया। इसका उद्देश्य ऐसा सौहार्द था, जिसके बिना कोई राजनैतिक हल तनिक भी महत्त्व का नहीं हो सकता। यह उनकी खुली कूटनीति की प्रथम विजय थी।

अब आगे की आयोजित कार्रवाईयाँ मई के आरम्भ में शिमले में केंद्रित रहेगी। उसमें इन अतिथियों के उपस्थित रहने की संभावना है—नेहरू, जिन्ना, पटेल, लियाकत, कृपलानी, बलदेवसिंह और शायद गांधीजी, नवाब भोपाल तथा वीकानेर के महाराजा।

देशी राज्यों के रेजीडेंटों की उपयोगी बैठक के बाद अब कल गवर्नरों की बैठक होनेवाली है। माउन्टबेटन ने अपनी योजना का मसविदा गवर्नरों के विचार जानने के लिए भेज दिया था। जबतक उसपर गवर्नरों के विचार ज्ञात न हो जाय तबतक माउन्टबेटन उसे अन्तिम रूप न देगे। माउन्टबेटन की योजना के मोटे सिद्धांत ये थे

१ यदि देश का विभाजन हो तो उसका उत्तरदायित्व पूरी तरह से भारतीयों पर ही रहे।

२ आमतौर पर प्रांतों को अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार हो।

३ मतदान के लिए बंगाल और पंजाब का कल्पित विभाजन करना होगा।

४ आसाम के ज्यादा मुसलमान-आबादी वाले जिले सिलहट को बंगाल के विभाजन से बनने वाले नये मुस्लिम प्रांत में मिलने का विकल्प प्रदान किया जाय।

५ सीमा-प्रांत में आम चुनाव किया जाय।

कुछ गवर्नर वाइसराय-भवन पहुंच गए थे और माउन्टबेटन ने सर फ्रेडरिक बॉर्न (मध्यप्रांत), सर जान कालविल (बंबई) तथा सर आर्चीबाल्ड नाइ (मद्रास) से कुछ बातें भी कर ली थीं। सब गवर्नरों के आ जाने पर माउन्टबेटन-दम्पती को एक ही भवन में ११ गवर्नरों और उनकी पत्नियों, उनके प्राइवेट सेक्रेटरियों तथा अग-रक्षकों का सत्कार करना होगा। ३४० कमरों और डेढ़ मील लम्बे बरामदों के वाइसराय-भवन के लिए भी मेहमानों की यह संख्या काफी बड़ी जान पड़ रही थी।

हैदराबाद के प्रधान मंत्री सर मिर्जा इस्माइल को बॉर्न के साथ बातचीत करने के लिए बुलाया गया था और उनके बीच बरार के संबंध में बातचीत हुई। बरार हैदराबाद राज्य का पुश्तैनी इलाका है और हैदराबाद के युवराज को बरार का शाह-जादा कहा जाता है। परन्तु इसका शासन-प्रबंध मध्यप्रांत के गवर्नर के अधीन है। निजाम इसे अवश्य ही वापस मांगेगा। मिर्जा इस्माइल ने बताया कि निजाम निकट-भविष्य में ही जिन्ना से मिलेगा। जहां तक उनका खुद का संबंध है, वह कहते हैं कि उन पर से निजाम का विश्वास तेजी से उठ रहा है और वह बहुत दिनों तक पदारूढ न रह सकेगा।

माउन्टबेटन के दिये गए भोज में मैं इस्माइल के साथ बैठा। वह नरम विचार, गंभीर प्रकृति और तीव्र बुद्धिवाले मुसलमान हैं। इसीलिए वह अकेले से हैं। उन्होंने मुझसे निजाम के प्रधानमंत्री की उलझनों की मुक्त होकर चर्चा की। निजाम का कोई प्रधानमंत्री चार वर्ष से अधिक पदारूढ रहने की आशा नहीं कर सकता।

इसमें केवल सर अकबर हैदरी, जो वृद्ध थे, अपवाद सिद्ध हुए। वह चौदह वर्ष तक जमे रहे। निजाम की राजनीति इतनी ही थी कि वह अपने प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे और अन्ततः उन्हें उन सब अधिकारों से वंचित कर देते थे, जो उन्होंने उनके लिए दूसरों से छीने थे। इस्माइल के कथनानुसार यह षड्यंत्रों का ऐसा निराशाजनक चक्र था, जिसमें किये-कराये पर पानी फिरने के अलावा कुछ नहीं होता।

: ५ :

## नई योजना पर गवर्नरों के विचार

नई दिल्ली, मंगलवार, १५ अप्रैल, १९४७

आज के पत्रों में गांधी-जिन्ना शांति-अपील बड़े-बड़े शीर्षकों के साथ प्रकाशित हुई। फलस्वरूप बड़े उत्साह के वातावरण में गवर्नरों का सम्मेलन आरम्भ हुआ। माउन्टबेटन ने अपने प्रारम्भिक भाषण में ब्रिटिश सरकार के निर्णय के शब्दों तथा भावों के प्रति वफादारी की धाराप्रवाह और प्रभावोत्पादक अपील की। यदि किसी को शका हो तो उसकी जानकारी के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जून, १९४८ ब्रिटिश-प्रस्थान की पक्की तारीख है।

यूरोपियनों के निष्क्रमण के विषय में पूरी-पूरी चर्चा हुई। कालविल और नाइ—वर्वाई तथा मद्रास प्रांत के गवर्नर—इस विषय पर निश्चित थे। परन्तु पंजाब के प्रतिभाशाली गवर्नर सर ईवान जेनकिन्स ने महसूस किया कि उन्हें पंजाब की स्थिति की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करना ही चाहिए। बिहार के गवर्नर हर ह्यूडो ने बताया कि उनके प्रांत की चार करोड़ जनसंख्या में केवल ५० यूरोपियन कर्मचारी हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि उनके प्रांत में न्याय और व्यवस्था बहुत कम है। आसाम के गवर्नर सर एड्रियु क्लो ने, जो अब रिटायर हो रहे हैं, चाय-वागीचो के मालिकों की चर्चा की। बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक वरोज वीमार थे और सम्मेलन में नहीं आ सके। उनके सैक्रेटरी जे डी टाइसन ने बताया कि बंगाल में २०,००० यूरोपियन हैं और मुफस्सिल जिले में रहने वाले ५,००० के बारे में उन्हें गंभीर चिन्ता है। वह महसूस करते थे कि प्रांत में न्याय और व्यवस्था की रक्षा कर सकने की गुंजाइश बहुत कम है, वहां कम्यूनिस्टों का आन्दोलन दूसरे प्रांतों से अधिक प्रबल है और वह निश्चित रूप से यूरोपियनों के विरुद्ध है।

माउन्टबेटन ने जोर देकर बताया कि यदि भारत में लोगों का आना रोकने के

सबध मे कोई कानून बनाया जाय तो उसे ब्रिटिश मत्रि-मंडल का समर्थन प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है। अन्त मे यह निर्णय हुआ कि यूरोपियनो के आवागमन के संबंध मे समझाने-बुझाने का तरीका काम मे लाया जाय।

इसके पश्चात् मुआवजे के कठिन प्रश्न पर सविस्तार चर्चा हुई। माउन्टबेटन ने अबतक की चर्चाओ का विवरण उपस्थित किया। कालविल ने भारतीयो को मुआवजा दिलाने के सबध मे माउन्टबेटन द्वारा प्रकट की गई कठिनाइयो का समर्थन किया। त्रिवेदी और हैदरी दोनो महसूस करते थे कि भारतीय लोग विशुद्ध देश-भक्ति के कारण नौकरियो मे बने रहना और मुआवजा छोड देना पसन्द करेगे।

दोपहर की बैठक मे विभिन्न गवर्नरो से अपने-अपने प्रात-सबधी रिपोर्टें सुनने के लिए बहस रोक दी गई। सीमाप्रात के बारे मे सर ओल्फ कैरो ने नये चुनाव करने की माग की। सीमाप्रात के प्रधानमंत्री डा खान साहब नये चुनाव नहीं चाहते थे। चुनावो से जिनको सबसे अधिक लाभ होना सम्भव था, वे सब लीग-समर्थक मुसलमान जेलो मे बन्द थे। माउन्टबेटन की राय थी कि यदि सम्भव हो तो अभी कुछ न किया जाय। परन्तु कैरो तने हुए थे और उनके मालम पडते थे। स्पष्ट था कि वह अपने विशाल उत्तरदायित्व के भार से दबे जा रहे थे।

जेनकिन्स ने पजाब के विभाजन के परिणामो का बडा साफ खाका खीचा। उन्होने बताया कि किस प्रकार मुसलमानों तथा गैरमुसलमानों का प्रश्न सिखो और हिन्दू जाटो की मागो से उलझ गया था। टाइसन ने उसी प्रकार बगाल की स्थिति का चित्रण किया। उन्होने कहा कि विभाजन होने पर पूर्वी बगाल एक देहाती गद्दी बस्ती का रूप धारण कर लेगा। बगाल मे ढाई करोड—कुल जनसंख्या के ४५ प्रतिशत—हिन्दू है। वे सब भारत मे रहना चाहते थे। 'पूर्वी बगाल' की कल्पना अनेक स्थानीय मुसलमानों को स्वीकार नहीं थी। बगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री सुहरावर्दी और जिन्ना के बीच सबध अच्छे नहीं थे। सुहरावर्दी विभाजन से डरते थे और हिन्दुओ के साथ मेल करने को तैयार थे। जेनकिन्स ने भी पजाब तथा बगाल मे पाकिस्तान-विरोधी भावनाओ के उभडने की आशंका बताई। बगाल के मुसलमान बगाल पर स्थानिक मुसलमानों का आधिपत्य हो जाने से सतुष्ट हो जायगे।

बिहार के गवर्नर ने खनिज सम्पत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया। स्वतंत्र बगाल के निर्माण के लिए छोटा नागपुर का औद्योगिक विकास करना सुहरावर्दी की योजना का अंग था। किन्तु गवर्नर महोदय महसूस करते थे कि यदि बिहार की सीमा का पुनर्निर्माण हुआ तो उसका परिणाम बहुत व्यापक होगा। आम बहस मे यह महसूस किया गया कि सिध-पजाब को मिलाकर बना पाकिस्तान आर्थिक-दृष्टि से व्यावहारिक न होगा। माउन्टबेटन का खयाल था कि पूर्वी बगाल सम्भवतः पाकिस्तान से अलग हो जायगा और सीमाप्रात एक घाटे का राज्य रहेगा।

नई दिल्ली, बुधवार, १६ अप्रैल, १९४७

गवर्नरो की आज की बैठक में जेनकिन्स ने पंजाब के बटवारे और सीमा-आयोग की स्थापना की आवश्यकता बताई। माउन्टबेटन ने विभाजन की जो योजना पेश की थी उसपर विस्तारपूर्वक बहस हुई। गवर्नरो द्वारा व्यक्त किये विचारों से स्पष्ट था कि देश का बहुत बड़ा भाग शांत था और किसी भी न्यायोचित हल को स्वीकार करने के लिए तैयार था।

आज मैंने पणिक्कर के साथ इम्पीरियल होटल में भोजन किया। पणिक्कर ने बताया कि मुस्लिम लीग का विधान इस प्रकार बनाया गया था कि मुस्लिम अल्पमत क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए जिन्ना मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के प्रतिनिधियों पर विशेष प्रभाव डाल सकते थे। बंगाल की बफादारी भारत के प्रति बढ़ती जा रही थी। उसकी व्यवस्था सावधानी से करनी होगी। उन्होंने भारत में प्रिवी कौंसिल जैसी संस्था स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि अप्रत्याशित रूप से उठनेवाली राजनैतिक और न्याय-सम्बन्धी समस्याएँ उसके सामने पेश की जा सकें।

माउन्टबेटन ने सुरक्षा-मंत्री बलदेवसिंह से बातचीत की। बलदेवसिंह ने जेनकिन्स के सामने इन्कार किया कि वह सिखों की अपील-निधि के कोषाध्यक्ष हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह निधि युद्ध फैलाने तथा अन्य कार्यों के लिए इकट्ठी की जा रही थी।

बलदेवसिंह ने सेना के राष्ट्रीयकरण की योजना पर सलाह मांगी। जून, १९४८ के पश्चात् ब्रिटिश सेनाओं के बने रहने की गुंजाइश कितनी थी? माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि यह सब इस बात पर निर्भर है कि भारत राष्ट्रमंडल में रहना चाहता है या नहीं। कांग्रेस ने २०, फरवरी के पूर्व जो प्रस्ताव स्वीकार करके भारत को "सम्पूर्णसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य" बनाने का निश्चय किया था, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए एक नया हल निकालना पड़ेगा। बलदेवसिंह के रुख से इस बात की पुष्टि होती थी कि अब विभाजन ही एकमात्र उपाय है, जिसे पंजाब के सब दल स्वीकार कर सकते थे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, १८ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मंडल की आज की बैठक में माउन्टबेटन बड़े प्रसन्न थे। कृष्ण मेनन के साथ उनकी मनोरंजक चर्चा हुई। कृष्ण मेनन ने 'सम्पूर्णसत्तासम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य' के सूत्र को पेश करने का थोड़ा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। फिर भी वह और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता ब्रिटेन के साथ संघ बनाये रखने के लिए कोई दूसरा हल निकालने को प्रयत्नशील थे। मेनन ने बताया है कि कांग्रेस के लिए स्वयं

पहल करना असभव है। ऐसा कोई प्रयास करने से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचेगा। इसका सुझाव तो किसी-न-किसी प्रकार हमारी तरफ से ही पेश किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली, शनिवार, १९ अप्रैल, १९४७

माउन्टबेटन ने सिख-नेताओं के साथ हुई बातचीत का हाल सुनाया। यह चर्चा भय पैदा करनेवाली भी थी और रोचक भी। उन्होंने अपने-आप को लम्बी दाढ़ी और विशाल कृपाणों वाले बूढ़े सज्जनों के सामने पाया, जो चग्मे लगाये हुए थे और देखने में शांतिपूर्ण इरादों से परिपूर्ण दयालु प्रोफेसरो की भाँति जान पड़ते थे। लेकिन बीच-बीच में झूठ का सहारा लेने में भी उन्होंने सकोच नहीं किया। उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि उन्हें पंजाब का विभाजन कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी बतलाया कि रावलपिण्डी के दगो में सबसे अधिक हानि सिखों को ही उठानी पड़ी थी।

कल डा० खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई उसमें यह सुझाव सामने आया कि माउन्टबेटन को जल्दी ही उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रदेश का दौरा करना चाहिए। अभी तक निश्चय यही था कि जबतक योजना का बड़ा भाग तैयार होकर स्वीकार नहीं कर लिया जाता तबतक दौरे स्थगित रखे जाय। किन्तु लगता ऐसा था कि सीमा-प्राप्त की स्थिति को देखते हुए पहले से ही कुछ खास 'इलाज' करना पड़ेगा। आम नीति-सम्बन्धी हमारी चर्चाओं में औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर फिर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। माउन्टबेटन ने बतलाया कि पूर्वी बंगाल के लीगी नेता नाजिमुद्दीन पाकिस्तान के बारे में जिन्ना के समान ही जिद पर अड़े हुए हैं। इसमें ने कहा कि हम दो पाकिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। इस पर माउन्टबेटन ने कहा कि मुझे लगता था कि पाकिस्तान अवश्यम्भावी है, उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो।

नई दिल्ली, बुधवार, २३ अप्रैल, १९४७

आज सवेरे माउन्टबेटन ने जिन्ना के साथ तीन घंटे तक बातचीत की। मैंने जार्ज एवेल के साथ भोजन किया और उन्होंने मुझे बताया कि जिन्ना का रुख मैत्रीपूर्ण था। कभी-कभी वह जान-बूझकर उद्धत बन जाते थे, परन्तु आज इनका रुख आदान-प्रदान का था। मालूम होता था कि उन्होंने मजबूर होकर बंगाल और पंजाब के विभाजन को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने यह नहीं पूछा कि इनकी सीमाएँ क्या होगी और न माउन्टबेटन ने ही कुछ बताया। वह सीमाप्राप्त के लिए 'बुद्धिमत्ता से काम लेने' की अपील निकाल रहे थे और यह जानकर उन्हें राहत मिली थी कि उन्हें वहाँ की 'सीधी कार्यवाही' को बन्द करने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा।



उन्होंने माउन्टबेटन से कहा “वात यह थी कि हिन्दुओं को किसी बात के लिए राजी कर पाना नामुमकिन था। वे हमें एक रुपये के सत्रह आने मांगते हैं।” इस पर जार्ज की टीका यह थी, “मुझे लगता है, कि यह सही है। साधारणतः हिन्दुओं का पक्ष मुसलमानों के पक्ष से प्रबल था, किन्तु वे ज्यादा ऊँची बोली बोलकर उसे बिगाड़ देते थे।”

कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम-नेता मौलाना आजाद ने एक नया सूत्र पेश किया था। गत दिसम्बर में भारतीय नेताओं और वेवल के बीच लन्दन में हुई चर्चाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य निकाला था। इसमें कहा गया था कि प्रांतों को किसी भी ‘समूह’ से बाहर रहने का अधिकार होगा। मौलाना आजाद का कहना था कि इस विषय में उन्हें माउन्टबेटन द्वारा लगाया गया अर्थ स्वीकार होगा। उन्होंने अपने सूत्र का आधार गांधीजी के इस कथन को बनाया था कि पूरे भारत के हित में क्या था और क्या नहीं था, इसके एकमात्र निर्णायक व्यक्तिगत रूप में माउन्टबेटन होंगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २५ अप्रैल, १९४७

कर्मचारी-मंडल की आज की बैठक में योजना के पहले मसविदे पर विचार किया गया। लेकिन यह साफ न हो सका कि इसे विभिन्न दलों और जनता के के सामने ठीक किस रूप में पेश किया जाय। आइन स्काट ने एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया, जिसपर काफी बहस हुई। उनका कहना था कि योजना को दोनों दलों की कार्य-समितियों के पास भेजने के पहले उसका खूब जोरों से प्रचार किया जाना चाहिए। इसका फल यह होगा कि सारी दुनिया की नजर दोनों दलों की कार्य-समितियों पर केन्द्रित हो जायगी। इस प्रकार कांग्रेस और लीग के अपेक्षाकृत ज्यादा नरम दली तत्व गायब फिर एक-दूसरे के नजदीक आ जायेंगे और एकता के महत्त्वपूर्ण ढाँचे को बनाये रखने का प्रयास करेंगे।

माउन्टबेटन इस बात से सहमत थे कि योजना की घोषणा में ऐसा न लगे कि विभाजन पूर्व-निश्चित बात थी, बल्कि लोगों को मालूम यह पड़े कि विभाजन के प्रश्न पर आखिरी निर्णय जनता की इच्छा पर छोड़ दिया जायगा। संयुक्त भारत की संभावना पर लौटने का अवसर देने के लिए घोषणा में वचाव की धारा जोड़ दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह, किसी भी ऐसी योजना को संयुक्त भारत की योजना मानने को तैयार होंगे, जिसमें मन्त्रिमंडलीय-योजना में वर्णित विषय केन्द्र के अधीन दिये गए होंगे। उदाहरणार्थ, विदेशी मामले, सुरक्षा और संचार-साधन। उनकी नजर में सारी बात का सार यह था कि मन्त्रिमंडलीय योजना के अन्तर्गत, केन्द्र में स्थित हिन्दू-बहुमत का पलड़ा हमें मुसलमान-अल्पमत से भारी

रहेगा और वह सुरक्षित विषयो का उपभोग उन्हें दवाये रखने के लिए करेगा । दूसरा उपाय यह था कि पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि समता के आधार पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें । यदि ऐसे सयुक्त भारत का निर्माण हो सका तो पंजाब, बंगाल और आसाम अखंड बने रह सकेंगे । एब्रेल ने बतलाया कि दो सत्ता-सम्पन्न राज्यों की सापेक्ष्य शक्ति पर निर्भर करनेवाली समता सच्ची समता न होगी । माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि वह इस तथ्य के प्रति सजग है । उन्होंने कहा, “मेरा उद्देश्य यह है कि या तो दो सर्व सत्तासम्पन्न राज्यों की स्थापना हो या ऐसे दो समूहों की रचना हो, जो केन्द्र के साथ आदान-प्रदान करें । बहुमत से निर्णय करने की प्रणाली के पक्ष में मैं नहीं हूँ ।”

माउन्टबेटन ने कलकत्ते के भविष्य के बारे में भी प्रश्न उठाया । उनका अनुमान था कि मुसलमान उसके लिए जनमत-पग्रह की मांग करेंगे और उसका भविष्य बड़ा पेचीदा प्रश्न बन जायगा । लेकिन इस सम्बन्ध में आत्मनिर्णय का मार्ग अपना अवाञ्छनीय होगा और उसका नतीजा भी शायद गलत निकले ।

उन्होंने कहा कि पटेल की गिकायत है कि “न आप खुद शासन करेंगे, न हमें करने देंगे ।” लेकिन सच बात यह थी कि नेताओं के साथ अंतिम चर्चा के लिए हम १९ मई जेमी निकट की तारीख तय कर रहे थे ।

नई दिल्ली, शनिवार, २६ अप्रैल १९४७.

कि यदि ब्रिटन ने उसके साथ कोई सैनिक या राजनैतिक संधि करने का प्रयत्न किया तो भारत सघ उसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई समझेगा ।”

इसपर माउन्टबेटन का विचार यह था कि उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ कि यदि भारत का कोई एक या अधिक भाग राष्ट्रमंडल में बने रहने की इच्छा प्रकट करे तो वह क्या रुख अपनाए । परन्तु ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट आदेश दिये हैं कि वह इस विषय में कोई ऐसी बातचीत न करे, जिससे भारत की एकता की संभावना खतरे में पड़ जाय । एकता स्थापित करना माउन्टबेटन की प्रथम महत्वाकांक्षा थी और यही उनका प्रमुख सकल्प रहेगा ।

: ६ :

## सीमा-प्रान्त की यात्रा

सरकारी भवन, पेशावर,  
सोमवार, २८ अप्रैल, १९४७

आज सवेरे तड़के मैं वाइसराय के दल के साथ हवाई जहाज द्वारा पेशावर के लिए रवाना हो गया । माउन्टबेटन-दम्पती पमेली को भी अपने साथ लाये थे । दल के शेष सदस्य थे आइन स्काट (जिनके आई सी एस जीवन का अधिकांश भाग सीमाप्रांत में ही बीता था), लेडी माउन्टबेटन की सहायक म्यूरियल वाट्सन और मार्टिन गिलियट । यात्रा में बहुत झोके लगे थे और खास तौर से पमेली और मुझे दोनों को ही कुछ-कुछ अस्वस्थता महसूस हो रही थी । मार्ग में सर्वाधिक प्रभावशाली दृश्य नगापर्वत का था, जो हवाई जहाज से लगभग सौ मील उत्तर में दिखलाई पड़ रहा था । वह बड़ी एकरूपता के साथ लगभग पच्चीस हजार फुट ऊँचा उठा चला गया था, और आसपास के शिखरों से कम-से-कम दस हजार फुट ऊँचा था । दोपहर के जरा बाद ही हम यहाँ के हवाई अड्डे पर उतरे ।

हमें आशा थी कि सरकारी भवन में पहुँचने पर, तीसरे पहर की बैठक के पूर्व, हम शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे । किन्तु यहाँ हमारा सामना एक सकटपूर्ण स्थिति से हुआ, जो आतंक की हद तक पहुँच गई थी ।

गवर्नर सर ओल्फ कैरो ने हमें बताया कि एक मील में भी कम दूरी पर मुस्लिम लीगी एक विराट् प्रदर्शन कर रहे हैं । वे वाइसराय के सामने अपनी गिकायत रखना चाहते थे और जलूस बनाकर सरकारी भवन पर कूच करने, और इस प्रकार कानून-भंग करने, पर भी तुले हुए थे । कैरो के कथनानुसार, इसका

एकमात्र उपाय यही था, कि वाइसराय स्वयं पहले ही उनपर 'कूच' कर दें और भीड़ के सामने उपस्थित हो जाय। प्रदर्शनकारियों की संख्या ७० हजार से अधिक थी और वे दूर-दूर के भागों से एकत्रित हुए थे। उसमें से बहुत से कई-कई दिनों का मार्ग तय करके आये थे। माउन्टबेटन नें कैरो और प्रधान मंत्री डा० खानसाहब के साथ संक्षेप में 'युद्ध-मंत्रणा' की और यह तय हुआ कि वाइसराय अविलम्ब भीड़ के सामने चले जाय।

इसके पश्चात् माउन्टबेटन प्रदर्शनकारियों के बीच पहुँचे। लेडी माउन्टबेटन भी बड़े साहस के साथ उनके साथ गई। निःसंदेह, हमारे सामने एकत्र भीड़ भयावह थी। हम ऐतिहासिक किले 'बाला हिसार' के निकट रेलवे के बाध पर चढ़ गये और हमने कनिंघम पार्क में इकट्ठी तथा दूर-दूर के खेतों तक फैली हुई विशाल भीड़ देखी। वह अनेक प्रकार की चेष्टाएँ कर रही थी और पाकिस्तानी चाद-तारे के अनेक हरे झंडे, जो गैरकानूनी थे, हिला रही थी। 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारों का समा बधा हुआ था।

परन्तु हमारे पहुँचने के कुछ ही मिनट बाद वह मनहूस आवेग दब गया। नारा भी बदल गया। अब 'माउन्टबेटन जिन्दाबाद' का नारा सुनाई पड़ने लगा और क्रोधभरे चेहरों पर मुसकराहट खेलने लगी। माउन्टबेटन और लेडी माउन्टबेटन दोनों खाकी बुश-शर्ट पहने हुए लगभग आध घंटे तक भीड़ की ओर, जिसमें बच्चों और स्त्रियों की भी आश्चर्यजनक संख्या थी, हाथ हिलाते रहे। किसी प्रकार के भाषण का तो प्रश्न ही नहीं था। परन्तु उस धर्मान्ध समुदाय पर उनके मैत्री तथा आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व का प्रभाव आश्चर्यजनक था।

जब हम नीचे आये और भोजन के लिए सरकारी भवन की ओर चले, उस समय गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों के चेहरों पर राहत का भाव छिपा नहीं रह सका। उन्होंने बताया कि यदि भीड़ ने सरकारी भवन पर कूच करने का निश्चय कर लिया होता तो स्थानीय पुलिस और सेना उसे शांतिमय उपाय से रोक नहीं सकती थी।

दोपहर के खाने के बाद माउन्टबेटन ने लवी मुलाकातो का सिलसिला शुरू किया। उनमें से दो के समय मैं वहाँ मौजूद था—एक तो खानसाहब और उनके मंत्रिमंडल के चार सदस्यों के साथ और दूसरी स्थानीय हिन्दुओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ। वह स्थानीय मुस्लिम लीगी नेताओं से भी मिले, जिन्हें इस मुलाकात के लिए जेल से लाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। उन झगड़ों के अलावा, जो कांग्रेस और लीग के आम संघर्ष को गम्भीर स्वरूप देने के लिए पर्याप्त थे, गवर्नर और उनके कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बीच के सम्बन्ध भी कम खराब नहीं थे। राष्ट्रीय-स्तर पर इस झगड़े का भी काफी व्यापक असर पड़ा।

डा० खानसाहब तथा उनके साथियों के साथ भेट में, जिसमें गवर्नर भी

उपस्थित थे, माउन्टबेटन की कूटनीतिक सूझबूझ का सुन्दर प्रदर्शन हुआ। मुलाकात शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपसे व्यक्तिगत भेंट करके अनुगृहीत हुआ। उन्होंने एक-दूसरे से प्रश्न पूछे। उन्होंने डा० खानसाहब के इस परामर्श की सराहना की कि उन्हें प्रदर्शनकारियों से भेंट करने जाना चाहिए। वास्तव में बाध पर खड़े हो जाने के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं किया था। पहले वह जिन्ना को सरकारी भवन तक जुलूस में लाने की इजाजत देने से इन्कार कर चुके थे। डा० खानसाहब ने यह बताने की कोशिश की कि उन्होंने लालकुर्ती दल के जुलूस का आयोजन भी रद्द कर दिया था।

माउन्टबेटन ने कहा कि मैं भारत को भारतीयों के हाथ में सौंपने और जनता की इच्छा के अनुसार सत्ता हस्तान्तरित करने आया हूँ। मैं पंजाब तथा बंगाल के लिए उपयुक्त समाधान की खोज कर रहा हूँ। परन्तु सीमाप्रान्त की स्थिति ने मेरे सामने विशेष कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी हैं। मैं मुस्लिम लीग से कहूँगा कि हिंसा के सामने सिर नहीं झुकाया जायगा। मैं निजी तौर पर आपको बताता हूँ कि चुनाव कराना आवश्यक है, परन्तु मैं मुसलमानों को पक्का आश्वासन नहीं दे सकता कि चुनाव कराये ही जायगे। जिन्ना का वादा है कि यदि चुनाव हुए तो हिंसा नहीं होगी। आपको मेरी ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। जिन्ना यह स्थिति स्वीकार करते हैं और अपने अनुयायियों को आदेश दे रहे हैं कि वे कानून-भंग करने का आदोलन बन्द कर दें।

माउन्टबेटन ने पूछा कि मुस्लिम लीग हाई कमान की बात कितनी मानी जाती थी। उत्तर मिला कि स्थानीय मुस्लिम लीग ने विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है। गत चुनाव में पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग को स्पष्ट पराजय हो चुकी थी और अब्दुर्रब निश्तर भी चुनाव में सफल नहीं हो सके। उस समय कांग्रेस की 'अग्रेजो, भारत छोड़ो' नीति की विजय हुई थी; परन्तु अब वह नारा लोगों को संगठित नहीं कर पा रहा था और लोग शका करने लगे थे कि कहीं वे हिन्दुओं के प्रभुत्व में तो नहीं फँस जायेंगे।

जब डा० खानसाहब ने पठानिस्तान का प्रश्न छेड़ा उस समय बातचीत कुछ विश्रुखल और विस्फोटक हो उठी। कुछ समय से गांधीजी पठानिस्तान की कल्पना में सक्रिय दिलचस्पी ले रहे थे। और इधर उन्होंने उसका काफी गुणगान किया था। यदि वह कल्पना मूर्तरूप ग्रहण कर सकी, तो एक नई सीमाप्रांतीय राष्ट्रियता का उदय हो जायगा, जो पाकिस्तान के प्रति प्रान्त की साम्प्रदायिक और राजनैतिक एकता को खडित कर देगी। डा० खानसाहब ने चेतावनी दी, "पठान राष्ट्र को नष्ट करने के परिणाम भयानक होंगे।"

माउन्टबेटन ने पूछा कि सीमाप्रान्त में मिली-जुली सरकार का संगठन क्यों नहीं किया गया? डा० खानसाहब ने उत्तेजित होकर कहा, "यदि कांग्रेस मिलीजुली

सरकार बनाना चाहेगी तो मैं उसमें न रहूंगा।" माउन्टबेटन ने तुरन्त उत्तर दिया, "मैंने केवल जानकारी के लिए पूछा था।"

खानसाहब ने आगे कहा, "हमारी जनता बहुत गरीब है। यहां की मुस्लिम लीग केवल अपने सकीर्ण, स्वार्थी और कुछ विशेषाधिकारी वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है।" कैरो ने बताया, "कांग्रेस के भी कुछ धनी समर्थक हैं।"

माउन्टबेटन ने प्रान्त में साम्प्रदायिक स्थिति की बात पूछी। कैरो ने उत्तर दिया, "मुस्लिम जनता हिन्दुओं और सिखों की रक्षा कर रही है। केवल हजारों में ऐसा नहीं। मुसलमानों का दिल और दिमाग सही है।" खानसाहब ने आरोप किया कि अधिकारियों ने मुसलमानों को कानून तोड़ने की छूट दे रखी है। कैरो ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मुझे एक उदाहरण भी नहीं मालूम, जिसमें कर्मचारियों ने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, फिर भी उन्हें हमेशा दोष दिया जाता है।

इसके पश्चात् वैधानिक कार्यविधि के बारे में बातचीत हुई। गवर्नर ने प्रधान मंत्री पर अनुचित शासनिक दबाव डालने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, प्रधान मंत्री ने गवर्नर पर हस्तक्षेप का दोषारोपण किया। माउन्टबेटन ने बीच में दखल देते हुए कहा, "मैं यहां कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नहीं आया। मैं जनता की इच्छा के अनुसार सत्ता-हस्तांतरण करना चाहता हूँ। आदर्श तो यह होता कि मैं यहां की जनता का मतसंग्रह कर लेता, परन्तु इसके लिए समय नहीं है।"

उन्होंने प्रान्तों को सत्ता हस्तांतरित करने और सामान्य दृष्टि से, तथा सीमा-प्रान्त की विशेष दृष्टि से देश के विभाजन की समस्याओं पर बातचीत की। अपने ऊपर आये हुए गंभीर कर्तव्य की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे सामने समस्या यह है कि हम जाने के पूर्व यहां चुनाव करा दें या वर्तमान न्याय और व्यवस्था सरकार को कायम रखने के लिए काफी है।" उन्होंने चुनावों के बारे में सलाह देने के लिए दोनों हाई-कमानों की संयुक्त बैठक का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, "अंग्रेजों ने सदैव मनमानों की थी, किन्तु मुझे निष्पक्ष रहने का आदेश मिला है।"

इस बैठक के बाद ही स्थानीय हिन्दुओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत आरम्भ हो गई। उन्होंने बताया कि उनका शिष्ट-मंडल राजनैतिक या लीग-विरोधी नहीं है, बल्कि साम्प्रदायिक है। उन्हें मन्त्रि-मंडल के भाग्य से कोई वास्ता नहीं, वे केवल निर्दोष हिन्दुओं और सिखों की रक्षा चाहते थे।

माउन्टबेटन ने कहा, "मैं वस्तुस्थिति जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्या आप सरकार के समर्थक हैं?"

हिन्दुओं ने उत्तर दिया, "हम किसी भी सरकार के शासन में शांतिपूर्वक रहने को तैयार हैं।"

माउन्टबेटन ने कहा, "मुझे इस बुद्धिमत्तापूर्ण रुख से प्रसन्नता है। मैं वैधानिक रूप से काम करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।"

पुलिस की कमी की शिकायतें की गईं। वास्तव में उसपर असाधारण भार था। चार ब्रिटिश ब्रिगेड उपलब्ध थे, फिर भी पेशावर में हत्याएं जारी हैं और पुलिस कोई प्रभावोत्पादक कार्रवाई नहीं करती। माउंटबेटन ने पुलिस के स्थान पर सैनिकों के उपयोग का खतरा बताया। दोनों का काम भिन्न है। उन्होंने कहा कि इस समय सीमाप्रान्त में भारत के सब प्रान्तों की अपेक्षा अधिक सेना है। केरो ने कहा कि उसका उपयोग जितना इस समय किया जा रहा है उतना गत २५ वर्षों में, जिनमें १९३०-३१ का काल भी सम्मिलित है, कभी नहीं हुआ। माउंटबेटन ने कहा कि मैं एक बड़ा हल निकालने और अस्थिरता का अंत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परन्तु यह ऐसा हल नहीं होगा, जो सबको स्वीकार हो।

मैं तीसरी बैठक के लिए नहीं रुक सका। यह बैठक उन मुस्लिम लीगी नेताओं के साथ हुई, जो इसके लिए विशेष रूप से जेल से छोड़े गए थे। इन व्यक्तियों में मनकी शरीफ के नौजवान और धर्मान्ध पीर और खान अब्दुल कय्यूम खा सम्मिलित थे। आइन स्काट से मुझे ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने अत्यन्त आवेश के साथ बड़े विस्तारपूर्वक अपनी बातें कही। माउंटबेटन ने यह बुद्धिमत्तापूर्ण आदेश दिया था कि इन सबको एक ही जेल में रखा जाय, जिससे ये एक-दूसरे से मिल सकें और परस्पर विचार-विनिमय कर सकें। वह उनके इस प्रस्ताव से भी सहमत हो गए कि उन्हें जिन्ना से परामर्श करने के लिए दिल्ली जाने दिया जाय।

वाइसराय-भवन, नई दिल्ली,

बुधवार, ३० अप्रैल, १९४७

हमारा दल दो टुकड़ों में विभक्त हो गया—माउंटबेटन पेशावर और रावलपिंडी के दौरे के बाद सीधे दिल्ली लौटे और लेडी माउंटबेटन ने दगाग्रस्त इलाके का दौरा जारी रखा। मैं उन सम्वाददाताओं के साथ व्यस्त हो गया, जो इस दौरे के नतीजों के बारे में अन्दरूनी जानकारी पाने के लिए उत्सुक थे। सावधानी से कदम रखने की जरूरत थी। कांग्रेस और लीग की सारी नजरे अस्थायी रूप से सीमान्त प्रदेश पर केन्द्रित थी। वातावरण तरह-तरह की अटकलों से भरा हुआ था।

मेरा पहला काम था 'डान' के सम्पादक अल्ताफ हुसैन से निवटना। अल्ताफ हुसैन ने अपने पेशावर-सम्वाददाता की एक निहायत गलत कहानी इन बड़े-बड़े शीर्षकों के अन्तर्गत छापी थी "माउंटबेटन की सीमान्त नेताओं से चर्चा—मनकी और कय्यूम ने पेरौल पर छोड़ा जाना ठुकराया—पठान स्त्री-पुरुषों द्वारा विराट् प्रदर्शन—वाइसराय हवाई जहाज से जमरूद जा रहे हैं।" चूँकि माउंटबेटन न दो घंटे से भी अधिक मनकी शरीफ के पीर और कय्यूम के साथ चर्चा में बिताये थे, जो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि-मंडल के प्रमुख प्रवक्ता थे, इसलिए उनकी पहली

प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्हें जिन्ना के पास व्यक्तिगत रूप से विरोध भेजना चाहिए। लेकिन अल्पताफ हुसैन के इस वादे पर कि यह कहानी कल सुधार दी जायगी, मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका। इस पत्र के सम्वाददाता की कल्पना-शक्ति ने सबसे बड़ी अक्लमन्दी तो इस बात में जाहिर की थी कि वाइसराय हवाई जहाज से जमरूद जायगे जबकि जमरूद में हवाई अड्डा ही नहीं है।

रायटर के डून कैम्पबेल ने आधी रात गये मुझे फोन पर बतलाया कि जिन्ना और डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अभी-अभी बड़े आवेशपूर्ण वक्तव्य पत्रों के लिए दिये हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने असल में 'कटे-फटे और घुन-लगे पाकिस्तान' के खिलाफ आन्दोलन का पहला तीर छोड़ा है, और कही अधिक विशाल आकार वाले राष्ट्रीय स्वदेश की महत्वाकांक्षा जाहिर की है। उनकी मांग है कि मन्त्रिमंडल-योजना के 'ख' और 'ग' भाग के समस्त प्रांतों (सिंध, पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश, बलूचिस्तान, बंगाल और आसाम) को उनके साम्प्रदायिक बहुमतों का विचार किये बिना प्रस्तावित "राष्ट्रीय स्वदेश" में शामिल किया जाय। ऐसा प्रतीत होता था कि राजेन्द्रप्रसाद के वक्तव्य में मुस्लिम लोग के १९४० के लाहौर-प्रस्ताव की जोर ध्यान आकर्षित किया गया था। इसी प्रस्ताव में पाकिस्तान की कल्पना सामने रखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल वही भाग पाकिस्तान में शामिल होंगे, जहां मुसलमानों का बहुमत है। विधान-सभा के तीसरे अधिवेशन में, जो इसी सप्ताह प्रारम्भ हुआ था, डा० राजेन्द्रप्रसाद ने सभा के नये अध्यक्ष के नाते बोलते हुए सदस्यों के दिमाग भारत-विभाजन के लिए तैयार कर दिए थे। अब वह लोगों के दिमाग प्रान्तों के बटवारे के लिए तैयार कर रहे थे।

डा० राजेन्द्रप्रसाद कांग्रेस हाई कमान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से हैं और अंतरिम सरकार में खाद्य तथा कृषि विभाग के मंत्री थे। अभी उस दिन, जब मैं उनके यहाँ चाय पीने गया तो मेरे ऊपर उनकी सौम्यता, दिमाग की गहराई और चरित्र की दृढ़ता का गहरा असर पड़ा। मूलतः, वह नरम विचारों वाले व्यक्ति है और समझौतावादी है। वह जनता के आदमी है और उनकी कीर्ति में किसी प्रकार के पाखंड का कोई योग नहीं। उनकी कीर्ति तो राष्ट्र की ईमानदारी से लम्बी सेवाओं का फलमात्र है। चाहे भारत संयुक्त रहे या विभाजित हो, उसकी नई सरकार में वह निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थिति में भाग लेंगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २ मई, १९४७

मैंने आज यह विज्ञप्ति प्रेस को दी थी कि माउंटबेटन सपरिवार थोड़े दिनों के लिए शिमला जा रहे हैं। माउंटबेटन यह स्पष्ट करने को व्यग्र थे कि इसमें उनके काम में किसी प्रकार का खलल नहीं पड़ेगा। इसलिए वक्तव्य में बतलाया



गया था कि भारतीय नेताओं के साथ उन्होंने अपनी प्रारम्भिक बातचीत पूरी कर ली है और मन्त्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में भाग लेने के बाद वह ६ तारीख को यहाँ से रवाना होंगे और मन्त्रिमंडल की अगली बैठक के समय तक यहाँ लौट आवेंगे ।

मैं आज रात दिल्ली मेल से रवाना हो रहा हूँ, जिससे सोमवार को शिमला में वाइसराय के मुख्य दल के पहुंचने के पूर्व कुछ दिन अपने परिवार के साथ शांति से मशोबरा में बिता सकूँ ।

: ७ :

## शिमला में संकट

‘दि रिट्रीट’, मशोबरा, शिमला,  
सोमवार, ५ मई, १९४७

पिछले अड़तालीस घंटे मैंने आराम करने में बिताये और अपने निवास में बैठकर हिमालय की भव्यता और एकातवास का रसपान किया । कई-कई दिनों तक कोहरा और बादल विनाल पर्दे की भाँति आकाश में तन जाते और नीचे की घाटी तथा पड़ोस के ‘शाली’-शिखर के अतिरिक्त, जो सिर्फ बारह हजार फुट ऊँचा है, और कुछ दिखलाई नहीं पड़ता । ‘शाली’ भी वसन्त के मौसम में बरफ से खाली रहता है । फिर सहसा यह पर्दा उठ जाता है और अनंत हिम की एक अटूट अर्द्ध-चन्द्र रेखा सामने आ खड़ी होती है, जिसमें कितनी ही पर्वतमालाएँ हैं, अधिकांश सोलह सौ फुट से अधिक ऊँचाई वाली । हिमालय की मुख्य पर्वतमाला में इतने ही प्रभावशाली और दृश्य भी होंगे, क्योंकि “दुनिया की यह छत” दो सौ पचास हजार वर्गमील में फैली हुई है और चौबीस हजार फुट से अधिक ऊँचाई वाले कम-से-कम चालीस शिखर उसमें शामिल हैं । शिमला से दृष्टिगोचर होनेवाला यह शानदार और सिहरन पैदा करनेवाला दृश्य उस विराट् का ही एक प्रतीक है ।

इधर मैं मशोबरा में आराम कर रहा था, उधर दिल्ली में राजनैतिक घटनाओं की गति तेज हो रही थी । इस्मै और एबेल दो मई को लन्दन के लिए रवाना हुए । प्रस्तावित मसविदा ब्रिटिश सरकार के विचार के लिए वे अपने साथ ले गए थे ।

गुनिवार को भारतीय पत्रों ने पहली बार माउंटबेटन पर भारी हमला किया । महत्त्व की बात यह थी कि यह हमला ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ में शुरू हुआ । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ को काफी मान दिया जाता था ।

लेख का प्रारम्भ इस प्रकार था “जब से लार्ड माउन्टबेटन ने वाइसराय का पद सभाला है तबसे पहली बार कांग्रेस-जनों और सिख-नेताओं के दिलों में यह आशका उठी थी कि शायद वह ईमानदारी से काम नहीं कर रहे।” इसके बाद वाइसराय के मुख्य निष्कर्षों का जिक्र था, जिनके सही अंदाज को देखकर लगता था कि पत्र को काफी अन्दरूनी जानकारी रही होगी। इसपर कांग्रेस की धमकी-भरी प्रतिक्रिया का भी उल्लेख था। यह बात भी काफी सही थी। कांग्रेस ने पंजाब में सिखों के लिए विशेष सुविधाओं की मांग की थी। सीमाप्रान्त में चुनाव की मांग मंजूर करने के बारे में भी आशकापूर्ण अनिच्छा का प्रदर्शन किया गया था। लेख में कहा गया था कि “कांग्रेस कार्यकारिणी ने सीमान्त के प्रश्न को कसौटी मान लिया है। उसने वाइसराय को साफ बतला दिया है कि अगर सीमाप्रान्त मन्निमडल को भग करने और नये चुनाव करवाने का सुझाव रखा गया तो कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के बारे में अपने सारे दृष्टिकोण को बदल देगी।”

ज्ञात हुआ कि माउन्टबेटन ने कल गांधीजी और जिन्ना के साथ दो महत्वपूर्ण चर्चाएँ की। इन चर्चाओं का असर यह हुआ कि माउन्टबेटन सोचने लगे कि शायद इस्मे को भेजने में जल्दबाजी हो गई। संयोगवश, पहले मुलाकाती के जाने के पहले दूसरे मुलाकाती वहाँ आ गए। माउन्टबेटन ने दोनों नेताओं को मिलाकर राजनैतिक सूझ-बूझ और सामाजिक शिष्टाचार का परिचय दिया। दोनों नेताओं की गत तीन वर्षों में यह पहली मुलाकात थी। लेकिन परस्पर अभिवादन खत्म होते ही जो कुछ हुआ उस से माउन्टबेटन के अनुमानों पर पानी फिर गया। दूर-दूर कुर्सियों पर बैठे गांधी और जिन्ना सुन सकने योग्य आवाज में बोलने में असमर्थ थे और लगता था, मानो दो पुराने षड्यंत्रकारी कठपुतलियों का तमाशा कर रहे हों। लाख कान लगाने पर भी माउन्टबेटन उनकी बातों का अधिकांश भाग नहीं सुन पाये। फिर भी, उनका असली मकसद तो पूरा हो ही गया। दोनों नेता जिन्ना के निवासस्थान पर विस्तृत चर्चा करने पर राजी हो गये।

शिमला के लिए प्रस्थान करने के पूर्व माउन्टबेटन इस विषय में पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश के गवर्नरों के मत जानने का प्रयास कर रहे थे कि उनके प्रान्तों में मत-संग्रह करना उचित होगा या नहीं। केरो सीमान्त प्रदेश में मत-संग्रह के पक्ष में थे। बरोज बंगाल के बारे में गोलमोल बात कहने थे, हालांकि सब मिलकर इसके खिलाफ थे। जेनकिन्स स्थिति को नितात निराशाजनक समझते थे और उन्हें शक था कि न जिन्ना इसे स्वीकार करें और न सिख लोग। फिर भी माउन्टबेटन का यह पक्का विश्वास था कि अंत में जिन्ना मत-संग्रह के लिए राजी हो जायेंगे और सिखों के लिए अपनी स्थिति को सुधारने का एकमात्र मार्ग है बातचीत।

शिमला, मंगलवार, ६ मई, १९४७

गांधीजी और जिन्ना के बीच जिन्ना के औरगजेब रोड स्थित निवास-स्थान पर तीन घंटे तक चर्चा हुई।

निम्नलिखित वक्तव्य दोनों की सहमति से प्रकाशित किया गया

“हमने दो विषयों पर चर्चा की। पहली भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित करने के प्रश्न पर। श्रीगांधी विभाजन के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। उनका विचार था कि विभाजन अवश्यभावी नहीं है। जबकि मेरा विचार है कि पाकिस्तान अवश्यभावी ही नहीं, बल्कि भारत की राजनैतिक समस्या का एकमात्र व्यावहारिक हल भी वही है।”

“जिस दूसरे विषय पर हमने चर्चा की वह था एक पत्र। जिसपर हम दोनों ने हस्ताक्षर कर जनता से शांति बनाये रखने की अपील की है। हम दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपने-अपने दायरों में हमें पूरा प्रयत्न कर यह चेष्टा करनी चाहिए कि हमारी इस अपील पर अमल हो और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।”

हालांकि जहाँ तक बातचीत का सम्बन्ध था, उसका कोई फल नहीं निकला, लेकिन, जैसा कि मयुक्त वक्तव्य के मसविदे से जाहिर था, पलड़ा जिन्ना का ही भारी रहा। मन्त्रिमंडलीय-योजना एक कदम और नीचे की सरक गई। सवाल अब सिर्फ यही था कि विभाजन की दिशा में बहने वाले प्रवाह को रोकने के लिए गांधीजी क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे।

शिमला, बुधवार, ७ मई, १९४७

आज वाइसराय भवन से बुलावा आने के साथ ही मेरे अल्पविश्राम का अन्त हो गया। माउन्टबेटन वी पी मेनन को अपने साथ लाये हैं। इन्होंने १९४५ की शिमला-वार्ताओं और १९४६ की मन्त्रिमंडलीय-योजना-सम्बन्धी चर्चाओं में काफी हाथ बटाया था। वह सरदार पटेल के विश्वासपात्र हैं।

आते ही मैं कर्मचारीमंडल की दो लगातार बैठकों में व्यस्त हो गया। एक में माउन्टबेटन उपस्थित नहीं थे। दोनों बैठकों में हमने वी पी मेनन की इस मान्यता के आधार पर दूसरी योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया कि जिन्ना प्रस्तावित योजना स्वीकार नहीं करेंगे। माउन्टबेटन ने कहा कि इस सभावना को उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा है कि जिन्ना उसे ठुकरा देंगे। इसलिए जिन्ना और लियाकत के साथ हुई मुलाकातों में इस इरादे का संकेत पाने के लिए सावधान रहे। लेकिन ऐसा कोई संकेत उन्हें नहीं मिला। हर नजर से विचार करने के बाद वह इसी नतीजे पर पहुँचे कि वे योजना को स्वीकार करेंगे। जिन्ना के इसे स्वीकार न करने के दो कारण हो सकते थे। पहला तो यह कि उनका असली इरादा अंग्रेजों को भारत

मे रखना हो, और सोदेबाजी को लम्बा करके वह अंग्रेजों के लिए यहाँ से जाना कठिन कर देना चाहते हो, जिससे अपने लिए और भी सुभीते पा सके। दूसरा यह कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हो कि पाकिस्तान की स्थापना व्यावहारिक नहीं है।

लेकिन वह नहीं सोचते कि इन दोनों में से कोई भी बात जिन्ना के दिमाग में थी। फिर भी वह वी. पी. मेनन के इस सुझाव से सहमत हो गए थे कि जिन्ना के साथ बातचीत करते समय उन्हें एक दूसरी योजना भी तैयार रखनी चाहिए। दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रान्तों में सत्ता का बटवारा वर्तमान विधान के अनुसार ही किया जायगा। प्रान्तीय विषय वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिये जायेंगे और केन्द्रीय विषय वर्तमान केन्द्रीय सरकार को। लेकिन इसमें मुसलमानों को हिन्दू बहुमत के अन्तर्गत काम करना पड़ेगा।

लन्दन भेजने के लिए एक तार का मजमून तैयार किया गया। सारी जानकारी देते हुए ऐसी योजना की स्वीकृति माँगी गई। भारत को राष्ट्रमंडल में बनाये रखने की सभावनाओं पर हमने आगे विचार किया। मेनन ने इस सम्बन्ध में पटेल और नेहरू के स्वीकारात्मक दृष्टिकोण की चर्चा की और सम्राट तथा साम्राज्य शब्दों को निकालने की जरूरत बताई, क्योंकि बहुत से भारतीय इनके खिलाफ थे अन्त में वी. पी. मेनन से एक अभिलेख तैयार करने को कहा गया, जिसमें विस्तार के साथ बतलाया गया हो कि विभाजन अथवा प्रान्तों में सत्ता वितरण की योजना के अन्तर्गत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की क्या कार्यविधि होगी।

शिमला, शुक्रवार, ९ मई, १९४७

नेहरू और कृष्ण मेनन यहाँ पहुँच गये हैं। अगर औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रश्न सामने आया तो उसकी सफरता का दारोमदार इसपर निर्भर करेगा कि माउन्टबेटन उसके लिए इन दोनों को राजी कर पाते हैं या नहीं। अभी से कृष्ण मेनन औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी आ जाने पर भारतीय सेना के टुकड़ किये जाने के खिलाफ थे। मिएविल का विचार था कि अगर भारत राष्ट्रमंडल में रहा तो राष्ट्रमंडल की अपेक्षा भारत को इससे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन माउन्टबेटन का कहना था कि भारत के शामिल होने से ब्रिटेन का दुनिया में मान भी बढ़ेगा और युद्धनीति की दृष्टि से भी उसे अपार लाभ होगा।

कल तीसरे पहर चर्चाओं के गम्भीर दौर से जरा छुट्टी मिली। माउन्टबेटन-दम्पति नेहरू को चाय के लिए रिट्रीट लाये।

चाय के बाद नेहरू ने कहा कि वह हमारे बच्चों को देखना चाहेंगे। माउन्टबेटन ने मेरे लड़के कीय को अपना मुह-बोला बेटा बतलाते हुए कहा, “यह इतना सीधा खड़ा होता है कि पीछे को जा गिरेगा।” फिर हम विशाल भवन ओर उसके बागों की सैर करने चले गए।

शिमला, शनिवार, १० मई, १९४७

कर्मचारी-मंडल की आज की बैठक में माउन्टबेटन ने बताया कि कांग्रेसी नेताओं को औपनिवेशिक स्वराज्यवाली बात अधिकाधिक अपील कर रही है। कृष्ण मेनन का दावा है कि यह सुझाव सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। उनका खयाल है कि नेहरू भी इस सुझाव से आकर्षित हुए थे, क्योंकि इसमें माउन्टबेटन अनिच्छुक राजाओं को प्रभावित कर सकेंगे। वी पी मेनन सोचते थे कि जबतक भारत का संविधान पूरा न हो जाय तबतक के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य भी कोई बुरी चीज नहीं है। किन्तु कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह दीखती थी कि वामपक्षी लोग कहेंगे कि औपनिवेशिक स्वराज्य लेकर ब्रिटेन के सामने घुटने टेक दिये गए हैं।

आज मैंने यह महत्वपूर्ण सूचना निकाली कि वाइसराय ने शनिवार १७ मई को साढ़े दस बजे सवेरे पांच नेताओं को तथा दोपहर बाद रियासतों के प्रतिनिधियों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात का उद्देश्य है सत्ता हस्तांतरण की ब्रिटिश-योजना से उन्हें परिचित करना।

शिमला, रविवार, ११ मई, १९४७

माउन्टबेटन ने मुझे फोन किया कि कल रात की विजप्ति में नेताओं के साथ बैठक की जो घोषणा की गई थी उसे स्थगित करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी विजप्ति तैयार कर डालू। शाम को साढ़े छ बजे जब मैं वाइसराय भवन पहुँचा तो निराशा और घबराहट का वातावरण देखने को मिला।

ऐसा लगता था कि माउन्टबेटन ने नेहरू को वह योजना दिखाई, जो लन्दन से सुधर कर और मजूर होकर आई थी। उसे पढ़कर नेहरू ने उसका कड़ा विरोध किया। उनका मत था कि माउन्टबेटन और उनके कर्मचारियों ने जो योजना तैयार की थी और जिसे लेकर इसमें और जार्ज एबेल इस महीने के प्रारम्भ में लन्दन गये थे, प्रस्तुत योजना उससे बुनियादी रूप से भिन्न थी।

नेहरू का विश्वास था कि मन्त्रिमंडलीय-योजना और माउन्टबेटन के मसविदे में यह मानकर चला गया था कि भारत कोई नया राज्य नहीं है। लेकिन लन्दन ने जो मसविदा भेजा था उसका अर्थ तो शुद्ध खड़ीकरण था। नेहरू असल में चाहते थे कि यह बात स्पष्टतः मान ली जाय कि भारत और उसकी विधान-सभा ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी है और पाकिस्तान तथा मुस्लिम लीग उससे पल्ला झाड़ने-वाले थे। उनकी उठाई बहुत-सी आपत्तियाँ विल्कुल गौण थी और उन्हें सहज ही निवटारा जा सकता था। उदाहरण के लिए, उनका कहना था कि वह बलूचिस्तान के भाग्य के निवटारे के लिए सुझाई गई कार्यप्रणाली को नहीं मानेंगे। यह वास्तव

मे अतिरजना थी, लेकिन असलियत यह थी कि लन्दन के मसविदे मे जो नई बाते जोड़ी गई थी उनसे उनका यह सशय फिर जाग उठा था कि लन्दन विदेशी सिविल कर्मचारियो का गढ है, जिनके दिल कठोर है और जहा तक भारत की समस्याओ का सम्बन्ध है, उनकी समझ निहायत सीमित है।

उनके इस दृष्टिकोण का एक तात्कालिक नतीजा यह हुआ कि माउन्टबेटन और उनके कर्मचारियो को तेजी के साथ एक सशोधित मसविदा तैयार करना पड़ेगा, जो तुरन्त इस्मे को भेजा जा सके।

दूसरी विज्ञप्ति तैयार कर मे मिएविल के साथ माउन्टबेटन की बैठक मे पहुचा। उन्होने बताया कि कैसे केवल उनकी सूझ मात्र से ही उनका सत्यानाश होते-होते बच गया है। इसके बिना ब्रिटिश सरकार के सामने वह मूर्ख सिद्ध होते, क्योंकि उन्होने लन्दन को यह आशा दिलाई थी कि नेहरू योजना को स्वीकार कर लेगे। उन्होने बतलाया कि उनके अधिकांश कर्मचारी नेहरू को पहले से योजना का मसविदा दिखाने के पक्ष मे नही थे। लेकिन उनकी सलाह की बजाय अपनी सूझ का अनुसरण कर उन्होने स्थिति सभाल ली।

काफी विचार-विमर्श के बाद यह विज्ञप्ति निकालना तय हुआ “चूँकि लन्दन की पार्लामेंट का अधिवेशन शीघ्र ही खत्म होनेवाला है, इसलिए हिज एक्सलेन्सी वाइसराय की भारतीय नेताओ के साथ शनिवार, १७ मई को होनेवाली बैठक सोमवार २ जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है।”

शिमला, सोमवार, १२ मई, १९४७

माउन्टबेटन ने कहा कि यद्यपि वह भारतीय नेताओ पर अपनी ईमानदारी का सिक्का जमा चुके है, फिर भी लन्दन से आने वाले प्रस्तावों के बारे मे उनके दिलो मे पुरानी शकाए और भय मौजूद है। स्पष्ट है कि भविष्य मे योजनाओ का सशोधित मसविदा भारत मे ही उनके कर्मचारियो को बनाना होगा। उन्होने यह निश्चय किया कि एक सशोधन तो यह होगा कि बंगाल या किसी अन्य प्रान्त के लिए दिये जाने का विकल्प मिटा दिया जायगा। उनका खयाल था कि इस निश्चय को दोनों पक्षों की प्रार्थना पर बदला भी जा सकता था। हमारी योजना के समान नेहरू की योजना थी कि अन्तरिम सरकार को ही औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर सत्ता सौपी जाय।

: द :

## योजना में परिवर्तन

वाइसराय भवन, नई दिल्ली,  
बृहस्पतिवार, १५ मई, १९४७

माउन्टबेटन को काफी विनम्र किन्तु जोर का बुलावा आया था कि वह विचार-विनिमय के लिए लन्दन आवे। पहले तो इस प्रस्ताव की उनके ऊपर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने कहा कि उनको लन्दन जान की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। किन्तु प्रधानमंत्री का दूसरा सुझाव कि यदि वह न आ सके तो मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को नई दिल्ली आना पड़ेगा, यह उन्हें और भी नापसन्द था।

आज की बैठक का अधिकांश समय इसमें को दिये जानेवाले जरूरी सन्देश की तैयारी और स्वदेश जाने की व्यवस्था में लग गया। लन्दन से प्रधानमंत्री ने माउन्टबेटन को प्रस्तावित स्वदेश-यात्रा के बारे में एक विज्ञप्ति का मसविदा भेजा था। मेरा खयाल है कि मसविदे की भाषा बहुत अच्छी थी। स्वभावतः माउन्टबेटन यह स्पष्ट करने को उत्सुक थे कि वह अपनी स्वेच्छा से घर जा रहे हैं, केवल जरूरी बुलावे के कारण नहीं। उनका इरादा था कि प्रस्तावित योजना पहले जिन्ना को दिखलाए और फिर नेहरू को। पटेल और लियाकत से भी वह आज मिलनेवाले थे। वी पी मेनन का अनुमान था कि शिमला में नेहरू की उदासी का मुख्य कारण था अपने साथियों से दूर होना। पटेल का सहारा प्राप्त होने पर उनकी उदासी दूर हो जायगी।

नई दिल्ली, शुक्रवार, १६ मई, १९४७

नेहरू और पटेल ने माग की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष कृपालानी का नाम भी नेताओं की बैठक में आमंत्रित व्यक्तियों में शामिल कर लिया जाय। वे सोचते थे कि ऐसा करने से उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में सरलता होगी। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना था कि कृपालानी की स्थिति वैसी ही है जैसी मुस्लिम लीग के सभापति व नेता जिन्ना की। माउन्टबेटन ने यह लिखने और कहने का निश्चय किया था कि यद्यपि वह कृपालानी के महत्त्व को स्वीकार करते हैं तथापि वह उन्हें बैठक में आमंत्रित करना स्वीकार नहीं कर सकते। हा, उनसे बैठक में तुरन्त पहले या बाद में अवश्य मिल सकते हैं। यह समस्या बड़ी पेचीदा थी। पहले देखने में तो यह बड़ी मामूली जान पड़ती थी किन्तु जल्दी ही सही स्थिति भी पैदा हो सकती थी। यदि कृपालानी को नहीं बुलाया जाता तो कांग्रेस को यह शिकायत

रहेगी कि जिन्ना के सामने उसे एक बार और दबना पड़ा। यदि उन्हें बुलाया जाता है तो जिन्ना को बुरा लगता था।

वी पी मेनन ने उन विषयों की एक बड़ी प्रामाणिक सूची तैयार की थी जिन पर सबकी सहमति थी। इनकी संख्या कुल आठ थी। नेता लोग अप्रिय निर्णय लेने से कतराते थे। इस बहाने की आड़ में छिपने का प्रयास करते हैं कि अपनी पार्टी की तरफ से वे हामी कैसे भरे। इस कठिनाई से पार उतरने का यह साहसिक प्रयास था। इस विषयसूची में इस माग का उल्लेख था कि अन्तर्कालीन व्यवस्था के रूप में भारत सरकार के १९३५ के विधान के सशोधित-आधार पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने की शीघ्रता की जाय। सर्वसत्ता-सम्पन्न एक अथवा दो राष्ट्रों का निर्माण हो। यदि एक ही राष्ट्र की स्थापना हो तो सत्ता वर्तमान केन्द्रीय सरकार को सौंप दी जाय। छठे सूत्र में कहा गया था कि दोनों राष्ट्रों का एक ही सर्वजन-जनरल हो। अतः मे सेना के विभाजन के हल का उल्लेख था। इसमें कहा गया था कि टुकड़ियों का ब्रह्मचर्य भर्ती के अनुसार होना चाहिए। जिस प्रदेश से भर्ती करके जो टुकड़ी बनाई गई हो उसे उसी प्रदेश की सरकार को सौंप दिया जाय। मिली-जुली टुकड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था का निर्देश था।

उक्त प्रस्ताव पर माउन्टबेटन जिन्ना और लियाकत अली की स्वीकृति पाने में असफल रहे। प्रस्ताव के आम सिद्धांतों से वे सहमत थे, लेकिन अपनी सम्मति लिखित रूप में देने को तैयार नहीं थे। वी पी मेनन के अनुसार पटेल और नेहरू यह चाहते थे कि जिन्ना उक्त योजना को ऐसे ढंग से स्वीकार कर ले कि यह निश्चित हो जाय कि यह उनकी आखिरी प्रादेशिक माग थी। यदि वह ऐसी घोषणा कर दे तो कांग्रेस को सतोष हो जायगा।

माउन्टबेटन ने कहा कि समझौते के अभाव में अन्तरिम सरकार को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के बारे में जिन्ना की प्रतिक्रिया उन्होंने परखी थी। जिन्ना ने शान्ति से कहा कि ऐसी स्थिति को वह किसी भी हालत में नहीं रोक सकते। कुछ दृष्टियों से माउन्टबेटन और जिन्ना के बीच यह कूटनीति का सबसे सूक्ष्म दौर था। माउन्टबेटन के अनुसार जिन्ना की प्रतिक्रिया असाधारण और अशान्तिकारक थी।

नई दिल्ली, रविवार, १८ मई, १९४७

माउन्टबेटन सबेरे ८॥ बजे पालम में लन्दन को खाना छोड़ गए। उनके स्थान पर कालविल स्थानापन्न वाइसराय बनेंगे। माउन्टबेटन अपने साथ वी पी मेनन को भी ले गये थे। इन दिनों मेनन का सितारा चमक रहा था और वह माउन्टबेटन के पूर्ण विश्वासभाजन थे। शासनिक-योग्यता और मसविदा बनाने की निपुणता उनमें ऊँचे दर्जे की है। समझौता-चर्चा में भी उनका योग सहायनीय रहा था। इससे पता



चलता था कि माउन्टबेटन उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करने में कितने पटु थे।

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, २२ मई, १९४७

जिन्ना ने ऐन समय पर एक चौकाने वाली माग की थी। वह पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए ८०० मील लम्बा गलियारा माग रहे थे। अपनी माग प्रकाशित करने में उन्होंने स्टालिन का अनुकरण किया था। यह माग उन्होंने रायटर के सवाददाता डून कम्पबैल के प्रश्नों का उत्तर देते हुए व्यक्त की थी। अर्सकिन क्रम को मैंने जो लन्दन तार दिया, उसमें लिखा था, “जिन्ना ने उत्तर मौखिक रूप से नहीं, बल्कि लिखित रूप में दिये।” ज्यो ही रायटर ने उक्त माग प्रकाशित की, त्यो ही जिन्ना के सेक्रेटरी ने फोन करके विदेशी पत्रकारों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। सवाददाता ने मुझे यह बताया कि जिन्ना स्वयं पत्रकारों से मिलने को तैयार थे। पत्रकारों का खयाल था कि जिन्ना अपना वक्तव्य देने को यो भी तैयार थे, रायटर के सवाददाता की प्रार्थना तो एक बहाना मात्र थी। रायटर का उपयोग जिन्ना ने अपना दबाव लन्दन पर डालने और ब्रिटिश समाचार-पत्रों में पूरा प्रचार पाने में किया।

माउन्टबेटन की समझौता-चर्चाएँ सरलतापूर्वक चल रही थी यद्यपि अटकल-बाजियाँ इसके विपरीत थी। लन्दन में उनकी उपस्थिति से ब्रिटिश अधिकारियों को ढाढस मिला। विरोधी दल के नेताओं से भी उन्होंने भेट की, क्योंकि उनके सहयोग बिना पार्लामेंट में ‘भारतीय स्वतंत्रता बिल’ शीघ्रता से पास होना संभव नहीं था। श्री एटली ने भारत सरकार की नीति और उसके परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली थी। हा, विभाजन के सेना-सम्बन्धी प्रश्न पर अवश्य काफी चिन्ता प्रकट की जा रही थी। माउन्टबेटन ओर वी पी मेनन द्वारा प्रस्तुत औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का जोरो से स्वागत किया गया।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २३ मई, १९४७

मैंने वरनोन को लन्दन में निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी है :

“जिन्ना की रायटर सवाददाता से मुलाकात के बारे में केवल ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ ने सम्पादकीय टिप्पणी की है। उसने दृढ़ रुख ग्रहण किया है। पर वह उत्तेजना फैलाने वाला नहीं है। गलियारे के बारे में वह साफ लिखता है कि यदि पाकिस्तान का अस्तित्व गलियारे पर ही निर्भर करता है तो पाकिस्तान कभी नहीं बन सकेगा। मेरा खयाल है कि यहा राजनैतिक क्षेत्रों तथा समाचार-पत्रों की प्रतिक्रिया की जितनी आशा थी, उससे कहीं मद हुई है। जिन्ना की माग का उद्देश्य मुख्य रूप से लन्दन को प्रभावित करना था।”

नई दिल्ली, सोमवार, २६ मई, १९४७

जिन्ना की गलियारे की माग की देर से ही सही, किन्तु जोरदार प्रतिक्रिया हुई। विवाद की ज्वालाएँ भभक रही थी और किसी तात्कालिक राजनैतिक निर्णय से ही शान्त हो सकती थी। माउन्टबेटन द्वारा निर्माण की गई सद्भावना का स्रोत उनकी अनुपस्थिति में सूख रहा था। राजेन्द्रप्रसाद और शंकरराव देव (कांग्रेस-मंत्री) ने जोरदार वक्तव्य निकाले थे। राजेन्द्रप्रसाद कहते थे, “जिन्ना की माग जरा भी ध्यान देने योग्य नहीं है।” देव का कहना था, “जिन्ना की माग इस भाति के कारण बढ़ रही है कि अंग्रेज अब भी उनकी मदद कर सकते हैं। देश पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा तथा गलियारे की माग पूरी नहीं की जा सकेगी।”

‘डान’ ने देव और राजेन्द्रप्रसाद को उत्तेजनात्मक जवाब दिया था। ‘सारे जड़-मूर्ख हैं’ शीर्षक से उसने लिखा, “गलियारे की माग कोई नई नहीं है। कायदे-आजम जिन्ना इस माग को कई बार दोहरा चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए अनिवार्य है। पाकिस्तान को यदि वास्तविक रूप देना है तो उसके पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशों को जोड़ने वाला गलियारा अत्यन्त आवश्यक है। हमें कोई सदेह नहीं है कि यदि मुसलमान पाकिस्तान ले सकते हैं तो कहीं-न-कहीं गलियारा भी बना सकते हैं। देव यह भली भाँति जानते हैं।”

शनिवार को नेहरू ने ‘युनाइटेड प्रेस आव अमेरिका’ को जो मुलाकात दी थी उसमें उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से गलियारे की माग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “जिन्ना का हाल का वक्तव्य सर्वथा अवास्तविक है और यह बतलाता है कि वह किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहते। गलियारे की माग विचित्र और निस्सार है। हम तो एक सयुक्त भारत के पक्ष में हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेशों को अलग होने का अधिकार प्राप्त रहेगा। हम दबाव नहीं डालना चाहते। यदि और प्रादेशिक मागें किये बिना समझौता नहीं किया जाता तो हम सयुक्त भारत का विधान बनाने और उसे कार्यान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर देंगे।”

नेहरू का कहना था कि चूँकि जिन्ना ने प्रस्तावित योजना को अस्वीकार कर दिया है, अतएव अन्तरिम सरकार को ही ओपनिवेशिक सरकार बना दिया जाय। उनकी शिकायत थी कि जिन्ना को जो मिलता है, उसे तो वे स्वीकार कर ही लेते हैं और फिर अधिकाधिक मागते जाते हैं। इस प्रकार एकतरफा वादे कैसे किये जा सकते हैं?

नई दिल्ली, मंगलवार, २७ मई, १९४७

बरोज द्वारा भेजी गई रिपोर्टों से पता चलता था कि वह कलकत्ता की अशांत स्थिति से बहुत चिंतित है। पिछले एक-दो दिनों में उन्होंने महसूस किया कि तनाव उनके अनुमान से कहीं अधिक गंभीर था। इसलिए चाहते थे कि सबको शांत करने

के लिए रेडियो पर भाषण दे, जिसके लिए वह माउन्टबेटन की अनुमति चाहते थे। उन्होंने 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपी एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें नेहरू के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि संधर्ष का नया दौर २ जून से शुरू हो रहा है, और शांति-पूर्ण समझौते की उन्हें कोई आशा नहीं।

इस कथित वक्तव्य के विषय में जांच करने पर मुझे मालूम हुआ कि यह निराधार था। यह घटना भी मौजूदा घबराहट और अनिश्चितता का उदाहरण थी।

मुझे मालूम हुआ कि कलकत्ता में हिन्दू और मुसलमान मोर्चे बनाकर उन पर आ डटे हैं। मकानों और पूरों-की-पूरी सड़कों को लड़ाई की चोकियों का रूप दे दिया गया था।

नई दिल्ली, शनिवार, ३१ मई, १९४७

माउन्टबेटन दिल्ली लीट आये हैं। अपने कर्मचारियों को उन्होंने तुरन्त विचार-विनिमय के लिए बुलाया। नेताओं की बैठक होने में अब एक ही सप्ताह शेष था जिसमें भारत के भविष्य का निर्णय किया जायगा।

माउन्टबेटन की शारीरिक और मानसिक शक्ति आश्चर्यजनक थी। अपनी लम्बी यात्रा से अथवा लदन की चर्चाओं से वह बिल्कुल भी थके हुए नहीं मालूम देते। इसके विपरीत वह पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और उत्साही जान पड़ते थे और कर्मचारियों को आदेश-पर-आदेश देते जाते थे।

माउन्टबेटन गांधीजी के हाल के प्रार्थना-प्रवचनों पर विस्तार से विचार करने को व्यग्र थे। इन प्रवचनों में गांधीजी ने संयुक्त भारत का पक्ष लिया था और उनके भाषणों से ऐसा लगता था मानो वह मन्त्रिमंडलीय-योजना के जबरन लादे जाने के पक्ष में हों। कालविल और बी. पी. मेनन, दोनों ने यह मत व्यक्त किया कि विभाजन के प्रति गांधीजी का विरोध योजना को तोड़ने की सीमा तक नहीं पहुँचेगा।

माउन्टबेटन का स्पष्ट मत था कि वह जिन्रा पर नाराजी के बजाय दुख ही प्रकट करेंगे। जिन्रा को बतलाएंगे कि उनकी गलियारे की मांग से उन्हें कितनी परेशानी हुई। जिन्रा के नाम चर्चिल का एक सदेश भी वह साथ लाये थे जिसे वह जरूरत पड़ने पर प्रयोग में ला सकते थे। चर्चिल ने अपने सदेश में कहा था कि योजना को स्वीकार करना जिन्रा के लिए जीवन-मरण के प्रश्न से कम नहीं है।

नई दिल्ली, रविवार, १ जून, १९४७

मैंने अपनी मा को लिखा

“यहाँ हम महत्वपूर्ण घटनाओं के द्वार पर खड़े हैं और मैं सत्ता-हस्तांतरण के बारे में माउन्टबेटन की ऐतिहासिक घोषणा की प्रचार-व्यवस्था को अंतिम रूप देने के काम में आकंठ डूबा हुआ हूँ। वातावरण बहुत ही क्षुब्ध है और अगर फैसला

विभाजन के पक्ष में हुआ—जैसा कि निश्चय-सा है—तो काफी साम्प्रदायिक दंगे हो सकते हैं। लेकिन आज की अनिश्चितता से तो कोई भी फैसला बेहतर ही होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह गुस्सा अन्तरिम और आपसी है। अंग्रेज हिन्दू और मुसलमानों दोनों में जितने लोकप्रिय आज हैं, उतने पहले कभी नहीं थे।

“सरकार की २० फरवरी वाली घोषणा का खास असर यह हुआ कि कांग्रेस हाई कमान को यह मान लेना पड़ा था कि विभाजन अवश्यम्भावी है। गांधीजी इस विचार-धारा से सहमत नहीं हो रहे थे और इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रहे थे। उनके इस विरोध की सीमा क्या होगी, यह कहना मुश्किल था।

“अन्तरिम सरकार के दोनों प्रमुख कांग्रेसी नेताओं नेहरू और पटेल ने इस धारणा पर विभाजन को स्वीकार किया था कि जिन्ना को पाकिस्तान देकर वे उनसे मुक्ति पा जायेंगे या जैसा कि नेहरू खानगी तौर से कहते थे, ‘सिर कटाकर हम सिरदर्द से छुट्टी पा लेंगे।’ उनका यह रुझान दूरदर्शितापूर्ण लगता था क्योंकि अधिकाधिक खिलाने के साथ-साथ जिन्ना की भूख बढ़ती ही जाती थी और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए ८०० मील लम्बे गलियारे की मांग उनकी सर्वग्राही नीति का सुन्दर उदाहरण था। इसलिए दोनों पक्ष समझौते पर बहुत ही अग्रोभनीय ढंग से विचार कर रहे थे। विभाजन निश्चय ही एक दुखात घटना थी, लेकिन इससे भी दुखात घटना होगी एक ऐसी एकता थोपने का प्रयास करना, जो १० करोड़ मुसलमानों के अधिकांश भाग को स्वीकार नहीं थी।”

: ६ :

## ऐतिहासिक समझौता

नई दिल्ली, सोमवार, २ जून, १९४७

ऐतिहासिक घड़ी आ पहुँची। अपनी बड़ी अमरीकी-कारों में सवार नेता लोग उत्तरी आगन में आने लगे हैं। जिन्ना सबसे बाद में आये, कुछ मिनट देर से। माउन्टबेटन ने इधर-उधर की बातें करने की पूरी कोशिश की, किन्तु साफ जाहिर है कि वातावरण काफी आवेशपूर्ण है। कृपालानी को शामिल करने की समस्या जिन्ना को अपने साथ रबनिस्तर को लाने की अनुमति देकर हल कर ली गई थी। इस प्रकार ‘पाँच बड़े’ अब ‘सात बड़े’ हो गए हैं।

माउन्टबेटन इस बात के लिए उत्सुक थे कि इस प्रारम्भिक बैठक की कार्यवाही

मे किसी प्रकार की रुकावट न आवे। इसलिए फोटो लेने का काम भारत सरकार के फोटोग्राफर तक ही सीमित रखा गया। इससे तत्काल भारतीय और विदेशी फोटोग्राफरों में बहुत नाराजी फैल गई और उन्होंने मेक्स डेस्फार के नेतृत्व में 'वाक् आउट' कर दिया और मुझे एक विरोध-पत्र भेजा। मैं उनकी शिकायत को पूरी तरह समझता था और आशा करता था कि कल इसका कोई इलाज कर सकूंगा। लेकिन आज तो महत्त्व की बात यह थी कि बिना किसी मानसिक खिचाव या विघ्न के माउन्टबेटन कार्यवाही का शुभ श्रीगणेश कर सके।

बैठक ठीक दो घंटे चली। वरनोन ने बतलाया कि अधिकांश बोलने का काम माउन्टबेटन ने ही किया और घटनाओं के विकास का तर्कपूर्ण विश्लेषण करने में बड़ी कुशलता दिखाई। उनके शुरू के शब्दों में नेताओं को उन परिस्थितियों के स्तर तक उठने की चुनौती थी, जिनका निर्माण उनके हाथों हो रहा था। उन्होंने कहा कि गत पांच वर्षों में उन्होंने युद्ध के भाग्य का निर्णय करने वाली बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। लेकिन शायद ही किसी बैठक में किये गए निर्णयों का विश्व के इतिहास पर इतना गहरा असर हुआ हो जितना आज की बैठक के निर्णयों का होगा। माउन्टबेटन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नेताओं की इच्छाओं के खिलाफ रफ्तार बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। जिन लोगों से उनकी बातें हुई, उन सबने ही स्थिति की विशद गंभीरता पर जोर दिया था। उन सबने मौजूदा अनिश्चितता का अन्त करने की इच्छा जाहिर की। इसलिए जितनी जल्दी सत्ता-हस्तांतरण हो, उतना अच्छा।

इसके बाद माउन्टबेटन ने मंत्रिमंडलीय-योजना को पुनरुज्जीवित करने का आखिरी औपचारिक प्रयास किया और जिन्ना ने अखिरी बार औपचारिक रूप से उसे ठुकरा दिया। अब माउन्टबेटन ने विभाजन द्वारा उत्पन्न दुविधा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत के विभाजन के सिद्धांत से सहमत नहीं है। लेकिन अगर विभाजन टाला न जा सके तो वह प्रान्तों के विभाजन का आग्रह करेगी, जिसमें मुसलमान या हिन्दू बहुमतवाले इलाकों पर कोई जोर-जबरदस्ती न हो। उधर जिन्ना प्रान्तों के विभाजन के विरोधी थे, लेकिन भारत के विभाजन की मांग करते थे।

माउन्टबेटन ने यह बतलाने की कोशिश की कि उनकी योजना को ब्रिटिश विरोधी दल का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लन्दन में पार्टीबन्दी की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा। उन्होंने सिखों की स्थिति के बारे में अपनी व्यथा की चर्चा की और कलकत्ता को स्वतंत्र बन्दरगाह बनाने या न बनाने के प्रश्न पर मत-संग्रह किये जाने के सुझाव को दृढ़ता के साथ अन्तिम रूप में रद्द कर दिया।

फिर बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने योजना की नई धारा २० को 'तुरन्त सत्ता-हस्तांतरण' शीर्षक के अन्तर्गत पेश किया। उन्होंने इसके फलस्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक स्वराज्य का पक्ष समर्थन किया, इसलिए नहीं कि समय की मर्यादा

बीत जाने पर भी ब्रिटेन यहा जमा रहना चाहता है, बल्कि यह आक्षेप किये जाने के भय से कि वह अपने दायित्व से भाग खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि इसलिए आवश्यकता होने पर ब्रिटेन को सहयोग से असमय हाथ नहीं खींचना चाहिए।

जिन्ना ने अपनी एक पिछली मुलाकात में एक प्रस्ताव पर 'सहमति' और 'स्वीकृति' में भेद बताकर माउन्टबेटन को चौंका दिया था। इस 'पाडित्य' का उपयोग आज माउन्टबेटन ने अपने सुभीते के लिए किया।

योजना की प्रतिया सबको बांट देने के बाद उन्होंने कहा कि वह महसूस करते हैं कि नेताओं से योजना के प्रति पूरी सहमति की माग करना नेताओं को अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करने पर मजबूर करना होगा। इसलिए वह उनसे केवल यही अनुरोध करना चाहेंगे कि वे योजना को शांतिपूर्ण भावना से अपनी स्वीकृति दे दें। जब नेहरू ने 'स्वीकृति' और 'सहमति' के भेद और उसकी परिभाषा करने को कहा तो माउन्टबेटन ने तुरन्त उत्तर दिया कि सहमति में यह विश्वास निहित है कि वह सही सिद्धांतों पर आधारित है। लेकिन चूंकि उन्हें दोनों पक्षों के सिद्धांतों की अवहेलना करनी पड़ी थी, इसलिए वह पूरी सहमति की माग नहीं कर सकते। वह केवल यह चाहते हैं कि योजना पर यह विश्वास प्रकट करते हुए स्वीकृति दे दी जाय कि देश की भलाई के लिए वह एक न्यायपूर्ण और ईमानदारी का हल है।

इस पर नेहरू ने कहा कि यद्यपि कांग्रेस इस योजना से पूरी तौर से सहमत तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन हा, उसे वह स्वीकार करने को तैयार है। निश्चय से कहा कि योजना की स्वीकृति में वस्तुतः उसे कार्यान्वित करने की सहमति निहित है। माउन्टबेटन ने इस पर अपनी हार्दिक स्वीकृति प्रकट की, और उस क्षण से जान लिया कि असली लड़ाई जीती जा चुकी है।

तब जिन्ना ने इस बात की लम्बी-चौड़ी सफाई दी कि सर्वशक्तिमान कायदे-आजम होते हुए भी वह क्यों स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों को उन्होंने आत्मसात् कर लिया है, किन्तु अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन्हें और उनकी कार्यसमिति दोनों को, अपने मालिकों, आम जनता, के सामने जाना पड़ेगा। माउन्टबेटन ने कहा कि ऐसे मौके भी आते हैं जब नेताओं को बिना अपने अनुयायियों से सलाह किये महत्वपूर्ण निश्चय करने पड़ते हैं—इस विश्वास के साथ कि बाद में वे उनका समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। ऊपर से एक निश्चय कर लिया जाय और बाद में जनता द्वारा उसकी पुष्टि हो जाय तो यह जनतंत्रीय कार्यविधि के अनुकूल होगा। फिर, जिन्ना स्वीकृतिसूचक निर्णय के इतने नजदीक पहुँच गए जितनी एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती थी जो बार-बार 'नहीं' कहकर ही इतनी सफलता पा सका हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपने मालिकों, आम जनता, के सामने इस योजना को तोड़ने नहीं, बल्कि उन्हें इसे स्वीकृति देने के लिए राजी करने के ईमानदारीपूर्ण इरादे से जायगे। अभी वह अपना व्यक्तिगत आश्वासन मात्र दे

सकते हैं कि वह अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे।

माउन्टबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कार्यसमितियों तथा सिखों की प्रतिक्रिया आधी रात तक जानना चाहते थे। कृपालानी और बलदेवसिंह ने उसी गाम पत्र भोजनामजूर कर लिया। जिन्ना ने अपनी कार्यसमिति की राय को लिखित रूप से भेजने में असमर्थता प्रकट की किन्तु वह इस बात पर राजी हो गए कि वाइसराय से मिलकर वह उन्हें मौखिक रिपोर्ट दे देंगे। माउन्टबेटन इससे सतुष्ट हो गए।

नेहरू, जिन्ना और बलदेवसिंह की इस बात के लिए स्वीकृति भी माउन्टबेटन ने प्राप्त कर ली कि अगले दिन गाम को वे उनके बाद आल इंडिया रेडियो से जनता के नाम सदेश प्रसारित करें। माउन्टबेटन ने कहा कि वह उन्हें अपने भाषण का मसविदा सुवह दिखा देंगे। पटेल ने, जो बहुत कम बोले थे, कुटिल मुसकान से कहा कि आम कायदा तो यह है कि रेडियो-भाषण की पाडुलिपियां प्रसारित होने से पहले सूचना-मन्त्री को (अर्थात् स्वयं उन्हें) भेजी जानी चाहिए। जिन्ना ने बिना मुसकराए उत्तर दिया कि वह अपने भाषण में वही कहेंगे जो उस समय उनके दिल में आयेगा।

जैसा कि पहले ही तय था, बैठक के बाद माउन्टबेटन ने जिन्ना से रुकने का कहा। इसके दो उद्देश्य थे। वह गांधीजी को, जो कभी कांग्रेसी नेताओं के साथ नहीं आते थे, अलग मुलाकात देनेवाले थे और इस विषय में मुस्लिम लीग की आलोचना को निस्तार कर देना चाहते थे। दूसरा कारण यह कि वह जिन्ना पर व्यक्तिगत दबाव डालना चाहते थे और जरा ज्यादा स्पष्टतया जानना चाहते थे कि अन्त में जिन्ना क्या रुख अपनायेंगे। लेकिन जिन्ना ने योजना पर कुछ नहीं कहा। अब सारा दारोमदार उनकी रात की भेंट पर निर्भर करता था।

फिर साढ़े बारह बजे महात्माजी आये। एक तरह से वह सारी कार्यवाही में उपस्थित रहे थे। विभाजन-योजना के औपचारिक रूप से पेश किये जाने पर उनकी अन्तिम प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चितता ने सवेरे की बैठक में कांग्रेसी-नेताओं के हाथ-पैर बाधने का काम किया था। अपनी अन्तरात्मा के आदेशों पर गांधीजी किसी चीज के बारे में क्या रुख अपनाते हैं, इस विषय में अनिश्चितता से कांग्रेसी नेता खूब परिचित थे। काफी लोगो को तो आगका थी कि अपनी अन्तरात्मा के आदेश पर वह योजना को तोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे जिससे, भारत के विभाजन को रोक सकें। माउन्टबेटन इस मुलाकात से काफी डर रहे थे। उनके आश्चर्य और राहत की सीमा न रही जब गांधीजी ने इस्तेमाल किये लिफाफो तथा रद्दी कागजों की पीठ पर लिखकर सूचित किया कि आज उनका मौन दिवस है।

भेंट खत्म हो जाने के बाद माउन्टबेटन ने कागज के इन टुकड़ों को उठा लिया। इन्हें वह ऐतिहासिक स्मृति-चिह्न समझते थे। उनपर महात्माजी ने लिखा था, "खेद है कि मैं बोल नहीं सकता। सोमवार के मौन का निर्णय लेते समय मैंने केवल दो अपवाद रखे थे। जरूरी मामलो पर उच्च-अधिकारियों से बात करना और

बीमारो की परिचर्या। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि मैं अपना मौन तोड़ूँ। क्या मैंने अपने भाषणों में एक भी शब्द आपके विरुद्ध कहा है? यदि आप स्वीकार करें कि मैंने नहीं कहा तो आपकी चेतावनी अनावश्यक है। दो-एक चीजों पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं। अगर हम फिर मिलें तो कहूँगा।”

इस विचित्र कार्यविधि में राजनैतिक त्याग, निस्पृहता और आत्मसमर्पण का महान् कार्य छिपा हुआ था। जब इस ऐतिहासिक बैठक के बाद मैं प्रेस-विज्ञप्ति के बारे में माउन्टबेटन से दो शब्द कहने अन्दर गया तो मैंने भी छोटी गोलमेज से एक तोफा खोज निकाला। यह था जिन्ना द्वारा अपनी महान्तम राजनैतिक विजय के क्षण में अनजाने एक सफेद कागज पर खींची लकीरो का गोरख-धवा। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, लेकिन मेरा खयाल है कि इस गोरख-धवे में शक्ति और गौरव के चिह्न सहज ही देखे जा सकते थे।

नई दिल्ली, मंगलवार, ३ जून, १९४७

माउन्टबेटन ने आजका काम सुबह ही कर्मचारी-मंडल की बैठक से शुरू किया, जिसमें उन्होंने कल आधी रात के समय जिन्ना के साथ हुई नाटकीय झड़प का हाल बताया। चूँकि जिन्ना ने योजना पर अपना उत्तर लिखित रूप में दे देने से साफ इन्कार कर दिया था इसलिए उनकी जवानी बात के गवाह के रूप में इसमें भी माउन्टबेटन के साथ शामिल हो गए। जिन्ना ने उन्हीं बातों को विस्तार से दोहराना शुरू किया जो उन्होंने सुबह नेताओं की बैठक में कही थी, और माउन्टबेटन के कितना ही दबाव डालने पर भी वह स्वीकृति देने पर राजी नहीं हुए कि मुस्लिम लीग कौंसिल की बैठक योजना पर दृढ़तापूर्वक अपनी सहमति प्रकट कर देगी। वह केवल इतना जिम्पा लेने को तैयार थे कि कौंसिल से योजना मनवाने का वह वैधानिक तरीके से भरसक प्रयत्न करेंगे और इस कार्य में उनकी कार्यसमिति उनका समर्थन करेगी।

माउन्टबेटन ने तब जिन्ना को याद दिलाई कि कांग्रेस को उनकी इस तरह की पैतरेवाजी पर भयंकर सदेह है, जिसे वह हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वह यह कि जब तक किसी योजना के बारे में कांग्रेस कोई पक्का निश्चय नहीं कर लेती तब तक तो वह इतजार करते रहते हैं और उसके कई दिन बाद मुस्लिम लीग के मन-माफिक फैसले की घोषणा करने की छूट रखते हैं। माउन्टबेटन ने चेतावनी दी कि नेहरू, कृपालानी और पटेल ने यह गर्त रखी थी कि यदि मुस्लिम लीग ने भी उनके साथ ही योजना को स्वीकार नहीं किया तो वे योजना को ठुकरा देंगे। उन्होंने यह भी शर्त रखी थी कि मुस्लिम लीग इसे एक अन्तिम समझौते के रूप में स्वीकार करे।

माउन्टबेटन के लाख कहने पर भी जिन्ना टस-से-मस न हुए। जिन्ना ने फिर एक बार यह बहाना किया कि मुस्लिम लीग कौंसिल की सलाह के बिना उन्हें निर्णय



करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं और कहा कि कौंसिल की बैठक तो वह अभी कई दिनों तक नहीं बुला सकेंगे। माउन्टबेटन ने कहा, “अगर यही आपका रुख है तो कांग्रेसी और सिख नेता भी कल सुबह की बैठक में योजना को नामजूर कर देंगे, फिर अराजकता फैल जायगी और आप अपना पाकिस्तान भी खो बैठेंगे शायद हमेशा के लिए।” जिन्ना ने कंधे हिलाते हुए केवल इतना कहा “जो होना होगा हो जायगा।”

इस पर माउन्टबेटन ने कहा, “मि जिन्ना, इस समझौते को तैयार करने में जो मेहनत लगी थी, उसे मैं आपको इस तरह बेकार नहीं करने दूंगा। चूंकि आप मुस्लिम लीग की ओर से स्वीकृति देने को तैयार नहीं इसलिए मैं उसकी ओर से बोलूंगा। मैं यह कहने का खतरा उठाऊंगा कि जो आश्वासन आपने मुझे दिये थे उनसे मैं सतुष्ट हूँ। यदि आपकी कौंसिल समझौते की पुष्टि नहीं करे तो आप मुझे दोष दे सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। जब सुबह की बैठक में मैं यह कहूँ कि मि जिन्ना ने मुझे कुछ आश्वासन दिये हैं, जिन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है और मैं उनसे सतुष्ट हूँ तो आप किसी भी हालत में उसका खडन नहीं करेंगे। और जब मैं आपकी ओर देखूँ तो आपको सहमति स्वरूप अपना सिर हिलाना होगा।”

इस प्रस्ताव के उत्तर में भी जिन्ना ने कोई मौखिक स्वीकृति न देकर केवल सिर हिला दिया। माउन्टबेटन का अन्तिम प्रश्न यह था, “क्या मेरा एटली को यह सलाह भेजना ठीक होगा कि वह योजना की घोषणा-कल कर दे?” इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा, “हां।” इस अन्तिम आश्वासन से माउन्टबेटन और इस्मे ने यह समझ लिया कि मुस्लिम लीग कौंसिल की बैठक होने से पहले, जो एक सप्ताह के अन्दर होगी, जिन्ना से जिस हद तक ‘हां’ कराना संभव था, वह करा ली गई।

जिन्ना के जाने के थोड़ी देर बाद ही कृपालानी का पत्र आया। इसमें कुछ छोटी बातों पर स्वीकृति न देने के अलावा बैसे आम तौर से पूरी योजना पर कांग्रेस कार्य-समिति की दृढ़ स्वीकृति प्रकट की गई थी।

नेताओं के साथ दूसरी बैठक का प्रारम्भ माउन्टबेटन ने कल रात जिन्ना के साथ हुई मुलाकात की रिपोर्ट देकर किया। उन्होंने बताया कि जिन्ना के आश्वासन उन्होंने स्वीकार कर लिये हैं। जिन्ना ने इसकी पुष्टि चुपचाप सिर हिलाकर की। फिर उन्होंने उन गंभीर आपत्तियों का जिक्र किया जो विभिन्न दलों ने योजना के अलग-अलग मुद्दों पर उठाई थी। इनके उठाए जाने पर उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी दल का कोई सुझाव किसी दूसरे दल को स्वीकार नहीं होगा, इसलिए वह उन्हें इस बैठक में छेड़ना ठीक नहीं समझते। अतः उन्होंने नेताओं से आग्रह किया कि वे उनकी इस बात को स्वीकार करें। नेताओं ने बात मान ली। इस प्रकार अपने-आप, और शायद अनजाने ही, विवाद के सब प्रश्न ठिकाने लग गये।

माउन्टबेटन के यह घोषणा करते ही कि शतप्रतिशत सहमति के जितने नजदीक पहुंचना संभव था, यह योजना, उतने नजदीक पहुंच गई है। जिन्ना, कृपालानी और बलदेवसिंह ने कहा कि वाइसराय ने उनके विचारों का ठीक अर्थ समझा है। माउन्टबेटन ने कहा कि अब योजना की सरकारी रूप से घोषणा की जायगी। इस पर किसी नेता ने कोई आपत्ति नहीं की।

इसलिए ऐसा लगने लगा कि आगे का रास्ता अब साफ है। लेकिन माउन्टबेटन के यह अपील करने पर कि छोटे नेता समय से काम ले और अतीत को भूल जाय जिससे सुन्दर भविष्य निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त हो सके, लियाकत से यह कहे बिना नहीं रहा गया कि समय की ज्यादा जरूरत छोटे नेताओं के बजाय बड़े नेताओं को है, जैसे गांधीजी को अपनी प्रार्थना सभाओं के समय। इससे कटुता के पुराने जख्म फिर हरे हो गए।

जिन्ना और लियाकत ने आरोप लगाया कि गांधीजी लोगों को मनमानी करने के लिए उकसा रहे हैं और इस बैठक में भाग लेनेवाले नेताओं को बजाय और किसी पर आस लगाने की सलाह दे रहे हैं। इस पर कृपालानी ने जवाब दिया कि गांधीजी के सारे क्रम अहिंसात्मक होते हैं। पटेल ने मत व्यक्त किया कि गांधीजी किसी भी फौसले का निष्ठा के साथ पालन करेंगे। माउन्टबेटन को यह कहकर इस खतरनाक विवाद का अन्त करना पड़ा कि उनकी राय में इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है।

फिर माउन्टबेटन ने बड़े नाटकीय ढंग के साथ विभाजन के प्रशासन-संबंधी नतीजों के अभिलेख को सिर तक उठा कर और फिर मेज पर पटकते हुए नेताओं के सामने पेश किया। बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा लिखा यह दस्तावेज आज ही के दिन के लिए तैयार किया गया था। इसमें फुलस्केप आकार के घने टाइप वाले चौतीस पृष्ठ थे। थोड़े में लिखने की कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण था।

बोलने की जरा-सी भूल को लेकर तिल का ताड़ बनाये जाने का एक और उदाहरण सामने आया। माउन्टबेटन ने सुझाव दिया कि इस दस्तावेज को 'मंत्रिमंडल की बैठक' के सामने पेश करने के पहले उसपर प्रारम्भिक चर्चा कर ली जाय। जिन्ना और लियाकत ने खट से लम्बी-चौड़ी आपत्ति की कि 'ब्रिटिश मंत्रिमंडल' इस बारे में निर्णायक अधिकारी नहीं। कई मिनट बाद पता चला कि जिन्ना समझे कि माउन्टबेटन का आशय भारतीय मंत्रिमंडल या अन्तरिम सरकार से नहीं, बल्कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल से है। इसपर उन्होंने शिकायत की कि उन्हें भ्रम में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा, "आपका आशय वाइसराय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल से है तो फिर स्पष्ट बात क्यों नहीं कहते?" उन्होंने कहा कि उनका दिमाग वैधानिक ढंग से काम करता है।

दस्तावेज में सुझाया गया था कि दोनों दलों की एक मिली-जुली विभाजन-समिति की रचना की जाय। इसके बारे में लियाकत ने पूछा कि क्या इस समिति में प्रश्नों का

निवटारा बहुमत के आधार पर किया जायगा ? माउन्टबेटन ने कहा, कि नहीं, वार्त्तालाप के आधार पर ही औचित्य का निर्णय किया जायगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भगोना है कि चूँकि विभाजन का प्रश्न अन्तिम रूप से तय हो चुका है, इसलिए जोप प्रश्नों पर विचार करने में एक नई भावना में काम लिया जायगा। लियाकत ने बड़ी तेजी में उत्तर दिया कि यह नई भावना का प्रश्न नहीं है। मेनाओ के विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न पर गभीर मतभेद है।

लेकिन जल्दी ही इस विवाद की गर्मी जाती रही। यह तय होते देर नहीं लगी कि बटवारा नागरिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और नागरिकता का आधार भौगोलिक होना चाहिए। जिन्ना ने बड़े जोश के साथ ऐलान किया कि पाकिस्तान में कोई साम्प्रदायिक भेदभाव नहीं किया जायगा और वहाँ रहनेवाले लोगों को उनके धर्म का विचार किये बिना पूरा नागरिक माना जायगा।

चार बजे रियासती वार्ता कमेटी के सदस्य कौंसिल भवन में एकत्रित हुए, जिसमें आज रात के सरकारी ऐलान और भाषणों के पहले उन्हें माउन्टबेटन और नेताओं के बीच हुए समझौते की पृष्ठभूमि समझाई जा सके।

विंगाल अडाकार मेज के इर्द-गिर्द रियासती जगत के श्रेष्ठ सलाहकार बैठे हुए थे। भोपाल, पटियाला, डंगरपुर, नवानगर और विलासपुर के शासक स्वयं। हैदराबाद के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, बड़ोदा के सर वी एल मित्तर, मैसूर के सर रामास्वामी मुदलियार, काश्मीर के काक, ग्वालियर के श्रीनिवासन, ब्रावनकोर के सर मी पी रामास्वामी ऐयर, जयपुर के सर वी टी कृष्णमाचारी, बीकानेर के पणिकर, सर सुस्तान अहमद और नरेंद्र मडल के प्रतिनिधि डी के सेन।

यह बात मार्को की थी कि ब्रिटिश भारत के बहुत से श्रेष्ठतम बुद्धिमान लोग रियासतों के दीवान हैं। उनमें से कई तो पहले दर्जे के वकील थे, जिससे उन्हें 'सार्व-भौमता के अन्त' के समान गुल्थीदार समस्याओं से निबटने में सहायता मिलती है। अपने राजाओं के साथ उनका वही सवध रहता था जो एक बैरिस्टर का अपने मूल्यवान मक्किल के साथ होता है।

वे लोग खासतौर से यह जानने को उत्सुक थे कि क्या ब्रिटिश भारत में सत्ता-हस्तांतरण के पहले ब्रिटिश-सत्ता का अन्त करना संभव होगा ? उनकी कल्पना यही थी कि ऐसा होने पर रियासतें सत्ता पाने वाली सरकारों से ज्यादा सुभीते के साथ मोल-भाव कर सकेंगी।

माउन्टबेटन ने बैठक को वास्तविकता के निकट लाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने बतलाया कि दो राज्यों के निर्माण का अर्थ होगा दो मजबूत केंद्रीय सरकारें, जो अपनी सत्ता का विभाजन सहन नहीं कर सकेंगी। दूसरी ओर ओपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लेने में उन राजाओं को, जिन्होंने ब्रिटेन के साथ हुई अपनी संधियों और दोस्ती का स्वामिभक्ति के साथ पालन किया था, सुरक्षा और मुआवजा



उनके गुरु के वाक्य मे अधिकारियों की इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि एक गैरसरकारी व्यक्ति के रूप मे आज से पहले उन्हें रेडियो पर भाषण देने की सहूलियत नहीं दी गई थी।" मैं उम्मीद करता हू कि भविष्य मे अपनी राय जाहिर करने की ज्यादा सुविधाएं मुझे मिल सकेगी और मेरी आवाज अखबारों के वेजान अधरो की बजाय ताजगी और सजीव आपके पास पहुंचा करेगी।" लेकिन उन्होंने जो कहा उसमे न मुझे ताजगी मिली, न सजीवता। इसका अगर थोडा बहुत आभास मिल। तो उन शब्दों मे, जो उन्होंने माउन्टबेटन को श्रद्धाजलि देते हुए कहे।

बड़ी चतुराई से उन्होंने योजना पर कोई ऐलान भी नहीं किया और स्वीकृति का आभास भी बनाये रखा। सब मे बड़ी गुत्थी उनके इन शब्दों मे छिपी हुई थी "हमे यह सोचना है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश की गई योजना को हम सहमति समझे या समझौता। इस बारे मे मैं पहले से कुछ कहना नहीं चाहता।" नेहरू के अन्तिम शब्द थे "जय हिन्द।" जिन्ना ने भाषण का अन्त "पाकिस्तान जिन्दाबाद" कहकर किया। लेकिन यह उन्होंने ऐसे जोर से कहा कि कुछ सुननेवालों को ऐसा लगा मानो कायदे-आजमे ने सारी सज्जनता को तिलाजलि देकर कहा हो, "पाकिस्तान हमारी मुट्ठी मे है।"

बलदेवसिंह सबसे बाद मे बोले। और यह देखते हुए कि विभाजन से सिखों को कितनी भारी हानि उठानी पड़ेगी और इससे उनके सहधर्मियों मे कितनी गहरी कटुता फैलेगी, उनके शब्द काफी जानदार और साहसपूर्ण थे। उन्होंने भारत की सेनाओं को आह्वान किया कि वे अनुशासन के ऊँचे आदर्शों पर कायम रहे, खासकर आंतरिक सुरक्षा के अप्रिय काम को अन्जाम देने मे। जिन्ना के विपरीत उन्होंने योजना को समझौता नहीं माना। उन्होंने कहा, "मैं इसे सहमति कहना पसन्द करूँगा।"

नई दिल्ली, बुधवार, ४ जून, १९४७

आज सवेरे लगभग तीन सौ भारतीय और विदेशी पत्रकारों के सामने लेजिस्लेटिव असेम्बली-भवन मे माउन्टबेटन ने जिस कुशाग्रता का परिचय दिया, वह मेरे लिए अभूतपूर्व था। बिना किसी कागज की सहायता लिये, और बिना भूले-भटके उन्होंने पौन घंटे तक योजना के बारे मे विभिन्न गुत्थियों की सुन्दर व्याख्या की।

इसके बाद उनसे करीब सौ सवाल पूछे गए। सवाल पूछनेवाले मुख्यतः भारतीय पत्रकार थे, जिनके प्रश्नों का उद्देश्य उतना जानकारी हासिल करना नहीं था जितना राजनैतिक प्रचार करना। माउन्टबेटन के ठीक नीचे इस्मे, मिएविल, जार्ज एवेल, आर्नेन स्काट, बी पी मेनन, वरनोन और मैं बैठे थे। लेकिन केवल दो बार ही उन्हें अपने कर्मचारियों की सहायता की आवश्यकता पड़ी।

काफी प्रश्न केवल कल्पना'पर आधारित थे, जिनके उत्तर भी उसी ढंग से दिये गए। जैसे, बिलकुल प्रारम्भ में उनसे पूछा गया, "अपने पिछले अनुभवों के आधार पर हम यह पूछना चाहेंगे कि यदि मुस्लिम लीग कौंसिल ने योजना को ठुकरा दिया तो पाकिस्तान का क्या होगा?"

माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, "यह तो एक कल्पित प्रश्न है। अगर यह सवाल कभी उठे तो मेरे पास आइएगा। मैं बतला दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ।"

प्रश्नकर्त्ता ने फिर पूछा, "लेकिन ऐसे अनुभव हमें पहले हो चुके हैं।" माउन्टबेटन बोले, "आपको हुए होंगे लेकिन मुझे नहीं। सच, अगर ऐसा हो तो मेरे पास आइएगा।"

उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रदेश में प्रस्तावित जनमत-संग्रह के प्रश्न पर भी उनसे बहुत से प्रश्न पूछे गये। इस प्रश्न पर आज भी कांग्रेस का ध्यान केन्द्रित है। राजाओं के बारे में भी उनसे काफी देर तक सवाल पूछे गये। इन सवालों का उत्तर देने में भी माउन्टबेटन का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि प्रत्येक उत्तर के साथ वह योजना का वैधानिक औचित्य स्पष्ट करने में सफल हुए थे।

जब एक प्रश्नकर्त्ता ने मुस्लिम लीग की "गलियारे" की मांग पर उनसे भेद निकालना चाहा, तो माउन्टबेटन ने उत्तर दिया, "आप योजना की किस धारा का जिक्र कर रहे हैं?" उनसे सिखों के भविष्य और उनके प्रति अपनाए रख के बारे में भी प्रश्न पूछे गये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के अन्तर्गत सिखों की समस्या ने उन्हें जितनी चिन्ता में डाला है, उतना अन्य किसी प्रश्न ने नहीं। सीमा-आयोग के बारे में उनसे विशेषकर प्रश्न पूछे गये। सीमा-आयोग को पंजाब, बंगाल और आसाम के मुस्लिम बहुमत प्रदेश की सीमाएँ निर्धारित करने का भार सौंपा गया था। एक सिख सवाददाता ने पूछा कि क्या सीमाएँ निर्धारित करने में अचल संपत्ति संबंधी योग्यता को भी एक आधार माना जायगा? माउन्टबेटन ने मुसकराते हुए उत्तर दिया, "ब्रिटिश सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अचल संपत्ति के आधार पर विभाजन से सहमत होगी, मौजूदा सरकार तो बिलकुल ही नहीं।"

इस सम्मेलन में उन्होंने पहली बार अनौपचारिक रूप से यह संकेत किया कि दोनों उपनिवेशों की सत्ता हस्तांतरित किये जाने की संभावित तिथि १५ अगस्त होगी। असल में उनको सबसे अधिक कसा गया इसी औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर। इसी प्रश्न पर देवदास गांधी से उनकी टक्कर हुई। देवदास गांधी का बात करने का ढक ऐसा विनम्र है कि वह विरोधी के सारे शस्त्र बेकार कर देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि जिस आग्रह के साथ वह प्रश्न करते रहे उससे उनके पिता की मन-स्थिति का भी कुछ अंदाज किया जा सकता था।

पहले तो माउन्टबेटन की समझ में ही नहीं आया कि देवदास पूछ क्या रहे थे। लेकिन असल में वह कह रही थी कि यदि कोई एक रियासत औपनिवेशिक दर्जा

प्राप्त करना चाहे तो ब्रिटेन को यह माग ठुकरा देनी चाहिए और जोर देना चाहिए कि पूरा भारत ही राष्ट्रमंडल की सदस्यता का फ़ैसला करे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि विभिन्न विधान-सभाओं को यह निर्णय करने की छूट देकर “भारी शैतानी की गुजाइश” पैदा कर दी गई है। इस प्रश्न के पीछे यही पुराना शक काम कर रहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य स्वाधीनता से कम है। इसके साथ यह डर भी जुड़ा हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने राष्ट्रमंडल के भीतर रहने का फ़ैसला किया और भारत बाहर चला गया, तो शायद पाकिस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अड्डा बन जायगा।

इस सबब में माउन्टबेटन के अन्तिम शब्द ये थे, “जो प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं उनसे मुझे लगता है कि एक बात लोगों के सामने स्पष्ट नहीं है। न जाने क्यों लोगों के दिलों में इस शब्द औपनिवेशिक स्वराज्य के बारे में कुछ शक भरे हुए हैं। इसका अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता है। अन्तर केवल इतना है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों का आपस में स्वेच्छा से नाता बना रहेगा। सहायता, पारस्परिक विश्वास और आगे चलकर स्नेह के लिए वे एक-दूसरे का मुह ताकेगे।”

वाइसराय-भवन लौटते ही माउन्टबेटन को यह मालूम होते देर न लगी कि देवदास की शकाओं का आधार जितना लगा उससे कहीं गभीर था। महात्माजी असंतुष्ट थे और शाम की प्रार्थना सभा में योजना की कड़ी आलोचना करनेवाले थे। इतना ही नहीं, कल नेताओं के रेडियो-भाषण के पहले उन्होंने कहा था कि कोई नता आलोचना के परे नहीं है। उन्होंने अपनी दुधारी आलोचना का खास लक्ष्य बनाया था नहरू को। उनको ‘हमारे राजा’ कहने के बाद उन्होंने कहा, “राजा जो कुछ करता है या नहीं करता, हमें उसके कहे में नहीं आना चाहिए। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो हमें उसके गुण गाना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो हमें यह भी साफ-साफ कह देना चाहिए।”

माउन्टबेटन का यह निश्चय ठीक रहा कि गांधीजी को समझाने का समय आ गया है। उनकी शकाओं की जड़े गहरी होने और खतरनाक शकल लेने के पहले ही यह काम किया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना सभा के जरा पहले उन्होंने गांधीजी को वाइसराय-भवन आने का आमत्रण दिया। गांधीजी सचमुच दुखी थे, योजना के पहले सदमे से उन्हें लग रहा था कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिए उनके सारे जीवन के प्रयत्नों पर पानी फिर गया था। किन्तु माउन्टबेटन ने मनाने की अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर उनसे कहा कि सरकारी ऐलान को माउन्टबेटन-योजना न समझ कर गांधी-योजना समझे। पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने गांधीजी के प्रमुख विचारों—जोर-जबरदस्ती न किया जाना, आत्मनिर्णय, अंग्रेजों के जाने की निकटतम तिथि और औपनिवेशिक स्वराज्य—को योजना में शामिल करने का भरपूर प्रयास किया था।

आज के दिन फिर माउन्टवेटन की ही जीत हुई। यह आज रात की गांधीजी की कही हुई बातों से देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, 'विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं है। वाइसराय का इसमें कोई हाथ नहीं। सच बात तो यह है कि वह विभाजन के इतने ही विरोधी हैं जितनी कि कांग्रेस है। लेकिन अगर हम दोनों—हिन्दू और मुसलमान—किमी और बात पर राजी होने को तैयार नहीं तो वाइसराय के सामने दूसरा चारा नहीं रह जाता है।' उन्होंने बतलाया कि वाइसराय ने बहुत मेहनत की है और समझौता कराने की जी-नोट कोशिश। यह योजना ही ऐसी चीज थी, जिसके आधार पर समझौता हो सका। वाइसराय देश को अराजकता के हाथों छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसीलिए उन्होंने समझौते की इतनी कोशिशें की। बावजूद ही किमी और वाइसराय ने गांधीजी के दिलाविमाग पर इतनी तेजी से इतनी गहरी जीत हासिल की हो।

कल की तारीख का एक व्यक्तिगत तार, जिसे जॉर्ज ने भेजा है, आज मुझे मिला। इसमें लिखा था "आज तीसरे पहर ठमाठस भरी कामन्स सभा में बड़ी गहरी उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री का ऐलान सुना गया। भारत में आये सुझावों और प्रतिक्रियाओं से यहाँ सब दलों को सतोष हुआ। आज जितनी एकता की भावना है और घटनाओं के भारी महत्त्व को समझने का जो प्रयास दिखाई देता है, उसकी तुलना लड़ाई के दिनों के ऐतिहासिक क्षणों से ही की जा सकती है।"

शाम को ७.३० बजे माउन्टवेटन ने कर्मचारी सडल की बैठक की। एक पीढ़ी पुराना गतिरोध तोड़ने के बाद भी उनके या हमारे किमी के लिए चैन नहीं थी।

रियामतों के प्रश्न पर तूफान के लक्षण मुझे नजर आ रहे थे। नवाब भोपाल ने नरेद्र-सडल की अव्यवस्था से स्तीफा दे दिया था और वह व्यक्तिगत अलगाव एवं स्वाधीनता के मार्ग से हटाए नहीं हटते थे, जो आज की मौजूदा प्रगति के खिलाफ पड़ता था।

'विभाजन के प्रशासन संबंधी नतीजों' पर तैयार दस्तावेज के बारे में नेहरू की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हो रही थी और अन्तरिम सरकार का ढाँचा तथा अस्तित्व बनाए रखने में लॉर्ड के चने चवाने पड़ेंगे।

नई दिल्ली, गुरुवार, ५ जून, १९४७



जरूरत थी। आरोप और प्रत्यारोप के इस वातावरण में माउन्टबेटन ने स्पष्ट कह दिया कि इन झगड़ों में पच बनने की प्रार्थना वह स्वीकार नहीं करेगा। इस कृतज्ञता-हीन काम को पूरा करने के लिए वह ऐसे पच की नियुक्ति करने पर सहमत हो गये जो दोनों को मजूर हों।

अडतालीस घंटे पुरानी विभाजन-योजना से निस्संदेह पूरे देश में तनाव कम हुआ, लेकिन दिल्ली-स्थित नेताओं में इससे कोई भाईचारे की भावना नहीं पैदा हो सकी। यहाँ की स्थिति अब भी तनावपूर्ण थी और मामूली-सी बात से भी गभीर सकट पैदा हो सकता था।

: १० :

## प्रशासन सम्बन्धी नतीजे

नई दिल्ली, रविवार, ८ जून, १९४७

माउन्टबेटन की मुख्य समस्या अब भी मूलतः राजनैतिक ही है और इस समय सबसे बड़ा भय यह था कि किसी दल द्वारा त्यागपत्र दे देने से अन्तरिम सरकार भग्न न हो जाय। अन्तरिम सरकार हमेशा से नाजुक चीज रही थी। विभाजन का सिद्धान्त पूरे तौर से स्वीकार हो जाने के बाद उसे मिलाकर स्थिर रखनेवाली आन्तरिक निष्ठा और उद्देश्य का दिखावा तक भी शेष नहीं रह गया था। माउन्टबेटन यह बात अच्छी तरह समझते थे कि विभाजन-योजना को ब्रिटिश पार्लामेंट द्वारा पुष्टि मिलने के पूर्व यदि किसी दल ने अन्तरिम सरकार से त्याग-पत्र दे दिया तो ३ जून की योजना की सफलता को भारी खतरा पैदा हो जायगा और उनकी स्थिति भी बुरी तरह से खराब हो जायगी।

आज ऐसा लगा कि ठीक यही आफत आनेवाली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से माउन्टबेटन उसे भग्न होने से रोक पाए। अन्तरिम सरकार के कर्तव्यों को सीमित करके झगड़े कम करने के इरादे से उन्होंने सुझाया कि नीति और बड़ी नियुक्तियों सम्बन्धी सब फैसलों को फिलहाल स्थगित रखा जाय।

मन्त्रिमंडल में प्रश्नों का निबटारा कांग्रेस के बहुमत द्वारा ही न हो जाया करे, इसलिए यह रास्ता निकाला गया कि ऐसे मामले सीधे माउन्टबेटन के पास भेजे जाया करे। इसके बाद नेहरू ने कुछ कूटनीतिक नियुक्तियों के लिए माउन्टबेटन की स्वीकृति मांगी और कहा कि माउन्टबेटन मानेंगे कि इससे पाकिस्तान को कोई

चास्ता नहीं। लियाकत ने तुरन्त आपत्ति उठाते हुए कहा कि उदाहरण के लिए वह नहीं चाहते कि मास्को में किसी राजदूत की नियुक्ति की जाय। दुर्भाग्य की बात यह कि सुझाव ठीक इसी नियुक्ति के विषय में किया गया था और जिनकी नियुक्ति की जानी थी वह थी स्वयं नेहरू की बहन श्रीमती विजयालक्ष्मी।

इसके बाद का दृश्य कोलाहलपूर्ण था—सब लोग एक साथ गरमी से बोल रहे थे। नेहरू ने कहा कि सरकारी काम में मुस्लिम लीग का हस्तक्षेप सहन करने की बजाय वह बहुमत के आधार पर काम करने का आग्रह करेंगे और अगर सरकार लीग को ही सौंपी जानी है तो वह तुरन्त स्तीफा दे देंगे।

नई दिल्ली, मंगलवार, १० जून, १९४७

मुस्लिम लीग कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका स्वर कांग्रेस को उभाड़ने वाला था। किंतु प्रस्ताव के शब्द ऐसे थे कि जिन्ना योजना को स्वीकार करने में इससे आगे शायद ही बढ़ना चाहेंगे। मन्निमडलीय-योजना को त्यागने के प्रति सतोष प्रगट करने के बाद प्रस्ताव में कहा गया था कि बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सहमति या असहमति सत्ता-हस्तांतरण के लिये ३ जून की योजना का पूरा अध्ययन कर लेने के बाद ही दी जायगी। प्रस्ताव में जिन्ना को यह अधिकार दिया गया था कि यदि वह चाहे तो योजना के मूल-सिद्धान्तों को समझौते के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।

समाचार-पत्रों को मैंने यह समाचार देकर फिलहाल मौन कर दिया था कि वाइसराय शिमला और वहां से काश्मीर जा रहे हैं।

नई दिल्ली, सोमवार, २३ जून, १९४७

शिमले में आराम करने के बाद फिर दिल्ली की भट्ठी में जलने आ गया हूँ।

पिछले दस दिन माउन्टब्रेटन और उनके कर्मचारियों ने एक बड़े व्यापक क्षेत्र में काम करने में बिताए थे, जिससे योजना के स्वीकार किये जाने के काम में भारी सहायता पहुँची थी। मुख्य घटना हुई थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा योजना की स्पष्ट स्वीकृति। दोनों दलों के मुख्य राजनैतिक निर्णयों के बारे में अब किसी प्रकार के सदेह की गुंजाइश नहीं रह गई थी।

ऐन मौके पर गांधीजी ने भी योजना का समर्थन कर दिया और कांग्रेस हार्ड कमान के साम्प्रदायिक तत्त्वों का अन्दरूनी विरोध दुबले-पतले शरीर वाले इस व्यक्ति की अजेय शक्ति के आगे साकार नहीं हो सका।

जहाँ तक उन प्रान्तों का प्रश्न था, जिनपर योजना का सीधा असर पड़ता था, काफी आत्म-चिन्तन और कुछ टालमटोल के बाद कांग्रेस ने उत्तर पश्चिमी-सीमान्त-

प्रदेश में मतसंग्रह करना स्वीकार कर लिया था। पहले तो डा खान साहब ने इसका बहिष्कार करने की धमकी दी। पर गांधीजी की सलाह पर तय हुआ कि स्थानीय लालकुर्ती वाले सविनय-अवज्ञा के सिद्धान्तों को अमल में लायेंगे और शान्ति के साथ इसमें भाग लेने से इन्कार कर देंगे। मत-संग्रह के समय केरो छुट्टी पर चले जायेंगे। माउन्टबेटन ने बुद्धिमानी से प्रान्त का शासन फौज के हवाले करने का निश्चय किया। भारत की दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेन्ट-जनरल सर रॉब लॉकहार्ट केरो की जगह गवर्नर का पद सभालेंगे।

बंगाल के प्रश्न पर जिन्ना की जिद बढ़ती जा रही थी। अन्तरिम सरकार में तो वह अपनी मुस्लिम लीग के लिए मंत्रिपद की मांग करना अपना अधिकार समझते थे लेकिन पश्चिमी बंगाल के कांग्रेसजनों को बंगाल के अन्तरिम शासन में यह अधिकार देने को तयार नहीं थे।

पंजाब व्यवस्थापिका सभा ने आज औपचारिक रूप से विभाजन का निश्चय किया है। तीन दिन पहले बंगाल ने भी ऐसा ही फैसला किया था। वहां सुहरावर्दी द्वारा रखा यह प्रस्ताव कि एक स्वतन्त्र और संयुक्त बंगाल का निर्माण किया जाय, दोनों दलों के विरोध से गिर गया था। इस प्रकार नियति का चक्र एक पूरा चक्र लगा चुका था और जिस कांग्रेस ने कर्जन की बग-भग योजना का कटुता से विरोध किया था, वही चालीस साल बाद आज खुद उसी नीति का सुझाव दे रही थी।

रियासतों के बारे में अपनी नीति के सबंध में नेताओं ने एक बुनियादी फैसला किया था। दिल्ली में एक रियासती विभाग कायम किया जायगा जो रियासतों के साथ नये सबंधों तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों के लिए उत्तरदायी होगा। इस बीच यह तय किया गया कि यह नया विभाग सत्ता को छोड़कर अन्य सभी चीजें ब्रिटिश सम्राट् के प्रतिनिधि के राजनैतिक विभाग से अपने हाथ में ले ले।

सत्ता-हस्तांतरण के बाद सर्वसत्ता-सम्पन्नता का प्रश्न राजनैतिक और कानूनी प्रश्नों से भरा हुआ था। यह बात माउन्टबेटन को उन चर्चाओं से स्पष्ट हो गई, जो उन्होंने पिछले दस दिनों विभिन्न नेताओं, निजाम के वैधानिक सलाहकार और आने पुराने दोस्त सर वाल्टर माँकटन, नवाब भोपाल और उनके सलाहकार सर जफल्लाखा के साथ की थी। वे कुछ रियासतों के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग कर रहे थे।

राजाओं की अनिश्चितता और निष्क्रियता का अनुभव तो माउन्टबेटन स्वयं काश्मीर में कर आय थे, जहां से वह आज ही लौटे थे। नेहरू और गांधी दोनों इस बात के लिए बहुत व्यग्र थे कि काश्मीर के महाराज स्वाधीनता की कोई घोषणा न करें। नेहरू खुद काश्मीर जाने को उत्सुक थे, जिससे अपने दोस्त शेख अबदुल्ला को, जो रियासती राज्य-परिपक्व के अव्यक्त थे, जेल से छुड़ा सकें। गत वर्ष जब नेहरू काश्मीर गए थे तो काश्मीर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गान्धीजी का

मत यह था कि उन्हें नेहरू के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। काश्मीर के महाराज ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वह दोनों में से किसी को आने देना नहीं चाहते। माउन्टबेटन यह कह कर दोनों की यात्रा टालने में समर्थ हुए थे कि महाराज ने उन्हें बहुत दिनों से काश्मीर आने का निमंत्रण दे रखा है और पहले वह स्वयं वहाँ जाना पसन्द करेंगे।

वहाँ पहुँचने पर उन्होंने पाया कि महाराजा राजनैतिक रूप से सहज पकड़ में नहीं आ रहे। उनके बीच तभी कुछ बातचीत हो पाती जब वह मोटर में बैठकर साथ घूमने निकलते थे। इन मौकों पर माउन्टबेटन ने उनको और उनके प्रधानमंत्री काक को समझाया कि स्वाधीनता की कोई घोषणा न करे, बल्कि जितनी जल्दी हो सके, काश्मीर की जनता की इच्छा मालूम करने की कोशिश करे और १४ अगस्त तक फैसला कर ले कि वह किस देश की विधान-सभा में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। माउन्टबेटन ने उन्हें बतलाया कि नव-निर्मित रियासती विभाग यह आश्वासन देने को तैयार है कि अगर काश्मीर पाकिस्तान में शामिल हुआ तो भारत सरकार इसे मित्रताहीन काम नहीं समझेगी। उन्होंने समझाया कि यदि सत्ता-हस्तांतरण के दिन तक काश्मीर को दोनों उपनिवेशों में से किसी का समर्थन प्राप्त न हो सका तो उसकी स्थिति कितनी खतरनाक हो जायगी। उनका इरादा था कि पहले यह सलाह महाराजा को व्यक्तिगत रूप में अकेले में दे और फिर इसे उनके प्रधानमंत्री के सामने जार्ज एवेल और रेजीडेंट कर्नल वेव की उपस्थिति में होनेवाली एक छोटी बैठक में दोहराए और इस बैठक की कार्यवाही का लेखा रखा जाय।

महाराजा ने सुझाया कि यह बैठक उनकी यात्रा के अन्तिम दिन हो। माउन्टबेटन यह सोचकर राजी हो गए कि इसमें महाराज को किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए काफी समय मिल जायगा। लेकिन जब बैठक का समय आया तो महाराजा ने कहला भेजा कि पेट में झूल उठने के कारण वह खाट से उठने में मजबूर है और मिलाए बैठक में भाग लेने में असमर्थ है।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २७ जून, १९४७

नई कौंसिल की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। माउन्टबेटन आज की बैठक के भी अध्यक्ष थे और उन्होंने आज भी पंच का काम करने से इन्कार कर दिया। लेकिन उनके लिए यह काम करना जरूरी नहीं रह गया था, क्योंकि कौंसिल ने बड़ी आश्चर्यजनक तेजी और एकमत के साथ जिन्ना का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि पंजाब और बंगाल के सीमा-आयोगों की अध्यक्षता के लिए सर साइरिल रेडक्लिफ को आमंत्रित किया जाय। दोनों आयोगों के बारे में उन्हें अपने निर्णायक-मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

उधर नेहरू सीमा-आयोग के लिए सरल उद्देश्य निश्चित करवाने में सफल हुए। यह उद्देश्य निम्न थे “मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बहुमत वाले प्रदेशों के आधार पर दोनों नये प्रान्तों की सीमाएं तय की जाय और ऐसा करते समय अन्य अशो का ध्यान भी रखा जाय।” इस समझौते से दोनों दलों को सतोष हुआ। मुस्लिम लीग ने सोचा कि बंगाल के बारे में विस्तृत शर्तों के आधार पर उसकी कलकत्ता पा लेने की संभावना बढ़ जायगी। कांग्रेस और सिखों ने सोचा कि अन्य अशो के अन्तर्गत सम्पत्ति तथा अन्य चीजों पर ध्यान देने से पंजाब में उनकी फायदा होगा।

पहले इरादा यह था कि सीमा निश्चित करने का कटीला काम संयुक्त राष्ट्र-संघ को सौंप दिया जाय। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसकी कार्यविधि बहुत पेचीदा होगी और समय भी बहुत अधिक लग जायगा। दोनों आयोगों में रेडक्लिफ की सहायता के लिए चार हाईकोर्ट के जज रहेंगे। इनमें से दो कांग्रेस द्वारा नामांकित किये जायंगे और दो मुस्लिम लीग द्वारा।

नई दिल्ली, सोमवार, ३० जून, १९४७

माउन्टबेटन के सुझाव पर स्थापित विभाजन कौंसिल बिना देरी या विवाद के भारतीय सेना के बटवारे के सवाल पर सहमत हो गई।

इसके लिए आचिल्लेक और इस्मे की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने सेना के ‘पुनर्निर्माण’ का ढांचा तैयार किया। लेकिन सकट की बड़ी में उड़ीसा के गर्वनर त्रिवेदी को विचार-विमर्श में सम्मिलित कर माउन्टबेटन ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। त्रिवेदी ही एकमात्र ऐसे भारतीय सिविल अधिकारी थे, जिन्हें युद्धकाल में सुरक्षा-विभाग के सचिव पद पर काम करने के कारण ऊंचे स्तर के सुरक्षा संगठन का काफी अनुभव था। उन्हें नेहरू और पटेल का विश्वास-भाजन बनते देर न लगी। लियाकतअली खा से उनकी पुरानी दोस्ती थी। छिछले सात दिन विस्तृत चर्चाएं कर वह दोनों पक्षोंको कुछ सहूलियतें देने पर राजी कर सके, जिसके फलस्वरूप वास्तविक समझौता हो सका।

## प्रशासन सम्बन्धी नतीजे

इस विषय में यह बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार किया गया भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाएं रखें, जिनमें क्रमशः गैर-मुसलमानों और मुसलमानों का बाहुल्य रहे। पन्द्रह अगस्त से यह सेनाएं अपनी-अपनी पृथक् कमानों के अन्तर्गत काम करें। दोनों पक्ष इस बात पर दृढ़ता से जमे हुए थे कि समझौते की पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उनकी सेनाएं पूर्णतः स्वतन्त्र रहेंगी। जिन्ना और लियाकत-अली खां ने तो खुले तौर से कहा था कि जबतक उनकी फौज नहीं बन जाती तबतक राष्ट्र-संघ को सौंप दिया जाय। लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसकी कार्यविधि बहुत पेचीदा होगी और समय भी बहुत अधिक लग जायगा। दोनों आयोगों में रेडक्लिफ की सहायता के लिए चार हार्डिकोर्ट के जज रहेंगे। इनमें से दो कांग्रेस द्वारा नामांकित किये जायेंगे और दो मुस्लिम लीग द्वारा।

नई दिल्ली, सोमवार ३० जून १९४७

माउन्टबेटन के सुझाव पर स्थापित विभाजन कौंसिल बिना देरी या विवाद के भारतीय सेना के बटवारे के सवाल पर सहमत हो गई।

इसके लिए आचिन्लेक ओर इस्में को जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने सेना के 'पुनर्निर्माण' का ढांचा तैयार किया। लेकिन सकट की घड़ी में उड़ीसा के गवर्नर त्रिवेदी को विचार-विमर्श में सम्मिलित कर माउन्टबेटन ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। त्रिवेदी ही एकमात्र ऐसे भारतीय सिविल अधिकारी थे जिन्हें युद्धकाल में सुरक्षा-विभाग के सचिव पद पर काम करने के कारण ऊंचे स्तर के सुरक्षा संगठन का काफी अनुभव था। उन्हें नेहरू और पटेल का विश्वास-भाजन बनते देर न लगी। लियाकतअली खां से उनकी पुरानी दोस्ती थी। पिछले सात दिन विस्तृत चर्चाएं कर वह दोनों पक्षों को कुछ सहूलियतें देने पर राजी कर सके, जिसके फलस्वरूप वास्तविक समझौता हो सका।

इस विषय में यह बुनियादी सिद्धान्त स्वीकार किया गया भारत और पाकिस्तान अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाएं रखें, जिनमें क्रमशः गैर-मुसलमानों और मुसलमानों का बाहुल्य रहे। पन्द्रह अगस्त से यह सेनाएं अपनी-अपनी पृथक् कमानों के अन्तर्गत काम करें। दोनों पक्ष इस बात पर दृढ़ता से जमे हुए थे कि समझौते की पहली शर्त यह होनी चाहिए कि उनकी सेनाएं पूर्णतः स्वतन्त्र रहेंगी। जिन्ना और लियाकतअली खां ने तो खुले तौर से कहा था कि जबतक उनकी फौज नहीं बन जाती तबतक वे सरकार की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे।

१५ अगस्त के बाद किसी प्रकार के केन्द्रीय प्रशासन संबंधी नियंत्रण के खिलाफ भी दोनों पक्षों ने जोरदार आपत्तियां उठाईं। लेकिन माउन्टबेटन ने इस प्रश्न पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जबतक सिपाहियों और साज-सामान के बटवारे का

काम पूरा नहीं हो जाता तबतक सेना के संचालन का काम आचिन्लेक के हाथ में रहना चाहिए। फिलहाल वह भारत में रहकर भारतीय सशस्त्र सेना का शासन चलायेंगे। यह काम वह संयुक्त सुरक्षा परिषद् के अन्तर्गत करेगा, जिसमें उनके अतिरिक्त दोनों देशों के गवर्नर-जनरल और सुरक्षा-मन्त्री सम्मिलित रहेंगे।

दोनों देशों के नये प्रधान-सेनापतियों के बारे में भ्रम से बचने के लिए १५ अगस्त से लेकर इस कार्य की समाप्ति तक आचिन्लेक को सर्वोच्च सेनापति कहा जायगा। सेना के बटवारे का काम करने की अन्तिम तिथि १ अप्रैल १९४८ ठहराई गई।

नई दिल्ली, मंगलवार, १ जुलाई १९४७

ज्यो-ज्यो १५ अगस्त का दिन नजदीक आता जा रहा था, पंजाब में तनातनी बढ़ रही थी। इस हवा के रुख का पता उस पत्र से मिलता है जो आचिन्लेक को दिल्ली के एक सिख विस्थापित ने भेजा था। पत्र में लिखा था, "सातवीं सिख पलटन अब भी बसरा में पड़ी फारस के तैल-क्षेत्रों पर पहरा दे रही है जबकि पिछले बारह महीनों में उनके स्वदेश में दुखान्त घटनाएँ घटी हैं, जिनसे विदेश में रहनेवाले हमारे बहादुर सिख भाइयों के दिमाग ठिकाने नहीं रह गए। जब भारत का विभाजन हो रहा है तो हमारे सिपाहियों को स्वदेश में अपने घरवालों के बीच होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि अगस्त का नाटक शुरू होने के पहले आप उन्हें घर लौटने की उचित आज्ञा देने में देरी न करेंगे।"

जेनकिन्स ने सूचना भेजी थी कि लाहौर और अमृतसर की स्थिति अत्यधिक चिन्तनीय है। यहाँ की व्यापक-हिंसा हत्या और लूट का रूप ले रही है। यह काम ऐसे चुपचाप और अचानक किये जाते हैं कि सामान्य सैनिक और पुलिस की कार्यवाही द्वारा उन्हें दबाना बहुत मुश्किल है। एक बार यह पता लग जाने पर कि भारत के नगरों को जलाना कितना सहज है, सबसे अधिक खतरा आग लगाने-वाली चीजों से पैदा हो गया है।

∴ ११

## नये गवर्नर-जनरल का प्रश्न

नई दिल्ली, बुधवार, २ जुलाई १९४७

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेता वाइसराय भवन के अलग अलग कमरों में बैठे हुए प्रस्तावित 'उपनिवेश विधेयक' की शर्तों पर विचार कर रहे थे। इस विधेयक का नाम अब 'भारतीय स्वाधीनता विधेयक' रख दिया गया था।

दोहरा रहे थे कि 'आप स्वयं हुकूमत नहीं करना चाहते, तो कम-से-कम हमें तो करने दीजिए।' इसपर जिन्ना की प्रतिक्रिया यह थी कि अगर एक भी लीगी-मत्री को हटाया गया तो वे सब सामूहिक रूप से स्तीफा दे देंगे, और कह देंगे कि वे अब किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे और पूरी विभाजन-योजना से हाथ धो रहे हैं। माउन्टबेटन जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो शांति और पाकिस्तान दोनों की सारी सभावनाएँ नष्ट हो जायगी।

थके और बोझ से दबे नेहरू पर कांग्रेस की इस मांग का दबाव बढ़ता जा रहा था कि वह तुरन्त अपने घर के मालिक बने। इसके कारण पिछले सप्ताह नेहरू स्तीफा देनेवाले थे। पहले तो जिन्ना ने ऐसे किसी भी सूत्र पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसका अर्थ मुस्लिम लीग सदस्यों द्वारा पद छोड़ना हो। इसे उन्होंने लीग के लिए अपमानजनक बतलाया। जब माउन्टबेटन ने एक योजना तैयार की और उनकी इस प्रकार की आपत्तियों का समाधान करने के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया तो जिन्ना बदल गए। उन्होंने कहा कि इस योजना को १९३५ के विधान के अन्तर्गत गैरकानूनी मानकर वह इसका विरोध करेंगे। इससे माउन्टबेटन ने एक नया रास्ता निकाल लिया। लन्दन से पूछ-ताछ करने पर उन्हें पता चला कि जिन्ना की कानूनी आपत्ति में इतनी सचाई थी कि नये विधान के पास होने के पूर्व वह सरकार का पुनर्संगठन नहीं कर सकते।

१५ अगस्त के बाद वह भारत के गवर्नर-जनरल पद पर बने रहे या नहीं, इस प्रश्न पर कोई आखिरी निर्णय करने के पहले माउन्टबेटन लन्दन से राजा, प्रधान-मंत्री तथा अन्य लोगों की अधिकृत सलाह चाहते थे। उनको यह भी आशंका थी कि कहीं ब्रिटिश सरकार यह न समझ बैठे, ओर उसका समझना गलत नहीं होगा, कि उन्होंने दोनों राष्ट्रों के मयुक्त गवर्नर-जनरल की सभावना के बारे में गलत विश्वास दिलाकर उन्हें भुलावे में डाल दिया है।

इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस तुरन्त लन्दन के लिए प्रस्थान करें। अधिकृत तौर से यही कहा जायगा कि वह लन्दन इसलिए जा रहे हैं, जिसमें 'भारत स्वाधीनता विधेयक' को संसद में पास करवाने में सरकार की सहायता कर सके। लेकिन इसके अलावा उन्हें गुप्त रूप से प्रमुख लोगों की राय भी प्राप्त करनी पड़गी कि माउन्टबेटन भारत रुके रहे या स्वदेश लौट आये। मैं भी इसमें के साथ जा रहा हूँ, जिससे नई स्थिति के बारे में समाचारपत्रों तथा अन्य जानकारों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकूँ।

लन्दन, मंगलवार, ८ जुलाई १९४७

रात को भोजन के बाद कल इसमें ने १०, डाउनिंग स्ट्रीट में एक वार्ता में भाग लिया, जो आधी रात के बाद तक चलती रही। हालांकि इस बारे में कुछ शकाएँ



दोहरा रहे थे कि 'आप स्वयं हुक्म त नहीं करना चाहते, तो कम-से-कम हमें तो करने दीजिए।' इसपर जिन्ना की प्रतिक्रिया यह थी कि अगर एक भी लीगी-मत्री को हटाया गया तो वे सब सामूहिक रूप से स्तीफा दे देंगे, और कह देंगे कि वे अब किसी प्रकार का सहयोग नहीं देंगे और पूरी विभाजन-योजना से हाथ धो रहे हैं। माउन्टबेटन जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो शांति और पाकिस्तान दोनों की सारी सभावनाएँ नष्ट हो जायगी।

थके और बोझ से दबे नेहरू पर कांग्रेस की इस मांग का दबाव बढ़ता जा रहा था कि वह तुरन्त अपने घर के मालिक बने। इसके कारण पिछले सप्ताह नेहरू स्तीफा देनेवाले थे। पहले तो जिन्ना ने ऐसे किसी भी सूत्र पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसका अर्थ मुस्लिम लीग सदस्यों द्वारा पद छोड़ना हो। इसे उन्होंने लीग के लिए अपमानजनक बतलाया। जब माउन्टबेटन ने एक योजना तैयार की और उनकी इस प्रकार की आपत्तियों का समाधान करने के लिए एक प्रेस-विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया तो जिन्ना बदल गए। उन्होंने कहा कि इस योजना को १९३५ के विधान के अन्तर्गत गैरकानूनी मानकर वह इसका विरोध करेंगे। इससे माउन्टबेटन ने एक नया रास्ता निकाल लिया। लन्दन से पूछ-ताछ करने पर उन्हें पता चला कि जिन्ना की कानूनी आपत्ति में इतनी सचाई थी कि नये विधान के पास होने के पूर्व वह सरकार का पुनर्संगठन नहीं कर सकते।

१५ अगस्त के बाद वह भारत के गवर्नर-जनरल पद पर बने रहे या नहीं, इस प्रश्न पर कोई आखिरी निर्णय करने के पहले माउन्टबेटन लन्दन से राजा, प्रधान-मंत्री तथा अन्य लोगों की अधिकृत सलाह चाहते थे। उनको यह भी आशंका थी कि कहीं ब्रिटिश सरकार यह न समझ बैठे, और उसका समझना गलत नहीं होगा, कि उन्होंने दोनों राष्ट्रों के मयुक्त गवर्नर-जनरल की सभावना के बारे में गलत विश्वास दिलाकर उन्हें भुलावे में डाल दिया है।

इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इस्म तुरन्त लन्दन के लिए प्रस्थान करें। अधिकृत तौर से यही कहा जायगा कि वह लन्दन इसलिए जा रहे हैं, जिसमें 'भारत स्वाधीनता विधेयक' को सदन में पास करवाने में सरकार की सहायता कर सकें। लेकिन इसके अलावा उन्हें गुप्त रूप से प्रमुख लोगों की राय भी प्राप्त करनी पड़गी कि माउन्टबेटन भारत रुके रहे या स्वदेश लौट आये। मैं भी इस्म के साथ जा रहा हूँ, जिससे नई स्थिति के बारे में समाचारपत्रों तथा अन्य जानकारों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकूँ।

लन्दन, मंगलवार, ८ जुलाई १९४७

रात को भोजन के बाद कल इस्म ने १०, डाउनिंग स्ट्रीट में एक वार्ता में भाग लिया, जो आधी रात के बाद तक चलती रही। हालांकि इस बारे में कुछ शक

उठाई गई कि दोनों देशों के गवर्नर-जनरल के रूप में पच होने की बजाय केवल एक देश का गवर्नर-जनरल बनने से उनकी स्थिति कैसी होगी, खासकर जब दोनों के बीच कोई झगड़े के सवाल उठेंगे। फिर भी मंत्रियों की सामान्य राय यह थी कि माउन्टबेटन भारत के आमंत्रण को स्वीकार कर ले। एटली ने तो यहाँ तक कह डाला कि माउन्टबेटन के अलावा कोई और इस काम को सिरे नहीं चढ़ा सकता। इस सुझाव के बारे में मुस्लिम लीग की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप लियाकत का जो पत्र इस्मै अपने साथ लन्दन ले गए थे, उसका सरकार पर गहरा असर पड़ा। दरअसल अब स्थिति यह थी कि दोनों दलों ने माउन्टबेटन से भारत में रुके रहने की प्रार्थना की थी।

आज सवेरे प्रधान-मंत्री ने निम्नलिखित विरोधी नेताओं को मिलने के लिए बुलाया। सेल्स्वरी, मेकमिलन, बटलर, सेम्युअल और क्लैम डेविस। इस्मै ने स्थिति का खुलासा उनके सामने रखा। लार्ड सेम्युअल अपने इस विचार पर अमल कराने के लिए उत्सुक थे कि वाइसराय दो गवर्नर-जनरलों का प्रधान रहे। यह सुझाव उन्होंने माउन्टबेटन को मेरे निवास-स्थान पर माउन्टबेटन के भारत जाने के पूर्व भी दिया था। लेकिन लोगों का आम मत यह था कि इस सुझाव को अमल में लाने का समय बीत चुका है, और कांग्रेस शायद ही इसे स्वीकार करे। उदारदली सदस्यों का हार्दिक मत था कि माउन्टबेटन भारत के गवर्नर-जनरल का पद सभाले। किन्तु अनुदार दली नेता भी, यद्यपि इस सुझाव से सहमत थे, तथापि उनका कहना था कि चर्चिल से सलाह किये बिना वे कोई फैसला नहीं कर सकते। चर्चिल उस समय हाल ही की बीमारी के बाद चार्टवेल में आराम कर रहे थे और ईडन भी बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए थे।

एटली ने इस्मै को सुझाया कि वह चार्टवेल जाकर चर्चिल से मिल आवे। इस्मै को जाते देर नहीं लगी। इस महान् नेता से अपनी मुलाकात के बारे में इस्मै के दिल में जो डर था, वे तुरन्त दूर हो गए। चर्चिल का विचार था कि जिन्ना के फैसले से स्थिति में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। समुद्रीतार द्वारा वाइसराय को भेजे जाने के लिए एक सदेश का मजमून उन्होंने इस्मै को लिखाया। इसका आशय यह था कि वैधानिक गवर्नर-जनरल को जानकारी प्राप्त करने और सलाह देने का असीम अधिकार रहता है। इसके आधार पर माउन्टबेटन नई सरकार को काफी मदद दे सकते थे, जिससे उन्हें सकोच नहीं करना चाहिए। यह फैसला माउन्टबेटन की कल्पना पर छोड़ते हुए कि उनकी उपयोगिता कब तक रहेगी, चर्चिल ने खास जोर उनके कर्तव्यों के राजनैतिक पक्ष पर दिया। उन्होंने कहा कि माउन्टबेटन साम्प्रदायिक तनाव कम करने, राजाओं के हितों को सुरक्षित रखने और भारत तथा शेष राष्ट्र-मंडल के बीच दोस्ती के सबंध पुष्ट करने का काम कर सकते हैं।

बड़ी राहत के साथ इसमें तुरन्त लन्दन लौटे और चर्चिल के अनुदारदली सायियो को अपनी मुलाकात और सदेग का पूरा व्योरा दिया। सदेग तुरन्त दिल्ली भेज दिया गया। इस निर्णायक सलाह ने सबके दिलो को हल्का कर दिया।

जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था औपचारिक चर्चाओ द्वारा कूटनीतिक उद्देश्य सिद्ध करने के बारे में मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था। जिस तरह मे इसमें माउन्टबेटन, ब्रिटिश सरकार और विरोधी दल के दिलो की गंकाए मिटाने में सफल हुए, वह काम इतनी सफलता और फुर्ती के साथ लम्बे पत्रो या तारो से करना संभव नहीं था।

लन्दन, बृहस्पतिवार, १७ जुलाई १९४७

आज शामको वुडरो वाएट ने कामन्स सभाभवन में पटवर्धन से मेरा परिचय कराया। पटवर्धन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के विश्वासपात्र हैं और भारतीय स्वाधीनता-विधेयक पर होने वाली बहस सुनने लंदन आये हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मत है कि माउन्टबेटन को गवर्नर-जनरल पद पर बने रहने का आमंत्रण देकर कांग्रेस ने दूरदर्शिता का काम किया है। समाजवादियो को आशा है कि माउन्टबेटन की उपस्थिति से राजाओ की अपरिवर्तनशीलता कम हो सकेगी और पुनर्मिलनके लिए द्वार खुला रहेगा। मैंने उनसे पूछा कि इस बारे में उनका स्पष्ट मत क्या है कि कांग्रेस द्वारा जनतंत्र की स्थापना करने के निर्णय किये जाने के बाद भी माउन्टबेटन में गवर्नर-जनरल के पद पर रुकने का आग्रह किया गया है? व्यक्तिगत रूप से बोलते हुए उन्होंने कहा कि समय आने पर इस बारे में नेहरू जो रुख अपनाएंगे उससे समाजवादियो को मतोप होगा। मैंने उनसे कहा कि वह विश्वास रखें कि माउन्टबेटन प्राप्त आमंत्रण से एक घटा भी ज्यादा नहीं रुकेंगे।

इस मुलाकात से मेरी यह धारणा बन गई है कि समाजवादी लोग माउन्टबेटन या औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर झगडा नहीं खडा करेंगे। वे अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे रियासतो पर, जहा कांग्रेस-समाजवादियो की काफी बड़ी सत्था मौजूद है। पटवर्धन इस बात के लिए व्यग्र है कि वाइसराय को रियासतो में प्रजातांत्रिक अधिकार दिलवाने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। मैंने कहा कि कुछ वामपथियो में मैंने वह प्रवृत्ति पाई है कि वे केवल 'क्रांति के लिए क्रांति' चाहते हैं। किन्तु पटवर्धन ने दृढ़ता से कहा कि स्वतंत्र क्रांति कोई अच्छी चीज नहीं है। वह वैधानिक रीति से परिवर्तन के पक्ष में है और आखिरी हथियार के तौर पर ही क्रांतिकारी कार्यवाई करने की सलाह देते हैं।

लन्दन, शुक्रवार, १८ जुलाई १९४७

वुडरो वाएट के साथ, जो १९४५ के चुनाव में वर्मिघम से लेबर-सदस्य

चुने गए थे, मरी कई मनोरञ्जक मुलाकातें हुईं। दोनों पक्षों में वह ही एकमात्र तरुण ससद-सदस्य है, जिन्होंने भारत को अपना विशेष विषय बनाया है। मन्त्रिमण्डलीय योजना के समय वह क्रिप्स के व्यक्तिगत सहायक के रूप में भारत आये थे। सुदूरपूर्व के लिए ससदीय प्रतिनिधि-मंडल के भी वह एक सदस्य थे।

इस महत्वपूर्ण प्रवास के बारे में उन्होंने एक मजेदार घटना सुनाई, जिसका सबब उनकी सहयोगिनी, एक स्पष्टवादी ससद-सदस्या मिसेज निकोल्स से था। प्रतिनिधिमंडल की गांधीजी से मुलाकात के समय उन्होंने सोचा कि दल की एकमात्र महिला-सदस्य के नाते उन्हें वातचीत को थोड़ा पारिवारिक स्वरूप देना चाहिए। इसलिए उन्होंने महात्माजी से उनके बच्चों के बारे में सवाल पूछा, “आपके कोई लडकी भी है?”

महात्मा जी ने उत्तर दिया, “मेरी लाखों बेटियाँ हैं? क्या आप इतने सतुष्ट हैं?”

मिसेज निकोल्स ने उत्तर दिया, “मैं तो सतुष्ट हूँ, मि गांधी! पर क्या आपको भी सतोष है?”

: १२ :

## संघ-प्रवेश-पत्र पर राजाओं के हस्ताक्षर

नई दिल्ली, मंगलवार, २२ जुलाई १९४७

आज तीसरे पहर हम पालम हवाई अड्डे पर पहुँच गए। यात्रा वैसे तो निर्विघ्न थी, लेकिन थकान बेहद हो गई थी। इस छ हजार मील लम्बी हवाई यात्रा के बाद कोई भी अभी तक ताजगी महसूस नहीं कर पाया था, और लंदन में घटनाओं की सरगर्मी के दौर के बाद तो हम राजनैतिक सत्ता-परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण आखिरी चरण में भाग लेने के लिए भी नितान्त पगु-से हो गए थे।

हमारी अनुपस्थिति में एक सकट को सरकारी तौर पर हल कर दिया गया था, हालाँकि तनातनी अब भी काफी थी। माउन्टबेटन ने अन्तरिम सरकार का इस प्रकार पूर्ण गठन कर लिया था कि वास्तव में दो अस्थायी सरकार कायम हो गईं। एक भारत और दूसरी पाकिस्तान के लिए। इनमें से प्रत्येक सरकार अपने निजी मामलों से मतलब रखेगी और केवल दोनों देशों से सम्बन्धित प्रश्नों पर ही एक-दूसरे से सलाह लिया करेगी। इस योजना का लाभ यह हुआ कि लोगी-मन्त्रियों के त्यागपत्र देने का प्रश्न हल हो गया।

भारतीय स्वतन्त्रता-अविनियम पर शाही-स्वीकृति प्राप्त होने के करीब चौबीस घंटे बाद, गत शनिवार को प्रकाशित आज्ञा में कहा गया था कि गवर्नर-जनरल ने 'मन्त्रि-पदों के पुनर्वितरण' की मजबूरी दे दी। नेहरू और पटेल बड़ी मुश्किल से इस योजना पर राजी हुए। जहां तक जिन्ना का सवाल था, जब माउन्टबेटन ने यह योजना उनके सामने रखी तो उन्होंने फिर यही कहा कि वह उसपर विचार करेंगे। लेकिन माउन्टबेटन अब उनसे यह कह सकने की स्थिति में थे कि उनके विचारों और सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि माउन्टबेटन अपने बलबूते और जिम्मेदारी पर ही नई व्यवस्था को लागू करने की आज्ञा जारी कर रहे थे।

अपनी स्वाभाविक मौलिकता के साथ माउन्टबेटन न अपने कर्मचारियों, मंत्रियों और विभाजन की व्यवस्था से सबंध रखनेवाले अन्य अधिकारियों के सुभीते के लिए एक कैलेंडर तैयार किया, जिसमें दिन और महीना दिया हुआ था और हर दिन के नीचे लिखा था, "सत्ताहस्तांतरण तैयारी के लिए इतने दिन शेष है।" विभाजन-कौंसिल इस काम के महत्व को समझ गई थी और फुर्ती से काम कर रही थी। वह काम में पिछड़ी भी नहीं। इसका मुख्य कारण यह था कि सचालन-समिति ने उसको बहुत अच्छी तरह सारा काम समझा दिया था। एच. एम. पटेल और मुहम्मद अली प्रारम्भिक काम निबटाने में काफी मेहनत करते थे। इसका फल यह हुआ कि १५ जुलाई की बैठक में कम-से-कम सात ऐसे विषय पच्चीस मिनट से भी कम समय में निबटा दिये गए, जिनको माउन्टबेटन अत्यधिक पेचीदा और विवादग्रस्त समझ रहे थे। स्वयं विभाजन-कौंसिल की भी नियमित रूप से हफ्ते में तीन बैठकें होती थी।

आज शाम मैंने सवा सात बजे माउन्टबेटन से मुलाकात की ओर चूँकि मैं अपने अन्तिम पत्र के पहले ही यहाँ पहुँच गया था, इसलिए उन्हें विभिन्न सदेशों और अनुभवों से लाद दिया। माउन्टबेटन बहुत खुश थे और लदन के हमारे काम की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। जब वह रात के खाने के लिए कपड़े पहन रहे थे, तब भी मैं उनसे बातें करता रहा। मैंने उन्हें बतलाया कि उनके भविष्य के बारे में कैम्प-कसी बातें चल रही हैं। लदन में तो यह भी अफवाह है कि आपको वाशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत का पद दिया जायगा उन्होंने फिर कहा कि वह अखाड़े में नहीं है और उनका यही निश्चय स्थिर है कि ब्रिटिश सरकार को वह यह वादा पूरा करने के लिए कहेंगे कि उन्हें नौसेना में ही वापस भेज दिया जाय। इसका एक कारण यह भी था कि वह थक गए थे। फिर अचानक उन्होंने पूछा, "तुमने समाचारपत्रों में मुझे दिये जाने वाले पद के बारे में सबसे ताज़ी खबर देखी है? मामूली चीज़ नहीं, जर्मनी का सिंहासन दिया जा रहा है।"

अब माउन्टबेटन रियासतों की समस्या में आकण्ठ डूबे हुए हैं। जैसा उन्होंने ३ जून की योजना के पहले की कूटनीति में किया था, वैसे ही इस समय भी वह जान-

बूझ कर एक जोखिम उठा रहे हैं। रियासतों के संघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजाओं को समझाने का काम वह खुद ही कर रहे थे। इस बीच वी पी मेनन ने कांग्रेस को इस योजना पर राजी कर लिया है। अपने काम का आरम्भ उन्होंने पटेल के उस सशक्त सहयोग के आश्वासन के बल पर किया था, जो पटेल ने हमारे लदन जाने के दिन नये रियासती-विभाग का उद्घाटन करते समय अपने राजनैतिक पूर्ण भाषण में व्यक्त किया था। लेकिन सबसे कठिन सवाल तो हैदराबाद का था, जिस पर निश्चय ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। माउन्टबेटन का कहना था, कि जब जरूरत हो वह वहा जाने के लिए तैयार है। उनकी धारणा थी की कोई उचित समझौता करने का एकमात्र तरीका यही है कि निजाम से व्यक्तिगत रूप में मिला जाय।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, २४ जुलाई १९४७

मेरा अधिकांश दिन विभाजन-कौंसिल के उस महत्वपूर्ण वक्तव्य के प्रसार की व्यवस्था करने में बीता, जिसमें पंजाब के विभाजित क्षेत्रों में एक सीमा-फौज स्थापना का ऐलान किया गया था। यह विशेष फौज १४ में से उन १२ जिलों में रखी जायगी, जिन्हें कोई-न-कोई पक्ष विवादग्रस्त बतला रहा था। इसके सेनापति होंगे मेजर-जनरल 'पीट' रीस, जो इसके पहले तक चौथी भारतीय डिवीजन के कमांडर थे।

नई फौज का निर्माण भी असल में मुख्यतः इसी डिवीजन से किया जायगा। सब मिलाकर इस फौज में पचास हजार अफसर और सैनिक होंगे, जो ज्यादातर उन टुकड़ियों में लिये जायंगे, जिनका अभी तक विभाजन नहीं हुआ और जिनमें ब्रिटिश अफसरों का भारी अनुपात है। शांति-काल में न्याय और व्यवस्था की रक्षा के लिए इतनी बड़ी फौज का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। अज्ञात आकार-प्रकार के खतरो के खिलाफ की जानेवाली यह सबसे बड़ी भौतिक तैयारी थी। और इस तैयारी में यह सट्टा खेला गया था कि शेष सारे देश में साम्प्रदायिक शांति बनी रहे। रीस को दो उच्च अधिकार-संपन्न सैनिक-सलाहकार मिलेंगे। भारतीय-सेना का एक सिख और पाकिस्तान-सेना का एक मुसलमान। पन्द्रह अगस्त के बाद इन क्षेत्रों में मौजूद दोनों देशों की सेनाओं के संचालन का भार रीस के हाथों में रहेगा। सर्वोच्च सेनापति और संयुक्त विभाजन-कौंसिल द्वारा वह दोनों सरकारों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

नई दिल्ली, शुक्रवार, २५ जुलाई १९४७

आज राजाओं के साथ माउन्टबेटन की पहली और आखिरी मुलाकात हुई, क्योंकि वाइसराय और ताज के प्रतिनिधि के रूप में वह अब कभी राजाओं के

सम्मेलन में भाषण नहीं दे सकेंगे। यह दुआ-सलाम और विदाई का औपचारिक मौका नहीं था, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण राजनैतिक अवसर था। राजाओं में फूट थी और वे बड़ी दुविधा में थे। घटनाओं की तेजी ने उन्हें चकरा दिया था। उधर माउन्टबेटन के पास भी अपने मत-समर्थन के लिए लड़ने से कोई विस्तृत आदेश नहीं आ पाए थे। तीन जून और मन्त्रिमंडल-मिशन योजना दोनों में राजाओं के बारे में जो थोड़ा जिक्र था, उनसे यही नतीजा निकलता था कि सत्ता का असली हस्तांतरण तो ब्रिटेन और ब्रिटिश-भारत के बीच ही होगा।

कौमिल-हाउस में वाइसराय तथा राजा-महाराजाओं के स्वागत के लिए लाल कालीन बिछा दी गई। नरेन्द्रमंडल के अध्यक्ष, विशाल दाढ़ी वाले महाराजा पटियाला और उनके छ फुटे शरीर के पास बौने से लगने वाले बी पी मेनन माउन्टबेटन का स्वागत करने के लिए प्रवेश-द्वार पर खड़े हो गए। बी पी मेनन यहाँ प्रस्तावित रियासती-विभाग के मनोनीत मंत्री के रूप में उपस्थित थे। पटेल ने उन्हें माउन्टबेटन के हार्दिक अनुमोदन के साथ अपना बाया हाथ बनाना निश्चित किया था। उनका नया पद इस नई व्यवस्था में निश्चय ही अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

लगभग चालीस बड़े राजा और उनके प्रतिनिधि विशेष परिचय के लिए पास के कमरे में एकत्रित थे और करीब आधा दर्जन मान्यता प्राप्त फोटोग्राफर अच्छे जगहों पर अड़्डा जमाने के लिए उनके बीच बेनकल्लुफी से डबल-उधर भाग रहे थे। वेहद उमस थी और नवानगर के स्थूलकाय जामसाहब कमरे के एकमात्र पखे के नीचे हवा लेते हुए शिकायत कर रहे थे कि यह पखा कितने धीरे-धीरे घूम रहा है। सब मिलाकर पच्चीस बड़े राजा और चौहत्तर रियासती प्रतिनिधि नरेन्द्र-मंडल के आदित्य-चन्द्राकार भवन में उपस्थित थे।

जब माउन्टबेटन इस गौरवशाली समुदाय के सामने भाषण देने के लिए खड़े हुए तो इस ऐतिहासिक सभा का चित्र लेने के लिए कुछ समय दिया गया। अपने चारों ओर फ्लेश बत्तों की चमक के समय माउन्टबेटन धीरज के साथ स्थिर रहे। इस मौके पर कुछ फोटोग्राफर उत्साह की सीमा पार गए और उनकी भागदौड़ से ऐसा लगता था कि मानो किसी मजाकिया फिल्म का दृश्य खींचा जा रहा हो। चूँकि भाषण विलकुल गोपनीय था, इसलिए फोटोग्राफरों के जाने के पहले माउन्टबेटन उसे शुरू भी नहीं कर सकते थे। फलतः, विवश होकर मुझे मंच के नीचे मेनन के पास से उठकर उनको बाहर खदेड़ना पड़ा।

माउन्टबेटन पूरी पोशाक में थे। इतने तमगे और पुरस्कार सीने पर लगे थे कि राजसी ठाठ के अभ्यस्त राजे भी चकित रह गए। आज भी वह किसी प्रकार के लेखे हुए संकेत देखे बिना बोले और एक जगह भी अटके या भटके नहीं।

अपने तरकस के सारे तीरों का उपयोग उन्होंने यही समझाने और स्पष्ट

करने में किया कि वी पी मेनन ने जो संघ-प्रवेश-पत्र तैयार किया था वह कांग्रेस की ओर से दिया जाने वाला ऐसा राजनैतिक मौका है, जो फिर दोहराया नहीं जायगा। दरअसल तो यह अभी पक्का रुक्का नहीं है, और इसके पक्के होने की संभावना इसी बात पर निर्भर करती है कि वे इसकी सामूहिक स्वीकृति पटेल तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। उन्होंने राजाओं को याद दिलाया कि पन्द्रह अगस्त के बाद वह ताज के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से मध्यस्थता नहीं कर सकेंगे। जो राजा अपने हथियारों के जखीरे बढ़ाने की सोच रहे थे, उनको उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनको मिलनेवाले हथियार पुराने और बेकार होंगे। उन्होंने एक बात ऐसे मौके की और ऐसे बल के साथ कही कि राजाओं पर उसका वार खाली नहीं गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने संघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये तो उन्हें विश्वास

कि औपनिवेशिक स्वराज्य के अन्तर्गत भी पटेल और कांग्रेस ब्रिटेन से उन्हें खिताब और सम्मान मिलने पर रोक नहीं लगावेंगे। माउन्टबेटन जानते थे कि राजतंत्र के समर्थक होने के कारण उनके लिए इन खिताबों का कितना मूल्य है। इस सबब में राजाओं से बात करने में उन्हें एक बड़ा सहारा यह रहा था कि वह ताज के प्रतिनिधि की हैसियत से ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बादशाह के चचेरे भाई की हैसियत से भी बोल सके थे। इन पुश्तैनी राजाओं के लिए शाही खून का बड़ा मान है। उनके आज के सदेश का सार यह था, “जिस प्रकार आप उस प्रजा से जान बचा कर नहीं भाग सकते, जिसके कल्याण का दायित्व आपके ऊपर है, उसी प्रकार आप अपनी पड़ोसी औपनिवेशिक सरकार से भी नहीं भाग सकते।”

लेकिन, मंरे लिए, इससे अधिक उलझन वाली सभा की कल्पना करना असंभव था, कि जिसमें माउन्टबेटन ने भाग लिया। यह सभा तो ऐसे पुश्तैनी गडरियों की थी, जो अपनी भेड़ों को खोकर बड़ी दयनीय स्थिति में पड़ गए थे। आज फिर मनोबल बढ़ाने की अपनी क्षमता का माउन्टबेटन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अपनी स्वाभाविक स्फूर्ति और फैसले लेने की शक्ति का उन्होंने न जाने कैसे राजाओं में भी संचार कर दिया। जैसे ही माउन्टबेटन ने उनके पूछे आड़े-टेढ़े प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, गंभीर रूप में प्रारम्भ हुई इस सभा में हसी-मजाक का रूप धारण कर लिया।

इस नाजुक घड़ी में अपने राज्य और देश दोनों से ही अनुपस्थित एक महाराजा ने न तो स्वयं इस बैठक में आने की जरूरत समझी और न अपने दीवान को कोई ही आदेश देने की। दीवान को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। माउन्टबेटन ने उनसे पूछा, “निश्चय ही आप अपने राजा के मन की बातों से तो परिचित ही हैं और उनकी ओर से फैसला कर सकते हैं?” बेचारे दीवान ने कहा, “मैं अपने राजा के मन की बात नहीं जानता और समुद्री तार से उत्तर भी नहीं मगवा सकता।” यह सुनकर माउन्टबेटन ने अपने सामने रखा हुआ गीशे का बड़ा-सा गोल पेपरवेट अपने



हाथ में उठाते हुए कहा, “इस काच में देखकर मैं आपको ठीक उत्तर बता देता हूँ।” फिर थोड़ी देर के नाटकीय मौन के बाद उन्होंने गभीरता से कहा, “आपके महाराजा आपको सध-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह रहे हैं।”

इस विशिष्ट-समुदाय की भावनाएँ उन्होंने इतनी अच्छी तरह भाप ली थी कि इस विनोद पर सब लोग ठहाका मार कर हसे। उनका विनोद सचमुच सौजन्य-पूर्ण झिड़की भी था, और समयोचित सलाह भी। ऐसा लगता था कि उपस्थित समुदाय के दिमाग की अभेद्य दीवारों को वेदने के लिए विनोद का प्रयोग करना ही उचित था।

वाइसराय-भवन लौट कर मैंने माउन्टवेटन को बतलाया कि उनके आज के काम की सभी पर गहरी छाप पड़ी है। मैंने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमें पत्रों के लिए पूरे गोपनीय भाषण का काफी कटा-छटा रूप ही तैयार करना पड़ेगा, जिसे मैं वी पी मेनन के साथ बैठकर तैयार किये लेता हूँ। माउन्टवेटन ने कहा कि मेनन और हम जो मसविदा तैयार करेंगे वह उन्हें स्वीकार होगा। वह उसे दुबारा नहीं देखना चाहेगा। उनका विचार था कि आज उनसे जो प्रश्न पूछे गए थे इनके पीछे कोई वास्तविकता नहीं थी। बहुत कम राजाओं अथवा उनके प्रतिनिधियों को दुनिया की घटनाओं का कोई ज्ञान था। अगर वे सध-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो वे खत्म हो जायेंगे।

फिर, उन्होंने वी पी मेनन की तारीफ करते हुए कहा कि वह सचमुच ही मेनन को चाहने लगे हैं और मेनन के समान राजनीति-कुशल बुद्धिवाले व्यक्ति उन्हें न कम देखें हैं।

इस मौके को माउन्टवेटन अपनी एक और व्यक्तिगत विजय मान सकते हैं। नेतृत्वहीन और कलहग्रस्त राजाओं ने अवसरवादिता और निर्णय-हीनता के पर्दे के पीछे मुह छिपाने की हरचन्द कोशिश की, लेकिन घटनाओं का प्रवाह इतना व्यापक और इतना तीव्र था कि रुकावट की उनकी चाले नहीं चल पाईं। पहले की नीतियों के गुण-दोष चाहे जो रहे हों, लेकिन ताज के अंतिम प्रतिनिधि के रूप में आज माउन्टवेटन को जिस परिस्थिति से साबिका पड़ा था, वह ऐसी थी कि केवल किसी प्रकार की मध्यस्थता के द्वारा ही इस असामयिक सामन्तवाद से पिड छुड़ाया जा सकता था।

नई दिल्ली, शनिवार, २६ जुलाई १९४७

कल रात माउन्टवेटन-दम्पति ने जिन्ना परिवार को जो दावत दी थी, उसके बारे में जार्ज एवल के साथ मेरी एक मनोरंजक बात हुई। दावत बिल्कुल अनौपचारिक थी और वाइसराय भवन के मेहमानों और कर्मचारी-मंडल के सदस्यों के अलावा कोई बाहरी लोग नहीं थे। खूब लम्बे और अधिकांश विनोदहीन मजाक

करके जिन्ना बातचीत पर एकाधिकार जमा बैठे। जब माउन्टबेटन ने जिन्ना को लेडी माउन्टबेटन से बात करने के लिए छोड़कर अपने पास बैठे मेहमानों से बात करके चर्चा को सतुलित करने का प्रयास किया तो जिन्ना सहसा रुके और फिर मेज के उस ओर से चिल्लाकर बोले, “मेरा खयाल है, माउन्टबेटन इस मजाक को सुनना चाहेंगे।” प्रथा के अनुसार राजा का प्रतिनिधित्व करने वाला वाइसराय भोजन करने के कमरे में आने और जाने में सबसे आगे रहता है। लेकिन इस दावत के खत्म होते ही जिन्ना भी माउन्टबेटन के साथ उठ खड़े हुए और उन्हीं के साथ-साथ बाहर गए।

जार्ज ने बतलाया कि दावत के बाद उन्होंने इस भावना से कि मैं तो पन्द्रह अगस्त को जा ही रहा हूँ, जिन्ना को सिखों के प्रश्न पर खूब आड़े हाथों लिया। जार्ज ने कहा कि पश्चिमी-पंजाब की सीमा के पास वाले इलाकों में निहायत अयोग्य आदिमी नियुक्त किये जा रहे हैं। जिन्ना ने बुरा नहीं माना और इतना ही कहा कि अपने लोगों की वह नस-नस पहचानते हैं। वह जरा तैश में आ गए जब जार्ज ने कहा कि असली दिक्कत यह है कि जिन्ना की योग्यता के लोग एक साथ सब जगह तो मौजूद हो नहीं सकते और इसमें कोई शक नहीं कि जिन्ना उन लोगों को देखने नहीं गये हैं कि जिनकी आलोचना की जा रही है। जार्ज का खयाल था कि सिखों के बारे में जिन्ना का रुख निहायत खतरनाक है।

नई दिल्ली, रविवार, २७ जुलाई १९४७

आज फिर माउन्टबेटन ने मुझे मिलने बुलाया। उन्होंने मुझे एक घटना का हाल सुनाया जो आज तो विचित्रसी लगती है, पर उस समय गंभीर शकल भी ले सकती थी। उन्होंने लार्ड किल्लर्न को सिगापुर से बुलवाया था और उनके साथ इस सभावना पर विचार-विमर्श कर रहे थे कि क्या वह पूर्वी-बंगाल का गवर्नर-पद सभाल सकेंगे? यह इसलिए, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान की इस चौकी को कोई ऊँची योग्यता वाला ब्रिटिश-शासक सभाले। जब वह नौकरी की शर्तों पर विचार कर रहे थे तब लार्ड किल्लर्न ने पूछा कि क्या दार्जिलिंग के पाकिस्तान में शामिल होने की कोई सभावना है? अगर यह नहीं, तो क्या यह व्यवस्था करना मुमकिन होगा कि बहुत गरम मौसम को वह आसाम के किसी पहाड़ी मुकाम, जैसे शिलांग, में बिता सके? उन्होंने कहा कि अब वह छियासठ वर्ष के हो आए हैं, उनके कई छोटे-छोटे बच्चे हैं और वह पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका की गरमी वर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें जानकारी मिली है कि ढाका में गवर्नर का प्रस्तावित-निवास बहुत ही खस्ता हालत में है। माउन्टबेटन ने इस विषय में पता लगाने का वादा किया।

सयोगवश इसके बाद ही उनकी मुलाकात हुई आसाम के प्रधान-मंत्री वार्दोलोई से। आसाम के बारे में कुछ मामूली कामों को चन्द मिनटों में निबटाने के बाद उन्होंने वार्दोलोई से ढाका के बारे में पूछा। क्या वहाँ कोई पहाड़ी जगह है? वार्दोलोई ने कहा कि पूरे इलाके में ग्यारह सौ फुट से ऊँची कोई जगह नहीं है। फिर माउन्टबेटन ने दार्जिलिंग के बारे में पूछा। सीमा-आयोग द्वारा उसके किनारे दिये जाने की संभावना है, पाकिस्तान को या भारत को? वार्दोलोई ने कहा कि उसका भारत में रहना निश्चित है। इसके बाद माउन्टबेटन ने शिलांग और आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी पूछताछ की।

वार्दोलोई इस पूछताछ के उद्देश्य को बिल्कुल गलत समझ बैठे और बड़ी घबराई हुई हालत में गांधीजी के पास पहुँचे। शिकायत की कि दार्जिलिंग, शिलांग और पहाड़ी क्षेत्रों को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए भयंकर पड़्यत्र रचा जा रहा है। गांधीजी ने कहा कि इसमें शक नहीं कि अंग्रेज ऐसी धोखाधड़ी करने की सामर्थ्य रखते हैं लेकिन वह यह विश्वास नहीं कर सकते कि माउन्टबेटन ऐसे किसी काम में हाथ बटाएंगे। इसके बाद वार्दोलोई पटेल के पास गये और पटेल इस प्रश्न को लेकर काफी फिक्र में पड़ गए। फलस्वरूप, आज सवेरे वी पी मेनन परेशान-से माउन्टबेटन के सोने के कमरे में आये।

माउन्टबेटन को पूरी बात का खुलासा करते देर नहीं लगी। उन्हें उम्मीद थी कि एकाध दिन में इस प्रश्न पर वह कांग्रेसी नेताओं से हसी-मजाक भी कर सकेंगे। लेकिन वह इस घटना को बड़ा उद्बोधक भी मानते थे, क्योंकि यह मामूली-सी गलतफहमी बड़े भारी सकट का रूप भी ले सकती थी।

नई दिल्ली, सोमवार, २८ जुलाई १९४७

आज रात लगभग पचास से ऊपर राजाओं और करीब सौ रियासती प्रतिनिधियों के सम्मान में वाइसराय भवन में एक शानदार समारोह हुआ। समारोह का ठाटवाट उस अयथार्थता और वेदना को ही बल देने वाला था, जो आज राजाओं को घेरे हुए थी। आज जब कि उद्देश्य की एकता का सवाल उनके लिए सबसे अधिक महत्व का होना चाहिए था, वे वैचैनी के साथ इन समस्याओं में डूबे हुए थे कि कौन किससे बड़ा है? हर एक का ध्यान इसी ओर था कि दूसरा क्या कर रहा है, और जैसा कि एक दीवान ने कहा, “वह वैरग लिफाफे के समान भटक रहे थे।”

जिन श्रीमन्तों ने अभी तक मध-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जाहिर नहीं की थी, उनको एक-एक कर ए डी सी मित्रतापूर्ण बातचीत के लिए माउन्टबेटन के पास ले जाने लगे। माउन्टबेटन उनको सबके सामने वी पी मेनन के हवाले

कर देते और मेनन उन्हें पटेल के पास पहुंचा आते। तीन-तीन की कतार में अर्द्ध-चन्द्राकार खड़े हुए राजालोग यह कार्यवाही देख रहे थे।

एक खुरीट राजा ने टिप्पणी की, “माउन्टवेदन अब किस पर डोरे डाल रहे हैं ?” गर्दन आगे बढ़ा कर देखने का प्रयास करते हुए उन्होंने बड़े मजे से कहा, “उन्हें मेरे ऊपर डोरे डालने की जरूरत नहीं। मैं कल हस्ताक्षर कर रहा हूँ।” फेने एक बूढ़े और एक तरुण राजा के बीच यह बातचीत होते सुनी बूढ़े राजा ने पूछा, “आपकी रियासत में कैसी स्थिति है ?” तरुण राजा ने उत्तर दिया, “हमारे यहाँ एक जगह (जगह का नाम बतलाया) स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब समझौता हो गया है।” इस पर बूढ़े राजा ने कहा, “हमारे यहाँ हर जगह स्थिति खराब है, लेकिन मैं उसे समझौते की सीमा तक नहीं पहुँचने देता।”

नई दिल्ली, बुधवार, ३० जुलाई १९४७

पौ फटते ही माउन्टवेदन कलकत्ता के लिए रवाना हो गए, जहाँ की गंभीर स्थिति का वह तत्काल परीक्षण करेंगे। बड़ी रात गये फोन पर उन्होंने मुझसे पत्रों सबकी कुछ मामूली समस्याओं को सुलझाने के लिए कहा, मानो सत्ता-हस्तांतरण का काम उन्हींके सुलझाये जाने पर निर्भर करता हो। बड़ी बातों पर वह कभी दुरायह नहीं करते, उन्हें परेशानी करती थी छोटी बातें, जो कर्मचारियों का नाको दम कर डालती थी, अगर उनका काम करना हो और उनके दिल का सदस्य बने रहना हो तो उन्हें इन छोटी समस्याओं से दूर रखना ही श्रेयस्कर था। लेकिन जब आपका ध्यान दूसरी ओर हो तो वह एकाध ऐसी समस्या कहीं-न-कहीं से पकड़ ही लाते थे।

उनकी गैरहाजिरी से मिले इम छोटे से विश्राम का उपयोग मैंने गांधीजी से भेंट करने में किया। इसके लिए मैंने बहुत दिनों से वादा किया हुआ था। उनसे मिलने में दोपहर को भगी वस्ती पहुँच गया। गत मई में, जब मैं शिमला में राजकुमारी अमृतकौर से मिला था, तबसे वह यह मुलाकात जमाने की कोशिश करती आ रही थी।

दिल्ली में अपने रहने के लिए भगी वस्ती का चुनाव करना वास्तव में गांधीजी का एक बड़ा सकेतात्मक काम है। लेकिन वैरागीपन की भी अपनी प्रशासनिक समस्याएँ होती ही हैं। मेरा खयाल है, शायद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने एक बार भगी वस्ती के बारे में कहा था, “काश, बापू जानते कि उन्हें गरीबी में रखना कितना खर्चीला होता है।” उनके ईर्ष-गिर्द यहाँ जो गरीबी है, वित्कुल वास्तविक है। वस्ती उस तजर भूमि पर स्थित है जो दिल्ली को घेरे हुए है, और उसकी पृष्ठ-भूमि कठोर चट्टानों और भूरी मिट्टी से अटी हुई है।

दो काफी भट्टे पहरेदारों ने मुझे मेरा नाम-पता पूछा और मुझे एक सेक्रेटरी के पास पहुँचा दिया। इन सज्जन ने जो निर्देश दिये उनसे कुछ पता ही नहीं चलता था कि मुझे किधर जाना चाहिए। इतने में एक दूसरे सेक्रेटरी दिखलाई पड़े और वह मुझे एक खाली कमरे में ले गए। मुझे बाद में बताया गया कि गांधीजी वहाँ सोते और काम करते हैं। मैंने उन्हें चबूतरे पर तकियों के सहारे बैठे हुए पाया। हमारी मुलाकात के बीच दो सेक्रेटरी चुपचाप अन्दर आये और चतुर अनुयायियों की भाँति अपना काम करने लगे।

जैसे ही मैं अन्दर दाखिल हुआ, गांधीजी ने हसते हुए कहा, “आप मुझसे खड़े होने की आशा तो नहीं करेंगे?” मुझे बैठने के लिए कुर्सी दी गई। लेकिन मैंने उनके सामने पालथी मारकर बैठना पसन्द किया। मैंने उन्हें याद दिलाई, “आपसे पहली बार मिलने का सौभाग्य मुझे आज से सत्रह वर्ष पूर्व हुआ था, जब मैं बालक था और वेस्टमिन्स्टर स्कूल में पढ़ता था। आप अचानक हमारे सामने भाषण देने आये थे और हम सब पर इस घटना की गहरी छाप पड़ी थी।” उन्होंने कहा कि यह घटना उन्हें थोड़ी-थोड़ी याद है—शायद किसी भले ईसाई पादरी ने उन्हें वहाँ आमंत्रित किया था। मैंने बतलाया कि उनके आने के दो दिन बाद लार्ड हैलीफेक्स भी हमारे सामने भाषण देने आये थे। गांधी-इर्विन समझौते के उस साल की सबसे याद रहने-वाली बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में कितने सौहार्द से बात की थी। दोनों ने हमारे शिशु-हृदयों पर यह छाप छोड़ी थी कि यह मानवता-भरी सद्भावना ही सच्चे समझौते को जन्म दे सकती है।” उन दिनों मैं लार्ड हैलीफेक्स के बहुत निकट था”, गांधीजी ने बीते दिनों की याद करते हुए कहा, “लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज नजदीक नहीं हूँ।”

मैंने कहा कि मैं अभी-अभी लन्दन से लौटा हूँ, जहाँ मैंने भारतीय स्वतंत्रता-अधिनियम को मसद् के दोनों सदनों से गुजरते हुए देखा था। इस विषय में हुई बहस की रिपोर्ट की तीन प्रतियाँ भी मैंने उन्हें भेंट की, जिससे उन्हें खुशी हुई। लार्ड-सभा में लार्ड सेम्पुअल ने उनकी जो प्रशंसा की थी, उसकी ओर मैंने उनका विशेष ध्यान खींचा। कहा कि यह उन्होंने देख लिया था और यह लार्ड सेम्पुअल की कृपा है कि उन्होंने ऐसे शब्द कहे। एक बार उनका लार्ड सेम्पुअल के साथ किसी विषय पर पत्र-व्यवहार हुआ था और उसमें चले तर्क में लार्ड सेम्पुअल ने अपनी गलती मानने की उदारता दिखलाई थी। गांधीजीने कहा कि यह व्यक्ति के बड़प्पन का लक्षण होता है।

स्वतन्त्रता-अधिनियम से पैदा हुई आम स्थिति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश-सत्ता के समाप्त होने से कांग्रेसी नेताओं के कंधों पर भारी उत्तरदायित्व आ पड़ा है। अवर्तक तो ये लोग केवल चंद लाखों रुपयों से ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब राज्य के विशाल साधन उनके हाथों में आ गए हैं। दोनों

सरकारों को समय की जरूरत है—सास लेने के मौके की, जिसमें वे अपने पाये मजबूत बना सकें। वह विभाजन को एक बुराई समझते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार थे कि अगर दोनों सरकारें एक-दूसरे के साथ न्याय का व्यवहार करें तो इस अशुभ सेशुभ परिणाम भी निकल सकता है। मैंने कहा कि भारत ही नहीं, समूचे एशिया का भाग्य दाव पर है। खास तौर से दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश भारत को ओर आखे लगाये हैं और चीन के गृह-युद्ध ने भारत के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने हार्दिक स्वीकृति जतलाते हुए कहा, “मारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। भारत कसीटी पर है।”

फिर यहाँ के अपने खास काम—समाचारपत्रों—की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि भारतीय पत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भारतीय पत्रकारों को विदेश जाकर नये अनुभव प्राप्त करने चाहिए। उन्होंने मजर किया कि इसकी जरूरत है, लेकिन इस मान्यता ने उन्हें अपने प्रिय विषय पर पहुँचा दिया। उन्होंने कहा, “भारतीयों में अपने निराकारण के लिए दूसरों का मुँह ताकने की खतरनाक प्रवृत्ति है। अपने आत्म-सम्मान की रक्षा कर हमें स्वयं अपनी मदद करनी चाहिए। दवाओं और डाक्टरों की ही बात लीजिये। मैं एक भी ऐसे अंग्रेज की बात नहीं जानता जो इलाज के लिए भारत आया हो। लेकिन इस या उस प्रसिद्ध यूरोपीय सर्जन ने इलाज करवाने के लिए भारतीयों के विदेश जाने की बात हम बराबर सुनते रहते हैं। यह ठीक नहीं है कि भारत को भारतीयों के मरने की ही जगह माना जाय। हमारे यहाँ काफी योग्य मर्जन हैं, जैसे डाक्टर अमारी ये।”

उनके तर्कों का सार यह था चूँकि भारत ने अब अपनी राजनैतिक स्वाधीनता पाली है, इसलिए भारतीयों का कर्तव्य यह है कि शब्दों नहीं, कर्मों के द्वारा देश के प्रति अपने विश्वास और गर्व का परिचय दें। वह यह समझे कि जो-मुविद्या के माध्यम उन्हें विरागत में मिले हैं वे वाहने दुनिया की चीज हैं और हमारे लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं हैं। भारतीय स्वाधीनता की यह असली चुनौती है।

प्रदर्शित करने के बाद वे राजा-लोग वाइसराय के ए डी सी लोगों के पजे में फस गए, जिन्होंने सघ-प्रवेश-पत्र के बारे में उनके मत के अनुसार उन्हें “हाँ” और “नहीं” की कतारों में खड़ा कर दिया। पटियाला और बीकानेर ‘नहीं’ की कतार में खड़े हो गए और खूब हँसे। इससे विनोद का वातावरण और भी गाढ़ा हो गया।

हैदराबाद और काश्मीर को छोड़ कर, जिनकी विशेष समस्याएँ हैं, अन्य सब पर माउन्टबेटन की सलाह का असर हुआ। केवल दो या तीन ही बड़े नरेश यह समझते हैं कि सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर न करने से लाभ होगा। दुर्भाग्यवश माउन्टबेटन के मित्र, भोपाल-नरेश, इस दल के अगुआ हैं, और उसमें भोपाल के निकट और महत्वपूर्ण पड़ोसी महाराज इन्दौर भी शामिल हैं। सबसे योग्य मुसलमान नरेश होने के नाते मैं खयाल करता हूँ कि वह पाकिस्तान की उच्च-स्तर की राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लेने में सक्षम नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक वह जिन्ना के निकटतम सलाहकार भी रहे थे। उनके लिए अभाग्य की बात यह है कि उनकी रियासत की अधिकांश आबादी हिन्दू है और वह भारत के मध्य में स्थित है।

नई दिल्ली, रविवार, ३ अगस्त १९४७

माउन्टबेटन उन नरेशों से मुलाकात करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जिनके सामने सघ-प्रवेश का प्रश्न विशेष समस्याएँ पैदा कर रहा है। लेकिन जैसे-जैसे अन्तिम घड़ी नजदीक आ रही है, जिम्मेदारियाँ और फैसले लेने का काम बढ़ता जा रहा है। इसलिए धौलपुर के महाराज राणा से व्यक्तिगत और गैर-सरकारी रूप से सम्पर्क स्थापित करने का काम उन्होंने मुझे सौंप दिया। महाराज राणा ब्रिटन के युवराज की १९२१ में भारत-यात्रा के समय से उनके मित्र हैं। उस समय दोनों युवराज के ए डी सी. थे।

उनके साथ अपनी लम्बी बातचीत के आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि वह बड़े विद्वान्-रागी, पाण्डित्यपूर्ण और साधु-वृत्ति के व्यक्ति हैं। राजाओं के दलील-अधिकारों में उनका गहरा विश्वास है। ब्रिटिशराज के साथ अपने दर्जे और अपनी जनता के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में उनकी धारणाएँ बड़ी ही रहस्यमयी हैं। अपने विशेषाधिकारों के बारे में वे हृदय ऊँचे खयालों के बावजूद अपने व्यवहार और पहरावे में वह बहुत सरल हैं। वह काफी ठिगने व्यक्ति हैं, गांधीजी से ज्यादा ऊँचे नहीं। वह गुलाबी साफा बांधे थे और बहुत चिंतित नजर आते थे।

ब्रिटन के साथ अपनी सन्धि के समाप्त होने के बारे में उन्होंने बड़ी भावुकता के साथ धीमे-धीमे चर्चा की। उनकी आवाज में नाराजी नहीं, आत्म-समर्पण था। भाग्यवादियों में पाई जानेवाली खिन्नता उनमें भरी हुई थी। ऐसे व्यक्ति के साथ यह तर्क काफी नहीं कि उसका हित कैसे सध सकता है। मूलतः वह यह सहानुभूति

और आश्वासन चाहते थे कि वह जो कुछ करेगा, उसे उचित माना जायगा। अपने दिल में उनको जरा भी उम्मीद नहीं थी कि नया भारतीय-उपनिवेश जिन्दा रह सकेगा। थोड़े ही दिन पूर्व की क्रान्तिकारी स्थितियों में ब्रिटेन के साथ १७६५ में हुई सार्वभौमिकता की सन्धि की वह अपने शासन काल की लम्बी और स्वामिभक्ति-पूर्ण परम्पराओं के साथ तुलना करते थे। ऐसे भावुक और ईमानदार व्यक्ति को ऐसी दुविधा में पड़े देखकर बड़ी वेदना होती थी। स्वाधीनता का तूफान इस तेजी से चल रहा था कि वह कुछ भी समझने में असमर्थ थे। अगर उनकी चेतना इतनी प्रबल न होती तो शायद वह एक तरफ हट जाना पसन्द करते।

जैसे-जैसे सत्ता-हस्तांतरण का दिन नजदीक आ रहा था, माउन्टबेटन और उनके अमले पर पड़नेवाले काम का बोझ बढ़ रहा था। मेरे ऊपर जन-सम्पर्क और पत्रों सम्बन्धी समस्याओं का इनका काम आ पड़ा था कि पूरा केन्द्रीय सूचना-कार्यालय उसे निबटाने में व्यस्त रहता था। कराची और दिल्ली में होने वाले समारोहों की बड़े मोच-विचार के साथ योजना तैयार की जा रही थी। जिन्ना ने एक बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया था। कराची में १३ अगस्त के समारोहों के अवसर पर माउन्टबेटन को क्या प्राथमिकता दी जाय ? काफ़ी दृढ़ता के साथ पर बड़े सरल जवाब में उन्हें बतला दिया गया था कि माउन्टबेटन इस समारोह में वाइसराय के नाते भाग लेंगे। और उनसे यह भी कह दिया गया था कि यह मुआव बिलकुल निरर्थक होगा कि विधान-सभा की विधेय वैश्व में वह जिन्ना के नीचे बैठे।

मेरी जिम्मेदारियों में ये काम भी शामिल हैं दोनों उपनिवेशों को भेजे जाने के लिए ब्रिटेन के राजा के सन्देशों का मसविदा तैयार करना। दोनों देशों की विधान-सभाओं को दिये जानेवाले माउन्टबेटन के भाषणों को ठीक-ठाक कर देना।

नई दिल्ली मंगलवार, ५ अगस्त, १९४७



पटेल इस कार्रवाई के विलकुल खिलाफ थे। उनका तर्क था कि इससे वह स्थिति और भी भयंकर रूप ले लेगी, जो आज भी हमारे नियंत्रण के बाहर है।

माउन्टबेटन ने कहा कि एक शर्त पर वह इन गिरफ्तारियों का समर्थन करने को तैयार है। स्थानीय अधिकारी इसे ठीक समझे तो। इसलिए माउन्टबेटन ने जनकिन्स को लिख भेजा कि पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के मनोनीत गवर्नरों, त्रिवेदी और मूडी, से चर्चा करे कि १५ अगस्त के पहले तारासिंह और उनके अन्य सिरफिरे साथियों को गिरफ्तार करना ठीक होगा या नहीं।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, ७ अगस्त १९४७

हमारे जीवन में विनोद के क्षण भी आते हैं। वाइसराय के कर्मचारी मडल की अडसठवीं बैठक का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ पहला विषय ज्योतिष। वाइसराय ने कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश के मनोनीत राज्यपाल श्री मंगलदास पकवासा को यह सुझाया था कि आप १४ अगस्त की वजाय १३ अगस्त को ही अपना कार्यभार सभाल लें, जिससे सर फ्रेडरिक वॉर्न पूर्वी-बंगाल के राज्यपाल का पद १५ अगस्त को सभाल सके। पकवासा ने कहा कि ज्योतिष के अनुसार यह संभव नहीं हो सकता। वाइसराय ने कहा कि मेरे कर्मचारियों में ज्योतिष-विषयक सलाह देने वालों का अभाव है। इसका इलाज तुरन्त ही यह घोषणा करके किया गया, “वाइसराय महोदय ने गवर्नर-जनरल के अवैतनिक ज्योतिषी-पद के लिए अपने ‘प्रेस एटेंची’ की नियुक्ति की।”

इसके बाद मैं पकवासा से मिला। पटेल ने उन्हें एक दावत दी थी और उसमें मैं और फे भी निमंत्रित थे। यह अवसर अनौपचारिक था। पकवासा और हम दोनों के अतिरिक्त केवल एक अतिथि और थे—मि डल नाम के एक अमरीकी सज्जन। पटेल के निजी सेक्रेटरी शंकर, जो आक्सफोर्ड में मेरे सहपाठी थे, तथा सरदार की पुत्री और अनन्य सेविका मणिबेन को मिला कर हम लोग कुल सात व्यक्ति थे। पटेल का घर नेहरू के घर के विलकुल पड़ोस में है तथा शान-शीत और लम्बाई-चौड़ाई में उसमें बहुत कम है।

सत्ता-हस्तान्तरण के बाद नेहरू और पटेल भारत की बागडोर सभालेंगे, और दोनों में अन्तर बतलाना स्वाभाविक बात है। दोनों की व्यक्तिगत और बाहरी आकृति में भी कम अन्तर नहीं है। धोती में सज्जित पटेल चोगा पहने हुए रोमन-सम्राट् का स्मरण कराते हैं। सच पूछिए तो इस पुरुष में काफी रोमन विशेषताएँ हैं—प्रशासनिक योग्यता, कठोर निर्णय करने और निभाने की क्षमता तथा चरित्र-बल के साथ, पाई जाने वाली सीम्यता। पर नेहरू के समान विश्व-ख्याति और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उनमें अभाव है। उन्होंने जान-बूझकर अपने-

आपको आन्तरिक राजनीति की समस्याओं तक ही सीमित रखा है। इस क्षेत्र में उनकी शक्ति और जिम्मेदारियाँ काफी व्यापक हैं। इनके अन्तर्गत सरकारी सूचना-विभाग, आन्तरिक सुरक्षा, पुलिस तथा भारतीय रियासती मामले शामिल हैं। जब उनकी सघ-प्रवेश-संबंधी नीति पर पूरा अमल हो जायगा तो पाकिस्तान बनने से भारत को जितने नागरिकों की हानि होगी, उससे कहीं अधिक नागरिक उसमें शामिल हो जायेंगे, क्योंकि इससे हैदराबाद और काश्मीर की दो करोड़ जनसंख्या के अतिरिक्त ९ करोड़ रियासती जनता भारत में मिल जायगी, जो पाकिस्तान की आवादी से कहीं अधिक है। पटेल के हाथ में ही कांग्रेस की सारी बागडोर है। किसी भी देश में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का इतना केन्द्रीकरण होना मामूली बात नहीं है। इस व्यस्तता के बावजूद पटेल ससार में भारत की स्थिति को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।

जब पटेल राज-काज के मामलों में नहीं लगे रहते तब वह एक विनम्र हिन्दू का आदर्श रूप उपस्थित करते हैं। औदार्य और स्मित के तो वह भंडार हैं। मैंने भारतीय-स्वतन्त्रता-अधिनियम के लदन में पास होने का हाल उन्हें बताया, जिसे उन्होंने दिलचस्पी से सुना। बातचीत के दौरान में भाषण देने की बात भी उठी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको भाषण देना अच्छा लगता है, तब वह और मणिबेन हम पड़े। मणिबेन ने मुझे बताया कि उनके पिता गुजराती के एक महान् वक्ता हैं।

भोजन के अवकाश समय मणिबेन मौन रही। वह सरदार की सभी गोपनीय एवं सरकारी हलचलों में उनकी विश्वास-पात्र हैं। तपस्विनी की भाँति खादी की साड़ी पहने हुए तथा कमर में चावियों का गुच्छा खोसे, वह सरदार की गृहस्थी की सुयोग्य एवं दत्तचित्त सचालिका जान पड़ती हैं।

प्रायः सभी भारतीय नेता अपने परिवार की महिलाओं में घिरे रहते हैं—चाहे वे पत्नी हों या पुत्री या बहन। नेताओं के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव है। मैं यह ख्याल लेकर भारत आया था कि भारतीय स्त्रियाँ बाहर नहीं आती और राजकीय मामलों में उनकी कोई आवाज या अभिरुचि नहीं है। किन्तु ऊँचे वर्गों में यह बान नहीं है। मिन फातिमा जिन्ना, श्रीमती विजयालक्ष्मी पटेल, वेगम लियावतजलीया और श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली स्त्रियाँ हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएँ और रुचियाँ अपने संबंधित पुरुषों में कुछ कम नहीं। उनमें ने नहीं मणिबेन की तरह पृष्ठभूमि में रहना पसन्द नहीं करेंगी, किन्तु अपने पिता पर जितना उनका अनुर है नायदही उनका किसी और का अपने घरो में हो।

लेडी गाउन्टवेटन समाज-सेवा के क्षेत्र में भारतीय स्त्रियों के सम्पर्क में आकर बड़ी प्रभावित हुई हैं। इन क्षेत्र में उनकी योग्यता ही बड़ी-चटी नहीं है प्रत्युत वे अपने बन्धनों को भी तोंड रही हैं। भारतीय महिलाओं की मूल्य भारतीय

स्वाधीनता-संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समय लेडी माउन्टबेटन के नेतृत्व में इस मुक्ति-आन्दोलन को और भी गति मिल रही है।

नई दिल्ली, शनिवार ९ अगस्त १९४७

आज भी कर्मचारी मंडल की बैठक में हमने पंजाब के सफ़ा पर विस्तार से चर्चा की। सीमा-प्रदेश की निहायत गंभीर स्थिति की रिपोर्ट भेजने के साथ ही जेनकिंस ने सेना, हवाई फौज और पुलिस की कुमुक जल्दी भेजे जानेकी मांग की है। इसके अतिरिक्त, जनसम्पर्क का विशाल काम भी माउन्टबेटन के सामने है जिस पर लोगो में मनोबल और व्यवस्था कायम रखना निर्भर करता है।

सुनने में आया है कि रेडक्लिफ आज शाम तक पंजाब सीमा आयोग का फैसला वाइसराय को दे देंगे। उनके हिन्दू और मुसलमान सहयोगियों में प्रत्याशित असहमति के कारण रेडक्लिफ को सारे फैसले अपने ही बूते पर करने पड़े हैं। लेकिन प्रकाशन का दायित्व जरूर वाइसराय पर है। शुरू से ही माउन्टबेटन ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दे दिये थे कि जबतक रेडक्लिफ मध्यस्थता के कठिन और नाजुक काम में लगे हैं, तबतक उनसे कोई सम्बन्ध न रखे जाय। वह खुद भी उनसे दूर ही रहे। इसलिए हमें ठीक-ठीक पता न था कि रेडक्लिफ ने कितनी मजिल पार कर ली है और किस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं।

फैसले के प्रकाशन के बारे में कई सुझाव आये। प्रशासनिक दृष्टि से यह तर्क दिया गया कि उसका ऐलान जल्दी होने से जेनकिंस को मदद मिलेगी और सत्ता-हस्तांतरण के पहले सेनाएँ सफ़ा-ग्रस्त इलाको में भेजी जा सकेंगी। दूसरा सुझाव यह था कि चूँकि इन फैसलों से अशान्ति फैलना सुनिश्चित है, इसलिए इनके प्रकाशन की सबसे उचित तिथि १४ अगस्त होगी। माउन्टबेटन ने कहा कि यदि इस बारे में उनकी कुछ भी चले तो वह इसका प्रकाश स्वाधीनता-दिवस के समारोहों के बाद तक के लिए मूलतः कर देंगे। उनकी धारणा थी कि प्रकाशन के समय का प्रश्न वास्तव में मनोवैज्ञानिक है। वह नहीं चाहते कि इसके प्रकाशन से जो विवाद और विपाद पैदा होनेवाला था उससे दोनों देशों के स्वाधीनता-दिवसों का उत्साह भग होने दिया जाय।

इस राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि रेडक्लिफ-फैसले को स्वतन्त्रता-समारोह के पहले या उसी दिन प्रकाशित करना हिन्दू, मुसलमान और सिखों को मिलने वाली स्वतन्त्रता के महत्व को ही नष्ट करना होगा। एक भारतीय की मित्रता जितनी सरलता से पाई जा सकती है, उतनी ही सरलता से खोई भी जा सकती है। उसकी आशाओं तथा उसके वातावरण के कारण उसके सुख और दुःख के बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं रहती। उसके आनन्द की शर्त यह है कि

वह आनन्द अनियंत्रित हो और अपने शाश्वत भयो से अस्थायी छुटकारा मिले ।

आज की बैठक में इसके बारे में कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया । वाइसराय के निजी सैक्रेटरी एवेल को आदेश दिया गया कि वह प्रकाशन के समय के विषय में जेनकिन्स के साथ भी चर्चा कर ले । सीमा-आयोग के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्पष्ट करने के लिए माउन्टबेटन ने यह निश्चय किया कि उसकी घोषणा वाइसराय भवन की विज्ञप्ति के रूप में न की जाकर 'असाधारण गजट' के रूप में हो ।

जेनकिन्स ने इस सुझाव को ठुकरा दिया है कि सिख-नेताओं को १५ अगस्त के पहले गिरफ्तार कर लिया जाय । उन्होंने माउन्टबेटन को बतलाया कि उन्होंने इस विषय की चर्चा मूड़ी और त्रिवेदी से कर ली है और वे भी एकमत हैं कि ऐसी कार्रवाई से परिस्थिति बिगड़ जायगी । इसलिए तीनों ने यह निश्चय किया कि कोई गिरफ्तारियां न की जाय ।

: १३ :

## पाक-भारत में स्वाधीनता-दिवस

सरकारी भवन, कराची, बुधवार, १३ अगस्त १९४७

माउन्टबेटन संयुक्त ब्रिटिश भारत के वाइसराय की हेमियत में अपने अंतिम कर्तव्य का पालन करने के लिए आज प्रातः काल दिल्ली में कराची के लिए रवाना हुए । यह कर्तव्य है नये पाकिस्तानी उपनिवेश के जन्म के समय, राजा को तथा अपनी नुभ-कामनाएँ व्यक्त करना ।

जब हम वाय्थान से उतरे तो मिन्च के मनोनीत गवर्नर हिदायतउल्ला ने माउन्टबेटन-दम्पति का स्वागत किया । फोटोग्राफरो का समुदाय भी बहस्तूर मौजूद था । सरकारी भवन को जाते समय जिन्ना के सैनिक सैक्रेटरी कर्नल वर्नी ने माउन्टबेटन से कहा कि उन्हें कल के जूझूम में जिन्ना के ऊपर दम फेंकने के एक पड्यत्र की सूचना मिली है । इसलिए विचार यह चल रहा है कि जूझूम ही रद्द कर दिया जाय या निरंक रान्ता बदला जाय । जिन्ना ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि माउन्टबेटन जूझूम में रहने को तैयार हैं, तो मैं भी तैयार हूँ । माउन्टबेटन तुम्हें सहमत हो गए कि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन न किया जाय ।

जिन्ना और मिन्च जिन्ना बड़े कमरे के प्रवेश-द्वार पर माउन्टबेटन-दम्पति की प्रतीक्षा कर रहे थे । कमरा हालीवुड में किन्म गेन के सेट की भांति मजा हुआ

था। चारों कौ बड़-बड़ लैंपो के चौधिया देनेवाले प्रकाश और झुलसा देने-वाली गर्मी के नीचे खड़े रह कर बारबार फोटो खिंचवाने की अग्नि-परीक्षा देनी पड़ी।

मैने पलेस होटल मे सरकारी सूचना-अधिकारी कर्नल मलिक से सम्पर्क स्थापित किया और कुछ विदेशी सवाददाताओं से भेंट की, जो कराची के अवतक के आयोजनों के कड़े आलोचक थे। कुछ का कहना था कि जिन्ना ने माउन्टबेटन के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित न रह कर उनका अपमान किया है। परन्तु मैने तुरन्त कहा कि माउन्टबेटन यह नहीं मानते कि शिष्टाचार का कोई अभाव रहा है या उसका कोई उल्लंघन हुआ है।

उन्होंने बतलाया कि कल सविधान-सभा की बैठक मे जिन्ना के प्रति पूर्ण दासता की भावना का वातावरण था। प्रत्येक व्यक्ति कायदे-आजम के सामने जबानी आत्म-समर्पण करने मे एक-दूसरे से होड़ लगाये हुआ था।

मेरी उत्सुक पूछताछ के उत्तर मे मलिक ने बताया कि आज रात के भोज मे जिन्ना प्रकाशन के लिए कोई निश्चित भाषण करने का विचार नहीं कर रहे है। इसकी सूचना मैने माउन्टबेटन को दे दी। परन्तु मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब भोज के अंत मे मैने देखा कि जिन्ना बड़े आदमियों के उस समुदाय-मे, जिसमे न केवल पाकिस्तान के प्रमुख लोग वरन् कूटनीतिक मंडलों के सदस्य भी उपस्थित थे, खड़े हुए और अपना चश्मा सवार कर कृत्रिम-स्वर मे एक लिखित-भाषण पढ़ने लगे। वह भाषण भारी राजनैतिक महत्व का निकला, क्योंकि उसमे ब्रिटन के साथ पाकिस्तान के भावी-संबंधों के बारे मे आत्मीयतापूर्ण विचार प्रकट किये गए थे और पाकिस्तान के निर्माण मे माउन्टबेटन के योग की चर्चा की गई थी।

यदि माउन्टबेटन को इस प्रकार अचानक भाषण के व्यूह मे फसने के कारण कोई घबराहट हुई हो तो उन्होंने उसे व्यक्त नहीं होने दिया। उन्होंने ऐसा सुन्दर भाषण दिया कि जिन्ना के लिखित-भाषण को भी मात कर दिया। दो मिनट तक उपयुक्त शब्दों और वाक्यों की अटूट धारा उनके मुख से प्रवाहित होती रही। कथाए कहने की उनमे विलक्षण योग्यता है। और उनके अनौपचारिक निशाने पर चोट करने वाले उनके भाषण, भोज के बाद दिये जाने वाले भाषणों का आदर्श उपस्थित करते है।

भोज के बाद हम एक भारी सत्कार-सभा मे शामिल हुए। उसमे हलके पेय तथा संगीत का कार्यक्रम था। सब परिस्थितियों का खयाल रखते हुए यह सत्कार सफल रहा। आज के मेजवान और मुख्य व्यक्ति के रूप मे जिन्ना अकेले-अकेले और कुछ अलग-अलग लगे। संभवत इसीसे वातावरण कुछ दबा-दबा सा था। अपने रुपहले वालों और वेदाग सफेद अचकन मे वह सबके ऊपर छाये नजर आते थे और बहुत ही कम बातें करते दीख पड़ते थे। लोग भी उनसे आत्मीयता जताने

का साहस नहीं करते। 'बेतार' से नेतृत्व करने की क्षमता की वह माझात प्रतिमा थे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी देश का निर्माता अपनी मफज्जा के सर्वोच्च क्षण में अपने अनुयायियों से इतनी दूर भाग सकेगा। उन्हें अकेला पाकर मैंने कुछ क्षणों तक उनसे बात की। मैंने उन्हें बर्बाद देने के लिए उपयुक्त शब्द खोजने का प्रयत्न किया, परन्तु उनकी ध्यानावस्थित अवस्था से सहम कर मेरे शब्द मुरझा गए।

सरकारी भवन, कराची और सरकारी भवन, नई दिल्ली,  
बृहस्पतिवार-शुक्रवार, १४-१५ अगस्त १९४७

विधान-सभा में होनेवाले समारोह में भाग लेने के लिए हम काफी तडके उठ गए। जुलूस के लिए निश्चित रास्ते से होता हुआ मैं जिन्ना और माउन्टबेटन के आध घंटे पहले वहाँ पहुँच गया। जनता का उत्साह और भीड़ मेरी आँखा में बहुत कम थी। यहाँ का उत्साह उसमें अधिक नहीं था जो समद के वार्षिक उद्घाटनों के अवसर पर हुआ करता है। लेकिन अर्द्धचन्द्राकार और गोल गुम्बद की श्रृंखला वाले विधान-सभा-भवन के सामने के मैदान की इच-इच जगह ठपाठम भरी हुई थी। माउन्टबेटन-दम्पति को भी वही स्वागत-सत्कार मिला, जो उनमें कुछ पहले आने वाले जिन्ना को मिला था। माउन्टबेटन और जिन्ना के भाषणों का मुख्य स्वर मोहार्द का था और उपस्थित सदस्यों की प्रतिक्रिया भी मोहार्द-पूर्ण थी। प्राथमिकता का प्रश्न अपने-आप हल हो गया। जने ही जिन्ना भाषण देकर बैठने लगे लेडी माउन्टबेटन ने स्नेह में कुमारी जिन्ना का हाथ दबाया।

अगर जिन्ना का व्यक्तित्व भावनाहीन और एकाकी था तो उसमें एक चमत्कारीय गुण भी था। उनमें नेतृत्व की ऐसी शक्ति थी जिसके आगे लोगों के घुटने टिक जाते थे। वैधानिक गवर्नर-जनरल होने का वह बहुत उद्यत और ऊँची दिग्गवा करते थे, और उस पद के लिए स्वयं अपना नाम मुजाने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया वह था १९३५ के विधान के भाग दो की बजाय नती अन्तर्ची के अनुसार विशेषाधिकार ग्रहण करने की घोषणा करना। उसने ऐसे तानाशाही अधिकार उनके हाथ में आ गए जो बादशाह का प्रतिनिधित्व करने वाले वैधानिक गवर्नर-जनरल को शायद ही पहले कभी मिले हों। पाकिस्तान के बादशाह धन-गर, शक्ति और प्रधान-मंत्री—उन सबके अधिकार शक्तिशाली हाथों-आजमे में निहित हैं।

मे प्रवेश करने लगी, जिन्ना ने बड़ी भावुकता के साथ माउन्टवेटन के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, “खुदा का शुक है कि मैं आपको हिफाजत से वापस ले आया हूँ।” दोपहर तक माउन्टवेटन-दम्पति ने बिदाई की रस्में पूरी कर ली। मिस जिन्ना ने लेडी माउन्टवेटन को गले लगाया और जिन्ना ने, जिनकी भावुकता अभी चुकी नहीं थी, अपनी गाँवत दोस्ती और एहसानमदी के इजहार किये। अब वह दिल्ली के विशाल समारोहों में भाग लेने के लिए हवाई जहाज से रवाना हुए। जब हम पंजाब के सीमा-प्रदेश के ऊपर से गुजरे तो हमने मनहूसियत की प्रतीक कई विशाल आगों को आसपास के मैदान पर मीलों तक फैले देखा।

दिल्ली पहुँचते ही मैं प्रचार-व्यवस्था के तूफान में फँस गया। मुझे समय की चुस्त पाबंदी और उलझे कार्यक्रम की समस्याओं से निबटना था, फोटोग्राफों और फिल्म लेने वालों के साथ रिहर्सल करने थे, सूचना मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करना था, प्रचार-सामग्री बाटनी थी, दिल्ली के एक सौ बीस भारतीय और विदेशी पत्रकारों को निमंत्रण देने थे और उनकी पूछताछ के उत्तर देने थे। रात की आखिरी घड़ी तक माउन्टवेटन और उनके कर्मचारी अपने काम में जुटे रहे। अपना डेरा-डण्डा उठाने के काम में वाइसराय का अमला आखिरी क्षण तक पूरे वेग से व्यस्त था।

जैसे ही आधी रात का समय होने को हुआ और वाइसराय की ओर से सेक्रेटरी आव् स्टेट के नाम अन्तिम तार का मसविदा तैयार कर भेजा गया, मैंने अपने-आप को माउन्टवेटन के साथ उनके अध्ययन-कक्ष में अकेला पाया। नये कानून के लागू होते ही तुरन्त सर्वशक्ति-सम्पन्नता का अधिकार ग्रहण किया जा सके इसलिए विधान-सभा का अधिवेशन चौदह तारीख की आधी रात को आयोजित किया गया था। स्वाधीनता की घोषणा, और माउन्टवेटन से पहले वैधानिक गवर्नर-जनरल के रूप में पद संभालने का प्रस्ताव पास होते ही डा राजेन्द्रप्रसाद और नेहरू माउन्टवेटन से मिलने आयगे और औपचारिक रूप से उन्हें न्योता देगे। उम्मीद है कि पौन वजे के लगभग उनका आना होगा।

जब आधी रात में घड़ी न टन किया उस समय माउन्टवेटन बहुत चुपचाप बैठे हुए थे। मैं उन्हें करीब-करीब हर प्रकार की मन स्थिति में देख चुका हूँ। कह सकता हूँ कि आज रात वह निहायत शान्त और निर्लिप्त थे। उनकी व्यक्तिगत सफलता इतनी महान् थी कि उसे खुशी दिखाकर व्यक्त नहीं किया जा सकता था, बल्कि इस नाटकीय घड़ी में, जब नये और पुराने का मिलन उनमें साकार होने को था, उनके इतिहास-विषयक ज्ञान और विवेक ने उनमें भारी धीरज भर दिया था।

धीरे-धीरे उन्होंने अपना चश्मा उतारा, कागज-पत्र रखने के सन्दूकों को बन्द किया और वाइसराय की सक्रियता के चिह्नों को हटाकर सफाई करने में मेरी मदद

चाही। हालांकि बाहर नौकरो की पल्टन-की-पल्टन मौजूद थी, उनकी मदद लेने का खयाल हम दोनों में से किसी के भी दिमाग में नहीं आया। जब सारे कागज करीने से लगा दिये गए और उनकी मेज साफ हो गई तब उन्हें बुलाकर कुछ भारी फर्नीचर इधर-उधर सरकाया गया, जिससे पत्रकारों के लिए जगह हो जाय।

विधान-सभा के समारोह में उपस्थित पत्रकारों का आना शुरू हो गया। उन्होंने बतलाया कि अपार भीड़ मार्ग पर खड़ी हुई है और इमींसे नेहरू और राजेन्द्रप्रसाद बाबू को जरा देर हो गई है। विधान-सभा की कार्यवाही बहुत ही शानदार रही थी। बड़े भावुकता पूर्ण ढंग से नेहरू ने कहा, “बहुत साल बीते हमने तकदीर के साथ एक बाजी बदी थी। और आज वह दिन आया है कि जब हम उस प्रण को पूरा करेंगे—पूर्णता के साथ तो नहीं, लेकिन काफी हद तक। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही है, हमारा भारत जीवन और स्वाधीनता के नव-जागरण में प्रवेश कर रहा है।”

विशाल जन-समूह की हर्ष-ध्वनि को पार कर थके लेकिन प्रसन्न राजेन्द्रप्रसाद और नेहरू ने प्रवेश किया। आगे जो हुआ उसमें दोस्ती की भावना ने औपचारिकता के सारे बन्धनों को तोड़ दिया। पत्र-सम्वाददाता घेरा बनाये खड़े थे और फोटोग्राफर मेज के पास मौजूद थे। हालांकि नेहरू ने सम्वाददाताओं की उपस्थिति की स्वीकृति दी थी, लेकिन मेरा खयाल है कि वह यह बात भूल गए थे। चाहे इस उपस्थिति के कारण हो, चाहे विधान-सभा की ऐतिहासिक घटनाओं के कारण, वे दोनों कर्तव्य-विमूढ़ खड़े थे।

आखिर, माउन्टबेटन और राजेन्द्रप्रसाद बाबू आमने-सामने आ खड़े हुए और नेहरू उनके बीच माउन्टबेटन की मेज पर आ बैठे। राजेन्द्रबाबू औपचारिक निमंत्रण देने लगे। लेकिन वह कहने वाले शब्दों को भूल गए और नेहरू उन्हें ठीक शब्द याद दिलाने लगे। दोनों ने मिलकर बतलाया कि विधान-सभा ने अधिकार सभाल लिये हैं और नेताओं की यह विनय मान ली है कि माउन्टबेटन भारत के नये गवर्नर-जनरल बने। इस सन्देश के उत्तर में माउन्टबेटन ने मुसकराते हुए कहा, “इस सम्मान को मैं अपना गौरव मानता हूँ। आपकी सलाह पर वैधानिक ढंग से अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा।”

यह होते ही नेहरू ने एक बड़ा-सा लिफाफा, जिस पर सुन्दर अक्षर लिखे हुए थे, माउन्टबेटन को देते हुए बड़े शिष्टाचार के साथ कहा, “नये मन्त्रिमंडल की सूची सेवा में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिये।” सारा समारोह दस मिनट के अन्दर पूरा हो गया। लेकिन इस उत्सव में विशाल समारोहों और परेडों की अपेक्षा कहीं अधिक इन्सानियत और आशा भरी हुई थी।

मे फिर माउन्टबेटन के साथ अकेला रह गया। अपनी उत्सुकता शान्त करने और अपनी सरकार के नये मन्त्रियों के नाम याद करने के लिए उन्होंने बड़े लिफाफे-



को खोला। लेकिन अपने प्रधान-मंत्री द्वारा तैयार की हुई सूची आज देखना उनकी तकदीर में नहीं बदा था। दैवयोग से नेहरूजी का दिया लिफाफा विलकुल खाली था।

सरकारी भवन, नई दिल्ली, शुक्रवार, १५ अगस्त, १९४७

आज से अधिक व्यस्त और स्मरणीय दिन गायद ही मुझे फिर देखने को मिले।

जिन तुरहियों और लाल-सुनहरी सजावटों के बीच बीस गवर्नर-जनरल पद ग्रहण कर चुके थे, उन्हींके बीच आज सवेरे ८-३० बजे दरबार हाल में स्वतन्त्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में लार्ड माउन्टबेटन के प्रवेश की घोषणा हुई। इस समारोह की खासियत यह नहीं थी कि वह माउन्टबेटन के वाइसराय-पद पर आसीन होने के समारोह से किसी प्रकार भिन्न था, बल्कि खासियत यह थी कि आज का समारोह हर बात में मार्च के समारोह से मिलता-जुलता था। फरक अगर था तो इतना ही कि गवर्नर-जनरल को शपथ दिलाने का काम एक भारतीय न्यायाधीश, डा० कानिया के जिम्मे था और नये उपनिवेश के मंत्रियों को शपथ दिलाई गृह-विभाग के एक भारतीय सेक्रेटरी ने। एक बार फिर सुनहरे सिंहासन पर लगे कीमती लाल मखमल के चदोवे छिपी हुई रोशनियों से जगमगा उठे। कालीन सुनहरे काम से चमचमा रहे थे और लेडी माउन्टबेटन अपनी सुनहरी पोशाक में इस समारोह की रौनक बढ़ा रही थी।

लार्ड और लेडी माउन्टबेटन सिंहासनो पर मुश्किल से बैठे ही होंगे कि किसी फोटोग्राफर के 'फ्लैश बल्ब' के धडाके से सारा दरबार-हाल गूँज उठा। वम की इस हू-ब-हू नकल से चिता की एक क्षणिक लहर दौड़ गई। माउन्टबेटन दम्पति पर तेज रोशनिया पड़ रही थी, फिर भी उन्होंने चेहरे से ऐसा नहीं लगने दिया कि बल्ब की चमक या उसके धडाके की आवाज उनके कानों तक पहुँची होगी। समारोह समाप्त होने के समय दरबार-हाल के विशाल दरवाजे खोल दिये गए। पहले 'गाड सेव दि किंग' और फिर 'जन गण मन' की धुने बजी, जो पुराने और नये युग को जोड़ने वाली कड़ी की प्रतीक थी।

कुछ ही पलों में सारे सभ्रान्त दर्शक वहाँ से लुप्त हो गए और वे कौंसिल-भवन को घेरे खड़ी अपार भीड़ में खो गए। माउन्टबेटन की राजकीय सवारी सरकारी भवन (जिसे कल तक वाइसराय भवन कहते थे) के मुख्य दरवाजों से निकल कर सरकारी सचिवालय भवनो के बीच से ढलवा मार्ग पर बढ़ना शुरू हुई थी, कि भारी भीड़ ने उसे रोक लिया और विशाल तथा प्रसन्न जनसमूह ने उनकी बगधी को मानो हाथों में उठा लिया।

इससे पहले कि भीड़ का दबाव जोर पकड़े, मैं फुर्ती से सरकारी भवन के क बगल के रास्ते से चलकर कौंसिल-भवन में जा पहुँचा। किन्तु ज्यों-ज्यों समय

बीतता जाता था कौंसिल-भवन के विशाल दरवाजों से सरकारी अतिथियों को अन्दर आने देना कठिन होता जाता था। उनके अन्दर आने के साथ ही जोरों से 'जय हिन्द' चिल्लाने वाले नागरिकों का एक रेला भी अन्दर घुस आता। कुछ देर में ही विशाल गोलाकार कौंसिल भवन ने फौजी घेरे में पड़े एक किले का रूप धारण कर लिया। किसी को सुझाई न देता था कि जब माउन्टबेटन दरवाजे पर पहुँचेंगे तो गाड़ी से उतर कर उनके अन्दर आने के लिए रास्ता कैसे किया जायगा। काफी देर तक स्थिति बड़ी खराब रही। लगभग ढाई लाख जनसमूह बलात् अन्दर घुसने की जो तोड़ कोशिश करने लगा। जनता को शांत करने के लिए नेहरू तथा अन्य बड़े नेताओं को बाहर बुलाना पड़ा। नेताओं की उपस्थिति ने पहले तो जनता की उत्तेजना को और भड़काने का काम किया लेकिन बावजूद इसके कि भारी भीड़ उनसे हाथ मिलाने के लिए धक्कामुक्की करती हुई आगे पिली पड़ रही थी, जैसे-तैसे माउन्टबेटन-दम्पति को अन्दर पहुँचा दिया गया। उनके पदक और राजचिह्न विल्कुल ज्यो-के-न्यो थे।

भवन के अन्दर भी उत्साह और आगे होने वाली घटनाओं के प्रति प्रतीक्षा की भावना बाहर-जैसी ही थी, लेकिन इतनी सयत अवश्य थी कि औपचारिक समारोह सपन्न हो सके। डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कार्रवाई का आरम्भ दुनियाभर से आये हुए बवाई सदeshों को पढ़कर सुनाने से किया। किन्तु किसी चूक के कारण, जिसकी तुलना कल रात के खाली लिफाफे की घटना से की जा सकती है, वह राष्ट्रपति ट्रूमैन का सदेश पढ़ना भूल गए। यह त्रुटि वह तभी सुधार सके जब अमरीकी राजदूत डा. ग्रेडी ने जोर से फुसफुसा कर उसकी याद दिलाई। हमेशा की तरह फोटोग्राफरों के बल्बों के धमाकों के बीच माउन्टबेटन भाषण देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले राजा जार्ज षष्ठ का सदेश पढ़कर सुनाया, जिसका हृदय से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उनके लिखित भाषणों की अपेक्षा कहीं अधिक जोश और बल था। हालांकि शब्दों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया गया था, किन्तु उनमें जो सच्चाई व हार्दिकता निहित थी वह भारी सभा की सहानुभूति और प्रशंसा प्राप्त करने में सफल हुई। उनके भाषण में रियासतों के सच-प्रवेश की नीति की सफलता, नेहरू और पटेल के नेतृत्व के उल्लेख, तथा उनके इस अनुरोध पर कि "मुझे आप अपना ही समझे" बड़ी हर्ष ध्वनि की गई। किन्तु गांधीजी के प्रति उनके उद्गारों पर सबसे अधिक तालिया पीटी गई और काफी देर तक उन्हें रुकें रहना पड़ा।

इसके बाद डा. राजेन्द्रप्रसाद ने एक लम्बा भाषण दिया—पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। दोनों ही भाषण सुनाई नहीं पड़ते थे। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं में डा. प्रसाद नम्र विचारों और स्वभाव वाले व्यक्ति माने जाते हैं। वह न कभी उत्तेजित होते हैं, न अतिशयोक्ति करते हैं। आज उन्होंने अपना दिल खोलकर

रख दिया। उन्होंने कहा, “आइये, हम कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें कि, हालांकि हमारी सफलता का काफी श्रेय हमारे बलिदानों और त्यागों को है, लेकिन वह विश्व की घटनाओं और स्थिति का भी परिणाम है। ब्रिटिश जाति की ऐतिहासिक परम्पराओं और जनतांत्रिक आदर्शों का भी उसमें कम हाथ नहीं है।” उस जाति के प्रतिनिधि के रूप में माउन्टबेटन को श्रद्धाजलि देने के बाद उन्होंने कहा, “भारत के ऊपर ब्रिटिश सत्ता का आज अन्त हो रहा है और भविष्य में ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, आपसी सद्भाव और पारस्परिक लाभ के आधारित रहेंगे।”

भाषणों के बाद विधान-सभा भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया और ३१ तोपों की सलामी दागी गई। आज दिन में जो अनेकों तूफानी सवारियाँ निकलने वाली थी, उनमें माउन्टबेटन के वापिस लौटने की सवारी का नम्बर केवल दूसरा था। सरकारी भवन तक का सारा रास्ता ‘जय हिन्द’ और “माउन्टबेटन की जय” के नारों से गुँज रहा था। कहीं-कहीं “पंडित माउन्टबेटन की जय” का घो भी कानों में पड़ जाता था।

दोपहर के खाने के बाद हमारी मोटरो का काफिला रोशनआराबाग की ओर चला, जहाँ पहुँच कर भीषण गर्मी में माउन्टबेटन-दम्पति पाँच हजार स्कूली छात्रों की भीड़ में घुलमिल गए। यहाँ अनेकों प्रकार के खेल-तमाशों का आयोजन था। इनमें से कुछ ने मनोरंजन किया, कुछ ने चकित और कुछ ने डरा दिया। एक फकीर को साप का फन खाते हुए देखकर और गर्मी तथा कोलाहल के मारे बेचारी पमेली की तो जान ही निकल गई। फिर भी पमेली और उसके माता-पिता बड़े साहस और सद्भाव के साथ समारोह में भाग लेते रहे।

पुरानी भारतीय परम्परा के अनुसार जाने के पहले माउन्टबेटन ने जो आखिरी काम किया वह था बच्चों में मिठाई बाँटना।

सरकारी भवन लौटकर माउन्टबेटन-दम्पति को मुश्किल से इतना समय मिल पाया कि आज के सब-से-बड़े सार्वजनिक समारोह में भाग लेने के लिए वे कपड़े बदल सकें। यह समारोह था प्रिंसेज पार्क के निकट युद्ध-स्मारक पर राष्ट्रीय झंडा फहराना। वहाँ जाकर देखा तो तीन लाख के लगभग जनता एकत्र थी जब कि समारोह के आयोजकों ने कुल ३० हजार के करीब जन-समुदाय के लिए प्रबंध किया था। नतीजा यह हुआ कि कोई व्यवस्था न रही और भीड़ बेकाबू हो गई। जन-समुदाय ने सब कुर्सियों पर अधिकार कर लिया था और एक-एक कुर्सी पर कुछ लोग आ खड़े हुए।

जन समुदाय के इस विशाल भवर में बड़े छोटे, काले-गोरे, स्त्री-पुरुष तथा नाना जातियों के व्यक्ति मिल कर एकाकार हो गए थे। हजारों लोगों की एकमात्र इच्छा यही थी कि जहाँ झंडा फहराया जाने वाला था उस केन्द्रीय मंच तक पहुँच जाय। दरअसल भीड़ ने एक विशाल महासागर का रूप धारण कर

लिया था जो चारों ओर से एक छोटे से द्वीप को घेरने के लिए आगे बढ़ा चला जा रहा था, और यह खतरा था कि किसी भी क्षण वह उस द्वीप को निगल जायगा। स्वयं नेहरू बड़ी मुश्किल से केन्द्रीय मंच पर पहुँच पाए और जब उन्होंने देखा कि पमेली भीड़ में फँस गई है तो लपके और धक्का-मुक्की करते, इसके सिर की टोपी उतार कर उसके सिर पर रखते हुए, पमेली को निकाल लाये। एक व्याकुल ए. डी. सी घबराया कि कहीं दगा न हो जाय। किन्तु उसने इस विशाल जन-समुदाय की मस्त और प्रसन्न-मुद्रा को नहीं पहचाना था।

जहाँ मैं खड़ा था, वही एक सूरमा साइकिल चलाने का असंभव प्रयत्न कर रहा था। ऐसा लगता था कि अपनी मजिल तक पहुँचने के पहले ही वह भीड़ में आ फँसा था। नतीजा यह हुआ कि वह न आगे बढ़ सकता था और न साइकिल से उतर सकता था। फे, मार्जोरी, ब्राकमेन तथा पमेली, निकोल्स भी बीच में फँस गए थे, लेकिन खुश भीड़ चिल्ला रही थी, "मेम-साहबों के लिए रास्ता छोड़ दो।" फे आखिर बी. बी. सी की गाड़ी पर पहुँच गए, जहाँ से विन्फोर्ड वागा टामस विदेशों के लिए एक अत्यन्त विस्तृत और शानदार ब्राडकास्ट कर रहे थे। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि इससे बड़ी भीड़ उन्होंने जीवन में नहीं देखी।

सहसा हर्ष-ध्वनि ने गरज का रूप ले लिया। जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से सफेद-पोश ए. डी. सी की एक झलक दिखलाई दी। उसके पीछे गवर्नर-जनरल के अग्ररक्षकों के भालों के ऊपर फहराते झंडों की झलक, फिर गवर्नर-जनरल की गाड़ी और फिर अग्ररक्षक। गाड़ी और अग्ररक्षक रुकते-चलते किसी प्रकार केन्द्रीय मंच के पच्चीस गज पास तक पहुँच गए। मैंने माउन्टबेटन को खड़े होकर जन-समूह का अभिनन्दन करते देखा जो हर्ष-ध्वनि करती हुई उनकी ओर हाथ हिला रही थीं। लोगों को शांत करने और थोड़ी जगह साफ करने के लिए नेहरू ने आखिरी बार कोशिश कर देखी, लेकिन जब उनकी आरजू-मिश्रित का कोई फल नहीं हुआ तो इसके सिवा कोई चारा ही न रहा कि माउन्टबेटन गाड़ी में ही खड़े रहे और झंडा फहराये जाने पर वही से सलामी ले।

झंडे के फहराये जाते ही बूँदा-बादी होने लगी और इन्द्रधनुष आकाश के आरपार तन गया। लगता था मानो झंडे के केंटरिया, सफेद ओर हरे रंगों से होड़ कर रहा हो। अगर हालीवुड ने यह दृश्य अपनी किसी फिल्म में दिखाया होता तो हम सब यही शिकायत करते कि यह अतिरजना है, लेकिन यह दृश्य निहायत स्वाभाविक था। मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का दिल लोड़े का बना हुआ हो वही ऐसे शुभ-अवसर पर प्रकट हुए इन शुभ-शकुन से प्रभावित हुए बिना रह सकता था।

माउन्टबेटन की सवारी की सरकारी भवन को वापिसी दोस्ती-भरी अनौपचारिकता की अन्तिम विजय थी। नेहरू अपनी मोटर तक पहुँचने में असफल रहे थे, इसलिए माउन्टबेटन ने उन्हें भी अपनी बग़्गी में खींच लिया, और वह गाड़ी के 'हुड' पर बठ गए। रास्ते में चार औरतो, एक बच्चे और गाड़ी के पहियों के नीचे दबते एक फाटोग्राफर को भी माउन्टबेटन ने अपने साथ ले लिया, जिससे गाड़ी में बैठे लोगो की संख्या बारह तक पहुँच गई। कर्जन और उनके दरबार की यह पुनरावृत्ति थी।

फिर, आज के इस ऐतिहासिक दिन के उपसहार स्वरूप हम सरकारी भोज में भाग लेने सरकारी भवन पहुँचे। मन्त्रिमंडल के सदस्य, कूटनीतिज्ञ लोग और बड़े-बड़े सैनिक तथा असैनिक नेता भोज में उपस्थित थे। गैरहाजिरो में खास थे वे एक-दो राजे-महाराजे, जो नई सरकार के सदस्यों के सामने उचित प्राथमिकता न मिलने के भय से हाजिर नहीं हुए थे। जब नेहरू ने खड़े होकर ब्रिटिश राजा के स्वास्थ्य की कामना की और उसके उत्तर में माउन्टबेटन ने औपनिवेशिक सरकार की शुभकामना की तो समारोह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इन दोनों के भाषण बिल्कुल अलिखित थे और केवल उपस्थित लोगो के कानों के लिए थे। इसलिए उनमें वह सजीदगी नहीं थी जो विश्वव्यापक प्रचार के विचार से भाषणों में आ जाना करती है।

नेहरू ने कहा, "आप लोगो ने देखा होगा कि कितने उत्साह से दिल्ली की जनता ने आज का दिन मनाया है। कोई शक नहीं कि सारे भारत में ऐसे ही दृश्य दिखलाई पड़े होंगे। दो देशों के बीच पैदा होने वाले संबंधों में राजनीति और अर्थ का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन भारत की जनता के साथ व्यवहार करने में मैं मनोवैज्ञानिक और भावना-संबंधी पक्षों के महत्व की ओर ध्यान खींचना चाहता हूँ। जो लोग दिल्ली में अपने दफ्तरों में बैठे हुए राजनैतिक समस्याओं और आर्थिक योजना पर विचार किया करते हैं, उनका देश के साथ वास्तविक-संपर्क नहीं होता है। इस बारे में अनक मत हो सकते हैं कि ब्रिटेन के साथ अपने अतीत संबंधों से भारत को फायदा हुआ या नहीं। लेकिन यह सोचना सरासर गलत होगा कि आजादी की जद्दोजहद करने वाली जनता पर किसी बड़े राष्ट्र को अपना आधिपत्य जमाये रखना चाहिये। चूँकि अब हिन्दुस्तान आजाद है, इसलिए जनता खुश ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों के प्रति उसके रुख में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है।"

माउन्टबेटन को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि माउन्टबेटन को आते ही यह समझने में देर नहीं लगी थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति का पालन करने के लिए फुर्ती से काम करने और भारत की ओर ठीक मनोवैज्ञानिक रुख अपनाना कितना अहम है। भारत और ब्रिटेन के संबंध भविष्य में चाहे जैसा रूप

## उत्तराधिकार का युद्ध

धारण कर ले, लेकिन एक नई गुरुआत तो हो गई है। उन्होंने आशा प्रकट की कि उनके बीच मैत्री कायम रहेगी।

अपने उत्तर में माउन्टबेटन ने कहा कि उनके पूर्वगामियों का दुर्भाग्य था कि उन्हें खड़ी साइकिल पर बैठने को तो मजबूर होना पड़ा था, और उस पर सतुलन बनाए रखना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन उन्हें तो पैडल मार कर तत्काल 'आगे बढ़ने' का आदेश दिया गया था। उनका काम था अधिकाधिक तेजी से पैडल मारना और आज वह इस स्थिति में पहुँच गए हैं कि यह साइकिल अपनी सरकार के हाथों में सौंप रहे हैं, जिसने हैन्डिल को कसकर पकड़ लिया है।

सवा नौ बजे तीन हजार मेहमान कतार से ऊपर पहुँचे और एक-एक कर माउन्टबेटन के सामने पेश किये गए। सरकारी भवन के सारे कमरे और बैठकें मेहमानों के लिए खोल दिये गए। तेज रोगनी से जगमग मुगल-उद्यान बड़ा मनोरम प्रतीत हो रहा था। अब जरा ठंडक भी हो गई थी और हवा मजेदार और सुगंधित थी। बड़े सद्भाव और हसी-खुशी के साथ यह दावत देर तक चलती रही। वह तनाव और अकड़ भी अब नहीं रही थी, जो मार्च की गार्डन-पार्टी में भारतीय मेहमानों में दिखलाई पड़ती थी। ऐसी सरलता और स्वच्छन्दता का वातावरण था जो समानता की व्याप्त भावना ही पैदा कर सकती है।

स्वाधीनता के अवसर पर निकाले गए विशेषांशों में बहुत-सी मोजू बातें लिखी गई थी। लेकिन सबसे अच्छे मुझे के एम मुशी के शब्द लगे, जो उन्होंने माउन्टबेटन की गवर्नर-जनरल पद पर नियुक्ति के बारे में लिखे थे

वह लिखते हैं "ब्रिटेन के अलावा इतिहास का कोई राष्ट्र इनकी शान से आजादी का दान नहीं दे सकता था, और भारत के अलावा कोई दूसरा देश इनकी शान के साथ इस ऋण का आभार नहीं मान सकता था।"

: १४ :

## उत्तराधिकार का युद्ध

नई दिल्ली, शनिवार, १६ अगस्त १९४७

आज सवेरे तड़के दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इस अवसर पर नेहरू ने लगभग पाँच लाख जनता के सामने भाषण दिया। 'भीड़ मुगलों के गौरव के एक और प्रतीक, विशाल जामा मसजिद तक फैली हुई थी।

लेकिन आज तीसरे पहर जब माउन्टबेटन ने रेडक्लिफ का फैसला नेताओं के हाथ में सौंपा तो सवेरे की खुशहाली पर उदासी की चादर पड़ गई। सरकारी भवन के कौंसिल-कक्ष में मन्त्रिमंडल की बैठक बुलाने के पूर्व उन्होंने फैसले का अध्ययन करने के लिए दो घंटों का समय दिया। लियाकत भी यहाँ मौजूद थे—और दरअसल माउन्टबेटन की यह बड़ी सफलता थी कि वह जिन्ना को इस बात के लिए राजी कर पाये कि पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री का पद संभालने के चौबीस घंटों बाद ही लियाकत अली दिल्ली की यात्रा करें। मन्त्रिमंडल की इस उदास और नाराजीभरी बैठक में मैं उपस्थित था। अगर इसमें किसी बात पर सहमति थी तो वह इस या उस साम्प्रदायिक 'अन्याय' की निंदा के विषय में थी। इससे माउन्टबेटन को काफी सामयिकता के साथ यह कहने का अवसर मिला कि चूंकि मजदूर रेडक्लिफ के फैसले में समान रूप से सतुष्ट नहीं है, इसलिए फैसले के उचित होने की सबसे असंदिग्ध कसौटी यही है कि सब उससे नाखुश हैं।

आनेवाली लम्बी और आवेशपूर्ण बहस का पहला सकेत हमें मिला। गुरदासपुर जिला पूर्वी पंजाब में शामिल किये जाने पर लियाकत को उतनी ही निराशा हुई जितनी चटगांव का पहाड़ी इलाका पूर्वी पाकिस्तान में मिलाये जाने पर पटेल को क्रोध। बलदेवसिंह की वेदना के आगे तो तीनों का रोप फीका पड़ गया। लेकिन किसी नेता ने पहले से बिना गर्त दिये गए इस वचन को भग नहीं किया कि फैसला चाहे जो हो, उसे अस्वीकार नहीं किया जायगा।

उधर हमारी बैठक हो रही थी उधर दोनों विभाजित प्रांतों से ऐसे समाचार आ रहे थे जो एक चेतावनी के साथ साहसपूर्ण नेतृत्व को चुनौती भी देते थे। पंजाब में लोगों ने कानून को ताक पर रखकर स्थिति अपने हाथ में ले ली थी। जिसे जेनकिन्स ने उत्तराधिकार का युद्ध कहा है, वह पांच नदियों के इस देश में पूरी वीभत्सता के साथ शुरू हो गया था। आज तीसरे पहर आचिन्लेक ने नेताओं को स्थिति के बारे में इतनी कटु और डरावनी रिपोर्ट दी कि नेताओं को अविलम्ब सीमा-फौज को मजबूत करने का फैसला करना पड़ा।

उधर कलकत्ता में, जहाँ इसी प्रकार की हिंसा का डर किसी प्रकार भी कम नहीं था, अपेक्षाकृत शांति है। हिंसा की घटनाएँ इक्की-दुक्की हैं। गांधीजी की उपस्थिति ने बंगाल के जख्म पर मरहम का काम किया है। वस्तु-स्थिति के औचित्य के बारे में अपने विवेक के अनुसार स्वाधीनता समारोह शुरू होने के पहले ही गांधीजी दिल्ली से चले गए थे। उनका विचार शायद यही था कि इन सरकारी उत्सवों में वह कोई मौजू भूमिका नहीं खेल सकेंगे और उनकी जरूरत पूरब की ज्यादा है। १३ तारीख को उन्होंने संयुक्त बंगाल के अन्तिम प्रधान मंत्री गहीद सुह्रावर्दी को, जो काफी रईसी तबियत के व्यक्ति हैं, न्योता दिया कि मुसलमान वस्ती के एक मामूली मकान में उनके साथ रहने आये और उनके सेवा-कार्य में हाथ बटाये। उसी रात हिन्दू

नौजवानों ने उनके मकान पर पत्थर फेंके। इसके उत्तर में गांधीजी ने कल के स्वाधीनता-दिवस को उपवास-दिवस के रूप में मनाया।

पंजाब की गंभीर स्थिति को देखते हुए नेहरू और लियाकत ने साथ-साथ तुरन्त अम्बाला जाने का निश्चय किया। अम्बाला से वे अमृतसर जायेंगे, जहाँ स्थिति का ठीक-ठीक मूल्यांकन कर तत्काल महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे।

आज रात अचानक मेरी मुलाकात उस फोटोग्राफर से हुई जिसे कल माउन्ट-बेटन ने कुचलने से बचाकर अपनी बग्गी में बैठा लिया था। वह एक चरम वामपंथी पत्र का प्रतिनिधि है। लेकिन अपने विचारों के बावजूद उसने मेरा हाथ झकझोरते हुए कहा, “दो सौ साल के बाद आखिर ब्रिटेन ने हिन्दुस्तान को जीत ही लिया।”

नई दिल्ली, बुधवार, २० अगस्त १९४७

भारी वर्षा के कारण कल हमारी बर्बड से दिल्ली की यात्रा कई घंटे पिछड़ गई और हम तीसरे पहर के बाद यहाँ पहुँचे। यहाँ हमने स्थिति की काफी गंभीर पाया है। नेहरू और लियाकत अम्बाला से अमृतसर गये, जहाँ पहुँचकर उन्होंने गति के लिए एक महत्वपूर्ण अपील निकाली। नेहरू ने एक रेडियो भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की सरकारें भारत और पाकिस्तान की सरकारों के पूरे सहयोग से इस वीभत्स कांड का अन्त करने पर कटिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “भारत कोई साम्प्रदायिक नहीं, धर्म-निरपेक्ष राज्य है, जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार हैं। सरकार इन अधिकारों की रक्षा करने पर अटल है।”

विस्थापितों की समस्या भी तूल पकड़नी जा रही है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग दो लाख व्यक्ति अस्थायी विस्थापित कैम्पों में भरे हुए हैं और ऐसी परिस्थितियों में रह रहे हैं कि किसी भी समय बड़े पैमाने पर हड़त को प्रकोप हो सकता है।

नई दिल्ली, सोमवार, २५ अगस्त १९४७

संयुक्त सुरक्षा-परिषद् की बैठक में पंजाब सीमा-सेना के भविष्य पर माउन्ट-बेटन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दोनों सरकारें चाहती हैं कि सीमा-फौज को राष्ट्रीय आधार पर विभाजित कर दिया जाय और उसके दोनों भाग अपने-अपने देश के प्रधान सेनापति के अधीन रहें। माउन्टबेटन इन जानकारी के साथ बैठक में गये थे कि यह कल्पना आधुनिक तथा रीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी। वह खुद भी उसके बिल्कुल विरोध में थे। उन्होंने पूरी बहस का संचालन ऐसी चतुरता से किया कि यह प्रश्न औपचारिक रूप से उठाया ही नहीं गया। किन्तु वह पाकिस्तानी वित्त-मंत्री और प्रतिनिधि बुन्दोहर को सीमा-फौज की गति-विधि के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कहने से रोकने में असमर्थ रहे।



माउन्टबेटन के लिए यह बिल्कुल असह्य था, क्योंकि वह जानते थे कि सीमा-फौज के मनोबल को बनाये रखने के लिए उसे नेताओं की शाबाशी और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अगर सीमा सेना को उचित सहारा नहीं मिला तो उसे हटाने के सिवा कोई चारा नहीं रह जायगा। इसके हटने से जो रक्तपात होगा उसकी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर होगी जो उसके भग किये जाते के दोषी है। एक बार उन्होंने चुन्द्रीगर को पितृतुल्य डाट बताते हुए कहा, “यदि आपके गवर्नर-जनरल आपको इस प्रकार बातें करते हुए सुनें तो वह जो कुछ कहेंगे उसकी कल्पना करना भी मुझे अप्रिय मालूम होता है।”

बैठक में सीमा-फौज के बारे में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। मैंने और वर्नॉन ने विज्ञप्ति का मसविदा तैयार किया। किंतु चुन्द्रीगर अड़ गए कि उसमें इस आशय का वाक्य होना चाहिए कि यदि सीमा-फौज ने अपना कर्तव्य पूरा न किया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायगी। दूसरी ओर, हम वर्तमान मसविदे के ही इस वाक्य को मुलायम करने का प्रयत्न कर रहे थे कि “कुछ अपवादों को छोड़ कर” सीमा-फौज बहुत अच्छा काम रही है।

काफी बहस के बाद इन कठोर शब्दों को निकालना तय पाया। इस पूरी घटना से यह साफ जाहिर है कि यदि दोनों सरकारें विद्रोह की स्थिति पैदा नहीं करना चाहती हैं तो उन्हें नाजुक काम में सलग्न अपनी सेनाओं के बारे में अपने रुख में भारी परिवर्तन करना पड़ेगा।

सरकारी भवन लौटने पर माउन्टबेटन ने हमें माकटन का एक तार दिखलाया। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं निजाम के वैधानिक परामर्शदाता के पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हो गया हूँ, हालांकि निजाम का विश्वास अबतक मुझ पर कायम है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अब सरकारी भवन में नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ गलत लगाया जा सकता है। इस समाचार से माउन्टबेटन को भारी चोट पहुँची। वह कह उठे, “हम डूब गए।”

सत्ता-हस्तांतरण के बाद भारत सरकार और हैदराबाद के बीच क्या सबब रहना चाहिए—इस सबब में जो कठिन बातचीत चल रही है, उसका बहुत कुछ दारोमदार जुलाई से ही माकटन के प्रभाव और निजाम के प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य के रूप में उनके उपलब्ध होने पर निर्भर रहा है।

अभी १२ अगस्त को ही माउन्टबेटन ने, समझौते का कोई लक्षण न देखकर निजाम को सूचित किया था कि उन्होंने निजाम के लिए स्वाधीनता-दिवस के बाद दो महीने की विशेष मोहलत मजूर करवा ली है। सरकार इस अवधि में हैदराबाद का संध-प्रवेश-पत्र स्वीकार करने को तैयार है। अतएव, वह इस सुअवसर का फायदा उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हालांकि अब वह ताज के प्रतिनिधि नहीं है, पर उन्हें भारत की ओर से बातचीत जारी रखने का अधिकार दे

दिया गया है। इस बीच, उन्होंने वरार के मध्य में, जो वैध रूप से निजाम-राज्य का अंग है, किन्तु अबतक मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रशासित होता रहा है, भारत से यथापूर्व स्थिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अन्त में उन्होंने वी पी मेनन से परामर्श करने के पश्चात् निजाम को यह महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिया था कि यदि निजाम वर्तमान परिस्थितियों में मध्य-प्रवेश न करने का निश्चय करे तो नई सरकार इसे शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं मानेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेताओं का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आर्थिक नाकेबन्दी करके कूटनीतिक दबाव डाला जाय।

हैदराबाद के प्रतिनिधिमण्डल के साथ आज बातचीत फिर शुरू होनी थी। माकटन का तार मिलने पर माउन्टबेटन ने वी पी मेनन को बुलाकर उनके साथ नई स्थिति पर विचार विमर्श किया। वर्नॉन और मै सीमा-फौज मंत्री विजयन्ति को ठिकाने लगाने के काम में लग गए। हमारे लौटने पर स्थिति में सुधार दिखलाई पड़ा। निजाम के पास से एक तार आया था। उसमें माउन्टबेटन से अनुरोध किया गया था कि वह निजाम की ओर से माकटन से मिले और उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए समझाए। निजाम ने स्वीकार किया था कि यदि माकटन इस सकट के समय चले गए तो उनके स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त करने में बहुत कठिनाई होगी।

माकटन तुरन्त आगे और उन्होंने बताया कि उनके त्यागपत्र देने का कारण उनके विरुद्ध राज्य के पत्रों का अतिशय उग्र आक्रमण है। इस आक्रमण का मगठन उग्र मुस्लिम मस्या इत्तिहादुल-मुसलमीन ने किया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण प्रधान मंत्री (नवाब छतारी) और वैधानिक मामलों के मंत्री ने भी त्यागपत्र दे दिया है। ये दोनों भी प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे। निजाम ने छतारी का त्यागपत्र स्वीकार करने में इन्कार कर दिया है। माकटन ने कहा कि यदि इत्तिहादुल-मुसलमीन रूप में अपना वक्तव्य वापस ले ले तो मैं भी अपना त्याग-पत्र वापस लेने को तैयार हूँ।

माकटन ने माउन्टबेटन को बताया कि उन्होंने निजाम को ऐसी सधि के लिए लगभग राजी कर लिया है जिसमें तीनों केंद्रीय विषयों, सुरक्षा, वित्तीय मामलों और संचार का समावेश हो जायगा। उन्होंने अपना यह विश्वास भी व्यक्त किया कि वह निजाम को 'मध्य-प्रवेश' के बराबर ही कोई दूसरी बात स्वीकार करने के लिए राजी कर लेंगे, वरन् कि 'मध्य-प्रवेश-पत्र' नाम को बदलकर 'मंत्री-सधि' जैसा कोई ऊपर ने मीठा लगाने वाला नाम रख दिया जाय। माउन्टबेटन ने उन्हें बताया कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिन पर पटेल लगभग अटल हैं। उनको भय है कि ऐसा करने में मध्य-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले अन्य राजा-महाराजा उन पर विश्वासघात का आरोप करेंगे। परन्तु माउन्टबेटन ने वचन दिया कि यदि माकटन मध्य-प्रवेश-पत्र के मूल तत्वों पर निजाम की स्वीकृति प्राप्त कर सकें, तो वह उन

पर भारत सरकार का समर्थन प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

आज यह समाचार भी मिला कि आखिर भोपाल नरेश भी भारत-संघ में शामिल हो गए हैं, भोपाल के नवाब को संघ-प्रवेश-पत्र की शत प्रकाशित होने के दिन से १० दिन की मोहलत दी गई थी। माउन्टबेटन ने कहा, "आजकल के दिन १५ अगस्त के पहले दिनों से कम तूफानी नहीं है।"

शिमला, शनिवार, ३० अगस्त १९४७

संयुक्त सुरक्षा-परिषद् की अध्यक्षता करने माउन्टबेटन कल लाहौर गये थे। जिन्ना को उसमें सदस्य के रूप में उपस्थित देखकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। काफी लम्बी-चौड़ी बहस के बाद सीमा-फौज को भग करने का फैसला किया गया। इतना बेजोड़ और कठिन काम करने के लिए पीट रीस का उचित आभार नहीं माना गया। दोनों देशों की सरकारों और समाचारपत्रों के समर्थन के अभाव में सीमा फौज और उसके कमांडर की स्थिति विचित्र हो गई। विश्वस्त और अनुभवी सेनाएं भी साम्प्रदायिक खिचावों को अपन सैनिक अनुशासन की अपेक्षा कहीं उग्रता से महसूस करने लगी।

पंजाब-सीमा-सेना के भग होने के साथ ही माउन्टबेटन के आखिरी शासकीय काम का अन्त हो गया है। उनका विचार है कि अब उन्हें अपने वैधानिक पद के अनुसार रोजाना के कामों से अलग हो जाना चाहिए। इसीलिए वह अब आराम के लिए शिमला आये हुए हैं।

शिमला, बृहस्पतिवार, ४ सितम्बर १९४७

आज तीसरे पहर माउन्टबेटन ने हमें बतलाया कि वी पी मेनन ने दिल्ली से फोन पर पटेल का यह आवश्यक सदेश दिया है कि माउन्टबेटन तुरन्त दिल्ली लौट आये। वी पी मेनन ने कहा कि नेहरू, पटेल और अन्य जिम्मेदार मंत्रियों का मत है कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि माउन्टबेटन की उपस्थिति ही उसे सभाल सकती है।

कल सवेरे हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

सकटकालीन कमेटी की पहली बैठक आज शाम को पांच बजे सरकारी भवन के कौंसिल कक्ष में हुई और दो घंटे तक चली। कमेटी की कार्यवाही गुरु करते हुए नेहरू ने माउन्टबेटन से कहा, “आपकी सलाह में इमी शर्त पर मान सकता हूँ कि आप अध्यक्षपद सभाले।” यह सुझाव माउन्टबेटन ने एक दूसरी शर्त पर स्वीकार कर लिया—वह यह कि इस बात को गुप्त रखा जायगा।

तय हुआ कि कमेटी में केवल कुछ मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग ही शामिल हों। जैसे—प्रधान सेनापति, सर्वोच्च-सेनापति के प्रतिनिधि, दिल्ली के चीफ कमिश्नर, पुलिस विभाग के अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन विभाग के डाइरेक्टर-जनरल और चिकित्सा तथा रेलवे विभाग के प्रतिनिधि। अन्य लोगों को जरूरत के अनुसार विगेष निमंत्रण पर बुलाया जा सकता था। नेहरू और पटेल कमेटी के स्थायी सदस्य होंगे। इनके अलावा यह मंत्री भी कमेटी में मिल जायेंगे बलदेव-सिंह (सुरक्षा), मथाई (रेलवे) और नियोगी (नव-निर्मित विस्थापित विभाग)। कुल मिलाकर पन्द्रह लोगों ने प्रारम्भिक बैठक में भाग लिया।

कमेटी का विधान तय होते ही हमने तुरन्त “अत्यन्त आवश्यक” प्रश्नों पर विचार शुरू कर दिया। विस्थापित मंत्रालय की स्थापना अभी नहीं हो पाई थी। कमेटी कल सवेरे तक यह जानना चाहेगी कि इस मंत्रालय के सेक्रेटरी पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद कमेटी ने इस विभाग के लिए जगह दिये जाने के कठिन और आवश्यक प्रश्न पर विचार किया। सकटकालीन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच संपर्क साधने का काम इस्मे को सौंपा गया।

‘मार्शल-ला’ लगाये जाने के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। माउन्टबेटन का विचार था कि पंजाब की स्थिति ‘मार्शल-ला’ लगाये जाने के अनुकूल है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब चारों सवधित सरकारें इसमें सहमत हों। लेकिन यह सभावना विलकुल असंभव होने के कारण कमेटी ने आदेश दिया कि पूर्वी पंजाब में लागू कानूनों को कड़ा करने की सभावनाओं और तरीकों पर अविलम्ब विचार किया जाय। कुल मिलाकर बारह प्रश्नों का निवटारा किया गया—लेडी माउन्टबेटन के अधीन रिलीफ कमेटी की स्थापना के प्रश्न से लेकर शाही हवाई बेंडे के यातायात के नियंत्रण और इन्तिहार गिराये जाने के प्रश्न तक। जब बैठक खत्म हुई तो सब लोग पस्त-थे।

कल की बैठक में पूर्वी पंजाब के गवर्नर त्रिवेदी, उनके प्रधानमंत्री गोपीचन्द भार्गव और गृह-मंत्री स्वर्णमिह भी भाग लेंगे।

कलक्ता से गांधीजी के ‘चमत्कार’ का समाचार आया है। सुहरावर्दी के साथ उनकी साझेदारी का अपेक्षित फल नहीं हुआ। डक्की-डुक्की हत्याएं और हिंसा जारी रही। इसलिए उन्होंने सोमवार से उपवास शुरू किया, जो नगर में शान्ति स्थापित होने पर ही खत्म होगा। बृहस्पतिवार को जब विभिन्न सम्प्रदायों

सकटकालीन कमेटी की पहली बैठक आज शाम को पांच बजे सरकारी भवन के कौंसिल कक्ष में हुई और दो घंटे तक चली। कमेटी की कार्यवाही गुरु करते हुए नेहरू ने माउन्टबेटन से कहा, “आपकी सलाह मैं इसी शर्त पर मान सकता हूँ कि आप अध्यक्षपद सभालें।” यह सुझाव माउन्टबेटन ने एक दूसरी शर्त पर स्वीकार कर लिया—वह यह कि इस बात को गुप्त रखा जायगा।

तय हुआ कि कमेटी में केवल कुछ मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण लोग ही शामिल हों। जैसे—प्रधान सेनापति, सर्वोच्च-सेनापति के प्रतिनिधि, दिल्ली के चीफ कमिश्नर, पुलिस विभाग के अध्यक्ष, नागरिक उड्डयन विभाग के डाइरेक्टर-जनरल और चिकित्सा तथा रेलवे विभाग के प्रतिनिधि। अन्य लोगों को जरूरत के अनुसार विशेष निमंत्रण पर बुलाया जा सकता था। नेहरू और पटेल कमेटी के स्थायी सदस्य होंगे। इनके अलावा यह मंत्री भी कमेटी में मिल जायेंगे बलदेव-सिंह (सुरक्षा), मथाई (रेलवे) और नियोगी (नव-निर्मित विस्थापित विभाग)। कुल मिलाकर पन्द्रह लोगों ने प्रारम्भिक बैठक में भाग लिया।

कमेटी का विधान तय होते ही हमने तुरन्त “अत्यन्त आवश्यक” प्रश्नों पर विचार शुरू कर दिया। विस्थापित मंत्रालय की स्थापना अभी नहीं हो पाई थी। कमेटी कल सवेरे तक यह जानना चाहेगी कि इस मंत्रालय के सेक्रेटरी पद पर किसे नियुक्त किया जा रहा है। इसके बाद कमेटी ने इस विभाग के लिए जगह दिये जाने के कठिन और आवश्यक प्रश्न पर विचार किया। सकटकालीन कमेटी और पाकिस्तान सरकार के बीच संपर्क साधने का काम इसमें को सौंपा गया।

‘मार्शल-ला’ लगाये जाने के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। माउन्टबेटन का विचार था कि पंजाब की स्थिति ‘मार्शल-ला’ लगाये जाने के अनुकूल है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब चारों संबंधित सरकारें इसमें सहमत हों। लेकिन यह सम्भावना बिल्कुल असंभव होने के कारण कमेटी ने आदेश दिया कि पूर्वी पंजाब में लागू कानूनों को कड़ा करने की सम्भावनाओं और तरीकों पर अविलम्ब विचार किया जाय। कुल मिलाकर बारह प्रश्नों का निवटारा किया गया—लेडी माउन्टबेटन के अधीन रिलीफ कमेटी की स्थापना के प्रश्न से लेकर शाही हवाई बंदे के यातायात के नियंत्रण और इंग्रितहार गिराये जाने के प्रश्न तक। जब बैठक खत्म हुई तो सब लोग पस्त-थे।

कल की बैठक में पूर्वी पंजाब के गवर्नर त्रिवेदी, उनके प्रधानमंत्री गोपीचन्द भार्गव और गृह-मंत्री स्वर्णमिह भी भाग लेंगे।

कलकत्ता से गांधीजी के ‘चमत्कार’ का समाचार आया है। सुहरावर्दी के साथ उनकी साझेदारी का अपेक्षित फल नहीं हुआ। डक्की-डक्की हत्याएं और हिंसा जारी रही। इसलिए उन्होंने सोमवार से उपवास शुरू किया, जो नगर में आन्ति स्थापित होने पर ही खत्म होगा। वृहस्पतिवार को जब विभिन्न सम्प्रदायों

के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि महात्माजी की हृदय-परिवर्तन की अपील का जनता पर उचित असर हुआ है, तो गांधीजी ने अपना उपवास खत्म कर दिया।

गांधीजी की प्रार्थना सभा के बाद हिन्दू और मुसलमान बड़ी सख्या में एक-दूसरे के गले मिले। मजे हुए पत्र-सम्वाददाताओं का कहना था कि सामूहिक प्रभाव का ऐसा बेजोड़ दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। माउन्टबेटन का अनुमान था कि जो चीज गांधीजी ने केवल आत्मिक-बल से प्राप्त कर ली है, उसे चार फौजी डिवीजन भी बल-प्रयोग में हासिल नहीं कर सकते थे।

नई दिल्ली, रविवार, ७ सितम्बर १९४७

हमारी बैठक ग्यारह बजे प्रारम्भ हुई, लेकिन त्रिवेदी और पूर्वी पंजाब के मंत्री-गण ठीक समय पर उपस्थित नहीं हुए। बैठक शुरू करते हुए माउन्टबेटन ने कहा कि गत चौबीस घंटे में दिल्ली की स्थिति काफी बिगड़ गई है। काफी हिंसा की घटनाएँ घटी हैं। यहाँ तक कि सरकारी भवन के इलाके तक में छुरे-बाजी हुई है। विस्थापित लोग भारी सख्या में आ रहे हैं और उनका प्रवचन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद उन्होंने हर प्रकार के हथियार रखने के ऊपर पाबंदी लगाने के प्रश्न की बात छोड़ी। इससे मिखो द्वारा बाधे जानेवाले कृपाण का नवाल अपने-आप उठ खड़ा हुआ। पटेल महसूस करते थे कि कृपाण पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाने में बड़ी कठिनाईयाँ उठ खड़ी होंगी, क्योंकि काफी वर्षों में सरकार कृपाण को धार्मिक हथियार मानती आई है। माउन्टबेटन ने कहा कि मिखो को कृपाण बाधने का आम अधिकार दिया जाना न्याय और व्यवस्था के लिए कार्रवाई करने में बाधक बन रहा है। लेकिन उन्होंने मंजूर किया कि वृन्ध्यादी नवाल यह है कि किन निर्णय में कम लोगों की हत्या होगी—कृपाण पर बन्दिता लगाने में या मिखों की धार्मिक भावना को रक्षा करने में ?

को देखते हुए दृढ़ता और ठड़े दिमाग के साथ काम किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। विलिंगडन हवाई अड्डे पर कल्लेआम होने का समाचार आया। सिखों ने आस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और अमरीकी राजदूत को धमकी भरे पत्र भेजे थे। माउन्टबेटन ने बैठक में चेतावनी दी कि कूटनीतिक प्रतिनिधियों की जान-माल की हिफाजत करने के प्रश्न पर भारत की इज्जत की वाजी लगी हुई है।

नई दिल्ली, सोमवार, ८ दिसम्बर १९४७

शाम को निजाम के प्रधान-मंत्री नवाब छतारी से मेरी लम्बी बातचीत हुई। वह निजाम के प्रति वफादार तो रहना चाहते हैं, परन्तु उन्हें जो विविध हुकम मिलते रहते हैं, उनका मतलब समझने में उन्हें कठिनाई होती है। स्पष्ट है कि उनका कार्य-काल और प्रभाव बहुत दिन न रहेगा। उन्होंने और माकटन ने—जो सरकारी भवन में ठहरे हुए थे—आज माउन्टबेटन से भी भेट की।

दिल्ली की मौजूदा सकट पूर्ण स्थिति के कारण हैदराबाद की समस्या कम आवश्यक मालूम पड़ती है। इससे माउन्टबेटन सोचते हैं कि 'सघ-प्रवेग' के नाम में परिवर्तन करने के लिए यह समय मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अनुकूल है। उधर, हैदराबाद में, माकटन की नौकरी कायम रखने की इच्छा के प्रमाणस्वरूप निजाम ने एक सप्ताह पूर्व जोरदार फर्मान निकाल दिया था। उसमें उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के विरुद्ध किये गए आक्रमण को राज्य के हितों के विरुद्ध बताकर उसकी कड़ी निन्दा की थी। माउन्टबेटन को लिखे पत्रों में भी उन्होंने इसकी चर्चा की और माकटन पर अपना विश्वास जाहिर किया। उन्होंने इतिहाद, और विशेषतः उसके धर्माध्यक्ष कासिम रिजवी, की प्रवृत्तियों की स्पष्ट भाषा में निन्दा की।

निजाम काफी झिझकते हुए समझाते की ओर बढ़ रहे हैं। परन्तु इस समय काग्रेसी गुप्तचर विभाग ने, जो कि रियासती मामलों की बहुत अच्छी जानकारी रखता है, निजाम सरकार के चेकोस्लोवाकिया से गस्त्रास्त्र मगाने और पृथक् प्रभुसत्ता स्थापित करने के प्रयत्नों के चितनीय समाचार प्राप्त किये हैं। तथापि छतारी भली-भाँति जानते हैं कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई हैदराबाद तथा भारत दोनों के लिए घातक होगी। आज की बैठक में दोनों पक्षों में गतिरोध को दूर करने की सच्ची इच्छा दिखलाई पड़ी। यह स्वीकार कर लिया गया कि शायद बातचीत में हिस्सा लेने वाले दोनों पक्षों के प्रमुख नेता पहले प्रयत्न में किसी सूत्र पर सहमत न हो सकेंगे। इस खयाल से यह निश्चय किया गया कि माकटन और छतारी हैदराबाद जाकर मतभेद को कम करने की फिर कोशिश करें।

नई दिल्ली, मंगलवार, ९ सितम्बर १९४७

आज माउन्टवेटन गांधीजी से मिले। गांधीजी अपने कलकत्ता के चमत्कारों के बाद अभी-अभी दिल्ली पहुँचे हैं। अपनी कलकत्ता की सफलताओं के बारे में गांधीजी बहुत विनम्र हैं, और उसे विशेष महत्व नहीं देते। उन्होंने माउन्टवेटन से कहा कि अब सरकारी भवन के बारे में उनका मत बदल गया है। विदेशी और झूठी सत्ता का प्रतीक कह कर अबतक वह इसकी निंदा करते आये थे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि "आपदाओं के सागर में वह निरापद द्वीप" का काम कर रहा है।

सकटकालीन कमेटी की मवेरे की बैठक में पेगावर तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश (जो अब पाकिस्तान आ गये हैं) की गंभीर स्थिति के बारे में रिपोर्टों पर विचार किया गया। इन रिपोर्टों की तात्कालिक प्रतिक्रिया यह है कि रिपोर्टें सही हैं।

: १६ :

## जूनागढ़ का संकट

नई दिल्ली, रविवार, १४ सितम्बर १९४७

माउन्टवेटन ने आज कर्मचारी-मंडल की जो बैठक की, उसमें मुख्यतः पुराने तिले की स्थिति पर विचार हुआ। पटेल कभी-कभी नय कर चुके हैं कि मुल्क-मानों ने हथियार छीनने के लिए एक ब्रिटिश नौसेना भेजी जाय। माउन्टवेटन का कहना है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई विनाशकारी होगी और कलह-आम भड़का देगी।



नान-कमीगण्ड अफसर और सैनिक विस्थापितों के गिविरो का संगठन करने में मदद करें। उनकी यह सहायता उपयोगी सिद्ध हुई और उसमें ब्रिटिश-प्रतिष्ठा भी बढ़ी। उन्हें आशा है कि तीन-चार सप्ताह में वह संकटकालीन कमेटी की अध्यक्षता नेहरू को सौंप कर उसके कार्य से मुक्त हो जायेंगे। अब वह मानते हैं कि १५ अगस्त को भारत न छोड़ कर उन्होंने अच्छा ही किया।

इसमें कराची में लौट आये हैं। उनका खयाल है कि इस समय उनका कराची जाना बहुत ठीक हुआ। उन्होंने पाया कि जिन्ना भारत-सरकार पर से अपना विस्वाम उठाने के बारे में कसमें खा रहे हैं और भारत से कूटनीतिक मन्त्र तोड़ देने पर उतारू हैं। इसमें अडतालीस घंटे कराची में रहे, जिनमें से ग्यारह घंटे उन्होंने जिन्ना के साथ बातें करने में बिताये। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिन्ना का विस्वाम पा लिया है। जिन्ना ने उनके मुह पर ही उन्हें "सज्जन व्यक्ति" कहते हुए उनकी प्रशंसा की।

साफ जाहिर है कि जिन्ना कांग्रेस के विरुद्ध क्रोध से उबल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इन आदमियों के द्वेष को कभी समझ नहीं सकता। युद्ध ठान कर निबटने के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आता।

इसमें ने बतलाया कि वह जिन्ना के साथ भिड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं अतिशयोक्ति करने का अभ्यस्त नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने प्राणों को गंत लगाकर कह सकता हूँ कि भारत-सरकार पूरी शक्ति के साथ दंगों को दवाने के लिए कमर कमें है। वे सब सच्चे आदमी हैं और पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें का खयाल है कि उन्होंने जिन्ना को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया।

नई दिल्ली, सोमवार, १५ सितम्बर १९४७

कमचारी-मंडल की आज की बैठक में इसमें की कराची-यात्रा से पैदा हुई आम स्थिति पर विचार किया गया। माउन्टबेटन का विश्लेषण यह था कि हिन्दू और मुसलमान तो समान अनुपात में अपनी-अपनी सरकारों के वश में हैं किन्तु सिख कानून के बाहर हैं और अब उनके नेता भी उनमें डरने लगे हैं। बी. पी. मेनन का खयाल है कि निकट भविष्य में भारत तथा पाकिस्तान के बीच कोई शांति नहीं हो सकती। ऐसी दशा में माउन्टबेटन को दोनों उपनिवेशों के बीच युद्ध की आशंका दृष्टिगोचर होती है। वह कहते हैं कि हमें युद्ध से जितनी दूर हो सके, रहना चाहिए। परन्तु बी. पी. मेनन मानते हैं कि जिन्ना के वर्तमान रव में यह आशा भी पूर्ण नहीं हो सकती।

माउन्टबेटन ने सिखों के उद्देश्य के बारे में पूछा। क्या उनका उद्देश्य सिख-राज्य कायम करना है? बी. पी. मेनन ने उत्तर दिया कि नहीं, राजनीतिक

मे आम छुट्टी मनाई गई थी ।

जूनागढ़ के बारे में यह सब गड़बड़ी फैली कैसे ? २५ जुलाई को माउन्टबेटन के साथ राजाओं की जो मुलाकात हुई थी, उसमें जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान ने बहुत से प्रश्न पूछे थे । उनमें किसी में जूनागढ़ के पाकिस्तान प्रवेश के इरादे का संकेत नहीं मिला था । दीवान ने तो यहां तक कहा था कि वह नवाब को भारत के साथ रहने की सलाह देगा । जूनागढ़ की सरकार ने घोषणा की थी कि जूनागढ़ काठियावाड़ की अन्य रियासतों के साथ रहेगा । ये सभी रियासतें भारत-संघ में शामिल हो गई हैं । परन्तु, सत्ता-हस्तांतरण के केवल ५ दिन पहले—१० अगस्त को—वहां तख्ता पलट गया । सिंधी मुसलमानों के एक गुट ने शासन पर अधिकार कर लिया । शाह नवाज भुट्टो दीवान बन गए और नवाब अपने ही महल में बन्दी बना दिया गया ।

यह मुक्त रूप से माना जाता है कि संघ-प्रवेश राजाओं के विशेष अधिकार की बात है । लेकिन भारत सरकार ने यह भी कह दिया था कि संघ-प्रवेश की अन्तिम तारीख १५ अगस्त होगी । माउन्टबेटन ने २५ जुलाई को राजाओं से जो अपील की थी उसका आधार भी यही था । माउन्टबेटन के उस भाषण से दो तत्व और भी निकले थे । संघ-प्रवेश का निर्णय करने में जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना गया था, उनमें से एक तो, माउन्टबेटन के ही शब्दों में था, “भौगोलिक विवशताएँ, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।” दूसरा प्रजा में किस धर्म वाले लोगों का बहुमत है ।

यद्यपि जूनागढ़ के पास समुद्र-तट भी है, एक छोटा-सा बन्दरगाह, वेरावल भी, और वह कराची के साथ सीधी पहुँच का दावा भी कर सकता है, फिर भी स्पष्ट है कि उसका पाकिस्तान-संघ में शामिल होना पूरी संघ-प्रवेश-नीति की बुनियादी वैधानिकता को एक सीधी चुनौती होगी । काठियावाड़ के राज्यों और हैदराबाद की वार्ताओं पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा । हैदराबाद के उग्र-पथी मुसलमानों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । जिन्ना ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जूनागढ़ के अलग रह जाने की भूल का भारी फायदा उठाया जा सकता है । भारत-सरकार ने जूनागढ़ पर भारत में शामिल होने के लिए कोई दबाव नहीं डाला । परन्तु जब जूनागढ़ के पाकिस्तान में प्रवेश करने के लक्षण दिखलाई पड़े तो भारत-सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दो बार अनुरोध किया कि वह अपने इरादों का साफ-साफ ऐलान करे लेकिन इनका, अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

माउन्टबेटन ने मुझे उन बैठकों में बुलाया, जो वह जूनागढ़ के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए इसमें और वी पी मेनन के साथ कर रहे हैं । वी पी बहुत चिन्तित हैं । उन्होंने माउन्टबेटन को समझाने का प्रयत्न किया कि फीजी और

मे आम छुट्टी मनाई गई थी ।

जूनागढ़ के बारे में यह सब गड़बड़ी फैली कैसे ? २५ जुलाई को माउन्टबेटन के साथ राजाओं की जो मुलाकात हुई थी, उसमें जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान ने बहुत से प्रश्न पूछे थे । उनमें किसी में जूनागढ़ के पाकिस्तान प्रवेश के इरादे का संकेत नहीं मिला था । दीवान ने तो यहां तक कहा था कि वह नवाब को भारत के साथ रहने की सलाह देगा । जूनागढ़ की सरकार ने घोषणा की थी कि जूनागढ़ काठियावाड़ की अन्य रियासतों के साथ रहेगा । ये सभी रियासतें भारत-संघ में शामिल हो गई हैं । परन्तु, सत्ता-हस्तांतरण के केवल ५ दिन पहले—१० अगस्त को—वहां तख्ता पलट गया । सिंधी मुसलमानों के एक गुट ने शासन पर अधिकार कर लिया । शाह नवाज भुट्टो दीवान बन गए और नवाब अपने ही महल में बन्दी बना दिया गया ।

यह मुक्त रूप से माना जाता है कि संघ-प्रवेश राजाओं के विशेष अधिकार की बात है । लेकिन भारत सरकार ने यह भी कह दिया था कि संघ-प्रवेश की अन्तिम तारीख १५ अगस्त होगी । माउन्टबेटन ने २५ जुलाई को राजाओं से जो अपील की थी उसका आधार भी यही था । माउन्टबेटन के उस भाषण से दो तत्व और भी निकले थे । संघ-प्रवेश का निर्णय करने में जिनका ध्यान रखना आवश्यक माना गया था, उनमें से एक तो, माउन्टबेटन के ही शब्दों में था, “भौगोलिक विवशताएं, जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।” दूसरा प्रजा में किस धर्म वाले लोगों का बहुमत है ।

यद्यपि जूनागढ़ के पास समुद्र-तट भी है, एक छोटा-सा बन्दरगाह, वेरावल भी, और वह कराची के साथ सीधी पहुंच का दावा भी कर सकता है, फिर भी स्पष्ट है कि उसका पाकिस्तान-संघ में शामिल होना पूरी संघ-प्रवेश-नीति की बुनियादी वैधानिकता को एक सीधी चुनौती होगी । काठियावाड़ के राज्यों और हैदराबाद की वातावरणों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा । हैदराबाद के उग्र-पथी मुसलमानों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । जिन्ना ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जूनागढ़ के अलग रह जाने की भूल का भारी फायदा उठाया जा सकता है । भारत-सरकार ने जूनागढ़ पर भारत में शामिल होने के लिए कोई दवाव नहीं डाला । परन्तु जब जूनागढ़ के पाकिस्तान में प्रवेश करने के लक्षण दिखलाई पड़े तो भारत-सरकार ने पाकिस्तान सरकार से दो बार अनुरोध किया कि वह अपने इरादों का साफ-साफ ऐलान करे लेकिन इनका, अब तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

माउन्टबेटन ने मुझे उन बैठकों में बुलाया, जो वह जूनागढ़ के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए इसमें और वी पी मेनन के साथ कर रहे हैं । वी पी बहुत चिन्तित हैं । उन्होंने माउन्टबेटन को समझाने का प्रयत्न किया कि फौजी और

नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करना आवश्यक था। उन्होंने यह मानकर एक वक्तव्य तैयार किया कि पाकिस्तान जूनागढ को धन-जन से सहायता करने को तैयार था।

ग्राम को मैं इसमें से मिलने उनके निवास-स्थान पर गया। मैंने पाया कि जूनागढ के प्रश्न से जो वैवैनी का वातावरण उत्पन्न हो गया था उससे उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। उनका खयाल था कि पाकिस्तान के वर्तमान साधनों और दायित्वों को देखते हुए यह समाचार मूर्खतापूर्ण मालूम होता था कि वह जूनागढ में हस्तक्षेप करेगा और उसने जूनागढ के बन्दरगाह के विकास के लिए आठ करोड़ रुपये का ऋण देने तथा उसकी सहायता के लिए २५,००० सेना भेजने का वचन दिया है।

नई दिल्ली, मंगलवार, १६ सितम्बर १९४७

हमें सूचना मिली कि जूनागढ के सघ-प्रवेग-पत्र पर हस्ताक्षर हो गए हैं और सील-सिक्का लगाकर उसे कराची भेज दिया गया है। परन्तु यह बात अभी तक सरकारी तौर पर पक्की नहीं हुई है। बी पी और माउन्टबेटन को दुबारा बातचीत के समय मैं उपस्थित था। इसमें ने जूनागढ के सम्बन्ध में जिन्ना की संभावित चालों पर बड़े तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। प्रत्यक्ष रूप में जूनागढ जिन्ना के लिए बेकार है। सैनिक दृष्टि से वह एक असह्य भार होगा। जहातक बुद्धि काम करती है जिन्ना की नीति इधर-उधर बिखरे हुए मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्रों को मिलाने की नहीं है, क्योंकि अभी भारत के अन्दर चार करोड़ मुसलमान मौजूद हैं।

इसमें का खयाल था कि जिन्ना की इस कार्रवाई का मूल उद्देश्य भारत को चक्कर में डालकर परेशान करना था। उन्हें आशा थी कि भारत को युद्ध में फंसा कर वह कानूनी मुद्दों पर अपने पक्ष में फैसले करवा लेगे। इसका उपयोग वे काश्मीर और हैदरावाद की बड़ी रियासतों पर अपन दात लगान में कर सकेंगे। कुछ हद तक जूनागढ हैदरावाद का एक छोटा रूप ही है। उसका नवाब मुसलमान है, किन्तु प्रजा अधिकांशतः हिन्दू। राज्य भी भारतीय प्रदेश के अन्दर है।

मैंने विज्ञप्ति का मसविदा तैयार कर लिया। कागजी तौर पर भारतीय पक्ष काफी मजबूत दिखलाई पड़ता था। परन्तु जहाँ तक पत्रों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध था मुझे यह चेतावनी देनी पड़ी “हालांकि उपरोक्त तर्क खुद में काफी सबल हैं, फिर भी इस समय मैं निक कार्रवाई करने से विदेशी पत्रों की प्रतिक्रिया बहुत हानिकारक होगी। किपी भी सैनिक कार्रवाई को आक्रमण-मूलक माना जायगा। विदेशी पत्र दोनों देशों की सैनिक कार्रवाइयों के बारे में बहुत सजग हैं।” मैंने सुझाव दिया कि अभी केवल यह घोषणा कर दी जाय कि जूनागढ का पाकिस्तान-प्रवेग हमें मान्य नहीं है और भविष्य में कोई भी कार्रवाई करने का हमारा अधिकार सुरक्षित

है। बातचीत के लिए भी गुजाइश छोड़ दी जाय।

नई दिल्ली, बुधवार, १७ सितम्बर १९४७

आज तीसरे पहर जूनागढ़ के बारे में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक के पहले माउन्टबेटन ने नेहरू और पटेल दोनों के साथ लम्बी बातचीत की। उन्होंने दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि हमें कोई ऐंगी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे ससार हमारी ओर अगुली उठा सके। हमें उस प्रदेश के विरुद्ध, जो अब पाकिस्तान का हो चुका है, युद्ध का निश्चय भी नहीं करना चाहिए।

उन्होंने इस्में के इस मत को दोहराया कि जिन्ना की यह सारी कार्रवाई एक जाल है। यह सब उनकी बृहत्तर योजना का अंग है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को ससार की दृष्टि में निर्दोष तथा असहाय राष्ट्र के रूप में पेश करना है, जिसपर भारतीय-आक्रमण का खतरा झूल रहा है। उन्होंने जोर दिया कि भारत जनमत-संग्रह के सिद्धान्त पर दृढ़ रहे जिसमें जनता की इच्छा भी मालूम की जा सके और हमला करके इलाके पर दखल करने के प्रश्न का भी अंत हो जाय।

माउन्टबेटन को नेहरू को सहमत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु पटेल को समझाने में समय लगा। जूनागढ़ ने पटेल की सारी सध-प्रवेश नीति और व्यक्तिगत भावनाओं पर भारी असर किया है। परन्तु माउन्टबेटन के तर्क और जिन्ना की मनोभावनाओं और इरादों के बारे में इस्में के मत वह भी मान गए। मंत्रि-मंडल की बैठक में जाकर उन्होंने अपना नया दृष्टिकोण सामने रखा। इससे उनके साथियों को अचम्भा तो जरूर हुआ होगा लेकिन अपने साथियों को समझाने में उन्हें मुश्किल नहीं हुई। बैठक में यह दो निर्णय किये गए एक—भारत की फौजे और सध में शामिल होने वाली रियासतों की स्थानीय फौजे जूनागढ़ की सीमा पर तैनात कर दी जाय। लेकिन वे जूनागढ़ पर दखल न करें। दो—वी पी मेनन जूनागढ़ जाकर नवाब और दीवान को बतलाये कि उनके पाकिस्तान में शामिल होने के क्या नतीजे होंगे।

लेकिन पहले की ये घटनाएँ बहुधा किसी एक ही सम्प्रदाय तक सीमित होती थीं और साथ ही यह आशा भी बनी रहती थी कि किसी-न-किसी दिन ये निष्क्रमणार्थी फिर अपने घरों को वापिस लौटेंगे। लेकिन आज बात दूसरी थी। इन निष्क्रमणार्थियों की सख्या पहले से कहीं विशाल थी और इस बार उनका लौटना कदापि न होगा।

निष्क्रमणार्थियों के काफिले की पहली झलक हमने फिरोजपुर और बुलाकी-हेड के बीच देखी थी। इसका पीछा करते हुए हम रावी पार बहुत दूर तक उड़े। विस्थापितों के इस प्रवाह के साथ लगभग पचास मील आगे तक गये किन्तु इसका छोर न मिला। बीच-बीच में बैलगाड़ियों और पैदल चलनेवाले परिवारों की सख्या बिल्कुल इनी-गिनी रह जाती थी, लेकिन जरा आगे बढ़ते ही फिर घनी अटूट कतारें नजर आने लगती।

बुलाकी हेड में, जो वास्तविक सीमा है, पुल पार करने की प्रतीक्षा करनेवाले विस्थापितों की अपार भीड़ थी और ऐसा लगता था मानो जबरदस्ती जमीन पर दखल करने वालों की वस्ती हो। यहाँ उनका चलना बिल्कुल रुक गया था, लेकिन वैसे भी उनकी गति बहुत धीमी थी। कुछ घुड़सवार हमें दिखाई पड़ रहे थे जो इधर-उधर घूमते हुए अपार जन-समूह को किसी प्रकार के आदेश दे रहे थे। सड़क के किनारे कुछ परिवार अपने जानवरों को लिये खड़े थे। कुछ लोगों की एकमात्र दौलत यह जानवर ही थे। लेकिन इनमें शायद ही कोई जानवर पुल पार कर सके। क्योंकि पुल पर इतनी भीड़ थी कि जो कि उसकी शक्ति से बाहर की थी।

भारत में दाखिल होने पर लायलपुर-लाहौर सड़क पर धीमी गति से आगे बढ़ने वाले मुसलमान विस्थापितों का काफिला देखा। अमृतसर शहर को बचाकर निकलने के लिए उन्हें बहुत लम्बा चक्कर खाना पड़ा था। हमने यह अनुमान लगाया कि इस काफिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ने में हमें पन्द्रह मिनट से भी अधिक लगे जबकि हमारे विमान की गति लगभग एक सौ अस्सी मील प्रति घंटा थी। इस प्रकार यह काफिला कम-से-कम पैतालीस मील लम्बा रहा होगा।

गत रविवार को हुए सम्मेलन में नेहरू और लियाकत ने कहा था कि शुरू-शुरू में वे आवादियों के सामूहिक परिवर्तन के कितने खिलाफ थे। लेकिन बाद में स्थिति उनके बूते के बाहर हो गई।

नई दिल्ली, सोमवार, २९ सितंबर १९४७

माउन्टबेटन का सारा दिन जूनागढ़ तथा पंजाब सव्धी नीति पर विचार करने वाली बैठकों में बीता। जूनागढ़ का सकट उत्तरोत्तर शतरज की बड़ी जटिल बाजी

लेकिन पहले की ये घटनाएँ बहुधा किसी एक ही सम्प्रदाय तक सीमित होती थीं और साथ ही यह आशा भी बनी रहती थी कि किसी-न-किसी दिन ये निष्क्रमणार्थी फिर अपने घरों को वापिस लौटेंगे। लेकिन आज बात दूसरी थी। इन निष्क्रमणार्थियों की सख्या पहले से कहीं विशाल थी और इस बार उनका लौटना कदापि न होगा।

निष्क्रमणार्थियों के काफिले की पहली झलक हमने फिरोजपुर और बुलाकी-हेड के बीच देखी थी। इसका पीछा करते हुए हम रावी पार बहुत दूर तक उड़े। विस्थापितों के इस प्रवाह के साथ लगभग पचास मील आगे तक गये किन्तु इसका छोर न मिला। बीच-बीच में बैलगाड़ियों और पैदल चलनेवाले परिवारों की सख्या बिल्कुल इनी-गिनी रह जाती थी, लेकिन जरा आगे बढ़ते ही फिर घनी अटूट कतारें नजर आने लगती।

बुलाकी हेड में, जो वास्तविक सीमा है, पुल पार करने की प्रतीक्षा करनेवाले विस्थापितों की अपार भीड़ थी और ऐसा लगता था मानो जबरदस्ती जमीन पर दखल करने वालों की वस्ती हो। यहाँ उनका चलना बिल्कुल रुक गया था, लेकिन वैसे भी उनकी गति बहुत धीमी थी। कुछ घुड़सवार हमें दिखाई पड़ रहे थे जो इधर-उधर घूमते हुए अपार जन-समूह को किसी प्रकार के आदेश दे रहे थे। सड़क के किनारे कुछ परिवार अपने जानवरों को लिये खड़े थे। कुछ लोगों की एकमात्र दौलत यह जानवर ही थे। लेकिन इनमें शायद ही कोई जानवर पुल पार कर सके। क्योंकि पुल पर इतनी भीड़ थी कि जो कि उसकी शक्ति से बाहर की थी।

भारत में दाखिल होने पर लायलपुर-लाहौर सड़क पर धीमी गति से आगे बढ़ने वाले मुसलमान विस्थापितों का काफिला देखा। अमृतसर शहर को बचाकर निकलने के लिए उन्हें बहुत लम्बा चक्कर खाना पड़ा था। हमने यह अनुमान लगाया कि इस काफिले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उड़ने में हमें पन्द्रह मिनट से भी अधिक लगे जबकि हमारे विमान की गति लगभग एक सौ अस्सी मील प्रति घंटा थी। इस प्रकार यह काफिला कम-से-कम पैंतालीस मील लम्बा रहा होगा।

गत रविवार को हुए सम्मेलन में नेहरू और लियाकत ने कहा था कि शुरू-शुरू में वे आवादियों के सामूहिक परिवर्तन के कितने खिलाफ थे। लेकिन बाद में स्थिति उनके बूते के बाहर हो गई।

नई दिल्ली, सोमवार, २९ सितम्बर १९४७

माउन्टबेटन का सारा दिन जूनागढ़ तथा पंजाब सञ्चयी नीति पर विचार करने वाली बैठकों में बीता। जूनागढ़ का सकट उत्तरोत्तर शतरंज की बड़ी जटिल वाजी

का रूप धारण करता जा रहा है। इस शतरंज की विसात है जूनागढ़, उसके पड़ोसी और अधीनस्थ राज्य, और मोहरे चलने वाले खिलाड़ी हैं कराची और दिल्ली।

पिछली बार जब लियाकतअली दिल्ली आये थे तब इस्मे ने उनसे बातचीत की थी। उसके आधार पर इस्मे को पूरा विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान जूनागढ़ के मामले को काश्मीर के लिए सौदेबाजी का आधार बनाना चाहता था। पाकिस्तान की यही चाल थी। इस विश्वास का सबूत लियाकतअली के इन शब्दों से मिला, जो उन्होंने उसी दिल्ली-प्रवास में माउन्टबेटन से कहे थे, “अच्छी बात है, भारत को आगे बढ़कर युद्ध छेड़ने दीजिये। फिर देखियेगा क्या होता है।”

दस दिन पूर्व वी पी मेनन जूनागढ़ गये थे। उनकी यात्रा का परिणाम सीमित रहा था। वह दीवान से मिले। दीवान ने कहा कि नवाब अस्वस्थ है और उनसे मिलना नहीं हो सकेगा। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मगरोल की छोटी-सी रियासत के गेख वी पी की उपस्थिति का फायदा उठाकर अपनी रियासत से आये और स्वेच्छापूर्वक भारत-संघ में शामिल हो गए। इसके पहले मगरोल जूनागढ़ को खिराज देने वाली रियासत थी। इसके पूर्व बाबरियावाड का शासक भी ऐसा ही कर चुका था। लेकिन मगरोल वापिस लौटने पर गेख को सब-प्रवेश का निर्णय रद्द करना पड़ा। २२ तारीख को भारत-सरकार ने निश्चय किया कि जिन परिस्थितियों में सब-प्रवेश को रद्द करने का पत्र लिखा गया था, वे ऐसी थी कि पत्र पर विचार नहीं किया जा सकता। जूनागढ़ ने मगरोल पर इस रक्तहीन विजय से प्रोत्साहित होकर बाबरियावाड पर अपनी सेनाएं दोड़ा दीं।

ये घटनाएं पटेल के क्रोध को भड़काने के लिए काफी थी। उनका खयाल था कि जूनागढ़ ने बाबरियावाड पर सैनिक चढ़ाई करके युद्ध छेड़ दिया है और भारत को उन सेनाओं को बाहर खदेड़ने के लिए सब आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। वास्तविकता यह थी कि यदि शक्ति का प्रदर्शन और अन्तिम उपाय के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जायगा तो वह त्यागपत्र दे देंगे।

माउन्टबेटन ने कल नेहरू को एक पत्र लिखकर सैनिक कार्यवाहियों की योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के अन्तर पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि दोनों उपनिवेशों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध से न केवल दोनों की नैतिक प्रतिष्ठा कम हो जायगी, बल्कि दोनों का अस्तित्व भी भयानक खतरे में पड़ जायगा। माउन्टबेटन की यह सलाह मान ली गई। किन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय सेना की तीनों शाखाओं के प्रमुखों ने अपनी स्वतंत्र समझ से भी इसी खतरे की ओर ध्यान दिलाया और इस काम में वे सैनिक सलाह की सीमा का उल्लंघन कर राजनैतिक क्षेत्र में पहुंच गए। इसने पटेल के क्रोध की आग में घी का काम किया।

माउन्टबेटन ने एक बीच का रास्ता सुझाया। उनके अनुसार जूनागढ़ के आस-



पास के विवादरहित प्रदेशों में भारतीय सेना की कुमुक भेजना जारी रखा जा सकता था। उन्होंने यह भी सलाह दी कि लियाकत को काठियावाड़ में आयोजित सैनिक गति-विधि की सूचना दे दी जाय और भारत-सरकार स्पष्ट घोषणा कर दे कि जिस राज्य के सघ-प्रवेश का प्रश्न विवादग्रस्त होगा, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार वहाँ के जनमत का निर्णय स्वीकार करेगी।

नई दिल्ली, बुधवार, १ अक्टूबर १९४७

लियाकत सयुक्त सुरक्षा-कौंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली आये। मेरा खयाल है कि आज सवेरे की बैठक बड़ी सुकटपूर्ण रही। बैठक के बाद दोपहर के खाने के समय मेहमान थे नेहरू और लियाकत और कर्मचारी मंडल में वर्नॉन तथा मैं। यहाँ भी वातावरण कुछ-कुछ तनावपूर्ण था। अम्बाला से मुसलमानों के निष्क्रमण के प्रश्न पर लियाकत नेहरू से उलझ पड़े। ऐसे मौके पर हम सबकी यही इच्छा थी कि किसी भी तरह विषय को बदल दिया जाय, लेकिन ऐसा करना शक्ति से बाहर था।

इस तनावपूर्ण बातचीत का असली कारण यह था कि पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पंजाब की सीमा में स्थित रावी पार 'बुलाकी-हेड' पुल पर आवागमन बन्द कर दिया था। कौंसिल की बैठक में पटेल ने लियाकत को इस पुल को खुलवाने के लिए हरचन्द मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फल नहीं हुआ। बाद में, निजी चर्चा के समय माउन्टबेटन ने लियाकत से अन्तिम अपील की और पाकिस्तान रवाना होने से पूर्व वह लियाकत से इस फैसले को रद्द करवाने में सफल हुए।

जूनागढ़ के बारे में भी कुछ साफ-साफ बातें हुईं। माउन्टबेटन को पहले तो किसी प्रधान मंत्री द्वारा इस प्रश्न को उठवाने में ही भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लियाकत का रुख था—“मैं क्यों उठाऊँ? हमने कोई गलती नहीं की। यदि भारत को परेशानी है तो वह उठाये।” उधर नेहरू महसूस करते थे कि यदि मैंने प्रश्न उठाया तो इसे कमजोरी का चिह्न समझा जायगा। आखिर माउन्टबेटन ने लियाकत को चर्चा छेड़ने के लिए राजी कर लिया। मगरोल और बाबरियावाड़ पर बातचीत होने लगी। नेहरू और माउन्टबेटन ने स्पष्ट किया कि इन दोनों राज्यों को भारत में शामिल होने का पूरा अधिकार है। नेहरू ने लियाकत से अनुरोध किया कि वह बाबरियावाड़ से जूनागढ़ की फौज हटाने का आदेश दे। जब ये बातें हो रही थी उस समय एक तार मिला कि जूनागढ़ की सेनाएं मगरोल में घुस गई हैं। नेहरू ने वचन दिया कि यदि जूनागढ़ की सेनाएं तुरन्त हटा ली गईं तो वह भारतीय सेनाओं को तबतक उन रियासतों में दाखिल न होने देंगे, जबतक उन दोनों की कानूनी स्थिति किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा तय न करा ली जायगी।

इस विषय में लियाकत का रुख समझोते का था, किन्तु जूनागढ़ के पाकिस्तान-प्रवेश के प्रश्न पर उनका हठ था कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। उनके तर्क का आधार यह था कि राज्य के शासक को नैतिक या साम्प्रदायिक पहलुओं का विचार किये बिना किसी भी सच में शामिल होने का पूरा अधिकार है।

: १८ :

## काश्मीर का झमेला

नई दिल्ली, मंगलवार, २८ अक्टूबर १९४७

सोमवार के सवेरे में भारतीय सेनाएँ हवाई जहाज द्वारा काश्मीर जा रही थी, यह सूचना पालम हवाई अड्डे पर उतरते ही वनों ने मुझे दी। लगभग पौने तीन बजे रात को मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि इतने में पीट रोम ने मुझे बुलाया और कहा कि माउन्टवेटन काश्मीर की नवीनतम स्थिति के बारे में मुझे तत्काल जानकारी देने को बुला रहे हैं।

माउन्टवेटन ने कहा कि घटनाओं ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। काश्मीर की ग्रीष्म राजधानी श्रीनगर पर तेजी से आने वाले उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रवेश के कवाडलियों का विशाल हमला रोकने के लिए पहली सिख बटालियन के तीन मी तीन मियाही काश्मीर भेजे जा चुके हैं। वह चाहते थे कि समाचार पत्रों में सम्पर्क बना रखने का काम मैं कल सवेरे में ही शुरू कर दूँ। लेकिन वह महसूस कर रहे थे कि इसके लिए पहले यह जरूरी होगा कि हम इस घटना के उन मूल-तत्वों को जान लें जो हमारे लन्दन-प्रवास के दौरान में घटी थी। मुझे उनकी जानकारी तो थी कि सितम्बर के प्रारम्भ में काश्मीर और पाकिस्तान के बीच कायम हुए नये-नये सम्बन्धों में गड़बड़ी उठ खड़ी हुई थी। काश्मीर सरकार ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया था कि वह कई अव्यावश्यक बम्बुएँ भेजने में आनाकानी कर रहा है और साथ ही सीमावर्ती हमलों के बारे में भी सिकायत की थी। उधर पाकिस्तान ने भी प्रत्युत्तर में कई आरोप लगाए थे। सत्ता-हस्तांतरण और सय-प्रवेश की आगिरी तांगीख के तीन दिनों पहले काश्मीर सरकार ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ "यथास्थिति समझौते" पर हस्ताक्षर करने के अपने निश्चय की घोषणा की। इसके फलस्वरूप भारत सरकार की नीति यह थी कि काश्मीर को सय-प्रवेश के लिए कुछ भी कहा-सुना न

जाय। इतना ही नहीं, पटेल के आदेशानुसार रियासती सचिवालय ने ऐसे सब कामों से अपना हाथ खींच लिया, जिसका अर्थ काश्मीर पर दबाव डालना हो सकता था और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि काश्मीर का पाकिस्तान में शामिल होना भारत में गलत नहीं समझा जायगा। प्रस्तुत सकट का सब में बड़ा कारण काश्मीर-नरेश की निर्णय न करने की पुरानी बीमारी समझना चाहिए। अगर कोई भी मार्ग अविलम्ब अपना लिया गया होता तो काश्मीर इस आफत से बच जाता। टालमटोल ही घातक सिद्ध हुआ। लेकिन लगता यह था कि बड़े सकट का सामना करने के लिए निजाम की भाँति काश्मीर नरेश भी अपने कूटनीतिक तरकस के इसी तीर का आसरा लेते हैं।

आज जो कदम उठाया गया था उसकी सैनिक और राजनैतिक प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी, इसके बारे में माउन्टबेटन को किसी प्रकार का शक नहीं। हालाँकि अब वह सलाह देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी यह दृढ़ धारणा थी कि उनकी उपस्थिति ने पंजाब और जूनागढ़ की समस्याओं में उलझी उनकी सरकार को नाजुक खतरों से बचाने में भारी सहायता पहुँचाई थी।

उनसे मझे पता चला कि गत शुक्रवार की रात को (२४ अक्टूबर) स्याम के विदेश-मन्त्री के स्वागत में दिये गए भोज के समय नेहरू ने इस अशुभ समाचार का पहली बार जिक्र किया था और बतलाया था कि सैनिक लारियों द्वारा कवाइलियों को रावलपिंडी रोड से काश्मीर भेजा जा रहा है। रियासती सेनाओं का कही पता नहीं था और स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही थी। माउन्टबेटन शनिवार २५ अक्टूबर को सुरक्षा-कमेटी की बैठक में उपस्थित थे। उसमें जनरल लाकहार्ट ने पाकिस्तान सेना के प्रधान कार्यालय से प्राप्त एक तार पढ़ कर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि लगभग पाँच हजार कवाइलियों ने मुजफ्फराबाद और दोमेल पर कब्जा कर लिया था और बड़ी भारी सख्या में कवाइली कुमुक इन स्थानों में पहुँचने की सभावना है। सूचनाओं से पता चलता था कि वे श्रीनगर से पैंतीस मील से ज्यादा दूरी पर नहीं थे।

सुरक्षा समिति का विचार था कि तात्कालिक आवश्यकता शस्त्र और गोला-बारूद भेजने की है, जिसकी काश्मीर सरकार ने माँग की थी। इसकी मदद से श्रीनगर की स्थानीय जनता हमलावरों के खिलाफ थोड़ी-बहुत मोर्चेबंदी कर सकेगी। सेनाएँ भेजने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। इस पर माउन्टबेटन ने समझाया कि जबतक काश्मीर भारत-संघ में शामिल नहीं हो जाता तबतक वहाँ सेनाएँ भेजना खतरनाक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संघ-प्रवेश अस्थायी होना चाहिए और उसकी पुष्टि बाद में जनमत-संग्रह द्वारा की जाय। २५ तारीख की रात को मेरे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई आखिरी फैसला नहीं किया गया, लेकिन यह जरूर तय हुआ कि वी. पी. मेनन तुरन्त हवाई जहाज से श्रीनगर जाय और वहाँ

की ठीक-ठीक स्थिति का पता लगावे ।

दूसरे दिन सुरक्षा-समिति को जो जानकारी मेनन ने श्रीनगर में लौट कर दी वह निश्चय ही काफी चिंताजनक थी। उन्होंने बतलाया कि घटनाओं के इस तेज दौर से महाराज के हाथ-पैर फूल गए हैं और वह अपने एककीपन और वक्की के भार से दबे हुए हैं। आखिर स्थिति को गंभीरता का बोध उन्हें हुआ और उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत ने सहायता नहीं दी तो सब चोपट हो जायगा। मेनन की जोरदार सलाह को मान कर उम्मीद दिन महाराज ने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ श्रीनगर छोड़ दिया। मेनन ने उन्हें समझाया कि हमलावरों ने वारामूला पर अधिकार कर लिया है। इसलिए उनका राजधानी में ठहरना भारी भूल होगी। महाराज ने मधु-प्रवेश-पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए। इस पत्र को मेनन ने सब-सुरक्षा-कमेटी के सामने पेश किया।

जहां तक सैनिक स्थिति का प्रश्न था, मेनन ने राय दी कि श्रीनगर में बाकी बची फौज हमलावरों को रोकने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि वह घुड़सवार सेना का एक स्क्वेडरन मात्र है। इस निराशापूर्ण परिस्थिति को ध्यान में रखकर मन्त्रि-मंडल ने निश्चय किया कि महाराज द्वारा भेजे मधु-प्रवेश-पत्र को स्वीकार किया जाय और दूसरे दिन सबेरे पैदल सेना की एक बटालियन हवाई जहाज द्वारा खाना की जाय।

इसके बाद माउन्टबेटन ने मुझे विस्तार के साथ बतलाया कि उन्होंने मधु-प्रवेश के प्रश्न पर सुरक्षा-समिति में यह ख बयौ अनायास था और बयौ वह इस विषय पर अपने पहले के मत को बदलने के लिए बाध्य हुए थे। उन्होंने कहा कि महाराज को उन्होंने यह सलाह दी थी कि वह सत्ताहस्तांतरण के पहले यह निश्चय कर लें कि वह किस देश में शामिल होंगे। लेकिन साथ ही, उन्होंने जून में अपनी काश्मीर-यात्रा के समय में लेकर अपना सारा जोर इस बात पर लगाया था कि जनता का मत लिये बिना वह दोनों में से किसी भी देश में शामिल न हो। जनता की राय वह मत-गणना या चुनाव या सार्वजनिक प्रतिनिधि सभाओं द्वारा प्राप्त कर सकते थे। जब पिछले अडनालिम घण्टों में उन्हें निश्चय हो गया कि अपने मैना-पतियों और गुद उनकी सैनिक सलाह के बावजूद सरकार काश्मीर की प्रायता पर हवाई जहाज द्वारा सहायता के लिए फौज भेजने पर तुली हुई है तो वह फिर मधु-प्रवेश के प्रश्न पर डब गए।

उन्होंने कहा कि एक तटस्थ देश में फौज भेजना भयंकर भूल होगी, क्योंकि ऐसा करने का हमें कोई अधिकार नहीं और पाकिस्तान भी चाहें तो ऐसा कर सकता है। और ऐसा होने का नतीजा सिवा युद्ध के और कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि यदि वे फौज भेजने पर तुले हुए हैं तो इसका अनिवार्य शर्त यह होगी कि इसके पूर्व ही मधु-प्रवेश की कार्यवाही पूरी हो जाय और यदि यह स्पष्ट

नहीं कर दिया जाता कि सध-प्रवेश काश्मीर हथियाने की चालमात्र नहीं तो यह खुद युद्ध भड़काने का कारण बन सकता था। इसलिए उन्होंने इजाजत चाही कि अपनी सरकार की तरफ से महाराज के सध-प्रवेश के विलय-पत्र के उत्तर में भेजे जाने वाले पत्र में उन्हें यह भी जोड़ दिया जाय यह सध-प्रवेश जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा, जिसका निश्चय न्याय और व्यवस्था कायम होते ही किया जायगा। यह सिद्धान्त तुरन्त स्वीकार कर लिया गया और नेहरू ने निर्विरोध इसे प्रस्ताव के रूप में पेश कर दिया।

सध-प्रवेश के बाद लोकप्रिय सरकार की स्थापना करने के उद्देश्य से महाराज ने नेशनल काफ़ेस के नेता शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया था। अब उन्हें अन्तरिम सरकार का प्रधान बनाया जा रहा था। सध-प्रवेश की नियमितता असंदिग्ध थी। इस प्रश्न पर जिन्ना को अपनी ही चाल का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही जूनागढ़ के प्रश्न पर शासक के व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार की अकाट्यता का सिद्धान्त पेश किया था।

चार बजे सवेरे के जरा पहले ही माउन्टबेटन ने हमारे ऊपर तरस खा कर हमें छुट्टी दे दी, अन्यथा मैं शायद उनके सामने ही झपकी लेने लगता।

आज के आफत भरे दिन ही सारी-की-सारी चीजें एक साथ टूट पड़ी थी। पत्रकारों को मुलाकातें देने के लम्बे ताते के बाद माउन्टबेटन और नेहरू से चर्चा करने के लिए बुलावा आ गया। उनके साथ आज तक की शासकीय सफलताओं के बारे में एक वक्तव्य तैयार करने के प्रश्न पर चर्चा हुई। इस वक्त तो यह चीज मुझे एक अच्छी-खासी दिमागी कसरत लग रही थी। नेहरू को इतना परेशान और अस्वस्थ देख कर मुझे बड़ा सदमा पहुंचा।

माउन्टबेटन 'स्टेट्समैन' के सम्पादकीय रुख से चिंतित थे। इस पत्र ने विगड़ते हुए भारत-पाक-सम्बन्धों से व्यग्र होकर भारतीय सेनाओं के काश्मीर-प्रवेश की भर्त्सना कर डाली थी। माउन्टबेटन ने मुझसे कहा कि पत्र के सम्पादक आइन स्टीफेस को मिलने के लिए बुलाने की व्यवस्था करो। लगभग एक घंटे बाद आइन स्टीफेस हमारे बीच आ पहुंचे। माउन्टबेटन ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, "किसी राष्ट्र का निर्माण तिकडमवाजी के आधार पर नहीं किया जा सकता।" उन्होंने कहा कि एबटाबाद में बैठे जिन्ना विजेता के रूप में काश्मीर पहुंचने की आस लगाये हैं। उनकी आशाओं पर तुपारपात हो गया। पहले जूनागढ़ की घटना घटी और फिर कल हैदराबाद के प्रतिनिधि मंडल के जवरन रोकें जाने की प्रमादपूर्ण घटना। काश्मीर के बारे में भारत ने जो कदम उठाया वह बिल्कुल अलग किस्म की बात थी। जनमत को स्वीकार करने का अपना निश्चय उसने पहले ही घोषित कर दिया था। अगर कोई फौजी कदम नहीं उठाया जाता तो क्वाइलियो द्वारा कल्लेआम किया जाना अनिवार्य हो जाता—श्रीनगर के कुछ सौ ब्रिटिश

नागरिक भी उससे नहीं बचते। महाराज द्वारा सघ-प्रवेश कर लेने के बाद जो भी कदम उठाये गए वे कानूनी तौर से बिलकुल जायज हैं।

अपनी चर्चा समाप्त करते हुए उन्होंने स्टीफेस से कहा कि आचिन्लेक के हस्तक्षेप के फलस्वरूप जिन्ना को इस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि काश्मीर-संकट के विषय में चर्चा करने के लिए माउन्टबेटन और नेहरूको कल लाहौर आमंत्रित किया जाय।

आज की सुरक्षा समिति की बैठक के बाद आचिन्लेक ने लाहौर से माउन्टबेटन को फोन पर कहा कि उन्होंने जिन्ना को कल रात का उनका यह हुक्म रद्द करने पर राजी कर लिया है कि पाकिस्तानी सेनाएँ काश्मीर में भेज दी जाय। जनरल मेनर्वी की अस्थायी अनुपस्थिति में जिन्ना का हुक्म पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधान सेनापति जनरल ग्रेसी के पास पश्चिमी पंजाब के गवर्नर के सेक्रेटरी द्वारा पहुँचा था, जहाँ जिन्ना ठहरे हुए थे। ग्रेसी ने उत्तर दिया कि सर्वोच्च सेनापति की स्वीकृति के बिना वह ऐसे कोई आदेश जारी करने को तैयार नहीं। ग्रेसी के जरूरी बुलावे पर आचिन्लेक आज सवेरे हवाई जहाज से लाहौर पहुँचे। उन्होंने जिन्ना को समझाया कि चूँकि काश्मीर भारत-संघ में शामिल हो गया है, इसलिए भारत सरकार को महाराज की प्रार्थना पर अपनी सेनाएँ काश्मीर में भेजने का पूरा-पूरा अधिकार है।

आचिन्लेक के वहाँ से चलने के पूर्व न सिर्फ यह हुक्म ही रद्द कर दिया गया बल्कि माउन्टबेटन और नेहरू को लाहौर आने का निमंत्रण भी दे दिया गया।

टेलीफोन पर लंबी माथापच्ची करने के बाद जब वर्नॉन काफी देर के बाद रात का खाना खाने पहुँचे तो उन्होंने कहा, “सब चोपट हो गया।” उन्होंने कहा कि “सारी योजना ठंडी हो गई, क्योंकि अस्वस्थता के कारण नेहरू लाहौर जाने में असमर्थ हैं।”

आज रात फिल्म-प्रदर्शन के बाद माउन्टबेटन ने रोनी, वर्नॉन तथा मुझे आज की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए बुलाया। माउन्टबेटन ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे हुई सुरक्षा समिति की बैठक में लाहौर जाने के लिए बहुत जोर डाला। उनका रौब इतना अधिक था कि वहाँ तो किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किन्तु उन्हें पता चला कि आज तीसरे पहर मंत्रिमंडल की बैठक में नेहरू पर लाहौर न जाने के लिए भारी दबाव डाला गया। घर पहुँचने पर नेहरू कमजोरी के मारे गिरते-गिरते बचे और उन्हें लिटा दिया गया। माउन्टबेटन का विश्वास था कि नेहरूकी अस्वस्थता वास्तविक है। नेहरू इस बात के लिए सहमत हो गए कि माउन्टबेटन जिन्ना को सन्देश भेज कर उनकी बीमारी की बात बतलाते हुए बैठक की तारीख बढ़ाने के लिए कहें। माउन्टबेटन ने कल सवेरे जिन्ना को फोन करके का निश्चय किया, जिससे नेहरू के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दे

उन्हें खुद दिल्ली बुलाने की कोशिश कर सके।

नई दिल्ली, बुधवार, २९ अक्टूबर १९४७

माउन्टबेटन आज सवेरे नैहरू को देखने उनके घर गये। पटेल भी वहाँ पहुँचे। लाहौर-यात्रा की उपादेयता के विषय में साफ-साफ बातें हुईं। माउन्टबेटन ने कहा कि वह अकेले जाने को तैयार है—जब दोनों देशों को विनाश से बचाने का सवाल सामने है तो वह अपने स्वाभिमान की भावनाओं को ताक पर रखने के लिए तैयार है। पटेल ने कहा कि वह और मन्निमडल के अन्य सदस्य दोनों में से किसी के भी जानें के सख्त खिलाफ है। इसपर माउन्टबेटन ने याद दिलाई कि लियाकत बीमार है और सयुक्त सुरक्षा-कौंसिल की बैठक वैसे भी इस सप्ताह होने की है। इस बैठक में भाग लेने के लिए नैहरू और उनका लाहौर जाना दोस्ती की भावना को बल देगा। नैहरू राजी हो गए। माउन्टबेटन ने सरकारी भवन लौटते ही जिन्ना को फोन किया। जिन्ना को इस प्रस्ताव से खुशी हुई। पाँच मिनट बाद डून कम्पवेल ने मुझ से फोन पर पूछा कि क्या इस अफवाह में कोई मचाई है कि माउन्टबेटन ने अभी-अभी जिन्ना से बात की है।

माउन्टबेटन की आज गांधीजी के साथ नव्वे मिनट तक बातचीत हुई। कल की प्रार्थना सभा के समय महात्माजी ने काश्मीर के बारे में एक विलकुल 'चर्चिल-पथी' बात कह डाली थी। उसका भाव कुछ इस प्रकार था—फल भगवान् के हाथ में है। मनुष्य तो केवल कर या मर ही सकता है। यदि काश्मीर की रक्षा करने वाली नन्ही-सी भारतीय सेना का थर्मोपली की वीरता से रक्षा करने वाली स्पार्टा-फौजों के समान सफाया हो गया, तो भी वह आसू नहीं बहाएंगे। शेख अब्दुल्ला और उनके मुसलमान, हिन्दू तथा सिख साथी यदि काश्मीर की रक्षा करते हुए काम आयेंगे तो उन्हें जरा भी दुःख नहीं होगा। पूरे भारत के लिए यह एक ज्वलंत उदाहरण होगा। इस वीरता भरे मुकाबले का पूरे देश पर असर पड़ेगा और सब लोग यह भूल जायेंगे कि हिन्दू, मुसलमान और सिख कभी एक-दूसरे के दुश्मन भी रहे थे।

तात्कालिक मौनिक स्थिति गंभीर थी। सोमवार को जो ब्रिटिश हवाई जहाज द्वारा भेजी गई थी उसके कमांडिंग अफसर मारे गए थे। फौजों को पीछे हटना पड़ा था और श्रीनगर के पश्चिम में लगभग साढ़े चार मील की दूरी पर भयंकर युद्ध हो रहा था।

यह ध्यान देने की बात है कि काश्मीर के संकट की हैदराबाद पर बड़ी तेज प्रतिक्रिया हुई। काश्मीर के मध-प्रवेश और वहाँ फौजों के पहुँचने के बीबीस घंटों बाद ही यह समाचार आया कि दिल्ली में यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रवाना होने वाले हैदराबादी प्रतिनिधि मंडल को इतिहादी भीड़ द्वारा बड़े

भारत में शामिल होता है तब तो “धोखा और हिंसा” लेकिन जब जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होता है तो कानूनी रूप से वैध। भारत के लिए जूनागढ़ सबकी प्रचार का तात्कालिक महत्व बहुत अधिक था, परन्तु पटेल अपने को रियामती-मंत्री पहले और प्रचार-मंत्री बाद को मानते थे।

यह मानना होगा कि भारत सरकार को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। १ अक्टूबर को लियाकत के साथ भेट होने के बाद नेहरू को कम-से-कम तीन बार पाकिस्तान सरकार को लिखना पड़ा कि मगरोल तथा बावरियावाड से जूनागढ़ को सेनाएं तुरन्त हटाई जावे। तीन सप्ताह बाद लियाकत का उत्तर आया, जिसमें पहले के एक लापता उत्तर का उल्लेख था और कहा गया था कि सेनाएं हटाने का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद भी हुआ कुछ नहीं।

अक्टूबर १६ को लाहौर में संयुक्त सुरक्षा-कौन्सिल की बैठक में लियाकत ने कहा कि मैं जूनागढ़ में जनमत-संग्रह के सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हूँ। नेहरू ने प्रस्ताव किया कि वी पी मेनन को सामान्य विचार-विमर्श के लिए लाहौर भेजा जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वी पी को कराची भेजने को कहा। २१ तारीख को सुरक्षा-समिति ने स्वीकार कर लिया कि मगरोल और बावरियावाड पर अधिकार करना ही होगा। दो दिन बाद एक योजना बनाई गई और उसके दो दिन बाद—किन्तु काश्मीर के विस्फोट से केवल ३६ घंटे पूर्व—उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

नई दिल्ली, रविवार, २ नवम्बर १९४७

अपने परिवार से मिलने मैं हवाई जहाज से शिमला गया था। जब दिल्ली लौटा तब मुझे माउन्टबेटन-परिवार के साथ भोजन करने का निमन्त्रण मिला। अतिथियों में वीकानेर के महाराजा भी थे। भोजन के बाद एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें विस्थापितों की निकासी और कल्याण-कार्य में वीकानेर राज्य के सहयोग का प्रदर्शन था। वीकानेर महाराज इस फिल्म की टीका करते जाते थे। इस सुन्दर रंगीन फिल्म में यह दिखाया गया था कि किस प्रकार पाँच लाख से अधिक विस्थापित राज्य से बाहर भेजे गए। ये लोग हजारों के झुंड बनाकर ऊपर जमीन पर होते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके कारण वीकानेर की साधन-सामग्री तथा यातायात के साधनों, पर, अचानक अत्यधिक भार आ पड़ा। इस पर भी सारी निकासी में केवल १५० मुसलमानों की रास्ते में मृत्यु हुई।

माउन्टबेटन खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि लाहौर में उनकी जिन्ना से ३॥ घंटे तक बातचीत हुई, जिससे उन्हें सतोष था। दोनों ने काफी खुलकर बातचीत की। यदि वह अपने-अपने प्रधान मंत्रियों के साथ होते तो ऐसा सम्भव न हो पाता। जिन्ना



भारत में शामिल होता है तब तो “धोखा और हिंसा” लेकिन जब जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होता है तो कानूनी रूप से वैध। भारत के लिए जूनागढ़ सबकी प्रचार का तात्कालिक महत्व बहुत अधिक था, परन्तु पटेल अपने को रियामती-मंत्री पहले और प्रचार-मंत्री बाद को मानते थे।

यह मानना होगा कि भारत सरकार को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। १ अक्टूबर को लियाकत के साथ भेट होने के बाद नेहरू को कम-से-कम तीन बार पाकिस्तान सरकार को लिखना पड़ा कि मगरोल तथा वावरियावाड़ से जूनागढ़ को सेनाएं तुरन्त हटाई जावे। तीन सप्ताह बाद लियाकत का उत्तर आया, जिसमें पहले के एक लापता उत्तर का उल्लेख था और कहा गया था कि सेनाएं हटाने का आदेश दिया जा रहा है। इसके बाद भी हुआ कुछ नहीं।

अक्टूबर १६ को लाहौर में संयुक्त सुरक्षा-कौन्सिल की बैठक में लियाकत ने कहा कि मैं जूनागढ़ में जनमत-संग्रह के सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हूँ। नेहरू ने प्रस्ताव किया कि वी पी मेनन को सामान्य विचार-विमर्श के लिए लाहौर भेजा जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वी पी को कराची भेजने को कहा। २१ तारीख को सुरक्षा-समिति ने स्वीकार कर लिया कि मगरोल और वावरियावाड़ पर अधिकार करना ही होगा। दो दिन बाद एक योजना बनाई गई और उसके दो दिन बाद—किन्तु काश्मीर के विस्फोट से केवल ३६ घंटे पूर्व—उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

नई दिल्ली, रविवार, २ नवम्बर १९४७

अपने परिवार से मिलने में हवाई जहाज से शिमला गया था। जब दिल्ली लौटा तब मुझे माउन्टबेटन-परिवार के साथ भोजन करने का निमन्त्रण मिला। अतिथियों में वीकानेर के महाराजा भी थे। भोजन के बाद एक फिल्म दिखाई गई, जिसमें विस्थापितों की निकासी और कल्याण-कार्य में वीकानेर राज्य के सहयोग का प्रदर्शन था। वीकानेर महाराज इस फिल्म की टीका करते जाते थे। इस सुन्दर रंगीन फिल्म में यह दिखाया गया था कि किस प्रकार पाँच लाख से अधिक विस्थापित राज्य से बाहर भेजे गए। ये लोग हजारों के झुंड बनाकर ऊपर जमीन पर होते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके कारण वीकानेर की साधन-सामग्री तथा यातायात के साधनों, पर, अचानक अत्यधिक भार आ पड़ा। इस पर भी सारी निकासी में केवल १५० मुसलमानों की रास्ते में मृत्यु हुई।

माउन्टबेटन खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि लाहौर में उनकी जिन्ना से ३॥ घंटे तक बातचीत हुई, जिससे उन्हें सतोष था। दोनों ने काफी खुलकर बातचीत की। यदि वह अपने-अपने प्रधान मंत्रियों के साथ होते तो ऐसा सम्भव न हो पाता। जिन्ना

ने बातचीत की शुरुआत इस शिकायत से की कि भारत सरकार ने अपने इरादों की चेतावनी पाकिस्तान सरकार को समय पर नहीं दी। माउन्टबेटन ने उत्तर दिया कि जिस ब्रैठक में काश्मीर को हवाई जहाज से फौज भेजने का निर्णय किया गया, उसकी समाप्ति पर नेहरू ने जो काम सबसे पहले किया, वह था लियाकतअली को तार देना। तब जिन्ना ने अपने इस सार्वजनिक वक्तव्य को दोहराया कि काश्मीर का भारत में मिल जाना वास्तविक नहीं, क्योंकि वह हिंसा और धोखेवड़ी पर आधारित था, और इसलिए उसको पाकिस्तान स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके बाद तर्क-वितर्क का एक बड़ा ही विषम-चक्र चल पड़ा। माउन्टबेटन ने इस बात को स्वीकार किया कि बल-प्रयोग के ही कारण काश्मीर भारत में सम्मिलित हुआ है। किन्तु बल-प्रयोग कबाइलियों की ओर से हुआ था, जिसके लिए भारत नहीं, पाकिस्तान उत्तरदायी था। इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा कि मेरी राय में तो सेना भेजकर भारत ने ही बल-प्रयोग किया है। किन्तु माउन्टबेटन अपने इसी तर्क पर अड़े रहे कि बल-प्रयोग तो वास्तव में कबाइलियों ने किया। बहस इसी तरह चलती रही। आखिर जिन्ना इसे माउन्टबेटन की धावली कह कर अपने क्रोध को छिपा नहीं सके।

माउन्टबेटन ने जिन्ना को बतलाया कि श्रीनगर में भारतीय सेनाओं की शक्ति कितनी थी और अगले कुछ दिनों में वह कितनी बढ़ जायगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब कबाइलियों के श्रीनगर में घुसने की संभावना नहीं रही। इस पर जिन्ना ने फिर अपना वही पुराना प्रस्ताव रखा कि दोनों दल अपनी-अपनी सेनाएं फौरन और एक साथ हटा लें। जब माउन्टबेटन ने उनसे पूछा कि कबाइलियों को वापस जाने के लिए किस तरह तैयार किया जायगा तो जिन्ना ने जवाब दिया “अगर आप इतना कर देंगे तो मैं आक्रमण का अन्त करवा दूंगा।” इससे कम-से-कम यह ध्वनि तो निकलती ही थी कि पाकिस्तान के इस सार्वजनिक प्रचार का, कि कबाइलियों का आक्रमण पाकिस्तान के अधिकार से बाहर की बात थी, आपसी बातचीत में ज्यादा सहारा नहीं लिया जायगा।

जाच-पड़ताल करने पर माउन्टबेटन को यह पता चला कि जनमत-संग्रह के बारे में जिन्ना की जो मनोवृत्ति थी, उसके पीछे यह विश्वास काम कर रहा था कि काश्मीर में भारतीय सेना की उपस्थिति और वहां की सत्ता का शेख अब्दुल्ला के हाथों रहने का अर्थ यह होगा कि वहां की साधारण मुस्लिम जनता इतनी भयभीत हो जायगी कि पाकिस्तान के पक्ष में मत नहीं देगी। माउन्टबेटन ने प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जनमत संग्रह किया जाय। इस पर जिन्ना ने कहा कि यह काम तो केवल दोनों गवर्नर-जनरल ही कर सकते हैं। इस सुझाव को माउन्टबेटन ने तुरन्त ठुकरा दिया और इस बात पर जोर दिया कि जिन्ना के हाथों में कितने ही अधिकार क्यों न हों, जहां तक (माउन्टबेटन का) अपना सवाल है,

उनकी वैधानिक स्थिति ऐसी है कि वह केवल अपनी सरकार के परामर्श के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं।

जिन्ना को इससे बड़ी निराशा हुई और उन्होंने सोचा कि जो भाग्य से बड़ा होगा, वही होगा। वह यही राग अलापते रहे कि भारत उनके बनाये हुए राष्ट्र को मिटा देना चाहता है। काश्मीर के सम्बन्ध में जिम् किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता या जिम् किसी नीति की चर्चा की जाती, सभी को जिन्ना अपने इमी रगोन चर्मे से देखते। माउन्टबेटन और इस्मे ने, जो अधिकांश वार्तालाप में मौजूद थे, जिन्ना को हर तरह से आश्वासन देने की भरपूर चेष्टा कीं। यह तो कहना कठिन है कि इसका उनपर प्रभाव पड़ा या नहीं। किन्तु कम-से-कम बाहरी तौर पर वे सौहार्द की भावना के साथ ही एक-दूसरे से विदा हुए।

माउन्टबेटन का कहना था कि २७ अक्टूबर को भारत ने हवाई जहाजों द्वारा सेना भेजने का जो काम किया था, उसकी गति के मामले तो दक्षिण-पूर्वी एशिया कमान की सरगर्मी भी फाँकी पड़ गई। निस्सन्देह इससे जिन्ना भी स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि भारतीय सेना का वह चमत्कार उनके अनुमान के विलकुल परे था।

माउन्टबेटन के आगावाद और स्पष्टवादिता के बावजूद पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएँ घटी, उनसे माउन्टबेटन और जिन्ना के बीच की खाई अनिवार्य रूप से चौड़ी हो जाती गई। उसे यह पिछली मुलाकात भी किसी प्रकार कम न कर सकी। जिन्ना ने माउन्टबेटन को अपने ही दृष्टिकोण से आका होगा और यह मान लिया होगा कि उन्हें अब भी वाइसराय के सभी अधिकार प्राप्त हैं। सम्भवतः उसी के फलस्वरूप उन्होंने यह भी सोचा होगा कि गायद माउन्टबेटन ने ही काश्मीर के विलय को स्वीकार करनेवाले पत्र को लिखवाया होगा, उन्होंने ही २७ अक्टूबर वाले वीरतापूर्ण चमत्कार का निर्देशन किया होगा। पाकिस्तान के हितों तथा महत्वाकांक्षाओं में अचानक यह जो गम्भीर बाधा पड़ी थी, साधन रूप में उसके भी वही प्रेरक रहे होंगे।

यदि बात ऐसी थी तो निस्सन्देह यह सत्य का एक विकृत और दुःखपूर्ण दिग्दर्शन था। ३ जून की योजना की स्वीकृति के बाद से ही माउन्टबेटन ने दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के बीच सद्भावना को बढ़ाना अपने मिशन का मुख्य लक्ष्य बना लिया था। जिन्ना वैयक्तिक मान-मर्यादा की ओर से उदासीन नहीं थे। किन्तु आश्चर्य की बात थी कि वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस कार्य में असफल होने को माउन्टबेटन भी एक वैयक्तिक असफलता मान सकते हैं। जिन्ना को काश्मीर के सम्बन्ध में दौखलाहट तो थी ही, इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव था कि जिन्ना इस बात को नहीं समझते कि व्यापक-दृष्टि से अब माउन्टबेटन को भारत सरकार के निश्चयों में नरमी लाने या मध्यस्थता कराने के अधिकार ही रह गए थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, गवर्नर-जनरल के उचित कर्तव्यों के सम्बन्ध में जिन्ना के विचार उसी समय स्पष्ट हो गए थे

जब उन्होंने स्वतन्त्रता विधेयक के अन्तर्गत मिले हुए अपने विशेष अधिकारों को फीरत ही अपने हाथों में ले लिया था।

यह बात भी कम महत्व की नहीं थी कि यद्यपि जिन्ना और माउन्टबेटन में एक-दूसरे के लिए काफी आदर की भावना थी, फिर भी जिन्ना ने अब अपना सारा ध्यान कूटनीति में ही लगा दिया था। गहरे भय और कठोर दावपत्र की जिन अतुल गहराइयों तक माउन्टबेटन नहीं पहुँच सकते, वे ही आज जिन्ना पर हावी थी।<sup>१</sup>

नई दिल्ली, सोमवार, ३ नवम्बर १९४७

मारा ध्यान काश्मीर के प्रश्न पर केन्द्रित होने के कारण हैदराबाद नजरो में ओचल हो गया था। लेकिन कल ही माउन्टबेटन के मामले में हैदराबाद का एक नया प्रतिनिधि-मंडल आया। तीन व्यक्तियों वाले इस प्रतिनिधि-मंडल के नेता मोइन-नवाज जग ये, जो इतिहास के मजबूत लोगों में गिने जाते थे। लगता था कि १५ अगस्त की अपेक्षा आज हम समझौते में कहीं दूर थे। काश्मीर के मय-प्रवेश और वहाँ नैनाएँ उतरने के दूसरे दिन जो घटनाएँ घटीं उनको देखते हुए यही कम अचरज की बात नहीं कि चर्चाएँ अब भी जारी थीं। अगर माउन्टबेटन और माकटन ने दृढ़ता न दिखाई होती तो चर्चाएँ कब की खत्म हो गई होती। आज हालत यह थी कि निजाम ने वह बचाखुचा विश्वास भी खो दिया था, जो भारत सरकार, खास कर सरदार पटेल, को उनमें था। मुझे शक था कि उनमें कभी फिर पहले जैसे सम्बन्ध स्थापित हो सकेगे।

इसमें और मेरी लड़न-यात्रा के काल में माउन्टबेटन ने ऐसा हठ खोजने में समझौता कराने की अपनी सारी कला खर्च कर दी थी, जिसमें मय प्रवेश और मय-सरकार के बीच के अन्तर को पाटा जा सके। उन्होंने यहाँ तक किया कि एक भारी भरकम समझौता तैयार कराया जो समझौते के रूप में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जा सके, और सरदार के लिए उसका अर्थ मय-प्रवेश ही और निजाम के लिए सहकार।

१. माउन्टबेटन के लिए जिन्ना का यह आदर-भाव किनता गहरा था। इनका रहस्योद्घाटन जिन्ना के एक निजी मित्र ने मुझे पिछले दिनों किया। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी मृत्यु ने कुछ दिन पहले जिन्ना ने यहाँ तक कहा था कि अपनी समाप्त जिन्दगी में जिस एक आदमी ने मुझ पर अंतर डाला है, वह है लार्ड माउन्टबेटन। जब मैं उनसे पहली बार मिला तब मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें 'नूर' है। उन्होंने यह भी कहा था कि माउन्टबेटन जिनके समय भी भारत में रहे मैंने कभी उनकी ईमानदारी पर शक नहीं की।

इस विश्वास से कि जबतक माकटन मौजूद रहते हैं तभी तक निजाम पर आधुनिकता का प्रभाव रह सकता था, माउन्टबेटन ने यह बात मजूर कराने की जीतोड़ कोशिश की कि वी पी मेनन को वहाँ जाने दिया जाय, जिसमें चर्चाएँ हैदराबाद में ही हो सकें। जब वी पी को दोनों ओर से परवानगी मिल गई और वह जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे कि निजाम ने इस बिना पर मेनन की यात्रा खारिज करा दी कि उनके आगमन से व्यर्थ प्रदर्शन होगा। जिन शब्दों में निजाम ने यह यात्रा खारिज की और जिन शब्दों में पटेल ने इसका उत्तर दिया वह दोनों पक्षों की भावनाओं को इस कदर चोट पहुँचानेवाले थे कि चर्चाओं का हमेशा के लिए अन्त हो जाता।

इसी समय माउन्टबेटन ने माकटन को अपने व्यक्तिगत अतिथि के नाते दिल्ली आने का बुलावा दिया। १० अक्टूबर को माकटन ने एक वर्ष के लिए 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर किये जाने का सुझाव दिया, जिससे भारत को सघ-प्रवेश के अधिकांश लाभ मिल जाते और निजाम का प्रतीकात्मक पद भी कायम रहता। इस आधार पर चर्चा चलाने के लिए माउन्टबेटन ने दो महीने की अवधि में भी वृद्धि करवा ली। इसके बाद ऐसी भयंकर और कटु सौदेबाजी चली कि चर्चाओं का अन्त निकट जान पड़ने लगा। लेकिन २२ अक्टूबर को 'यथास्थिति समझौते' का एक ऐसा मसविदा तैयार हो गया जो मेनन और निजाम के प्रतिनिधि-मंडल, दोनों को स्वीकार था।

इस विषय को ठोस रूप देने के लिए प्रतिनिधि-मंडल हैदराबाद लौट गया। उसी शाम मसविदा निजाम को दिखाया गया, जिन्हें उसका रूप-रंग अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूरे मसविदे को अपनी कार्यकारिणी समिति को सौंपने का निश्चय किया। कार्यकारिणी समिति ने अगले तीन दिन मसविदे पर विचार करने में लगाये। प्रतिनिधि-मंडल भी इस विचार के समय उपस्थित रहा, जिससे आवश्यक स्पष्टीकरण कर सके। शनिवार २५ अक्टूबर को तीन मतों के खिलाफ छ मतों से यह औपचारिक फैसला किया गया कि निजाम को सलाह दी जाय कि मसविदे को बिना किसी परिवर्तन या विलम्ब के स्वीकार कर ले। मतदान का नतीजा प्रतिनिधि-मंडल ने निजाम को उसी शाम सूचित कर दिया और निजाम ने फैसले पर अपनी स्वीकृति दे दी। ऐसा मालूम हुआ कि अगला पूरा दिन निजाम ने दो नत्थी-पत्र तैयार करने में लगाया। इन पत्रों में से एक में यह बचन दिया गया था कि वह पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, और दूसरे पत्र में उन्होंने भारत के राष्ट्र-मंडल छोड़ने या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की हालत में अपनी स्थिति के परिवर्तन का उल्लेख किया था। चूँकि प्रतिनिधि-मंडल दूसरे दिन सवेरे दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था इसलिए उन्होंने निजाम से मसविदा मगवाया। लेकिन बिना किसी खुलासे के निजाम ने उस रात उस पर अपने हस्ताक्षर करने से

इन्कार कर दिया।

दूसरे दिन सवेरे तीन बजे के लगभग बीस हजार लोगों को एक भीड़ ने छतारी, माकटन और सर मुलतान अहमद के मकानों को घेर लिया। भीड़ के बीच लाउड स्पीकर लगे हुए थे, जिनके द्वारा लोगों से व्यवस्थित रहने की अपीलें की जा रही थी और समझाया जा रहा था कि प्रतिनिधि-मंडल को जाने से रोकने के अलावा और कोई दगा न करे। पूरी घटना के समय हैदराबाद पुलिस कहीं दिखलाई नहीं पड़ी और इम लडाकू चुनोती का इतिहाद ने खुले रूप से श्रेय अपने ऊपर लिया। करीब पांच बजे सवेरे छतारी मेना के अधिकारियों से सम्पर्क करने में सफल हुए और प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों और लेडी माकटन को निरापद एक सैनिक अधिकारी के घर में पहुँचाया जा सका।

आठ बजे सवेरे निजाम ने प्रतिनिधियों को सन्देश भेजा कि अभी कुछ दिनों वे दिल्ली न जाय। उन्होंने तार द्वारा माउन्टबेटन को भी सूचित कर दिया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रतिनिधि-मंडल तुरन्त दिल्ली लौटने में असमर्थ है। और आशा प्रकट की कि यदि प्रतिनिधि-मंडल बृहस्पतिवार या शुरुवार तक पहुँचेगा तो गवर्नर-जनरल बुरा नहीं मानेंगे। माउन्टबेटन तुरन्त राजी हो गए। निजाम ने २७ अक्टूबर को प्रतिनिधि-मंडल को मुलाकात देने पर कहा कि वह पूरी स्थिति पर फिर से विचार कर रहे हैं और इस बीच उनको रोके रखना चाहते हैं। लेकिन अपनी कार्यकारिणी के फ़ैमले से उन्होंने पूरी सहमति बतलाई। साफ़ शब्दों में उन्होंने इतिहाद और रिजवी की निन्दा की, जो व्यक्तिगत रूप से इस विंगत-प्रदर्शन का गगनत कर्म के उत्तरदायी थे। उन्होंने कहा कि वह रिजवी को यह फ़ैमला मजूर कराने पर मजबूर करेंगे।

दूसरे दिन निजाम ने प्रतिनिधि-मंडल को दूसरी बार मिलने के लिए बुलाया। रिजवी भी उसमें बजाये गए। लेकिन बजाय इसके कि वह रिजवी को राजी कर पायें, रिजवी निजाम पर छा गए। रिजवी ने इस समय के हद्दराबाद की मोत बतलाते हुए फिर से चर्चा शुरू करने के लिए मोका पाने की सलाह दी। उनका गयाल था कि भारत सरकार दूसरी जगह दिक्कतों में फ़ंसी हुई है और चर्चा करने के लिए यह ज्यादा मुभीने का मोका था। उन्होंने एक नये प्रतिनिधि-मंडल का मुताय रगा, जिनमें उन लोगों का रखना उचित होगा जिन्होंने कार्यकारिणी में उन मन्त्रिों के मिश्रण मत दिये थे। माकटन छतारी और अहमद मदन कहा कि ऐसा कोई काम उठाना होगा और बिनाजतारी होगा। उन पर उन्होंने अपने उत्तीर्ण भी दे दिये।

कहा था “यह तुम्हारा और तुम्हारी दौलत दोनों का अन्त है।”

इसी समय माउन्टबेटन के नाम निजाम का तार आया। उसमें कहा गया था, “बदली हुई राजनैतिक परिस्थिति” के कारण पुराना प्रतिनिधि-मंडल भग कर दिया गया है और नयेका निर्माण कार्यकारिणी के विरोधी सदस्योमे से किया गया है। नये प्रतिनिधि-मंडल के अध्यक्ष मोइन नवाज जग, मीर लायक अली के साले जो छतारी के स्थान पर प्रधान मंत्री बनाये गए थे। सितम्बर तक वह संयुक्त-राष्ट्र-संघ में पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे।

यह संभावना असंभव नहीं है कि निजाम की ये सब चालें हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करने की भूमिका है। लाहौर में जिन्ना के साथ हुई बातचीत में माउन्टबेटन ने खुले शब्दों में यह बात छेड़ी थी। सत्ताहस्तांतरण के पहले से कराची और हैदराबाद के बीच बराबर सम्पर्क कायम रहा था। लेकिन जिन्ना ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि निजाम के फैसले में परिवर्तन होने का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं और उन्होंने निजाम के साथ कभी किसी प्रकार के समझौते पर चर्चा नहीं की थी।

आते ही मोइन ने दून की हाकना गुरु किया। उन्होंने कहा कि निजाम हैदराबाद को सर्व-प्रभुसत्ता-सम्पन्न राज्य बनाना चाहते हैं, जिसका दोनों देशों से गहरा सम्बन्ध रहेगा और जिसकी विदेश-नीति आमतौर से भारत के समान होगी। लेकिन माउन्टबेटन उनके और उनके प्रतिनिधि-मंडल के साथ बड़ी कठोरता से पेश आये। कल उनसे पहली मुलाकात के समय उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय चर्चाओं के अपने लम्बे अनुभव में उन्होंने कभी ऐसा नासमझी भरा और अजीबो-गरीब रवैया नहीं देखा, जो हैदराबाद ने अपनाया था। कितने ही दिनों के धैर्यपूर्ण विचार के बाद जिस मसविदे को दूसरा पक्ष ठुकरा चुका था, उसे फिर सामने लाना क्या अर्थ रखता था। शक की किसी गुज़ाईश के बिना उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उनकी सरकार ‘यथास्थिति समझौते’ के इसी अन्तिम मसविदे पर दृढ़ है, जो पिछले-प्रतिनिधि-मंडल के दिल्ली से जाने के पूर्व लिखा गया था, जिसे निजाम की कार्य-कारिणी ने स्वीकार किया था और जिसे कुलॉट लगाने के पहले स्वयं निजाम ने मंजूर कर लिया था। अगर निजाम अपने ही फैसलों को भग करते रहेगे तो चर्चा टूट की सारी जिम्मेदारी उन पर ही होगी और भारत सरकार सारी दुनिया को यह बात बतलायगी।

एक रेडियो-भाषण द्वारा नेहरू ने काश्मीर के प्रश्न पर राष्ट्र-संघ के तत्वावधान में जनमत-संग्रह किये जाने का उदार सुझाव रखा है। यही बात माउन्टबेटन गत शनिवार को जिन्ना से कह चुके थे। उनका वक्तव्य काफी उदार और तर्कपूर्ण था। लेकिन, जैसा कि जिन्ना लाहौर की बैठक में स्पष्ट कर चुके थे, उनका विरोध जनमत-संग्रह के सुझाव से नहीं, बल्कि, उसके दौरान में काश्मीर में भारतीय-

सेनाओं की उपस्थिति से था। उनका कहना था कि ऐसा होने पर जनमत-संग्रह निष्पक्ष नहीं होगा। नेहरू और पटेल का अनुमान था कि जनमत-संग्रह का काम जाड़े के दिनों में नहीं हो सकेगा और उसके इन्तजाम में समय लगेगा।

नई दिल्ली, शनिवार, ८ नवम्बर १९४७

जूनागढ़ की समस्या नया सिरदर्द पैदा कर रही है। गत सोमवार को सुरक्षा-समिति की बैठक में केवल यह साधारण सूचना दी गई थी कि १ नवम्बर को मगरोल तथा बाबरियावाड पर भारतीय सेनाओं ने शांतिपूर्वक अधिकार कर लिया। यह आशा करना उचित ही था कि पटेल यही पसन्द करेंगे कि अन्य बड़ी समस्याओं के हल होने तक जूनागढ़ पर अधिकार करने का प्रश्न उठा रखा जाय।

परन्तु आज लगभग १ बजे रात को जूनागढ़ के दीवान ने भारत सरकार को राज्य पर अधिकार करने का औपचारिक आमन्त्रण दिया। दीवान ने लियाकत को सूचित किया कि वह लोकमत के बल, राज्य परिषद् के विशिष्टाधिकार और स्वयं नवाब की सम्मति से यह कार्यवाही कर रहे हैं। नवाब थोड़े ही समय पूर्व कराची चला गया था। भारत-सरकार ने तुरन्त दीवान का अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने राजकोटस्थित प्रादेशिक कमिश्नर को आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दे दिया।

ये सब बातें आज शाम को ही माउन्टबेटन को बताई गईं। यह पहला ही अवसर था, जबकि सरकार ने उनके साथ पूर्ण विचार-विनिमय किये बिना नीति-सम्बन्धी बड़ा निर्णय किया। वह महसूस करते हैं कि शायद पटेल और श्री बी पी मेनन ने उन्हें विषम उलझन से बचाने के लिए ही ऐसा किया था।

उधर निजाम बड़ी धृष्टता के साथ नई दिल्ली में उनके प्रति बची-खुची सद्भावना को भी खत्म किये दे रहे थे। 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्होंने और समय की मांग की है। चार दिन के कठोर परिश्रम के बाद उनके प्रतिनिधिमंडल को इस बात के लिए राजी किया जा सका था कि वह निजाम को सलाह देगा कि बिना किसी फेर-बदल के समझौते को स्वीकार कर लिया जाय। इस बिना पर कि माउन्टबेटन लन्दन जानेवाले थे, निजाम ने २५ नवम्बर तक की मोहलत मांगी। अपनी सरकार से सलाह करने के बाद माउन्टबेटन ने इसकी स्वीकृति दे दी, बशर्ते कि इस महीने के अन्त तक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिय जाय।

नई दिल्ली, रविवार, ९ नवम्बर १९४७

माउन्टबेटन-दम्पति को लन्दन के लिए विदा करने हम सवेरे तड़के पालम पहुँच गए। आखिरी मिनट तक माउन्टबेटन जाने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन



इस बात के अलावा कि राजकुमारी एलिजाबेथ उनकी चचेरी बहन है, दूल्हे लेफ्टिनेन्ट फिलिप माउन्टबेटन उनके भतीजे होने के अतिरिक्त पिछले अठारह वर्षों से उन्हींके परिवार में रहते रहे हैं, इसलिए उनका जाना अनिवार्य था।

दस बजे सवेरे मैंने राजगोपालाचारी की शपथ-विधि समारोह में भाग लिया। माउन्टबेटन की अनुपस्थिति में राजाजी ही गवर्नर-जनरल का कार्य करेंगे। सत्ता-हस्तांतरण के बाद से कांग्रेस के यह बुजुर्ग और प्रसिद्ध नेता बड़ी दक्षता के साथ पश्चिमी-बंगाल के गवर्नर का कार्य कर रहे हैं। यह समारोह कौंसिल भवन में मन्निमडल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। सफेद धोती पहने हुए राजाजी ने अपने मोटे और काले चश्मे के पीछे से हसते हुए दोनों हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। जब गृह-विभाग के सेक्रेटरी बनर्जी ने शाही आज्ञा-पत्र पढ़ना शुरू किया तो सब लोग उठकर खड़े हो गए, “हमारे विश्वस्त और सर्वप्रिय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बधाई।” प्रमुख न्यायाधीश कानिया ने शपथ दिलवाई, जिसमें केवल एक ही परिवर्तन किया गया था, “सोगन्ध” की जगह “प्रतिज्ञा” शब्द रखकर।

समारोह पांच मिनट के अन्दर पूरा हो गया, लेकिन अपने ऐतिहासिक महत्व का बोध कराने के लिए यह समय काफी था। अंग्रेजी राज्य के प्रतीक, जिस राजा की सत्ता का खात्मा करना इस बूढ़े कांग्रेसी के जीवन का मुख्य लक्ष्य था, उसीके द्वारा राज्य के प्रधान पद पर नियुक्त किये जाने के दृश्य में उद्देश्य-पूर्ति भी थी और नाटकीय व्यंग्य भी था।

कार्यवाहक गवर्नर-जनरल ने अपने अमले के लोगों को पहली भोज-पार्टी दी। मैं भी उसमें उपस्थित था। राजाजी की लजीली और गम्भीर प्रकृति वाली विवाहिता पुत्री श्रीमती नामगिरी ने अतिथिसत्कार का भार ग्रहण किया। जब परिचय के समय महिलाओं ने झुककर राजाजी का औपचारिक अभिवादन किया तो उन्होंने विनय से कहा, “मेरे लिए ऐसा मत कीजिए।”

: १६ :

प्रगति और अवगति

शिमला, शनिवार, २९ नवम्बर १९४७

राजाजी की अनुमति लेकर मैं अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गया हूँ। मेरी सेक्रेटरी मेरी सदरलैंड सरकारी भवन से आवश्यक कागज-पत्र

## प्रगति और अवगति

मुझे भेजती रहती है और टेलीफोन से पूरा सम्पर्क भी बनाये रहती है।  
आखिर निजाम ने 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर कर दिये थे। सरदार पटेल ने एक सुन्दर वक्तव्य दिया था, जिसमें चर्चाओं के दौरान में माउन्टबेटन द्वारा दिये गए निर्णायक सहयोग की पूरी-पूरी प्रशंसा की गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े निजाम के साथ चर्चा करना बड़े धीरज का काम था, क्योंकि वह परम्परागत पूर्वी कूटनीति के कट्टर उपासक है। बाहरी दुनिया की हलचलो से अनभिज्ञ निजाम अपने-आपको अपने ही पड़्यन्त्रों के जाल में फसाय बिना कोई निर्णय नहीं ले पाते।

अन्त तक ये चर्चाएँ बड़े ओछे ढग से चली। जब प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को माउन्टबेटन के साथ आखिरी मुलाकात हुई तो उसने निहायत मामूली गान्धिक परिवर्तनों के लिए हठ करना शुरू किया। यह बात इस सीमा तक जा पहुँची कि सिर्फ अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए और इस दावे को पक्का करने के लिए कि भारत सरकार उस मसविदे में परिवर्तन करने को तैयार हो गई थी, जो उनके पूर्वगामियों ने तैयार किया था, उन्होंने अल्प विराम की जगह अर्द्ध विराम लगाने के लिए आग्रह करना शुरू कर दिया। इसलिए माउन्टबेटन ने भी यही समझाने की कोशिश की कि वह एक अल्प विराम तक में परिवर्तन नहीं करेंगे। नत्थी-पत्रों में कुछेक आवश्यक मामूली सशोधन स्वीकार कर लिये गए, लेकिन यहाँ भी भारत सरकार अपने इस निश्चय पर अटल रही कि हैदराबाद को विदेश में अपने अलग कूटनीतिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं होगा।

इतिहाद और उसके उग्र नेता कासिम रिजवी, जो संयोगवश चर्चा के अन्तिम दौरे के समय दिल्ली में मौजूद थे, इससे अधिक कोई दावा नहीं कर सकते कि 'यथास्थिति समझौता' विशुद्ध हैदराबादी प्रतिनिधि-मंडल के हाथों हुआ था, लेकिन उनकी नाक रखनेका यह काम भी काफी कीमत चुकाने पर हो गया। निजाम और उनके इरादों से पटेल का विश्वास उठ गया। इस सब के बावजूद भी यथास्थिति समझौते ने एक साल की मोहलत दी थी, जिसमें दिमाग बड़े हो सके और दिल उदार।

नेहरू ने फिर एक सुन्दर भाषण दिया —विस्थापितों की समस्या पर। इसमें उन्होंने प्रतिहिंसा और प्रतिकार की भावनाओं का कड़ा विरोध किया और पूरी समस्या का बड़ा सतुलित चित्र पेश किया। गोमालास्वामी आयर ने ऐलान किया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारत-पाक चर्चा पहले सेक्रेटरियो के बीच होगी और फिर मंत्रियों के बीच। इसका अर्थ यह हुआ कि आपसी सम्बन्ध कामचलाऊ ढग से सुधारने के लिए हार्दिक प्रयास किया जायगा। पटेल न लियाकत के साथ हुई अपनी चर्चा को "सोहार्दपूर्ण" बतलाया और जिन्ना से सलाह करने के लिए लियाकत दिल्ली से रवाना हो गए। समुक्त सुरक्षा-कौंसिल को जिन्दा रखा

जायगा और अगली बैठक लाहौर में ६ दिसम्बर को होगी ।

शिमला, सोमवार, १ दिसम्बर १९४७

ऐसा लगता था कि काश्मीर की समस्या भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ देगी । नेताओं की समझ में यह बात आने लगी थी कि रियासत को भारत सभ में रखने के लिए तीस लाख काश्मीरी मुसलमानों को हजम करना और खुश रखना जरूरी होगा । इसलिए शेख अब्दुल्ला जनमत-संग्रह के पक्ष में होते जा रहे थे, जिसका भारत वादा कर चुका था । इस प्रश्न पर हिन्दू महासभा के खिलाफ गान्धी-नेहरू-अब्दुल्ला का संयुक्त मोर्चा बनने के आसार नजर आ रहे थे । कांग्रेस के अन्दर की साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी विचारधाराओं के बीच संघर्ष के लक्षण दिखलाई दे रहे थे । वे कांग्रेसी, जो हिन्दू-राष्ट्र के पक्ष में थे, काश्मीर के डच्छुक नहीं थे । लेकिन सरकार द्वारा काश्मीर में उठाये गए कदम ने उनका मुह बन्द कर दिया था ।

यह गहरा और नाजुक संघर्ष काश्मीर की समस्या तक ही सीमित नहीं था । इसका रूप काफी व्यापक था । हिन्दू महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विस्थापितों विषयक प्रस्ताव की निन्दा की थी । कांग्रेस के इस प्रस्ताव में कहा गया था कि कांग्रेस उन मुसलमानों को यहाँ से जाने के लिए प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं रखती जो यहाँ रुकने के डच्छुक थे । प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह सलाह दी गई थी कि विस्थापितों को अपने-अपने घरों को लौट जाना चाहिए । इसमें महासभा और कांग्रेस के बीच भारी संघर्ष के बीज निहित थे, और दोनों प्रस्तावों की कड़ी शब्दावली निकट भविष्य में विस्फोट का संकेत करती थी ।

हैदराबाद के साथ 'यथास्थिति समझौते' का पहला फल यह निकला कि निजाम ने कांग्रेस के स्थानीय राजनीतिक बढ़ियों को छोड़ने का निश्चय किया । राज्य-कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामानन्द तीर्थ सहित अधिकांश महत्वपूर्ण नेता चर्चाओं के दौरान में जेल में थे ।

शिमला, शनिवार, ६ दिसम्बर, १९४७

व्यवस्थापिका सभा में नेहरू ने विदेशनीति पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया । यह एक ऐसा क्षेत्र था, जिसमें उनके दिमाग को खुलकर काम करने का अवसर मिलता था । मुझे लगता है कि अपनी सरकार में विदेशमन्त्री के पद पर काम करने से उन्हें हार्दिक सतोष प्राप्त होता था । वह भारत को बड़ी शक्तियों के गुत्थम-गुत्थे से अलग रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे । बड़ी नाराजी से नेहरू इस बात का विरोध करते थे कि उनका लक्ष्य तटस्थता है । लेकिन इसमें शक नहीं कि उनकी

नीति का असर इसमें भिन्न नहीं होगा। वह संयुक्त-राष्ट्र अमरीका और ~~नेहरू~~ के साथ सहयोग का आह्वान करते थे और ब्रिटेन अथवा राष्ट्रमंडल के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते कि उन्हें आशा है कि राष्ट्रमंडल के कुछ सदस्यों के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार होगा। यह दक्षिण अफ्रीका पर परोक्ष आक्रमण जैसा प्रतीत होता था।

फिलस्तीन के विभाजन के विषय में संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के विषय में बोलते हुए नेहरू ने भारत के इस सुझाव पर आग्रह किया कि एक सत्र के अन्तर्गत दो स्वायत्त राष्ट्रों की स्थापना की जाय। उन्होंने कहा कि यह सुझाव राष्ट्र सत्र में विभाजन से ज्यादा बुद्धिमानी पूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विभाजन से काफी सकट पैदा हो चुके थे और आगे भी काफी होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व की बड़ी समस्याओं पर स्वतंत्र मत व्यक्त करने से भारत का मान बढ़ेगा। एक बड़े मार्क की बात उन्होंने कही राजनैतिक रूप से विदेशनीति देश के अन्दर चलने वाली आर्थिक नीति पर निर्भर करती है। भारत की आर्थिक नीति अभी तक निश्चित नहीं हो पाई। तात्कालिक आंतरिक सकट ने उसे भटकने पर मजबूर कर दिया है।

उधर, संयुक्त-राज्य अमरीका में नेहरू के प्रथम राजदूत, आसफअली, वाशिंगटन में अमरीकी आर्थिक सहायता के लिए हाथ-पैर मार रहे थे। उनका कहना था कि भारत की देनदारी की स्थिति दृढ़ है और वह एक अच्छी मडी है। भारत-पाक सम्बन्धों के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी आशा है कि ये सम्बन्ध सुधरेगे—कम-से-कम आर्थिक स्तर पर।

नई दिल्ली, गुरुवार, ११ दिसम्बर १९४७

विभिन्न दस्तावेजों के अध्ययन और माउन्टब्रेटन के साथ अपनी लम्बी बातचीत की सहायता से मैं काश्मीर में गत पखवारे के नाटकीय परिवर्तनों का इतिहास समझने की चेष्टा कर रहा था। इस पखवारे में इतनी कूटनीतिक हलचलें हुईं, जितनी प्रायः एक वर्ष में भी नहीं हुआ करती। दोनों देशों के बीच खाई को पाटने और पूरे प्रायद्वीप को छिन्न-भिन्न होने से बचाने के लिए माउन्टब्रेटन ने निसन्देह बड़े साहस का काम किया था।

इसमें ने भी शान्ति-स्थापना के काम में महत्वपूर्ण योग दिया—लियाकत और नेहरू के बीच नवम्बर के प्रारम्भ और गत सप्ताह दिल्ली में हुई, “सौहार्दपूर्ण” बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका खेलकर। दोनों नेताओं को एक-दूसरे से मिलाने में माउन्टब्रेटन को फिर से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था,, क्योंकि लियाकत ने बैठक के जरा पहले ही एक ऐसा तार भेजा, जो नेहरू को उत्तेजित करने के लिए काफी था। उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला को “देशद्रोही” कहा और भारत

सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह रियासत की पूरी मुसलमान आबादी का नाश करना चाहती है। अपनी यह माग भी उन्होंने दोहराई थी कि अविलम्ब एक निष्पक्ष और स्वतंत्र शासन की स्थापना की जाय।

सौभाग्य-वश नेहरू ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपने उचित रोप को झूठे अभिमान का रूप लेते हैं। इसलिए माउन्टबेटन उन्हें और लियाकत को काश्मीर के बारे में पहली बार स्पष्ट तौर से बातचीत करने के लिए राजी कर सके। नेहरू द्वारा मामले को विस्तार से पेश किये जाने के बाद लियाकत ने, जो अपनी हाल की बीमारी के बाद बहुत गिथिल और कमजोर दिखलाई पड़ते थे, कई प्रासंगिक सवाल पूछे और कुछ प्रस्ताव रखे, जिन पर विचार करने का नेहरू ने वादा किया। इसमें उच्च-स्तर के प्रस्तावों के मसविदे बनाने में बड़े निपुण थे। दोनों सरकारों की ओर से वी पी मेनन और मोहम्मद अली के सहयोग से उन्होंने तुरन्त इन प्रस्तावों को औपचारिक स्वरूप दे दिया। यही प्रस्ताव आगामी दोनों दिनों की चर्चा का आधार बने।

सक्षेप में प्रस्ताव ये थे पाकिस्तान विद्रोही 'आजाद काश्मीर' सेनाओं को युद्ध रोकने तथा कबाइलियों और अन्य हमलावरों को यथाशीघ्र काश्मीर की भूमि से लौटाने तथा उनके द्वारा फिर से हमला न होने देने में अपने सारे बल का प्रयोग करे। भारत अपनी सेना का अधिकांश भाग लौटा ले। केवल गड्ढवाड़ी को दवाने के लिए छोटी टुकड़ियाँ भर रखे। संयुक्त-राष्ट्र-संघ से कहा जाय कि वह काश्मीर में जनमत-संग्रह के लिए एक कमीशन भेजे और उसके पहले वह भारत-पाकिस्तान और काश्मीर से सिफारिश करे कि वे जनमत-संग्रह को सच्चा और निर्विघ्न बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कार्यवाहियाँ करने का विचार है, जैसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई और विस्थापितों की वापसी, उनकी तुरन्त घोषणा कर दी जाय।

इसमें की सहायता से बातचीत के अन्त में स्थिति यह रही कि हालांकि कोई निश्चित समझौता नहीं हो सका लेकिन नेहरू की आलोचना वस्तुस्थिति के विस्तार तक ही सीमित रही। लियाकत तीन शर्तों का आग्रह करने दिल्ली आये थे—दोनों पक्षों की काश्मीर से वापसी, जनमत-संग्रह के पूर्व एक निष्पक्ष शासन-व्यवस्था और निष्पक्ष जनमत-संग्रह। वह केवल अपनी तीसरी शर्त ही पूरी तौर पर मनवा सके और दूसरी शर्त आंशिक रूप में। इस प्रकार वह सैद्धांतिक रियायत देने में भी पीछे नहीं रहे। इसमें को पूरा विश्वास था कि राजनीतिक और शासनिक दोनों दृष्टियों से उक्त प्रस्ताव एक ऐसा हल प्रस्तुत करते हैं, जो कार्यान्वित हो सकता है। उनका यह भी विश्वास था कि समस्या के हल के लिए ऐसे प्रस्ताव पहली बार ही पेश किये गए हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि नींव सचमुच अच्छे ढंग से रखी जा चुकी है। किन्तु समझौता कराना हमेशा दिल तोड़ने वाला काम होता है।

दो दिन पहले माउन्टबेटन को एक ऐसी बैठक का सभापतित्व करना पड़ा

जिसको उन्होंने अपने जीवन की सबसे निराशाजनक बैठक बताया। मुरक्षाममिति के समक्ष पटेल और बलदेवसिंह द्वारा तवाही की खबर लेकर उपस्थित हुए। वे लोग मोर्चे पर से अभी-अभी लौटे थे। जो खबर वे लाये थे और जो सूचनाएँ नेहरू के पास स्वतंत्र रूप से पहुँची थी, उनके कारण मंत्रिमंडल का रुब-सुब खल हो गया और वह तात्कालिक जनमत-संग्रह और फिरहाल समझौता-चर्चा चलाने के भी विरुद्ध हो गए। उनकी तीन शिकायतें थीं। एक तो पश्चिमी पंजाब में कबाडलियों और हमलावरों की बड़ी संख्या में जमा होने की खबरें, दूसरे दिल्ली में लोटने के तुरन्त बाद ही लियाकत का हमलावरों को काश्मीर पर धावा बोलने के लिए उकसाने में मारी शक्ति लगा देना, तथा तीसरे, गर-मुसलमानों की सामूहिक हत्या, काश्मीरी लड़कियों की विक्री तथा अन्य क्रूरताओं की लगानार लोमहर्षक कहानियाँ।

दोनों के बीच फिर सम्पर्क-स्थापन का काम माउन्टबेटन द्वारा लियाकत को दिये इसी मुझाव में सम्भव हो सका कि समझौता-वार्ता पुनः चालू करने की तारीख की सूचना लियाकत तार द्वारा नेहरू को दे दे। लियाकत ने ऐसा ही किया और साथ ही यह भी आग्रह किया कि खून खराबी को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि मिलते-जुलते रहें। नेहरू ने तुरन्त इस मन्देश की भावना को स्वीकार कर लिया और वह पिछले सोमवार को मयूक्त-मुरक्षा-कोमिल की बैठक में शरीक होने के लिए माउन्टबेटन के साथ लाहौर गये।

वोच में भोजन के समय को निकालकर काश्मीर पर विचार-विनिमय ३ बजे से लेकर आधी रात तक, कुल ७ घंटे, चलता रहा। यह बैठक सामान्यतः मंत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और उत्तेजना की बातें केवल यदाकदा ही कही गईं। फिर भी माउन्टबेटन को, जिन्होंने विरोधी विचारों को मुलजाने का भरमक प्रयास किया, यह पता लग गया कि गतिरोध इतना पूर्ण था, तथा बाहरी और अन्दरूनी राजनैतिक दबाव इतना गहरा था कि अन्तर्गोष्ठीय अधिकार रखनेवाला कोई तीसरा दल ही स्प्रेच्छा से बीच-बचाव करने में समर्थ हो सकता है।

इन मोर्के पर माउन्टबेटन ने मुझाव दिया कि मयूक्त राष्ट्र मंच को तीसरे दल के रूप में बुलाया जाय। लियाकत ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि इसमें हमलावरों को रोकने में उन्हें बल मिलेगा। उन्होंने जिज्ञा के इस सदन का समय नही किया कि कराची के हुक्म मात्र में ही ये हमलावर लीटाए जा सकते हैं। नेहरू जानना चाहते थे कि मयूक्त राष्ट्र मंच के विधान की किस धारा के अन्सार अपील की जा सकती है। चूंकि अब आधी रात हो गई थी इसलिए माउन्टबेटन ने मुझावा कि इस विषय को और बागीकी में देखना चाहिए। यदावद के मारे नेहरू ने स्वीकृति-सूचक गर्दन हिलाई और बैठक समाप्त हो गई।

दिल्ली लौटने के बाद माउन्टबेटन गांधीजी और मेहनत में मिश्र चके थे। दोनों मयूक्त राष्ट्र मंच की मध्यस्थता के पक्ष में थे। आज उन्होंने नेहरू से और बातें की।

प्रस्ताव के पक्ष में उनका रख अब उतना नकारात्मक नहीं था।

नई दिल्ली, गुरुवार, १८ दिसम्बर १९४७

क्षितिज पर फिर काली घटाए घिर आई हैं और जैसा कि अक्सर गर्म देशों की आबतवा में हुआ करता है, सूरज छिपने के पहले ही तूफान हमारे सिरो पर आ फटा। सरकारी भवन में पहुँचने वाली खबरों से पता चलता था कि काश्मीर का मकट और भी गहरा होता जा रहा है। युद्ध की ओर झुकाव बढ़ गया था। ऐसा लगता था कि पटेल ने कड़ा हुक्म दिया था कि जब तक पाकिस्तान हमलावरों को महायना देना बन्द नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ हुए किसी भी वित्त-सम्बन्धी समझौते पर अमल नहीं किया जायगा। सवाल पचपन करोड़ रुपये का था और व्यापक राजनैतिक तथा नैतिक नतीजों के अलावा पाकिस्तान के लिए इसका आर्थिक परिणाम काफी गम्भीर होगा। पाकिस्तान के पास सिल्लक में केवल दो करोड़ रुपये थे, और उमें ऋण बहुत से चुकाने थे। इस वारे में सिर्फ यही तर्क दिया जायगा “अपने सिपाहियों की हत्या करने को हथियार खरीदने के लिए हम उन्हें रुपया क्यों दे ?” और यह तर्क मन्त्रिमंडल के सामने पेश किया जाने पर शायद ही उसका विरोध किया जाय।

अपने स्वतंत्र सूत्रों से भी भारतीय नेताओं को काश्मीर पर हमले में पाकिस्तान के सहयोग के अधिकाधिक सबूत प्राप्त हो रहे थे। उनके रख में कड़ाई आने का यही प्रधान कारण था। कुछ लोगों का खयाल था कि काश्मीर की घटना एक बड़े और व्यापक षडयंत्र का छोटा अंश मात्र है। उनका कहना था कि भारतीय सेनाओं को काश्मीर में फसाने के बाद पाकिस्तान हैदराबाद में सकट खड़ा करेगा और फिर पंजाब की सीमाएँ पार कर स्वयं दिल्ली पर चढ़ दौड़ेगा।

एक दूसरा मत यह भी था, जो कम उन्मादपूर्ण होने पर भी कहीं अधिक खतरनाक था। वह यह कि अगर पाकिस्तान हमलावरों को प्रवेश करने से रोकने में असमर्थ था, तो यह काम स्वयं भारत को करना पड़ेगा। लेकिन यह काम भारतीय फौजों को पाकिस्तानी सीमा से उस पार भेजने पर ही किया जा सकेगा। अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो छिपे युद्ध से खुला युद्ध कहीं श्रेयस्कर होगा। जहाँ तक इसके लिए उचित समय का सवाल था वे मेकबेथ<sup>१</sup> के इस सिद्धांत का समर्थन करते थे कि “अगर इसे करना ही है तो, जल्दी-से-जल्दी करना ज्यादा अच्छा होगा।” सरकारी क्षेत्रों में इस वारे में बड़ी चिन्ता फैली हुई थी कि सिखों की समस्या पर काश्मीर का कसा असर पड़ेगा। उनका अनुमान था कि काश्मीर की

तनातनी और युद्ध जितना अधिक चलता रहेगा, सिखों पर नियंत्रण रखना भी भारत सरकार के लिए उतना ही कठिन होता जायगा। ऐसा लगता था कि अगर लियाकत उचित राजनैतिक सुझाव पेश नहीं करेंगे, जिन्हें निगलना शायद उनके देश और उनके साथियों के लिए कठिन होगा, तो स्थिति निरन्तर खतरनाक होती जायगी।

जनता का सारा ध्यान काश्मीर पर केन्द्रित था। इस बीच पटेल उड़ीसा और मध्यप्रदेश से महत्वपूर्ण काम करके दिल्ली लौट आये थे। वी पी मेनन के सहयोग से वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पूर्वी रियासतों (जिनकी संख्या कुल नौ है, क्षेत्रफल छप्पन हजार वर्ग मील और आबादी सत्तर लाख) को इस बात के लिए राजी कर सके थे कि सब-प्रवेश से एक कदम आगे बढ़कर अपने को दोनों पड़ोसी राज्यों में विलीन कर दें। नई शर्तों के अनुसार हालांकि सारे अधिकार नये सच के अधीन चले जायेंगे लेकिन राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति, खिताब और उत्तराधिकार के अधिकार आदि ज्यों-के-त्यों कायम रहेंगे।

इससे सारे छोटे और बड़े राजाओं के लिए एक नई परम्परा का निर्माण हो गया था, जो अब उनको और भी ज्यादा बल से केन्द्रीय सरकार की ओर घसीटेगी। प्रसंगवश, यह याद दिलाना उचित होगा कि उड़ीसा की रियासतों को उड़ीसा प्रान्त के शासकीय सम्पर्क में लाने का पहला सुझाव करीब बीस वर्ष पहले साइमन-कमीशन की एक उपसमिति ने दिया था, जिसके अध्यक्ष थे साइमन के एक छोटे और ख्यातिहीन साथी मि सी आर एटली।

नई दिल्ली, सोमवार, २२ दिसम्बर १९४७

भारतीय मन्त्रिमंडल ने आखिर शनिवार को यह फैसला कर डाला कि हमलावरों को मदद देने के आरोप में पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सच में अपील की जाय। लियाकत और मुहम्मद अली कल शाम से दिल्ली में थे, लेकिन कल और आज की चर्चाओं का ऐसा कोई नतीजा नहीं निकला जिससे इस गम्भीर निर्णय को रद्द किया या टाला जा सके। अधिकांश समय अत्याचार के आरोपों और प्रत्यारोपों में ही निकल गया। शिकायत का औपचारिक पत्र आज नेहरू ने लियाकत को दे दिया। मामले को राष्ट्र सच के समक्ष पेश करने की यह आवश्यक भूमिका थी। लियाकतने जल्दी उत्तर देने का वादा किया। इस प्रकार काश्मीर के ऊपर होने वाले राजनैतिक और कूटनीतिक संघर्ष का पहला दौर समाप्त हुआ।

नई दिल्ली, बुधवार, ३१ दिसम्बर १९४७

१९४७ का वर्ष सामान्यतः भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों और विशेषतः काश्मीर



के भविष्य के लिए अपशकुन के साथ समाप्त हो रहा था। अलिप्त होकर भारत में व्यनीत नो प्रयासपूर्ण महीनो का लेखा-जोखा करना कठिन था। तात्कालिक परिस्थितियाँ हमेशा हमारे विचारों और मन पर हावी रहती हैं।

कम-से-कम काश्मीर के सम्बन्ध में तो हम इस सकट की कुछ स्पष्ट कल्पना के साथ १९४८ में प्रवेश कर रहे थे। जैसा कि माउन्टबेटन का अनुमान था, एटली ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उनका विचार था कि सामान्य समझौता कराने वाले की भूमिका खेलने के अतिरिक्त वह कोई निश्चित काम नहीं कर सकेगा। वह संयुक्त राष्ट्र सभ के “उचित माध्यम” पर निर्भर करना अधिक पसन्द करने थे। फिर भी, सावधानी से काम लेने पर जोर देते हुए उन्होंने नेहरू को एक बड़ा सुन्दर संदेश भेजा था।

मि एटली का उत्तर मिल जाने पर लियाकत के उत्तर के लिए अधिक न ठहर कर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सभ से अपील की दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया था। शिकायत की वाक्यावली नरम थी, और उसका मसविदा तब तैयार किया गया जब माउन्टबेटन ग्वालियर में थे। उसमें चिन्ताजनक वाक्य केवल एक था, वह यह कि परिस्थिति का तकादा होने पर सरकार को सैनिक कार्यवाही करने का हक होगा। माउन्टबेटन ने स्पष्ट कह दिया था कि धमकी या धमकी के संकेत के प्रति सुरक्षा परिषद् की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं हो सकती।

माउन्टबेटन ने नेहरू को समझाने का भरसक प्रयत्न किया कि पाकिस्तानी धरती पर आक्रमण करने का, विशेषतः जब भारत की शिकायत (संयुक्त राष्ट्र सभ के) विचाराधीन थी, क्या अर्थ होगा। विश्व के लोकमत पर तो इसका विघातक प्रभाव पड़ेगा ही, साथ ही दोनों उपनिवेशों में काम करनेवाले ब्रिटिश अफसरों को भी वापस चला जाना होगा। मेरे खयाल से, यह भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के तात्कालिक हितों के अधिक विपरीत होगा। परन्तु नेहरू भली-भाँति जानते थे कि इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही से भारत में माउन्टबेटन की सेवाओं का अन्त हो जायगा।

संयुक्त राष्ट्र सभ के पास भारत की अपील रवाना हो जाने के बाद ही लियाकत का उत्तर प्राप्त हो गया। वह प्रत्यारोपों का एक लम्बा सूचीपत्र ही था। प्रत्यारोपों को जानबूझकर काश्मीर तक सीमित नहीं रखा गया, वरन् इस सामान्य प्रकरण तक फैला दिया गया था कि भारत ने विभाजन मानने से इन्कार किया और वह पाकिस्तान को नष्ट कर देने के लिए कमर कसे था। लियाकत जूनागढ़ से लेकर अब तक के सब काडों में संयुक्त राष्ट्र सभ का हस्तक्षेप चाहते थे, “जिससे सारे विचाराधीन मतभेदों को मिटाया जा सके।” इन अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की पृष्ठ-भूमि में यह समाचार उत्साहजनक है कि उरी पर कोई आक्रमण नहीं किया गया और वहाँ की भारतीय सेना की विरोधी सेना से कोई मुठभेड़ नहीं हो पाई। माउन्टबेटन का अनुमान है



था, जो लोग दिल्ली में घटना-स्थल पर मौजूद नहीं थे, उन्हें मेरे लिए यह समझाना कठिन था कि अपने रोब और सम्मान के बावजूद माउन्टबेटन वैधानिक गवर्नर-जनरल मात्र हैं। भारत सरकार स्वयं अपने समाचार-पत्र-सम्बन्धी कष्टों से पीड़ित थी। काश्मीर के झगड़े को संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख भेजे जाने के निर्णय के अममय बाहर फूट निकलने से नेंहरू बड़े सकट में पड़ गए थे। यह समाचार मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति द्वारा ही बाहर पहुँच सकता था।

माउन्टबेटन द्वारा गत बैठक में नेंहरू को दिये गए सुझाव के अनुसार कर्नल कौल मरे घर पर मुझे मिलने आये। कर्नल कौल गोपाला स्वामी आयगार और शेख अब्दुल्ला के साथ जा रहे थे, जो लेक सक्सेस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा काम था कर्नल कौल को उनके सामने आने वाली जनसम्पर्क की कुछ समस्याओं के बारे में सलाह देना। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया कि शेख अब्दुल्ला का रंगीन व्यक्तित्व सहज ही लुटिया डुबो दे सकता है। दूसरी ओर आयगार, जिनके कन्धों पर मुख्यतः भारत का मामला पेश करने का भार रहेगा, अज्ञात व्यक्ति हैं। इसलिए लक्ष्य यह रहना चाहिए कि इस सतुलन को सुधारने के लिए आयगार को आगे रखा जाय और अब्दुल्ला को पीछे। जैसी प्रेस-काफ़ेस शेख अब्दुल्ला श्रीनगर में देते आये थे, वैसी लेक सक्सेस में सफल नहीं होगी। मैंने चेतावनी दी कि मामले के बल को जरा भी कमजोर नहीं होने दिया जाय, क्योंकि परिषद् में पेश किये जाने के पूर्व ही वह प्रेस काफ़ेस द्वारा सबकी निगाह में आ जायगा।

\* नई दिल्ली, बुधवार, ७ जनवरी १९४८

रियासती विभाग के मंत्री सरदार पटेल की हार्दिक सहमति से माउन्टबेटन इस सप्ताह बड़े और छोटे राजाओं में दो अलग-अलग दलों में सरकारी भवन में बैठ कर रहे थे। वह पुनः उनमें वह जीवन-शक्ति भरने का प्रयास कर रहे थे, जिसका राजाओं में स्वतः अभाव प्रतीत होता था। उन्होंने आज बड़े राजाओं को समझाया कि उनके राजकीय मामलों का नियंत्रण करने के लिए विशेषाधिकार समितियों की स्थापना करने का क्या महत्व था।

इस पर जो आम चर्चा हुई उसमें केवल अलवर-नरेश ने ही आपत्ति करने की जरूरत समझी। बड़े जोश और झगड़ालू स्वर में उन्होंने कहा, "अगर जनता नर्क में रहना पसन्द करे, तो उसे स्वर्ग में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।" जब माउन्टबेटन बड़े धैर्य के साथ बतला रहे थे कि राजाओं और राजपरिवार के लोगों द्वारा भारत सरकार की कूटनीतिक सेवा में शामिल होने के लाभ क्या होंगे, तो अलवर-नरेश ने उनकी बात काट कर कहा, "इसमें अहसान की कौन-सी बात हुई! अगर मेहनत रियासती विभाग के सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो महाराजा बीकानेर

## भारत-विभाजन की कहानी

आरोप लगाया। साफ जाहिर था कि उन्हें काबू में रखना टेढ़ी खीर थी। अगर यह उस नीति का पूर्वाभास था कि जो वह अमरीका में अपनाते जा रहे थे, तब तो भारत के हित को आग बढाने का काम खतरे में ही था।

नई दिल्ली, सोमवार, १२ जनवरी १९४८

दिल्ली जिमखाना क्लब में पत्रकारों की एक दावत में मुझे इस बात की पहली खबर मिली कि गांधीजी फिर आमरण अनशन शुरू करनेवाले हैं। उनके इस निश्चय की घोषणा प्रार्थना-सभा में इतनी अनायास हुई कि हम सभी स्तब्ध रह गए। मुझे तो और भी ज्यादा अचरज हुआ। इस घटना के कुछ ही पहले वनों के साथ 'स्ववेश' खेलकर लौटते समय माउन्टबेटन के बैठक की खिडकियों के सामने से गुजरते हुए मैंने उन्हें गांधीजी के साथ बातचीत करते देखा था। मुझे मालूम था कि मुलाकात जल्दी में तय की गई थी, लेकिन यह कल्पना नहीं थी कि इसका कोई विशेष महत्व भी हो सकता है।

वास्तव में वह अपनी प्रार्थना-सभा के बाद ही माउन्टबेटन से मिलने आये थे। इस प्रार्थना-सभा में उन्होंने कहा था कि यह उपवास तभी टूटेगा "जब मुझे विश्वास हो जायगा कि सब सम्प्रदाय के लोगो में हार्दिक मेल हो गया है। और यह किसी बाहरी दबाव से न होकर कर्तव्य की आंतरिक चेतना मात्र से हुआ है। और यह किसी ही मेरा सर्वोच्च और एकमात्र पथ-प्रदर्शक है, इसलिए मैंने यह महसूस किया कि यह निश्चय तो मुझे किसी और सलाहकार की सलाह के बिना ही लेना चाहिए।" प्रार्थना-सभा के पहले उनका मौन-दिवस खुला था। फलस्वरूप नेहरू और पटेल तक को उनके प्रस्तावित निश्चय का पहले से कोई पता न चल सका। फिर उन्होंने दिल्ली की दयनीय साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में अपनी गहरी पीड़ा की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इसका प्रायश्चित्त करेंगे।

माउन्टबेटन के साथ अपनी बातचीत में गांधीजी ने माउन्टबेटन से पूछा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को नकद सिल्लक में से पचपन करोड़ रुपये देने से इकार करने के बारे में उनका क्या मत था। माउन्टबेटन ने निस्कोच उत्तर दिया कि वह इस निश्चय को निहायत अराजनीतिज्ञ और अक्लमंदी से दूर समझते हैं। गांधीजी ने कहा कि इस विषय में वह नेहरू और पटेल से दूर समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में माउन्टबेटन की राय और उन्होंने ही किया था

आरोप लगाया। साफ जाहिर था कि उन्हें काबू में रखना टेढ़ी खीर थी। अगर यह उस नीति का पूर्वाभास था कि जो वह अमरीका में अपनाते जा रहे थे, तब तो भारत के हित को आगे बढ़ाने का काम खतरे में ही था।

नई दिल्ली, सोमवार, १२ जनवरी १९४८

दिल्ली जिमखाना क्लब में पत्रकारों की एक दावत में मुझे इस बात की पहली खबर मिली कि गांधीजी फिर आमरण अनशन शुरू करनेवाले हैं। उनके इस निश्चय की घोषणा प्रार्थना-सभा में इतनी अनायास हुई कि हम सभी स्तब्ध रह गए। मुझे तो और भी ज्यादा अचरज हुआ। इस घटना के कुछ ही पहले वर्नॉन के साथ 'स्वदेश' खेलेकर लौटते समय माउन्टबेटन के बैठक की खिड़कियों के सामने से गुजरते हुए मैंने उन्हें गांधीजी के साथ बातचीत करते देखा था। मुझे मालूम था कि मुलाकात जल्दी में तय की गई थी, लेकिन यह कल्पना नहीं थी कि इसका कोई विशेष महत्व भी हो सकता है।

वास्तव में वह अपनी प्रार्थना-सभा के बाद ही माउन्टबेटन से मिलने आये थे। इस प्रार्थना-सभा में उन्होंने कहा था कि यह उपवास तभी टूटेगा "जब मुझे विश्वास हो जायगा कि सब सम्प्रदाय के लोगों में हार्दिक मेल हो गया है। और यह किसी बाहरी दबाव से न होकर कर्तव्य की आंतरिक चेतना मात्र से हुआ है। भगवान ही मेरा सर्वोच्च और एकमात्र पथ-प्रदर्शक है, इसलिए मैंने यह महसूस किया कि यह निश्चय तो मुझे किसी और सलाहकार की सलाह के बिना ही लेना चाहिए।" प्रार्थना-सभा के पहले उनका मौन-दिवस खुला था। फलस्वरूप नेहरू और पटेल तक को उनके प्रस्तावित निश्चय का पहले से कोई पता न चल सका। फिर उन्होंने दिल्ली की दयनीय साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में अपनी गहरी पीड़ा की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह साम्प्रदायिकता जीवन के हर अंग में समा गई है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इसका प्रायश्चित्त करेंगे।

माउन्टबेटन के साथ अपनी बातचीत में गांधीजी ने माउन्टबेटन से पूछा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को नकद सिल्लक में से पचपन करोड़ रुपये देने से इकार करने के बारे में उनका क्या मत था। माउन्टबेटन ने निःसंकोच उत्तर दिया कि वह इस निश्चय को निहायत अराजनीतिज्ञ और अक्लमंदी से दूर समझते हैं। गांधीजी ने कहा कि इस विषय में वह नेहरू और पटेल से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वह उन्हें स्पष्ट कर देंगे कि इस पूछताछ का प्रारम्भ उन्होंने ही किया था और उन्होंने ही इस विषय में माउन्टबेटन की राय जाननी चाही थी।

## भारत-विभाजन की कहानी

दवाव और आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है। इस उपवास से ऐसी शक्ति पैदा हुई कि सब लोग अपने-अपने कामों को छोड़कर उसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे और उस वेदनामय कर्तव्य में हाथ बटा रहे थे, जिसकी कोई भी इन्सान पूरी तौर से उपेक्षा नहीं कर सकता।

बीकानेर, बुधवार, १४ जनवरी १९४८

गांधीजी के उपवासके वावजूद निश्चय किया गया कि माउन्टवेदन की चिर-प्रतीक्षित बीकानेर-यात्रा स्यगित न की जाय। लेकिन महात्माजी के प्रति सम्मान-स्वरूप शाही-भोज अवश्य नहीं होगा।

हमारे जाने के थोड़े समय पूर्व पटेल और नेहरू अगल-अलग माउन्टवेदन से मिलने आये। गांधीजी के निर्णय के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएँ इस बात की सबसे अच्छी समीक्षा है कि इस समय दोनों के विचारों और दृष्टिकोणों में कितना अंतर था। पटेल ने कहा कि उपवास का समय बहुत गलत चुना गया है और उसका असर गांधीजी के इच्छित प्रभाव के विल्कुल विपरीत होगा। दूसरी ओर नेहरू गांधीजी के निश्चय के प्रति अपनी खुशी और सराहना की भावना को छिपाने में असमर्थ थे।

लालगढ़ महल, बीकानेर, शुक्रवार, १६ जनवरी १९४८

आज पणिकर के साथ, जो अब भी महाराज के दीवान-पद पर थे, मेरी रोचक बातचीत हुई। वह गांधीजी के उपवास के बारे में बहुत आशावान थे। उनके विचार से यह उपवास पटेल के खिलाफ लक्ष्य करके किया गया था। उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले जब गांधीजी दिल्ली आये थे तो पटेल और गांधी में सर्वप्रथम की नौबत आ गई थी। तब गांधीजी ने कहा था, "बल्लभभाई, मैं तो हमेशा समझता आया था कि तुम और हम एक हैं। लेकिन देखता हूँ कि हम दो हैं।" वापू की इस गलतफहमी से पटेल के बारे में पणिकर की समीक्षा इस प्रकार थी हालांकि दोनो के सबबों के बारे में पणिकर को पता था पर वह जानते थे कि गांधीजी अब भी पटेल का कांग्रेस-संगठन पर पूरा नियंत्रण था पर वह जानते थे कि गांधीजी अब भी जनता के सर्वस्व हैं, और अगर वह चाहे तब भी महात्माजी के प्रभाव को तोड़ नहीं सकते। उधर गांधीजी नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन ऐसा करने में वह पटेल को तोड़ना नहीं, सिर्फ झुकाना चाहते थे।

इसके बाद पणिकर ने गांधीजी के राजनैतिक विवेक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लगभग बीस वर्ष के बाद वह हाल में गांधीजी से मिले, और इस मुलाकात में उन्होंने गांधीजी से विनय की कि रियासतों में वैधानिक सुधार के काम में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की नीति अपनाये। गांधीजी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा

दबाव और आत्मशुद्धि के लिए उपवास करना हिन्दू धर्म का अभिन्न अंग है। इस उपवास से ऐसी शक्ति पैदा हुई कि सब लोग-अपने-अपने कामों को छोड़कर उसकी ओर खिंचे चले आ रहे थे और उस वेदनामय कर्तव्य में हाथ बटा रहे थे, जिसकी कोई भी इन्सान पूरी तौर से उपेक्षा नहीं कर सकता।

बीकानेर, बुधवार, १४ जनवरी १९४८

गांधीजी के उपवासके बावजूद निश्चय किया गया कि माउन्टवेदन की चिर-प्रतीक्षित बीकानेर-यात्रा स्यगित न की जाय। लेकिन महात्माजी के प्रति सम्मान-स्वरूप शाही-भोज अवश्य नहीं होगा।

हमारे जाने के थोड़े समय पूर्व पटेल और नेहरू अगल-अलग माउन्टवेदन से मिलने आये। गांधीजी के निर्णय के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएँ इस बात की सबसे अच्छी समीक्षा है कि इस समय दोनों के विचारों और दृष्टिकोणों में कितना अन्तर था। पटेल ने कहा कि उपवास का समय बहुत गलत चुना गया है और उसका असर गांधीजी के इच्छित प्रभाव के बिल्कुल विपरीत होगा। दूसरी ओर नेहरू गांधीजी के निश्चय के प्रति अपनी खुशी और सराहना की भावना को छिपाने में असमर्थ थे।

लालगढ़ महल, बीकानेर, शुक्रवार, १६ जनवरी १९४८

आज पणिक्कर के साथ, जो अब भी महाराज के दीवान-पद पर थे, मेरी रोचक बातचीत हुई। वह गांधीजी के उपवास के बारे में बहुत आशावान थे। उनके विचार से यह उपवास पटेल के खिलाफ लक्ष्य करके किया गया था। उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले जब गांधीजी दिल्ली आये थे तो पटेल और गांधी में सवर्ण की नीवत आई थी। तब गांधीजी ने कहा था, "बल्लभभाई, मैं तो हमेशा समझता आया था कि तुम और हम एक हैं। लेकिन देखता हूँ कि हम दो हैं।" बापू की इस गलतफहमी से पटेल को आखे भर आई थी।

दोनों के सत्रों के बारे में पणिक्कर की समीक्षा इस प्रकार थी। हालाँकि पटेल का कांग्रेस-संगठन पर पूरा नियंत्रण था पर वह जानते थे कि गांधीजी अब भी जनता के सर्वस्व हैं, और अगर वह चाहे तब भी महात्माजी के प्रभाव को तोड़ नहीं सकते। उधर गांधीजी नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए कटिबद्ध थे। लेकिन ऐसा करने में वह पटेल को तोड़ना नहीं, सिर्फ झुकाना चाहते थे।

इसके बाद पणिक्कर ने गांधीजी के राजनैतिक विवेक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लगभग बीस वर्ष के बाद वह हाल में गांधीजी से मिले, और इस मुलाकात में उन्होंने गांधीजी से विनय की कि रियासतों में वैधानिक सुधार के काम में धीरे-धीरे आगे बढ़ने की नीति अपनाये। गांधीजी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा

“आप चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रियावादियों को पैर जमाने दूँ।” पणिकर ने कहा, “इसका मेरे पास कोई उत्तर न था।” बात सही भी थी। फिर पणिकर ने कहा कि गांधीजी अपने श्रोताओं की भाषा बोलते थे। इपीलिए उनकी प्रार्थना-सभा जैसे अवसर अपनी सादगी के कारण भ्रम पैदा कर देते थे। व्यक्तिगत चर्चा में वह ज्यादा तीखेपन से काम लेते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधीजी का “गुप्तचर” विभाग भी बड़ा सुव्यवस्थित था। सारे देश से उनके पास व्यक्तिगत पत्र आते रहते थे, जिनसे उन्हें देश की स्थिति के समाचार मिलते रहते थे।

आज तीसरे पहर हमने सुना कि सद्भावना के प्रतीकस्वरूप मन्निमडल ने पाकिस्तान को पचपन करोड़ पये देना स्वीकार कर लिया है। फिल्म शो के बाद माउन्टबेटन ने कहा कि पिछले तीन महीनों की यह सबश्रृंखला घटना है। लेकिन पणिकर ने चिन्ता प्रगट करते हुए कहा कि पटेल पर इस फैसले की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी।

नई दिल्ली, रविवार, १७ जनवरी १९४८

सवेरा होते ही हम दिल्ली के लिए चल पड़े। शाही अतिथि-सत्कार की छाप हम अपने साथ लेकर चले थे। बीकानेर परम्परा और सुधार का सुन्दर मिश्रण था और अपनी जनता की सामाजिक एकता और नगर रक्षक के प्रति राजनैतिक निष्ठा के मामले में अपने नरेश-ब्रह्मों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा था।

हमारे लौटने के थोड़ा ही देर बाद माउन्टबेटन-दम्पति गांधीजी से मिलने बिडलाभवन गये। गांधीजी काफी कमजोर हो गए थे। उन्होंने स्वागत करने हुए कहा, “आपको यहाँ बुलाने के लिए उम्मास की जरूरत पड़ती है।” फिर उन्होंने इसे समाप्त करने के बारे में चर्चा की। गांधीजी ने कहा कि उन्होंने सात शर्तें रखी थीं। इन सबका समय दिल्ली और सन्तरे भारत में रहनेवाले मुजलमानों की बुनियादी सुरक्षा और नगरिक अधिकारों से था। उनके पूरे होने पर ही वह उम्मास समाप्त करने का विचार कर सकते थे।

: २१ :

गांधी का बलिदान

नई दिल्ली, रविवार, १८ जनवरी १९४८

पचपन करोड़ के बारे में मन्निमडल का फैसला होने ही राजद्रवात्रू और मौलाना आजाद के निदर्शन में एक अन्तर-साम्प्रदायिक-शांतिकमेढी की स्थापना



की गई। इस कमेटी ने बड़े मराहनीय उत्साह से काम किया, और आज सवेरे महात्माजी को यह विश्वास दिलाने में सफल हुई कि दिल्ली में आवश्यक हृदय-परिवर्तन हो गया है और अब उन्हें अपना उपवास तोड़ देना चाहिए। उपवास को शुरू हुए एक सौ इक्कीस घंटे से ज्यादा हो चुके थे, जिससे गांधीजी के कृश शरीर की सचित-शक्ति पर भारी जोर पड़ा था।

उपवास ने मुसलमानों का मनोबल बढ़ाने में निःसंदेह भारी योग दिया था। लेकिन सिख लोग अवश्य अड़े हुए थे। "गांधी को मरने दो" के नारे लगाते हुए और हाथ में काले झंडे लिये सिखों के जलूस विडला-भवन के सामने से निकाले गए। लेकिन सिख-प्रतिनिधियों ने अन्तर-साम्प्रदायिक कमेटी में भाग लेने से इंकार नहीं किया।

अपनी प्रार्थना-सभा को आज शाम भेजे गए एक सन्देश में गांधीजी ने कहा कि अगर उनका प्रण पूरा हो गया तो वह "दुगने बल से भगवान से प्रार्थना और कामना करेंगे कि वह पूर्णायु होकर आखिरी क्षण तक मानवता की सेवा करते रहे।" कुछ विद्वान पूर्णायु का अर्थ कम-से-कम एक सौ पच्चीस साल मानते हैं और कुछ एक सौ तैंतीस।

नई दिल्ली, मंगलवार, २० जनवरी १९४८

गांधीजी के उपवास की समाप्ति के उपलक्ष में होने वाली खुशियां विडला-भवन के बागीचे में हुए बम्ब-कांड से फीकी पड़ गई, यह हाथ का बना वम उपवास के बाद की पहली प्रार्थना-सभा में फूटा, जिसमें गांधीजी उपस्थित थे। विस्फोट का सारा जोर एक दीवाल पर पड़ा, जो थोड़ी-सी ढरक गई थी। किमी के कोई चोट नहीं पहुंची, न कोई भगदड़ ही मची। गांधीजी का प्रवचन ऐसे चलता रहा मानो कोई अनिष्टकारी घटना घटी ही न हो। लेडी माउन्टवेटन ने समाचार सुनते ही वहां पहुंचने पर उन्हें विलकुल अनद्विग्न पाया। उन्होंने लेडी माउन्टवेटन से कहा, "मैं समझा कि कहीं नजदीक में सैनिक-अभ्यास चल रहे हैं।"

नई दिल्ली, शुक्रवार, ३० जनवरी १९४८

माउन्टवेटन आज मद्रास से वापस आ गए। वहां जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया।

शाम को ६ बजे से १० मिनट के लगभग मैं जार्ज निकोल्स के कमरे में गया। उन्होंने बताया कि गांधीजी की हत्या का प्रयत्न किया गया था और उन्हें तीन गोलियां लगी हैं। आधे घंटे बाद मैंने माउन्टवेटन के ड्राइवर पियर्स से सुना कि गांधीजी नहीं रहे। अपने मोटर में लगे हुए रेडियो में यह समाचार सुना था। उसने बताया कि माउन्टवेटन तत्काल सीधे विडला-भवन जा रहे हैं।

## गांधी का बलिदान

मैं मोटर के पास ही खड़ा था कि माउन्टबेटन बाहर आये। उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से अपने साथ चलने को कहा। वह बहुत व्यग्र थे और छोटे-छोटे अधूरे वाक्यों में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राजगोपालाचारी न कलकत्ता से फोन किया था कि नेहरू की रक्षा के अधिक-से-अधिक प्रबन्ध की आवश्यकता है। केवल दो दिन पूर्व ही जब नेहरू अमृतसर की एक सभा में भाषण दे रहे थे तो दो व्यक्तियों को हथगोलो सहित गिरफ्तार किया गया था।

माउन्टबेटन का खयाल था कि यह घटना अत्यन्त गम्भीर है। इससे नेहरू बिल्कुल एकाकी रह गए हैं और राजनैतिक रूप से बे-सहारे-से हैं। अब सब-कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि उनमें आगामी कुछ घंटों की स्थिति पर नियंत्रण रखने की कितनी क्षमता है। उनका गीघ्र-से-शीघ्र राष्ट्र को सदेश देना आवश्यक है, परन्तु उन्हें जो कुछ कहना है, उसपर पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि देश उनके कहे पर चलेगा।

हमारे विडला-भवन पहुंचने के समय तक वहां भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। चारों ओर गडबडी थी। नौजवानों की भीड़ भवन की खिड़कियों पर टटी पड़ रही थी। अन्दर लगभग सभी मंत्री और प्रमुख कांग्रेसजन शोक से स्तब्ध खड़े थे। हम गांधीजी के शयन-कक्ष में गये। वहां धूप की सुगन्ध आ रही थी। कमरे में लगभग ४० व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें नेहरू और पटेल भी थे। हर एक की आखों से आसू बह रहे थे। कमरे के बाहर अमरुप जूते रख थे, जिन्हें लोगों ने अन्दर आने के पहले उतार दिया था।

सुदूर कोने में गांधीजी का निष्प्राण शरीर प्रतिष्ठित था। पहले मैंने समझा कि उसे किसी बड़े कम्बल से ढक दिया गया है, परन्तु बाद में मैंने देखा कि उनके आसपास लगभग एक दर्जन महिलाएँ बैठी थी और आर्त स्वर में प्रार्थना कर रही थी। उनमें से एक महिला उनके सिर को सम्भाले हुए थी।

गांधीजी की मुद्रा शान्त थी और तीव्र प्रकाश में कुछ पीली दिखलाई पड़ती थी। उनका लोहे के फ्रेम का चरमा में कुछ पीली दिखलाई पड़ती थी, उतार लिया गया था। धूप की सुगन्ध, महिलाओं के भजन का स्वर, छोटा-सा 'दु'ल शरीर, सोती हुई-सी मुख-मुद्रा और मूक-दर्शक—कदाचित् ये मेरे जीवन के सबसे अधिक सनसनीपूर्ण क्षण थे। वहां खड़ा-खड़ा मैं भविष्य के बारे में व्याकुल हो रहा था, इस दुष्कृत्य पर चकरा रहा था। परन्तु पराजय के स्थान पर विजय की अनुभूति भी कर रहा था। मैं महसूस करता था कि इस छोटे-से पुरुष के आदर्शों की शक्ति हत्यारे की गोलियों और उनमें निहित विचार-धारा को दवाने के लिए काफी प्रबल सिद्ध होगी।

कुछ देर तक मोन श्रद्धाजलि देने के बाद हम बड़े कमरे में आ गए। बाहर जन-समुदाय बढ़ता ही जा रहा था और खिड़कियों के काचों पर लगातार हाथ पीटते

जा रहे थे। मन्निमडल के सदस्य दूसरे कमरे में थे। अतएव माउन्टबेटन उनसे बात करने के लिए वहाँ चले गए।

मैने माउन्टबेटन को कहते हुए सुना कि गांधीजी ने उनसे अन्तिम भेंट में कहा था, "मेरी सबसे बड़ी इच्छा नेहरू और पटेल में हार्दिक मेल कराने की है।" यह सुनकर दोनों ने नाटकीय ढंग से एक-दूसरे का आलिंगन किया। कुछ देर बाद माउन्टबेटन बाहर निकल आये। उन्होंने कहा, "पर मैने पटेल को नेहरू के साथ आज रेडियो पर बोलने को सहमत कर लिया है।" वह इसे बड़ी विजय समझते थे—और इसमें तथ्य भी था। उन्होंने फिर कहा कि सब कुछ नेहरू द्वारा स्थिति को तुरन्त सम्भाल लेने पर निर्भर करता है।

तनातनी इतनी अधिक थी कि कोई भी असावधानी भरा शब्द या अफवाह दावानल के समान फैल जायगी। माउन्टबेटन के आते ही किसी आतक फैलाने वाले ने उनका इन शब्दों से स्वागत किया था, "हत्यारा मुसलमान था।" उस समय तक हत्यारे के धर्म और नाम का हमें कोई पता नहीं था। परन्तु माउन्टबेटन ने यह समझ कर कि यदि वह मुसलमान था तो ससार की कोई शक्ति नितान्त विनाशक गृह-युद्ध को टाल नहीं सकती, अन्तःप्रेरणा से तुरन्त उत्तर दिया, "मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि वह हिन्दू था।"

कुछ मिनट बाद मुझे वी पी मेनन से पता चला कि हत्यारा एक मराठा है। जैसे ही गांधीजी अपनी प्रार्थना-सभा में जाने के लिए निकले उसने विलकुल निकट से उनपर तीन गोलियाँ चलाई। मैने डाक्टर से भी बात की, जो अन्तिम समय से गांधीजी के पास था। उसने कहा कि मकान में एक भी दवा नहीं थी, लेकिन अगर होती भी तो कोई फायदा न होता। गांधीजी ने जरा-सा पानी पिया और फिर उनकी चेतना जाती रही, जो कभी नहीं लौटी। अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। गांधीजी का स्पष्ट आदेश था कि उनके शरीर को सुरक्षित न रखा जाय, "बल्कि हिन्दू-पद्धति के अनुसार शीघ्र-से-शीघ्र जला दिया जाय।" माउन्टबेटन चाहते थे कि दाहनास्कार कम-से-कम २४ घंटे बाद हो, ताकि उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। परन्तु स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था कि वह कल प्रातःकाल किया जायगा। अतएव प्रबन्ध का भार मन्त्रालय को सौंप देन का निश्चय किया गया। माउन्टबेटन ने अपनी अग-रक्षक टुकड़ी को भी मदद के लिए भेज दिया था। समय के साथ भीड़ बढ़ती ही गई। मौलाना आजाद जैसे कुछ लोग नोरव चिन्ता में निरत थे, श्री मुंशी जैसे कुछ अन्य व्यक्ति स्वेच्छा से व्यवस्था करने में व्यस्त थे। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और गांधीजी के शरीर के दशनो के लिए आग्रह कर रही थी। चारों तरफ से सैकड़ों आखे भवन पर लगी हुई थी और लगता था कि शीशों की खिड़कियाँ शायद ही जन-समूह के दबाव के भार को सभाल पायगी।

मैने नेहरू को इस सामूहिक हमले के खतरे के प्रति सचेत किया। नेहरू अवर्णनीय

## भारत-विभाजन की कहानी

६८

मे दब गए। अर्थी की गाड़ी को कांग्रेस के झण्डों और फूलों से सजा कर तैयार किया गया था, जिसे नौसेना के सैनिक खींचेंगे। अर्थी के निकट स्थान पान के लिए मंत्री और जनरलों को सामान्य नागरिकों से कन्धे-से-कन्धे मिलानी पड़ रहे थे—यह गांधी जी के मन की चीज थी।

कांग्रेस के चार आना सदस्य, जो उनकी कितनी ही लडाइयों के सैनिक रहे थे, पूरे जोश के साथ वहां उपस्थित थे। शरीर को छत से लाकर अर्थी पर रख दिया गया। जब शव को अर्थी पर प्रतिष्ठित किया गया, तो एक बार फिर मुझ पर उस शान्त-मुद्रा का गम्भीर असर पड़ा। आसपास गांधीजी के पुत्र और पौत्रिया बैठी थीं।

बालिकाएं अब भी रो रही थीं और धीरे-धीरे उनके सिर पर थपकिया दे रही थीं। पटेल भी पास ही निश्चल भाव से सामने देखते बैठे हुए थे। गांधीजी के निधन और गण दिखलाई पड़ते थे। यह व्यवस्था के उन कठिन कामों में कोई भाग नहीं ले रहे थे, जिनमें नेहरू और माउन्टबेटन जुटे हुए थे।

गई रात नेहरू और पटेल दोनों के ही भाषण बहुत मर्मस्पर्शी थे। पहले से तैयार न किये जाने के कारण वे ज्यादा प्रभावशील बन पड़े थे। गांधीजी के निधन से पटेल की व्यक्तिगत क्षति तो हुई ही, साथ ही उन्हें गृह-मंत्री की हैसियत से भी एक भारी धक्का पहुंचा। यह सच था कि गांधीजी ने सरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करने से इकार कर दिया था परन्तु यह भी उतना ही सच था कि दस दिन पूर्व के बम-विस्फोट और कल के जघन्य-कार्य में सम्बन्ध था और पुलिस इतने दिनों तक उसकी टोह पाने में असफल रही थी।

गोलियां खाकर गिरने से पूर्व गांधीजी पटेल से ही बातें कर रहे थे और उन्हें बातचीत के कारण कुछ विलम्ब भी हो गया था। पटेल ने अर्थी के पूरे जलूस में शामिल होकर इसका पूर्ण प्रायश्चित्त किया, क्योंकि उनकी ७२ वर्ष की अवस्था और गिरा हुआ स्वास्थ्य इसके योग्य नहीं था।

अतः मे उस अपार मानव-सागर से अपना रास्ता निकालता हुआ अर्थी का जलूस आगे बढ़ चला। इस समय लगभग ग्यारह वजे थे और सारे रास्ते विशाल जन-समूह एकत्रित था। उनकी सख्या इतनी थी कि पुलिस और मेना उसे काबू में नहीं रख सकती थी। उनके भारी दबाव के कारण अर्थी की चाल एक मील प्रति घंटा से अधिक नहीं बैठ सकी। जलूस के आगे बढ़ने की गति इतनी धीमी होने के कारण लोगो ने जलूस के साथ चलना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोड़ा देर से अर्थी के पीछे चलने वाले समूह की सख्या इतनी ही विशाल हो गई जितनी कि आगे मौजूद लोगो की थी।

सरकारी भवन में लौटने पर हमने दरबार भवन के गुंबज के ऊपर चढ़कर देखा। जलूस 'किंगज्वे' के खुले मैदान पर मानो रुक गया था। भीड़ ने अर्थी के आस-पास होकर आगे बढ़ना असंभव बना दिया था।

मे दब गए। अर्थी की गाड़ी को कांग्रेस के झण्डों और फूलों से सजा कर तैयार किया गया था, जिसे नौसेना के सैनिक खींचेंगे। अर्थी के निकट स्थान पाने के लिए मंत्री और जनरलों को सामान्य नागरिकों से कन्धे-से-कन्धे मिलाना पड़ रहे थे—यह गांधी जी के मन की चीज थी।

कांग्रेस के चार आना सदस्य, जो उनकी कितनी ही लड़ाइयों के सैनिक रहे थे, पूरे जोश के साथ वहाँ उपस्थित थे। शरीर को छत से लाकर अर्थी पर रख दिया गया।

जब शव को अर्थी पर प्रतिष्ठित किया गया, तो एक बार फिर मुझ पर उस शान्त-मुद्रा का गम्भीर असर पड़ा। आसपास गांधीजी के पुत्र और पौत्रिया बँठी थीं। बालिकाएँ अब भी रो रही थी और धीरे-धीरे उनके सिर पर थपकिया दे रही थीं। पटेल भी पास ही निश्चल भाव से सामने देखते बैठे हुए थे। वह पीले पड़ गए थे और गण दिखलाई पड़ते थे। यह व्यवस्था के उन कठिन कामों में कोई भाग नहीं ले रहे थे, जिनमें नेहरू और माउन्टबेटन जुटे हुए थे।

गई रात नेहरू और पटेल दोनों के ही भाषण बहुत मर्मस्पर्शी थे। पहले से तैयार न किये जाने के कारण वे ज्यादा प्रभावशील बन पड़े थे। गांधीजी के निधन से पटेल की व्यक्तिगत क्षति तो हुई ही, साथ ही उन्हें गृह-मंत्री की हैसियत से भी एक भारी धक्का पहुँचा। यह सच था कि गांधीजी ने सरक्षण की व्यवस्था स्वीकार करने से इकार कर दिया था परन्तु यह भी उतना ही सच था कि दस दिन पूर्व के बम-विस्फोट और कल के जघन्य-कार्य में सम्बन्ध था और पुलिस इतने दिनों तक उसकी टोह पाने में असफल रही थी।

गोलिया खाकर गिरने से पूर्व गांधीजी पटेल से ही बातें कर रहे थे और उन्हें बातचीत के कारण कुछ विलम्ब भी हो गया था। पटेल ने अर्थी के पूरे जलूस में शामिल होकर इसका पूर्ण प्रायश्चित्त किया, क्योंकि उनकी ७२ वर्ष की अवस्था और गिरा हुआ स्वास्थ्य इसके योग्य नहीं था।

अतः मे उस अपार मानव-सागर से अपना रास्ता निकालता हुआ अर्थी का जलूस आगे बढ़ चला। इस समय लगभग ग्यारह वजे थे और सारे रास्ते विशाल जन-समूह एकत्रित था। उनकी सख्या इतनी थी कि पुलिस और मेना उसे काबू में नहीं रख सकती थीं। उनके भारी दबाव के कारण अर्थी की चाल एक मील प्रति घंटा से अधिक नहीं बैठ सकी। जलूस के आगे बढ़ने की गति इतनी धीमी होने के कारण लोगो ने जलूस के साथ चलना गुरु कर दिया, जिसके फलस्वरूप थोड़ा देर में अर्थी के पीछे चलने वाले समूह की सख्या इतनी ही विशाल हो गई जितनी कि आगे मौजूद लोगो की थी।

सरकारी भवन में लौटने पर हमने दरबार भवन के गुंबद के ऊपर चढ़कर देखा। जलूस 'किंगजवे' के खुले मैदान पर मानो रुक गया था। भीड़ ने अर्थी के आस-पास एकत्र होकर आगे बढ़ना असंभव बना दिया था।



“हमें अब चलना चाहिए।” इतना कह कर वह चल दिया और हमें बहुत से लोगों ने भी उनका अनुकरण किया। इसका अच्छा परिणाम हुआ। बहुत से लोगों का स्व-वदल गया।

जैसे-जैसे हम भीड़ से बाहर जा रहे थे चिता की ज्वालाएँ और धुआँ आकाश की ओर उठता जा रहा था।

नई दिल्ली, मंगलवार, ३ फरवरी १९४८

गांधीजी की मृत्यु पर विश्व में इतनी प्रतिक्रिया हुई, जिसकी मुझे-कल्पना नहीं थी। दुनिया के कोने-से-कोने से श्रद्धाजलि और प्रशंसा के सन्देशों का ताता लगा हुआ था, जिनसे पता चलता था कि उनका प्रभाव भारत की सीमा के बाहर बहुत-दूर-दूर तक फैला हुआ था। हो सकता था कि उनके जीवन का पूरा दर्शन बहुत से लोगों के पल्ले न पड़ा हो, लेकिन उसका रहस्य तो स्वीकार किया ही जाता था। जैसा कि किंग्सले मार्टिन ने, जो इस तमाम घटना में मेरे साथ थे, मुझसे कहा था, “भौतिकवाद और राजनैतिक बल-प्रयोग दुनिया में ज्यादा सफलता पान में कामयाब नहीं हुआ। दुनिया स्वीकार करती है कि गांधीजी का उद्देश्य इन दोनों से भिन्न था। नैतिक मूल्यों पर उनके आग्रह से लगता है कि उनके उद्देश्य शायद बेहतर भी थे। इसीलिए वह मानवता के मानस पर अमिट छाप छोड़ गए थे।”

‘न्यूयाक टाइम्स’ के शब्दों में, “जैसे अन्य लोग सत्ता और सम्पत्ति के लिए हाथ-पैर मारते थे, वैसे ही उन्होंने पूणता के लिए प्रयास किया। उनका राजनैतिक प्रभाव जैसे-जैसे कम होता गया उनकी मीहार्द-भावना वैसे-ही-वैसे बढ़ती गई। ‘नये टस्टामेन्ट’ की भावना के अनुरूप उन्होंने अपने शत्रुओं को प्रेम करने का प्रयास किया और उनकी भलाई करने की कोशिश की कि जो उनके साथ द्वेष का बरताव करते थे। वह अमर हो गए।” ‘दि क्रिश्चियन सायस मानीटर’ ने उन्हें “प्रस्तुत युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिवादी” के रूप में देखा। इस प्रकार वह भारतीय राष्ट्रीयता के नेता मात्र नहीं थे, वह समस्त विश्व के प्रतीक थे। इस पत्र ने फिर एक बड़े मार्क की बात कही थी, जो उनके उद्देश्यों और “द्विमूर्खी” व्यक्तित्व के बारे में भ्रम का असली कारण था। लेख में कहा गया था, “उनका यह विश्वास कि नैतिक प्रेरणा से व्यक्ति पहाड़ तक को उठा सकता है उसमें पश्चिमी विचारकों की एक बड़ी देन, कानून के प्रति आदर की भावना से विहीन था।” लुई फिशर ने कहा था, “अधिकांश लोगों के लिए राजनीति का अर्थ था सरकार, गांधीजी के लिए इसका अर्थ था मानव-जाति। लेकिन सरकार के अभाव में मनुष्य अपने उद्देश्यों को नापन में असमर्थ रहता है। इसीलिए दुनिया ने गांधीजी में चतुर राजनीतिज्ञ और अकलुप और अटल साधुत्व का मिश्रण पाया। उन्होंने अकेले व्यक्ति के नैतिक बल को प्रमाणित कर दिखाया।”





हो कर गाय कि अगर गांधीजी होते तो आशीर्वाद दिये बिना न रहते।

उपसहार के रूप में आज रेडियो पर माउन्टबेटन ने गांधीजी को अपनी अन्तिम श्रद्धाजलि दी। यह गांधीजी की स्मृति में श्रद्धाजलि-भाषणों की आखिरी कड़ी थी, जिसका प्रारम्भ ३० जनवरी को नेहरू और पटेल के भाषणों से हुआ था, जिसमें उन्होंने एकता और प्रायश्चित्त का दृढ़ आह्वान किया था। करीब-करीब सभी कांग्रेसी-नेताओं ने भाषण दिये थे। कई के भाषण बड़े मार्मिक थे और उन्होंने अंग्रेजी गद्य पर—असाधारण अधिकार का परिचय दिया। जो शब्द और विचार मेरे दिमाग में बचे रह गए, उनमें सरोजिनी नायडू के शब्द भी हैं, “इसलिए यह उचित ही था कि वह राजाओं की नगरी में मरे।” और फिर उनका नाटकीय आह्वान, “मेरे पिता, चैन मत लेना। न हमें लेने देना। हमें हमारे पथ पर अटल बनाये रखना।”

राजन्द्रप्रसाद ने कहा, “असली त्याग का समय तो अब आया है, जब हमें त्याग करने के लिए बुलाया जा रहा है।” राजाजी ने बड़े पैने ढंग से कहा, “दमन और बल-प्रयोग के बिना इस अपूर्ण ससार में काम नहीं चल सकता, लेकिन हम हमेशा के लिए यह जान ले कि बिना सद्भाव के सद्भाव पदा नहीं किया जा सकता।”

: २३ :

## फिर वही संघर्ष

नई दिल्ली, रविवार, २२ फरवरी १९४८

वाल्टर माकटन एक सप्ताह हैदराबाद में रहने के पश्चात् अभी-अभी यहां आये थे। हमें मालूम था कि वह फरवरी के मध्य में निजाम से मिलने वाले हैं। अतएव माउन्टबेटन ने निजाम को लिखा था कि वह भारत के साथ सामान्य समझौता करने की दृष्टि से माकटन की यात्रा का लाभ उठाये।

निजाम ने माउन्टबेटन की सलाह एकदम स्वीकार कर ली, यह माउन्टबेटन के लिए किंचित् आश्चर्य की बात थी। मैं ‘आश्चर्य’ इसलिए कहता हूँ कि निजाम ने इन दिनों माउन्टबेटन के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से जो विचार व्यक्त किये थे, वे प्रशंसापूर्ण नहीं थे। हमें मालूम था कि वह माउन्टबेटन को हैदराबाद का मित्र नहीं बताते थे। उन्हें अधिकारहीन बताते थे और कहते थे कि माउन्टबेटन का भावी वार्ताओं में सहायता करना या न करना से कोई अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु अब

उन्होंने यह आशा व्यक्त करते हुए उत्तर दिया कि माउन्टबेटन "इंग्लैंड के शाही-परिवार के सदस्य की हैसियत से, दीर्घ-कालीन समझौता कराने में, जो दुनिया की नजर में हैदराबाद की ऊँची स्थिति के अनुरूप हो, हैदराबाद को अपनी बहुमूल्य सहायता और समर्थन प्रदान करे।" मजे की बात थी कि वह सदा ही माउन्टबेटन के शाही सम्बन्ध की दुहाई देते थे, मानो उससे माउन्टबेटन को हैदराबाद के साथ चर्चा करने के लिए कोई विशेष अधिकार या दर्जा प्राप्त हो गया हो।

'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर होने के बाद एक मास तक करीब-करीब पूरी शांति रही। परन्तु नववर्ष के कुछ ही बाद एक घटना घटी, जिससे ज्ञात होता था कि शांति धोख की टट्टी थी। भारत के नव-नियुक्त एजेंट-जनरल के एम मुगी को निवास-स्थान देन के बारे में जगड़ा उठ खड़ा हुआ। वह था तो बहुत छोटा, लेकिन बिल्कुल अर्थहीन नहीं। जो भवन उनके लिए निर्धारित हुआ था वह तैयार नहीं था। इसलिए यह सुझाव पेश किया गया कि वह ग्यारह दिनों के अन्तरिम-काल में किसी एक रिक्त रेसीडेन्सी में रहे। निजाम ने तुरन्त इस प्रस्ताव का विरोध किया। उन्हें इसमें सर्वोच्च सत्ता को पुनरुज्जीवित करने की दुरभिमधि दिखलाई पड़ी। भारत की ओर से यह सीधा-सादा उत्तर दिया गया कि मुगी को समुचित और उपयुक्त निवास-स्थान नहीं दिये जाने पर उन्हें या किसी अन्य एजेंट-जनरल को भेजा ही नहीं जायगा। इस मोके पर माउन्टबेटन की याद की गई और पत्रों तथा तारों के तेज आदान-प्रदान के बाद निजाम हठ छोड़ने के लिए राजी हुए। मुगी ५ जनवरी को अपना कार्य-भार सभालने के लिए रवाना हो गए।

इस महीने के अंत तक हैदराबाद और भारत का सम्बन्ध इतना खराब हो गया कि दोनों ओर से 'यथास्थिति समझौते' के भंग कर दिये जाने की आशंका दिखलाई पड़न लगी। सीमा के पास घटनाओं की मख्या में भयानक वृद्धि हो गई। छोटी-छोटी बातों में परेशान करने की नीति अपनाये जाने के कारण उत्तजना फूटती जा रही थी। हैदराबाद-सरकार ने इस नीति का आरम्भ राज्य से कुछ धातुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा कर किया। बाद में साधारण व्यापार के लिए भारतीय मुद्रा पर से मान्यता उठा ली।

इन दोनों में अधिक उत्तेजनात्मक कार्रवाई यह थी कि पाकिस्तान को २० करोड़ रुपये का ऋण दे दिया गया। इन सौदे की परिस्थितियाँ गुप्त और अज्ञानिकारक थीं। माउन्टबेटन ने इस मामले का बहुत बारीकी के साथ अध्ययन किया और उन्हें जो प्रमाण मिले उनसे इन निष्कर्षों को टाटना कठिन था कि यह गोदा जर्मन विदेश-मंत्री मोडन नवाज जग ने उन समझौता, जब वह 'यथास्थिति समझौता-वार्ता' करने वाले प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य थे। उनके अनिश्चित यह उन जनान्मज कार्यदात्री उन समझौते की गई जब भारत-सरकार पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये देने का विचार कर रही थी। हैदराबाद की ओर से भी आर्थिक नाकेबंदी की विन्तन

शिकायते आ रही थी।

गांधीजी के दाह-संस्कार के दिन माउन्टबेटन ने हैदराबाद के नये इतिहासी प्रधान मंत्री मीर लायकअली से पहली बार भेंट की। माउन्टबेटन ने उन्हें साफ साफ शब्दों में सलाह दी कि उनकी सरकार को अपना रवैया सुधारना चाहिए और आमतौर से भारत के साथ दोस्ताने ढंग से काम करने की कोशिश करना चाहिए, तथापि माउन्टबेटन को विश्वास नहीं था कि उनकी बात का कोई गहरा असर हुआ होगा। मीर लायकअली के विनम्र बाहरी व्यवहार के पीछे उन्होंने धर्मन्यता तथा चालवाजी का वह रूप देखा, जिसे हम इतिहास तथा उसके नेताओं का प्रमुख चिह्न मानने के लिए बाध्य हो गए थे। अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि माकटन निजाम को किस हद तक रचनात्मक नीति अंगीकार करने को समझा सकते हैं, और माउन्टबेटन पटेल तथा भारत-सरकार का धर्म कायम रखने में कहा तक सफल हो सकते हैं।

नई दिल्ली, सोमवार, २३ फरवरी १९४८

आज सबेरे माउन्टबेटन ने अपने कर्मचारियों-मंडल की जो अनौपचारिक बैठक की उसमें वाल्टर माकटन और वी पी मेनन भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। हम अपने कार्यक्रम को सीमा तोड़कर काश्मीर के सब-विलय सम्बन्धी स्मरण-पत्रों और राष्ट्र-मंडल की नागरिकता पर अटकलवाजियों में लग गए। काश्मीर के विषय में माकटन ने कहा, "साफ बात यह है कि इस महादेश के बाहर इस प्रश्न को समझा ही नहीं गया।" वी पी मेनन ने जोर देकर कहा कि वास्तव में सत्ता-हस्तांतरण के पूर्व भावी पाकिस्तान सरकार को सब-विलय नीति के विषय में अब्दु-र-रबनिस्तर की सहमति प्राप्त कर ली गई थी। बाद में पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकार भी किया था कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलना मूलतः समझौते के खिलाफ था। काक जुलाई में दिल्ली आये थे और उन्होंने पटेल से भेंट की थी। पटेल ने उनसे कहा था कि हम जनता की इच्छा के विरुद्ध काश्मीर को भारत में शामिल करना नहीं चाहते। उस समय माउन्टबेटन की मदद से उन्होंने जिन्ना से भी भेंट की थी।

वैदेशिक मामलों में नेहरू के मुख्य सचिव सर गिरिजाशंकर वाजपेयी के साथ लम्बी बातचीत में गार्डन वाकर ने इन्तानुपूर्वक कहा था कि रूस के साथ मंत्री केवल पराधीनता के मूल्य पर खरीदी जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत में रूप का कोई बुनियादी हित नहीं है। सयोग में मैंने यह भी सुना था कि वाजपेयी ने अमरीकी राजदूत ग्रेंडो के साथ कोरिया के प्रश्न पर बातचीत आरम्भ की है। अडीमवी अक्षांश रेखा से रूपों तथा अमरीकी असरवाले क्षेत्रों को विभाजित कर देने के कारण उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की स्थिति बहुत-

कुछ पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी की स्थिति के समान हो गई थी। वाजपेयी का तर्क यह था कि यदि अमरीकी सेना कोरिया से नहीं हटाई जाती तो भारतीय सेना को काश्मीर से हटने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए ?

आज सबेरे की बैठक में मैंने जोर दिया कि गार्डन वाकर में २९ फरवरी तक, जब कि लियाकत के आने की संभावना थी, हर जान का आग्रह किया जाय। मेरी दृढ़ धारणा थी कि लियाकत और नेहरू के बीच आगामी बातचीत में एक ब्रिटिश-मन्त्री का उपस्थित रहना मोहार्द तथा समझौते का प्रेरक होगा। अत्रिंक उचित स्थान और उचित समय पर कभी भी कोई योग्य मध्यस्थ उपस्थित नहीं रह सका।

माउन्टबेटन ने मुझे आदेश दिया कि मयुनराष्ट्र मंत्र के द्वारा विश्वलोकमत को प्रभावित करने में भारतीय पक्ष को जो अपकृत्य मित्रों, उसका स पर्यवेक्षण करू। मैंने कहा कि भारतीय पक्ष में गुण-दोष कोई भी हो, इनका तो मही था कि उसे नितान्त अयोग्य ढंग से पेग किया गया है। जन-मार्क के प्रायः प्रत्येक नियम की उपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, मेरा खयाल था कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के आरोपो—विशेषतः अब्दुल्ला के द्वारा महाराजा को आत्मसमर्पण कराने के काप्रपो “षड्यंत्र”—का उत्तर देने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार के आरोपो की उपेक्षा मात्र कर देना समझदारी की बात नहीं थी।

नई दिल्ली गुहजार, ४ मार्च १९४८

हैदरावाद का नया प्रतिनिधि-पडल, जिसमें मीर लायक अली, मोइन नवाज जग (मीर लायक अली के सहवाकाक्षी और शक्तिशाली सम्बन्धी) और माकटन थे, दिल्ली आये हुए हैं। प्रतिनिधि-मडल ने मंगलवार को और आज माउन्टबेटन से भेट की। मेनन भी दोनों बैठकों में उपस्थित थे।

कल मीर लायकअली कराची गये थे और माउन्टबेटन के सुझाव पर उन्होंने लियाकत से कहा कि वह हैदरावाद के २० करोड़ रुपये के ऋण को यथास्थिति समझौते के काल में बैंक से न निकालने का वादा कर दे। वह इस बारे में लियाकत का मौखिक वादा लेकर लौट थे।

दोनों ओर से शिकायतों के लम्बे गान गाये गये हैं। बी पी ने पाकिस्तान को ऋण दिये जाने और भारतीय मुद्रा को अवैध घोषित करने वाले आर्डिनेस की कहानी कही। मीर लायक अली ने हैदरावाद के विरुद्ध पूरी आर्थिक नाकेबन्दी का व्योरा दिया। माउन्टबेटन ने बताया कि भारत में साम्प्रदायिक सेनाएं भा कर दी गई हैं और हैदरावाद को भी सांकेतिक रूप में इतिहास की सैनिक शाखा, रजाकार सगठन को, जिस के अत्याचारों की गम्भीर कहानियां सुनाई दे रही थी, भग कर देना चाहिए। उन्होंने हैदरावाद में शीघ्र उत्तरदायी शासन स्थापित करने की

आवश्यकता भी समझाई।

यहा समय और कार्य-पद्धति सम्बन्धी पुराना गतिरोव, जिसको तह में सत्ता के सघर्ष छिपा हुआ था, फिर शुरू हो गया। पटेल महसूस करते थे कि जबतक 'यथास्थिति समझौता' उचित रूप से अमल में नहीं आता, तब तक दीर्घकालीन समझौते की बातें करना बेकार थी। और 'यथास्थिति समझौते' के कार्यान्वित होने की आशा तबतक नहीं की जा सकती जबतक कि किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना न हो जाय। उनकी प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में पटेल इस सुझाव का समर्थन करने को तैयार नहीं थे कि बराबर सख्या में हिन्दुओं और मुसलमानों की अतिरिक्त सरकार की स्थापना कर दी जाय। दूसरी ओर, मीर लायकअली अपने को दीर्घकालीन समझौता होने के पूर्व हिन्दू-बहुल सरकार कायम करने में असमर्थ समझते थे। वह समान सख्या के सुझाव से आगे जाने को तैयार नहीं थे। फिर भी उनका खयाल था कि दीर्घकालीन समझौता और हिन्दू बहुमत सरकार को स्थापना, दोनों बातें एक साथ हो सकती थी।

बठक के बाद एक विज्ञप्ति निकालने के प्रश्न पर अच्छा-खासा तूफान उठ खड़ा हुआ। पटेल ने उसमें किसी भी ऐसी बात को शामिल करने से इन्कार कर दिया, जिससे सकेत मिलता हो कि भारत ने 'यथास्थिति समझौते' को भग किया है। जहातक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध था, यहा पटेल का आधार दृढ़ था। उपद्रवों का स्तर प्रादेशिक था और उनके लिए स्थानिक अधिकारी जिम्मेदार थे। शासकीय बोझ और अनुभवहीनता की वर्तमान अवस्था में आदेश दे देना, उनके कार्यान्वित होने की व्यवस्था करने से कहीं सरल था। पटेल विज्ञप्ति में यह कहने को भी तैयार नहीं थे कि हैदराबाद को जाने वाला माल, जिसे रोका गया बताया जाता है, छोड़ दिया जाना चाहिए। शायद इसकी तह में यह शका थी कि यदि इस बात को स्वीकार किया गया तो यह अर्थ लगाया जायगा कि उन्होंने व्यापक क्षेत्र में हैदराबाद के आरोप स्वीकार कर लिये हैं। माकटन बहुत परेशान थे। माउन्टबेटन ने एक भोज से लौटने के बाद टेलीफोन पर उनसे बातें करके कल इस विषय को फिर उठाने का आश्वासन दिया।

नई दिल्ली शुक्रेवार, ५ मार्च १९४८

माकटन आज तडके हैदराबाद के लिए रवाना हो गए और माउन्टबेटन ने उनकी अनुपस्थिति में विज्ञप्ति के सम्बन्ध में पूछताछ की। उन्होंने नेहरू से बातें कीं। उनका ख बहूत उचित और सहानुभूतिपूर्ण था। परन्तु वह उत्सुक थे कि इस प्रश्न का हल पटेल के साथ ही किया जाना चाहिए, जो रियासती मन्त्री की हैसियत से हैदराबाद के मामले के लिए उत्तरदायी है। आज तीसरे पहर माउन्टबेटन पटेल से मिलने वाले थे, परन्तु भोजन करते समय पटेल को हृदय का दौरा

हो गया और उनकी हालत खराब हो गई। अब उन्होंने खाट पकड़ ली और उनके डाक्टर ने अनिश्चित समय के लिए किसी प्रकार का भी काम करने पर पाबन्दी लगा दी। पाबन्दी का यह समय हमारे यहाँ से जाने के पहले खत्म होता नहीं दीखता।

मेरा खयाल था कि गांधीजी की मृत्यु के बाद पूरे छ घंटे अर्थी के साथ चलकर उन्होंने अपने स्वास्थ्य को चोपट कर लिया था। जब मैंने उन्हें राजघाट पर देखा था, तब वह बहुत दुबले और बीमार मालूम होते थे। ऐसा लगता था मानो वह मूर्छा में हो। सारी दुखान्त घटना ने उन पर भारी आघात किया था और, निस्सन्देह उन्हें गृहमन्त्री की हैसियत से गांधीजी की समुचित रक्षा का प्रयत्न न कर सकने पर आलोचनाओं का उचित से अधिक प्रहार सहना पड़ा। इस राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सकट के समय उनकी बीमारी सरकार के लिए एक भारी चोट थी। इससे जाहिर होता था कि शासन-यंत्र अपने दो नेताओं का किस कदम मोहताज था।

जहाँ तक हैदराबाद के तात्कालिक प्रश्न विज्ञप्ति, का सम्बन्ध था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, जो उनके अन्तिम निर्णय को बदलने की जिम्मेदारी ओढ़ सके। अतएव, माउन्टबेटन माकटन को लिख देने के लिए विवश हो गए कि फिलहाल कोई प्रेस वक्तव्य नहीं निकाला जाना चाहिए।

नई दिल्ली, शनिवार, ६ मार्च १९४८

माउन्टबेटन ने हैदराबाद स्थित भारतीय एजेंट जनरल के एम मुशी से भेंट की। मुशी काफी उत्साही, ध्येयवादी, और मैं समझता हूँ, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यद्यपि उनके पास ब्रिटिश राज की खिलाफत में कारावास जाने का कांग्रेसी सर्टीफिकेट नहीं है, फिर भी वह कांग्रेस के शासकीय आकाश में ऊपर उठ रहे थे। इससे उनकी राष्ट्रीयता में उग्रता आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

महात्मा जी के सम्बन्ध में अपने सस्मरण प्रसारित करते हुए उन्होंने अपने आपको अहिंसा का विद्यार्थी बताया था। वह इस आधार पर गांधीजी से झगड़ने को तैयार थे कि “१९४२ का सत्याग्रह आन्दोलन असफल रहा था। वह अहिंसा की कसीटी पर खरा नहीं उतरा था क्योंकि उसमें शत्रु के प्रति प्रेम की बजाय क्रोध की सृष्टि हुई थी।” आज उन्होंने माउन्टबेटन से जो कुछ कहा उसमें स्पष्ट था कि वह हैदराबाद के साथ वर्तव करने में अहिंसा पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे। उनकी सलाह थी कि यदि रजाकारों की प्रवृत्तियों को तुरन्त रोकना नहीं जाता तो भारतीय पुलिस को भेज कर उन्हें रोकना चाहिए। ‘यथास्थिति समझौते’ की उनकी कानूनी व्याख्या के अनुसार ऐसा करना उसकी शर्तों के अनुकूल होगा। उनका विश्वास दृढ़ था कि रजाकारों को वर्तमान शासन न तो रोक सकता था और न रोकना चाहता था।

माउन्टबेटन ने दृढ़ता के साथ कहा कि भारत को हैदराबाद के प्रति नैतिक

तथा उचित व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसे विश्व के लोकमत के सामने उचित ठहराया जा सके। बातचीत की वर्तमान अवस्था में मुंशी का पुलिस-कार्यवाही का सुझाव बिल्कुल गलत था। मीर लायकअली को रजाकारो से निबटने, 'यथास्थिति समझौते' को कार्यान्वित करने और किसी हद तक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

वाद को माउन्टबेटन ने मुझ से कहा कि हालांकि उन्हें मुंशी की तत्परता और योग्यता के बारे में कोई शंका नहीं थी, लेकिन वह नहीं समझते कि मुंशी का स्वभाव और राजनैतिक दृष्टिकोण इस नाजुक दौर में निजाम से निबटने के लिए उपयुक्त है। इस समय तो असाधारण कूटनीतिक धैर्य और साम्प्रदायिकताहीन वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता थी।

माकटन हैदराबाद से लन्दन के लिए रवाना हो गए हैं। हमें डर था कि कहीं यह समझकर कि इस सप्ताह जैसी बातचीत केवल समय बर्बाद करना था, वह पूरे मामले से भी हाथ न धो बैठे। माकटन के बिना माउन्टबेटन द्वारा पहल करने की संभावना काफी कम हो जायगी।

: २४ :

## परिभाषा और अनुसंधान

नई दिल्ली, शुक्रवार, १९ मार्च १९४८

हम ८ मार्च को कलकत्ता, उड़ीसा, बरमा और आसाम की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। सब मिलाकर नौ दिन की यात्रा के बाद हम फिर दिल्ली आ गए थे और काम में जुट गए। दो महीने बाद आज लियाकत और नेहरू मिले। सयुक्त सुरक्षा कौंसिल के तत्वावधान में उन दोनों की भेंट कराने में माउन्टबेटन को काफी कठिनाई हुई। उन्होंने निश्चय किया कि सयुक्त सुरक्षा कौंसिल की यह अन्तिम औपचारिक बैठक होगी। वैसे वह किसी भी हालत में १ अप्रैल को समाप्त हो ही रही थी, लेकिन माउन्टबेटन चाहते थे कि वह अपन मौजूदा रूप में (उनके जाने तक उनकी अध्यक्षता में, और फिर जिस देश में बैठक हो उसके प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में) एक वर्ष और कायम रहे, जिसमें आगे चलकर इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर वित्त मंत्री और आर्थिक मामले, संचारसाधन और विदेशी मामले भी इसमें शामिल कर लिये जाय। हालांकि यह इरादा दोनों में से किसी भी पक्ष को पस-

नहीं आया, फिर भी दोनों प्रधान-मंत्रियों ने एक हृदयक व्यक्तिगत संपर्क के साधन के रूप में संयुक्त सुरक्षा कौंसिल के महत्व को मान लिया। सामान्य रुचि के विषयों पर चर्चा करने के लिए उन्होंने हर महीने वाद मिलना स्वीकार कर लिया।

कटुता और दुराशा भरे पिछले छ महीनों की एक विशेष बात यह रही थी कि नेहरू और लियाकत ने अपनी सौम्यता को कायम रखा था। ऐसा लगता था कि यदि इन दोनों को सारे फैसले करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाय, और उनपर निरन्तर डाले जाने वाले दबाव और बोझ हटा लिये जाय तो सारे मतभेदों के बारे में दृढ़ समझौता होने में देर नहीं लगेगी।

आज की बैठक में गौण विषयों पर सौहार्दपूर्ण समझौता हो जाने पर भी काश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका कारण यह नहीं था कि इस बारे में बात करने की कोई नई बात नहीं थी बल्कि सुरक्षा परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष, चीनी प्रतिनिधि डा सियांग ने स्वतः निजी प्रेरणा में कुछ सुझाव रखे थे जो बुनियादी तौर पर भारत के मन माफिक थे। लेकिन अभाग्यवश डा सियांग ने अपनी योजना के लिए ज्यादा व्यापक समर्थन पाने की चेष्टा नहीं की। इसका नतीजा यह होगा कि इससे कटुता ही बढ़ेगी और सद्भावना की रही-सही संभावना भी नष्ट हो जायगी। इससे अनुमान होता था कि लेक सक्सेस के काम करने के ढंग में कोई भारी टोष था।

संयुक्त राष्ट्र सभ में काश्मीर विषयक प्रचार की शायद सब में अनिष्टकारी, हालांकि अप्रत्याशित नहीं, घटना यह थी कि जफरुल्ला खा ने भारत की शिकायत के जवाब में पाकिस्तान की ओर से आरोपों का क्षेत्र काफी व्यापक बना दिया था और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए वह ऐसे प्रचार पर उतर आये थे, जिसे अमरीकी लोग "चारित्रिक हत्या" कहते थे। ऐसे मौके पर उन्होंने माउन्टबेटन का नाम बीच में घसीटा, जब अपनी वैधानिक स्थिति के कारण माउन्टबेटन सार्वजनिक रूप से कोई उत्तर देने में असमर्थ थे।

कर्मचारी मंडल की बैठक में इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई और बड़ी बुद्धिमानी से माउन्टबेटन ने निश्चय किया कि पाकिस्तानी आरोपों के उत्तर में उनके वक्तव्य को आवश्यक प्रमाणों सहित संयुक्त सुरक्षा कौंसिल के भग होने के पूर्व उसकी कार्यवाही में शामिल कर लिया जाय। इसमें उनके उत्तर, भारत और पाकिस्तान, दोनों सरकारों के समक्ष आ सकेंगे। इस बारे में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी पूरी जानकारी देने का फैसला किया, क्योंकि वाइसराय के रूप में उन पर होने वाले हमलों से ब्रिटिश सरकार भी अछूती नहीं बच सकती थी।

जफरुल्ला के दो मुख्य आरोप थे वाइसराय के नाते माउन्टबेटन को जुलाई के प्रारम्भ से सिखों की योजना का पता था। यह जानते हुए भी उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार करने और उपद्रवी तत्वों को कुचलने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, हालांकि ऐसा करने का वादा वह कर चुके थे।



अपने स्मरणपत्र में माउन्टबेटन ने यह स्पष्ट किया था; हालांकि सरकार के ऊचे पदों पर काम करने वाले लोग सिखों की समस्या के बारे में किसी प्रकार के भ्रम में नहीं थे और उम्मेद सल्लुखाने की आवश्यकता महसूस करते थे, किन्तु किसी विशेष 'सिख योजना' का उन्हें या किसी और को कोई पता नहीं था। ५ अगस्त को ब्रिटिश खुफिया अधिकारी से मुलाकात के पूर्व इसका कोई संकेत तक नहीं था। इस मुलाकात में भी 'योजना' के आकार-प्रकार और काम करने के ढंग के बारे में कोई सतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी थी। माउन्टबेटन ने अपने तर्क का आधार जेनकिन्स के ९ अगस्त के पत्र को बनाया था। इसमें जेनकिन्स ने पंजाब के तीनों गवर्नरों, खुद अपना और अपने उत्तराधिकारी मनोनीत गवर्नरों का मत प्रेषित करते हुए लिखा था कि तीनों एकमत थे कि सत्ता-हस्तांतरण के पहले सिखों की गिरफ्तारी की योजना तैयार करने में अधिक कुछ नहीं किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान ने एक और भी आरोप लगाया था। सीमा आयोग के निर्णय के प्रकाशित होने के पूर्व वाइसराय भवन के दबाव पर उसे पाकिस्तान के खिलाफ बदल दिया गया था। इसके मबूत में पेश किया गया एवेल का जेनकिन्स के नाम लिखा ८ अगस्त का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि सीमा आयोग का निर्णय ११ अगस्त को प्रकाशित करने का विचार है। इसमें प्रस्तावित निर्णय की एक रूपरेखा भी योजित थी, जिसमें फिरोजपुर और जीरा तहसीलों को पाकिस्तान के अन्तर्गत दिखाया गया था।

वात दरअसल यह थी कि रेडक्लिफ के सेक्रेटरी ने अन्तरिम निर्णय की एक रूपरेखा एवेल को दी थी। यह रूपरेखा एवेल ने जेनकिन्स को भेज दी, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व माग की थी कि पहले से इस विषय में कोई सूचना मिलने से उन्हें पुलिस और सेना तैनात करने में मूढ़लियत होगी। यह पूर्वसूचना "दो तहसील" और "दो दिन" के विषय में गलत निकली। वस वास्तविकता तो इतनी ही थी।

नई दिल्ली, रविवार, २१ मार्च १९४८

चीनी-योजना की भारत के पत्रों में प्रत्याशित प्रतिक्रिया हुई। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' इसे "झगड़े को युक्तिपूर्ण और व्यावहारिक ढंग से निवटाने का पहला उचित प्रयास" मानता था। उसका कहना था "मुख्य सुझाव ऐसे हैं कि कोई भी स्वाभिमानी और शांति-प्रिय राष्ट्र उसे स्वीकार कर सकता है।" लेकिन डान ने आशा प्रकट की, "सुरक्षा परिषद् पहले जैसे यथार्थवाद का परिचय देगी और 'समझौते' के लिए प्रस्तुत चीनी सुझावों को, जो एक पक्ष को सब कुछ देने को तैयार थे, और दूसरे को कुछ भी नहीं, पहले जैसी रोगनी में देखेगी।" पाकिस्तान का तर्क अब भी यही था कि शासकीय व्यवस्था का प्रश्न काश्मीरी जनता के स्वतंत्र्य और

निडर मतदान के बाद ही निवटाया जाना चाहिए, पहले नहीं।

इस निराशाजनक वृहस में एक मात्र नई चीज थी २० मार्च के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित सुझाव। देवदास गांधी और जी डी विडला के ऊँचे सवधो को देखते हुए, इस पत्र के सुझावों पर हमेशा विचार करना पड़ता था। जनमत संग्रह में काश्मीरी जनता के मिलने वाले विकल्पों की चर्चा करते हुए पत्र ने लिखा था, "हमारा मत है कि उनसे केवल इस या उस राष्ट्र में शामिल होने के लिए मत देने की माग करना गलत और अनुचित होगा। उनको इस बात का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए कि दोनों में से चाहे जिस राष्ट्र में शामिल हो या स्वतन्त्र रहे।"

नई दिल्ली, बुधवार, ७ अप्रैल १९४८

हमारे वरमा से लौटने पर माउन्टबेटन के नाम निजाम का एक पत्र आया हुआ था। चूँकि माउन्टबेटन फिर दिल्ली से बाहर जाने वाले थे और इस विवाद से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए अपने वैधानिक अधिकारों के अनुसार उन्होंने रियासती सचिवालय से उसका उत्तर भेज देने को कहा। इस आशय की सूचना उन्होंने निजाम को भी भेज दी। रियासती सचिवालय का यह पत्र पहले लिखा गया बी पी मेनन द्वारा, पटेल ने उसमें गरमी भरी, नेहरू ने टिप्पणी किया। माउन्टबेटन ने इसकी प्रति मूल-पत्र चले जाने के बाद देखी और पत्र उन्हें काफी कड़ा और धमकी भरा लगा। पत्र में खुले तौर पर निजाम के ऊपर 'यथास्थिति समझौता' भंग करने का आरोप लगाया गया था और माग की गई थी कि उसका पालन किया जाय और इतिहाद तथा रजाकारों पर प्रतिव्रत लगा दिया जाय।

माकटन ने पहले भी इस आशय का विचार प्रकट किया था कि वह इस झमेले से अपने को दूर रखना पसन्द करेंगे। अब वह पुनः मैदान में लौट आये हैं। २८ मार्च को वह हैदराबाद आ गए थे। रियासती सचिवालय के पत्र और रियासत की आम स्थिति का उनपर बड़ा गहरा अमर हुआ। सामान्यतः शांत और खुशदिल रहने वाले माकटन सबसे लोहा लेने के इरादे में कमर कसकर कल रात दिल्ली आये। निजाम का उत्तर वह अपने साथ लाए थे। यह पत्र बड़ी चतुराई के साथ लिखा गया था और भारतीय पत्र को कई जगह नीचा दिखलाने वाला था। पत्र पर उनकी प्रतिभा को साफ-साफ मुहर अंकित थी।

दोनों के बीच दृढ़ दोस्ती और एक दूसरे को भली प्रकार समझने के आधार पर उनमें खुलकर चर्चा हुई। माउन्टबेटन माकटन को यह विश्वास दिलाने में सफल हुए कि भारत सरकार का अन्तिमोत्पन्न देने का कोई इरादा नहीं, और हैदराबाद की नाकेबंदी के लिए वह जिम्मेदार नहीं। थोड़ी देर बाद नेहरू ने भी आकर इसी बात की पुष्टि की।

भारत के कई पत्रों में एक जिहादी भाषण छपा है, जो 'धर्मान्धि इस्तिहाद' नेता, कामिम रिजवी ने ३१ मार्च को "हैदराबाद शस्त्र-दिवस" के उद्घाटन अवसर पर दिया कहा जाता था। इसने एक नई खलबली मचा दी थी। छपी सूचना के अनुसार रिजवी ने हैदराबाद के मुसलमानों को ललकारा था कि जबतक इस्लाम की विजय का लक्ष्य पूरा न हो जाय, तबतक अपनी तलवारों को म्यान में न रखे। उसके भाषण के सबसे कुत्सित शब्द थे "भारत सध में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई हमारा पाचवा दस्ता होंगे।" इस प्रकार की भाषा का उद्देश्य पूरे दक्षिण भारत में साम्प्रदायिक आग भड़काना था, जो ईश्वर की कृपा से अभी तक उत्तर भारत में फैले घातक प्रभाव से बचा हुआ था।

नई दिल्ली, रविवार, ११ अप्रैल १९४८

रिजवी का मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा था। माकटन कल हैदराबाद लौट गए। उनको दृढ़ विश्वास हो गया था कि निजाम को शीघ्र ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। वह निजाम को शीघ्र रिजवी की गिरफ्तारी करने का परामर्श भी देगे। परन्तु आज माकटन के पास से एक तार आया था। उसमें माउन्टबेटन को सूचित किया गया था कि हैदराबाद सरकार को सतोष था कि ३१ मार्च का कथित जिहादी भाषण कभी किया ही नहीं गया और इससे लगता था कि मंत्रीपूर्ण सत्रों की स्थापना में अड़गा डालने का यह सोच-विचार कर रचा गया षडयंत्र था।

माउन्टबेटन ने तुरन्त मुझे बुलाया और मुझसे उपलब्ध तथ्यों की शीघ्र छानबीन करने को कहा। इसलिए अब मैं जासूस बनकर "रिजवी के वक्तव्य के रहस्य" की छानबीन करने में निमग्न हूँ। यदि इस घटना को आच्छादित किये हुए परस्पर-विरोधी और अनिर्णायक प्रमाणों में से ही सही मार्ग निकालना था तो मुझे शर्लाक होम्स की सारी तर्क-शक्ति की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान स्थिति में तो मैं डा. वाट्स की उलझन का ही भागी हूँ। पहला विचित्र पहलू तो यह था कि भाषण भारतीय पत्रों में एक सप्ताह के साधारण विलम्ब से प्रकाशित हुआ। उसका बहुत-सा भाग प्रत्यक्ष भाषण के रूप में था और उसमें श्रोताओं के उत्साहपूर्ण उद्गार भी दिये गए थे।

दो दिन पूर्व भारतीय ससद् (लेजिस्लेटिव असेम्बली) में नेहरू ने उसे हिंसा तथा हत्याओं को प्रत्यक्ष उत्तेजना देने वाला भाषण बताते हुए कहा कि वह "रिजवी के अनेक उत्तेजनात्मक भाषणों में से एक" है। कल इसकी पुष्टि में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा अन्य पत्रों ने रिजवी के इसी प्रकार के अन्य भाषणों के उद्धरण प्रकाशित किये, जो बहुत सावधानी के साथ सकलित किये गए थे। इनमें से कुछ

मैंने पहले नहीं देखे थे। किन्तु बताया गया था कि ग्रह सब सितम्बर के बाद के हैं। अब, असोसियेटेड प्रेस के एक प्रामाणिक समाचार के अनुसार रिजवी ने एक और जवानी हिंसा कर डाली थी, जो उससे भी बेहदा थी और जिसकी मैं छानबीन कर रहा हूँ। कहा जाता है कि उसने मद्रास में मिलाये गए प्रदेश को वापिस सागने का साहस किया और मुगल सम्राट के समान दम से कहा, “वह दिन दूर नहीं जब बगाल की खाड़ी की लहरे हमारे गहशाह के कदमों को चूमेगी।”

नई दिल्ली, शुक्रवार, १६ अप्रैल १९४८

मीर लायकअली और रिजवी ने सफाई में यह कहा था कि ३१ मार्च को न कोई रैली हुई थी और न कोई ‘हैदराबाद शस्त्र दिवस’ कि जिसमें उक्त भाषण दिया बताया जाता है। लेकिन यह सही नहीं था। ‘टाइम्स’ के दिल्ली स्थित सवाददाता एरिक ब्रिटर वहाँ मौजूद थे। जहाँ तक उनकी जानकारी थी, उतने तथ्यों का मैंने पता लगा लिया था। उनका कहना था कि ३१ मार्च को ८ और १० बजे के बीच सवेरे हुई परेड में वह उपस्थित थे। लगभग चार-पाँच हजार रजाकारों द्वारा उन्होंने रिजवी को सलामी दिये जाते देखा। लेकिन उनकी उपस्थिति में कोई भाषण नहीं दिया गया। उन्होंने परेड समाप्त होते देखी और उसके बाद बीस मिनट तक वहाँ खड़े रहे। उसके बाद वे बरामदे वाले एक मकान में लौट आये, जहाँ बीस-तीस और लोग भी मौजूद थे। चाय और केक के दौर चल रहे थे और मामूली चीजों के बारे में चर्चा हो रही थी। ब्रिटर का कहना था कि रिजवी उन्हें विदा करने दरवाजे तक साथ आया था। लेकिन वह यह कहने की स्थिति में नहीं कि बाद में रिजवी ने कोई सभा की या नहीं। इस प्रकार, रहस्य का पर्दा फाश नहीं हो सका।

दूसरे जरियों से मैंने जो जानकारी एकत्रित की थी, उससे लगता था कि रिजवी की आम और खानगी सभाओं में मुंशी और निजाम दोनों के ही खफिया नियमित रूप से मौजूद रहते थे। मेरा विश्वास है कि रिजवी एक ऐसे राजनैतिक आन्दोलन में व्यस्त था, जिसकी सफलता का अर्थ हो सकता था रक्तपात कि जिसे वह निरन्तर उकसाया करता था, और भारत तथा हैदराबाद के बीच हमेशा के लिए संघर्ष-विच्छेद।

इस समय माउन्टबेटन इस खतरनाक गतिरोध को भग करने का रास्ता निकालने के लिए बैठकों में लग चुका है। माकटन बुधवार को यहाँ आ गए थे और मीर लायकअली कल। आज सरकारी भवन के शांत-सरोवर के एकाकीपन में मीर लायकअली ने माउन्टबेटन के साथ दोपहर का भोजन किया। वह कुल मिलाकर दो घंटे साथ रहे और माउन्टबेटन का अनुमान था कि मीर लायकअली के अडियल व्यक्तित्व और पेचीदा दृष्टिकोण पर उनकी बात का थोड़ा-थोड़ा असर हो चला है।

लेकिन, माउन्टबेटन का यह विश्वास अब भी दृढ़ था कि आगे आने वाले कठिन दिनों के लिए वह उपयुक्त प्रधान-मंत्री नहीं थे। अगर उनका अडियलपन यो ही चलता रहा तो बातचीत हमेशा के लिए टूट जायगी।

यह संभवतः निर्णायक क्षण था। पटेल का स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया था और अब वह सरकारी वार्ताओं में हिस्सा ले सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि निजाम को छोड़कर बाकी सब मुख्य पात्र बातचीत में भाग ले रहे थे। माउन्टबेटन उसमें एक व्यक्ति "सद्भावना आयोग" के रूप में भाग ले रहे थे।

नई दिल्ली, शनिवार, १७ अप्रैल १९४८

तीन दिन की सरगम वार्ताओं के बाद एक चार-सूत्री कार्यक्रम का सिद्धांत स्वीकार हो गया। इसके लिए माउन्टबेटन मीरलायकअली के साथ औपचारिक बैठक में सर्वसम्मत नीति पर चलने के लिए रोज सवेरे नेहरू, बी पी मेनन और माकटन से चर्चा कर लेते थे। बी पी उसे लेकर पटेल के पास मसूरी गये थे, जहाँ पटेल स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। माउन्टबेटन की खुशी और अचरज का ठिकाना न रहा कि पटेल ने पूर्ण सघ विलय के अलावा किसी योजना को ठुकराने का अपना आग्रह छोड़ दिया था और योजना को अपना अमूल्य समर्थन दे दिया था।

निजाम की स्वीकृति के लिए ये चार सूत्र तय हुए थे —

१ रिजवी पर नियंत्रण करने के लिए अविलंब कार्रवाई, जिसका आरम्भ रजाकारो के जलूमो, सार्वजनिक प्रदर्शनों, सभाओं तथा भाषणों पर प्रतिबन्ध लगा कर किया जाय।

२ राज्य के कांग्रेस-जनो की रिहाई, जिसका आरम्भ नेताओं को अविलम्ब रिहा करके किया जाय।

३ वर्तमान सरकार का सच्चा और अविलम्ब पुनर्निर्माण, जिसे वह दोनों सम्प्रदायों की प्रतिनिधि हो सके।

४ उत्तरदायी शासन की शीघ्र स्थापना और वर्ष के अन्त तक संविधान-सभा का निर्माण।

माकटन ने माउन्टबेटन से कहा कि वह निजाम को सलाह देंगे कि वह अपने प्रधानमंत्री को बदलकर इन सूत्रों की पुष्टि करें। वह महसूस करते थे कि मीर लायकअली पर यहाँ किसी को रस्ती भर भी विश्वास नहीं रह गया। किसी और चीज से निजाम के इरादों के बारे में इतना विश्वास पैदा नहीं होगा, जितना हैदराबाद के दिल्ली-स्थित एजेंट-जनरल, जैन यार जग के समान योग्यता और सम्यता वाले व्यक्ति की इस पर पद नियुक्ति से। निजाम के प्रति उनकी निष्ठा सदेह से परे थी और सदेह से परे था उनका दृढ़ यथार्थवाद। उन्होंने भारत सरकार, खासकर बी पी मेनन, पर गहरी छाप छोड़ी थी।



: २५ :

## गतिरोध

नई दिल्ली, शनिवार, २४ अप्रैल १९४८

माकटन १९ को लन्दन के लिए रवाना हो गए। कराची से एक पत्र लिखकर उन्होंने निजाम के साथ हुई अपनी बातचीत की सूचना माउन्टबेटन को दी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दिल्ली में जिन चार सूत्रों पर समझौता हुआ था, उसमें से सबसे कष्टकर और समस्या को सुलझाने के मार्ग में आड़े आने वाला सूत्र वह होगा, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए शासन-यंत्र की रचना से सबध रखता था। सामान्य आबादी के आधार पर निर्मित विधान सभा, जिसमें एक सप्ताह के अन्दर हिन्दुओं का भारी बहुमत हो जायगा, निजाम के गले नहीं उतरेगी। लेकिन माकटन ने यह आग्रह अवश्य किया था कि निजाम अपनी सरकार का पुनर्निर्माण करे, जिसमें वह सब सम्प्रदायों की प्रतिनिधि सरकार का रूप ले सके। निजाम चाहते थे कि माकटन रुके। लेकिन उन्होंने यह कहकर रुकने से इकार कर दिया कि नई सरकार की स्थापना न होने की स्थिति में उनका वहां रुके रहना उनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था।

आशा यह की जाती थी कि अपने फरमान के द्वारा निजाम चार-सूत्री योजना को अमली रूप दे देंगे। सदा की तरह कल फरमान जारी हुआ था, और हमेशा की तरह सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चार सूत्रों को स्वीकार करके प्रदत्त व्यावहारिक रियायतों से पैदा होने वाले मनोवैज्ञानिक लाभ को एक ही वाक्य में साफ कर दिया गया। फरमान में पहले यह आगा प्रगट की गई कि “वे राजनैतिक दल, जो हैदराबाद के वर्तमान अन्तरिम शासन में शामिल नहीं हैं, गीघ्र ही उसमें हाथ बटायेगे और सरकार का भार सभाल लेंगे।” फिर फरमान ने अन्तिम वचन के रूप में कहा, “मुझे डर है कि किसी और जगह की सरकार की नकल मात्र करने से हमारे देश का वातावरण कहीं अधिक विषाक्त न हो जाय, जैसा कि अन्य स्थानों पर हो रहा है।” छोटी-सी विजय प्राप्त करने को इतना भारी मूल्य चुकाने के लिए तत्पर होना, निश्चय ही चकित करने वाली बात थी।

नई दिल्ली, शुक्रवार, ३० अप्रैल १९४८

हैदराबाद के प्रश्न पर तनातनी बढ़ती जा रही थी। सीमावर्ती घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, जिससे गरम दिमाग और भी गरम हो रहे थे। नेहरू ने अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने गत शनिवार को बंबई में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने यह कहा बताया गया था “अब हैदराबाद के सामने १० ही रास्ते हैं—युद्ध या सध-प्रवेश।” इससे राजनैतिक तापमान उबाल पर पहुँच गया था।

माउन्टबेटन ने यात्रावास में दूसरे दिन समाचारपत्रों में यह शीर्षक पढ़ा—“सध-प्रवेश या युद्ध।” पढ़कर वह स्तम्भित रह गए। दिल्ली लौटकर उन्होंने तुरन्त नेहरू से सपर्क किया। नेहरू को भी कम विस्मय नहीं था। उन्होंने बतलाया कि रिपोर्ट गलत छपी है, क्योंकि उन्होंने न तो युद्ध का कोई जिक्र किया था न सध-प्रवेश का। गलती का कारण शायद यह रहा हो कि भाषण हिन्दी में दिया गया था, जिसे लिखा था एक मद्रासी-भाषी स्टेनोग्राफर ने।

नेहरू कल प्रेस कान्फेस में इस गलती को सुधार देंगे। लेकिन एक हफ्ता बीत चुका था और प्रचार का यह स्वयं-सिद्ध सिद्धांत है कि तुरन्त किये जाने वाले सुधार या खडन का भी, पहले छोटी झूठी रिपोर्ट के असर का, दशांश से अधिक असर तभी होता। उधर हैदराबाद में मीर लायकअली ने हैदराबाद व्यवस्थापिका सभा के सामने एक लम्बा-चौड़ा भाषण दिया जिसमें चारों में से एक सूत्र का भी जिक्र नहीं किया गया था। इससे निजाम के फरमान में निहित सद्भावना के प्रति दिल्ली का बचाखुचा विश्वास भी जाता रहा।

नई दिल्ली, मंगलवार, ४ मई १९४८

हैदराबाद के गतिरोध से माउन्टबेटन बहुत चिंतित थे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक, दोनों कारणों से वह चाहते थे कि मामला जल्दी खुशी-खुशी निबट जाय। लगभग छ मप्ताह बाद वह गवर्नर-जनरल पदका भार राजाजी को सौंपने वाले थे, और उनका अनुमान था कि यदि इस छोटे से असें का ठीक से उपयोग किया जाय तो दोनों पक्षों को अपने मतभेद दूर करने की प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन यह कहना कोई मामूली काम नहीं था कि माकटन की अनुपस्थिति में कब और कैसे उनके प्रभाव का पूरा-पूरा फायदा उठाया जा सकेगा।

माउन्टबेटन ने सुझाव दिया कि अब निजाम को आखिरी चेतावनी का पत्र भेजा जाना चाहिए। इसका मजमून भी बड़ी तत्परता से तैयार किया जा रहा था। लेकिन मैंने इसका विरोध किया। मैंने आग्रह किया कि अन्य सब इलाज बेकार हो जाने पर ही यह रास्ता अपनाया जाना चाहिए। मेरा कहना था कि पत्र का यह मजमून मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है।

आज सवेरे दस बजे हुई बैठक में, जिसमें वी पी मेनन, वरनोन और मैं थे, माउन्टबेटन मेरे मत से सहमत हो गए।

इसके बाद रियासतों की स्थिति पर चर्चा छिड़ गई। राज्यों के विलीनीकरण

का जो काम उड़ीसा और बिहार राज्यों के साथ प्रारम्भ हुआ था, और जिसे पटेल की ओर से वी पी ने अत्यन्त तत्परता के साथ आगे बढ़ाया था, अब ऐसे स्थान पर पहुँच गया था कि आगे बढ़ने की गुजाइश नहीं रह गई थी।

सबसे बड़े राज्य-संघ के समीप पर २२ अप्रैल को हस्ताक्षर हुए। इसका नाम था मालव-संघ, जो ग्वालियर-इंदौर-मालवा-क्षेत्र के बीस राज्यों से मिलकर बना था। इसका क्षेत्रफल मैतालिस हजार वर्गमील और जनसंख्या सत्तर लाख से ऊपर है। राजप्रमुख (या संघ के वैधानिक अध्यक्ष) का नाम तय करने का काम बड़ा नाजुक था। यह पद ग्वालियर नरेश को मिलने वाला था, जिन्हें इक्कीस तोपों की मलामी मिलती है। राजधानी का प्रश्न और भी कठिन था। इस बारे में यह समझीता हुआ कि ग्वालियर जाड़ों की राजधानी रहे और इंदौर गर्मियों की। भोपाल ने मालव-संघ के बाहर बने रहने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन सरकार के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली थी और राज्य में उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ करने की घोषणा की थी।

एक और किस्म का विलीनीकरण भी आज हो रहा था। कच्छ राज्य सीधा भारत सरकार में मिलाया जा रहा था। यह कच्छ-राज्य के सामरिक महत्व को देखते हुए किया जा रहा था। विलीनीकरण का काम अलग-अलग स्वरूप धारण कर रहा था। दक्षिणी रियासतों और गुजरात के ठिकानेदार, जिनकी संख्या लगभग सौ है—अलग समझौतों द्वारा बड़ई प्रांत में विलीन हो गए थे। पूर्वी पंजाब और मद्रास ने भी पड़ोसी राज्यों से ऐसे ही समझौते कर लिये थे। सबसे आत्म-निर्भर-संघ बना था मोराष्ट्र संघ, जिसमें काठियावाड़ के दो नौ नवराज्य शामिल हुए थे। इसके राजप्रमुख नवानगर के जामसाहब थे जो बड़े उन्माह में नई व्यवस्था में गरीब हुए थे। आशा है कि वह केन्द्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका खेलेंगे। इन संघों का गानन लोकप्रिय सरकार चलाएगी।



प्रारम्भ छोटे राज्यों के विलीनीकरण से हुआ। फिर, उदयपुर द्वारा उसमें शामिल होने का निश्चय कर लेने पर उसने ज्यादा ठोस रूप ग्रहण कर लिया। जब माउन्टबेटन उदयपुर गये थे, तब महाराणा ने उनसे कहा था कि यह फैसला उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया था। उदयपुर का राजवंश भारत के सबसे सम्मानित राजकुलों में से है और संघ में उनके शामिल होने का राजपूताने के अन्य बड़े राज्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह अन्य बड़े राज्य आत्मनिर्भर है और केन्द्रीय विधान परिषद् में उनके अपने-अपने प्रतिनिधि हैं। इस अधिकार का उपयोग करनेवाली उन्नीस रियासतों में से सात रियासतें किसी-न-किसी मध्य में शामिल हो गई थी।

सफल कूटनीति यही थी कि क्रांतिकारी परिवर्तनों को भी परम्परागत परिपाटियों का जामा पहने रहने दिया जाय। वी पी मेनन ने आज कहा कि बाप के पापों का फल बेटों के सिर पड़ा है। पटियाला और बीकानेर के भूतपूर्व नरेशों ने १९३५ की संधीय-योजना (फेडरल प्लान) को अस्वीकार कर दिया था, जिससे पूरे भारत के ढाँचे को भारी धक्का लगा था। ऐन मौके पर माउन्टबेटन द्वारा मध्य-प्रवेश की योजना हाथ में लेने से स्थिति काबू में आ गई थी और वर्तमान पटियाला तथा बीकानेर नरेशों को नये सबंध दृढ़ करने का अवसर मिल गया था।

माउन्टबेटन ने खुले रूप से स्वीकार किया कि गत वर्ष जब उन्होंने मध्य-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कराने का काम हाथ में लिया था, तब उन्हें कल्पना तक नहीं थी कि उन विषयों में वृद्धि की मांग इतनी जल्दी की जायगी या उसे स्वीकार कर लिया जायगा। इम सिलसिले में उन्होंने नाइ की राय का उल्लेख किया। नाइ का कहना था कि रियासती समस्या की गंभीरता भारत के बाहर बिल्कुल नहीं समझी गई। वास्तव में कांग्रेस, मुसलिम लीग अथवा सिखों से निबटने की अपेक्षा यह कहीं गंभीर विषय था। नाइ ने कहा कि राजाओं से किसी प्रकार के मंत्रीपूर्ण समझौते की उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दी थी। पन्द्रह अगस्त के बाद उन्हें भारी पैमाने पर गंभीर उपद्रवों की आशंका थी। मई १९४८ तक जो प्रगति हुई, उस तक पहुँचने में अगर एक पीढ़ी का समय भी लग जाता तो उन्हें कोई अचरज न होता। उनका मत था कि इस सफलता को इतिहास में अभूतपूर्व माना जायगा।

सारी फिजा ही कितनी बदल गई थी। इसका आभास धौलपुर नरेश द्वारा नई योजना में सम्मिलित होने से मिलता था। गत वर्ष उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि एकीकरण से अधिक किसी प्रकार का विलय उन्हें सर्वथा अस्वीकार होता। आज वह यहाँ मौजूद थे—मत्स्य राज्यमध्य के राजप्रमुख के रूप में।

नई दिल्ली, सोमवार, १० मई १९४८

मुझे और वरनोन को लगता है कि हमें निजाम की स्थिति के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। ऐसी हालत में हम माउन्टबेटन को किसी उचित कार्यवाही की सलाह नहीं दे पायेंगे। दोनों पक्षों के बीच जो अन्तिम पत्र-व्यवहार हुआ है उससे एक नया गतिरोध उत्पन्न हो गया है। दिल्ली न आने के बारे में निजाम ने जो दुराग्रह किया है, उसके कारण अब यह आशा बिल्कुल ही नहीं रही, कि भारत सरकार माउन्टबेटन को हैदराबाद जाने की सम्मति देगी।

हम महमूस करते हैं कि यदि माउन्टबेटन के किसी सहायक कर्मचारी को 'राजा' का दूत बनाकर निजाम के पास भेजा जाय तो कुछ व्यक्तिगत संपर्क तथा निश्वास स्थापित हो सकेगा और वर्तमान भयानक गतिरोध को मिटाने में सहायता मिलेगी, हमने माउन्टबेटन से यह बात कही। उन्होंने इसे बहुत पसन्द किया और मुझे ही 'राजा के दूत' का काम करने का आदेश दिया। वह नेहरू, वी पी मेनन और जर्डन से इस विषय में बात करेंगे।

नई दिल्ली, बुधवार, १२ मई १९४८

सब से स्वीकार कर लिया है कि मैं शीघ्र निजाम से मिलने के लिए हैदराबाद जाऊँ। व्यक्तिगत रूप से स्थिति का अध्ययन करने के साथ-साथ निजाम तथा उनके सलाहकारों को माउन्टबेटन के वचे हुए थोड़े से कार्यकाल का सर्वोत्तम उपयोग करने और पुनर्वाताएँ आरम्भ करने के लिए समझाऊँ। मुझे यह भी समझाना है कि कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक की जानी चाहिए। आज सबेरे कर्मचारी मंडल की बैठक में वी पी मेनन उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस बात के काफी प्रमाण मिल गए हैं कि अब कम्युनिस्टों तथा राजाकारों ने आपस में गठबन्धन कर लिया है। परन्तु अब तक इस पहलू पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा था। माउन्टबेटन को इस गठबन्धन पर विश्वास नहीं होता। किन्तु मेनन को इस पर दृढ़ विश्वास है और वह इसे परिस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं।

माउन्टबेटन ने बैठक का आरम्भ पटेल के स्वास्थ्य के बारे में पूछ-ताछ से किया। वी पी मेनन ने बताया कि उनकी नाडी अनियमित है और यह अनियमितता बढ़ती जाती है। इससे चिन्ता उत्पन्न हो रही है।

नई दिल्ली, गुरुवार, १३ मई १९४८

कल माउन्टबेटन ने मेरी उपस्थिति में नेहरू से पुष्टि करवा दी कि वह चाहते हैं कि मैं हैदराबाद जाऊँ। यदि निजाम सघप्रवेश के लिए राजी हो गए तो वह उन्हें पूर्ण वैयक्तिक सुरक्षण देंगे। मेरे काम के बारे में मुझे आदेश दिये जाते समय यह

सभावना भी नजरन्दाज नहीं की गई कि शायद निजाम अपने घर के मालिक नहीं रहे हैं और किसी प्रकार की गुप्त राजमहली क्रान्ति या तो हो गई है या होने वाली है।

सुरक्षा-समिति की बैठक के बाद मैं फिर नेहरू से मिला और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने उनके साथ हो लिया। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा के बारे में वह कुछ खास बात कहना चाहते हैं। उनका मत है कि सकट को टालने की कोशिश करना अक्सर उसे निमन्त्रण देने का सबसे पक्का ढग होता है।

हैदराबाद की सीमा पर प्रतिदिन जो गडबडी और गोलाबारी होती रहती है उसको चुपचाप देखते रहना संभव नहीं है।

जब मैं लौटा उस समय भी मेहनत माउन्टवेटन के साथ बातें कर रहे थे। वह सुरक्षा-समिति के कार्य से सतुष्ट दिखलाई पड़े। उससे सैनिक तथा अ-सैनिक अधिकारियों को एक-दूसरे को अधिक निकट से जानने का अवसर मिला था।

माउन्टवेटन मेरी यात्रा के बारे में बड़े आशावादी हैं। तय हुआ कि मैं हैदराबाद सरकार की व्यवस्था के अन्तर्गत यात्रा करूँ। ५ वजे मैं जईन और उनके पुत्र अलीखा से मिलने हैदराबाद भवन गया। जईन ने कहा "यदि भारत सरकार ने बहुत अधिक दबाव न डाला तो सारी बात हल हो जायगी।"

नई दिल्ली, शुक्रवार, १४ मई १९४८

मैंने फिर जईन के साथ बातचीत की। मैं भीर लायक अली का अतिथि रहूँगा। मेरी यात्रा की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई। यह मुझे मौके पर तय करने की आजादी है। मेरे हैदराबाद छोड़ने के पहले जईन भी वहाँ पहुँच जाने की आशा करते हैं।

मैं जो पत्र ले जा रहा हूँ उसमें निजाम के उत्तर पर निराशा व्यक्त की गई है और बताया गया है कि कार्यभार बहुत होने और कार्यकाल के बहुत थोड़ा रह जाने के कारण माउन्टवेटन का हैदराबाद आना संभव नहीं। तथापि माउन्टवेटन ने लिखा है "मैं बहुत उत्सुक हूँ कि भारत छोड़ने के पहले आपके साथ कुछ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकूँ।" बाद में, मुझे अपने सहायक मण्डल का सबसे पुराना सदस्य बताकर उन्होंने कहा है, "यह मेरे विचारों को मज़ीभाति जानते हैं और इन पर मेरा पूरा विश्वास है।"

अन्त में उन्होंने कहा है, "हैदराबाद से कम्युनिस्ट और साम्प्रदायिक स्थिति के जो-समाचार आ रहे हैं, उन्होंने मुझे बचैन कर दिया है। उनका आपकी स्थिति पर जो असर हो रहा है वह विशेषरूप से चिन्ताजनक है। अतएव, मुझे विश्वास है कि आप श्री कैम्पबेल जान्सन को सामान्य तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से स्थिति

का स्पष्ट परिचय कराने में सकोच न करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा सदेश अकेले में ही आपको दिया जाय, आपके सिवा किसी दूसरे को नहीं। मुझे आशा है कि श्री कैम्पबेल जान्सन आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सकेंगे। दूसरों की उपस्थिति से यह सबध दूषित हो सकता है।”

सो कल मैं रवाना हो जाऊंगा। केवल एक बात निश्चित है कि आगामी ४८ घंटों में मुझे माउन्टवेटन तथा भारत सरकार के संपर्क में कटा रहना पड़ेगा। माउन्टवेटन के साथ छ वर्ष की सेवा में मुझे सबसे कठिन काम यही मिला है। फिर भी मैं उनके पास काफी समय तक रह चुका हूँ और उनकी स्फूर्ति का कुछ अंश तो मुझे भी मिल गया है।

: २६ :

## निजाम से भेंट

हैदराबाद, शनिवार, १५ मई १९४८

मेरे नाश्ते के बाद विलिंगडन हवाई अड्डे से रवाना होकर, भोपाल में थोड़ा ठहरता हुआ, भोजन के पहले हैदराबाद पहुँच गया। हवाई अड्डे पर मीर लायक अली की ओर से कैप्टन वेग और मुशी की ओर से कम-से-कम तीन व्यक्ति मेरा स्वागत करने के लिए आये थे। तीन मिनट के अन्दर ही मुझे अपना कूटनीतिक कार्य प्रारम्भ कर देना पड़ा, क्योंकि मुशी के प्रतिनिधियों ने मुझे उनका आग्रह भरा न्योता दिया कि मैं पहले उनसे मिलूँ और उनके साथ ही खाना भी खाऊँ। मुझे उत्तर देना पड़ा कि मैं लायकअली का अतिथि हूँ और उनकी योजना को जाने बिना कोई कार्यक्रम नहीं बना सकता। फिर भी मैं मुशी से मिलूँगा अवश्य।

मुशी मेरे आने का समाचार पाकर विशेष रूप से बगलोर से आ गए थे। मेरी जो यात्रा गुप्त रूप से होनी थी उसपर अब प्रचंड प्रकाश पड़ गया था, क्योंकि मुशी ने मेरे आने और अपनी वापसी की सूचना सम्वाददाताओं को दे दी थी।

इससे निवटने के बाद हमने सिकन्दराबाद और हैदराबाद नगरों को पार करते हुए १० मील का मार्ग तय किया। मार्ग में बहुत लोग दिखलाई नहीं पड़े। जो दिखलाई पड़े वे आराम से चलते-फिरते अपने कामों में लगे हुए थे।

प्रधान मंत्री के निवासस्थान 'शाहमजिल' में पहुँचते ही मुझे एकदम मीर लायकअली के पास पहुँचाया गया। वह कुछ बीमार थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपके

लिए भोजन की विशेष व्यवस्था नहीं की हे इसलिए मुशी का आमन्त्रण स्वीकार कर लेना उचित होगा। उन्होंने यह इस खयाल से भी कहा कि मुशी कल वापस बगलोर जाने वाले है। उन्होंने कहा कि वह सब विचारों के नेताओं के साथ मेरी भेंट कराने का प्रबंध कर रहे हैं। मुझे इच्छानुसार घूमने-फिरने और जहा चाहूं वहां जाने की स्वतन्त्रता है। उन्होंने मुख्य बात यह कही कि आर्थिक नाकेबंदी में अब भी ढील नहीं की गई है, जिससे हमें पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ बसे मगाई है, जो बबई में जग खा रही थी। मैंने कहा कि निश्चय ही इन शिकायतों को अधिक व्यापक समझौते के द्वारा दूर किया जा सकता है।

देर से भोजन करने के बाद मुझे बताया गया कि निजाम ५ बजे मुझसे मिलेंगे। मुझे समय पर उनके निवास-स्थान "किंग कोठी" पहुंचा दिया गया। प्रधान मंत्री कोई १० मिनट पहले ही वहां पहुंच चुके थे। मुझे मामूली सजावट वाले एक कमरे में ले जाया गया। धुंधले प्रकाश में मैंने देखा कि कमरा विकटोरिया के काल की साज-सज्जा से सुशोभित था और एक ओर पचमजार्ज का चित्र टंगा हुआ था।

मीर लायकअली ने आगे बढ़कर निजाम से, जो एक कुर्सी पर अदृश्यप्राय बैठे थे, मेरा परिचय कराया। एक क्षण के लिये मैं चकित रह गया। किन्तु बाद में शीघ्र ही मैंने अपनी सुध-बुध बटोरकर यथोचित शिष्टता के साथ उनका अभिवादन किया। वह निहायत भट्टे कपड़े पहने हुए थे—एक सफेद सूती शेरवानी और सफेद पाजामा, परो में भूरी स्लीपरें थी और हलके भूरे मौजे टखने पर बेतरतीब फैले हुए थे। सिर पर वादामी रंग की तुर्की टोपी थी जो सिर के पिछले भाग पर रखी हुई थी। उनकी कमर झुकी हुई थी और दांतों का खराब हाल था। उनके हाथ काप रहे थे और बात करते समय उनके घुटने इस बुरी तरह आपस में टकरा रहे थे मानो वे मृगी रोग से पीड़ित हो। उनके व्यक्तित्व का सबमें सबल अंग है उनकी अभिव्यक्ति का पैनापन और स्वर की कर्कशता।

मैं निश्चय नहीं कर सका कि मीर लायकअली बैठे रहेंगे, या चले जायेंगे, परन्तु जब मैंने निजाम को माउन्टबेटन का पत्र दिया, और वह उसे धीरे-धीरे पढ़ने लगे, उस समय वह चाहते तो मुझसे एकांत में बातें कर सकते थे। परन्तु उन्होंने इस मौके को नहीं अपनाया। मीर लायकअली वही डटे रहे। पत्र पढ़ने के बाद निजाम बड़े भयानक ढंग से मेरी ओर मुड़े। उन्होंने कहा कि मैं लार्ड माउन्टबेटन के सीमित समय तथा अधिकारों को खूब जानता हूँ। "वह एक महीने में क्या कर सकते हैं?" उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि लार्ड माउन्टबेटन अच्छी तरह समझते हैं कि मेरा हैदराबाद छोड़ना बिल्कुल असंभव है। यदि लार्ड माउन्टबेटन को यहाँ आने और मुझसे मिलने की फुरसत नहीं है, तो फिर (उन्होंने विदाई का इशारा किया) मुझे अफसोस है। उन्हें मेरा सलाम है, और खुदा हाफिज।"

निजाम ने कहा, जहां तक भारत सरकार के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है,



मीर लायकअली ने बातचीत को राष्ट्रमंडल के प्रश्न पर टाल दिया। निजाम जानना चाहते थे कि भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने की क्या संभावना है। मैंने बताया कि इस प्रश्न पर बहुत जोरो से विचार हो रहा है और बहुत-से प्रभावशाली लोग भारत के राष्ट्रमंडल में बने रहने के समर्थक हैं। मैंने यह भी कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिसका वाइसराय के कर्मचारी मंडल का सदस्य होने से कोई संबंध नहीं है। वह यह कि भारत राष्ट्र-मंडल में रहे या न रहे, वर्तमान ब्रिटिश लोकमत केवल इसी आधार पर भारत के एक भाग के साथ अधिक अनुकूल और दूसरे भाग के साथ कम अनुकूल व्यवहार का समर्थन नहीं करेगा। यदि इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जायगा तो वह भ्रामक होगा। मेरा खयाल है कि मेरी इस बात का असर हुआ।

इसके बाद विश्व की सकटापन्न स्थिति पर कुछ बातें हुईं। अन्त में निजाम ने माउन्टबेटन के प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त कीं और बातचीत समाप्त हो गई।

निजाम के प्रतिकूल रुझान के कारण एक घंटे की यह भेंट सरल तो नहीं रही, किन्तु उससे उनके व्यक्तित्व और मानस के अध्ययन का अच्छा अवसर मिला। निजाम का शरीर भले ही बूढ़ा गया हो, उनका मस्तिष्क सतर्क है और अपनी बुद्धि पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। मुझ पर यह छाप पड़ी, मानो मुझसे किसी वृद्ध, सनकी प्रोफेसर ने अपने विशेष विषय पर बातचीत की हो। निजाम पुराने ढंग के राजा हैं—अहंकारी और सजुचित विचारों के, परन्तु अपने निजी क्षेत्र में अजेय। सारी बातचीत में उनका रुझान घोर भाग्यवादी था।

मुझे कोई चिह्न दिखाई नहीं पड़ा कि निजाम बड़ी है। कोठी के सामने भारी सड़ियाँ में पुलिस तैनात है, किन्तु निजाम की हत्या का जो प्रयत्न किया गया था, उसे दृष्टि में रखते हुए उसमें कोई असाधारण बात दिखाई नहीं पड़ती। राजमहल मुख्य-मार्ग से बहुत दूर भी नहीं है, दिल्ली के साधारण मकान भी सड़क से उतनी ही दूरी पर है। मेरे विदा लेने के बाद मीर लायकअली वहीं ठहरे रहे।

मीर लायकअली के मकान में मोइन मुत्तसे मिलने आये। स्पष्ट था कि वह जानना चाहते थे कि निजाम की बातों पर मेरी क्या प्रतिक्रिया है। मैंने केवल इतना कहा कि बातचीत सामान्य ढंग की थी और उससे कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ।

हमने सवि या सव-प्रवेश पर बातें कीं। उन्होंने कहा कि हमें भय है कि तीन-विषयों में सव-प्रवेश बाद की तैयारी में सव-प्रवेश बना दिया जायगा। उसमें कानूनों की मान्यता स्थापित करने तथा आंतरिक स्वतन्त्रता खोने का भी प्रश्न उठेगा, जिसे निजाम कभी स्वीकार नहीं करेगा।

इसके बाद मैं मुर्शी के साथ भोजन करने के लिए चला गया। वहाँ पहुँचने में तेज मोटर पर मुझे लगभग ४० मिनट लगे। उनका निवासस्थान सिकंदराबाद के एक छोटे पर हवाई अड्डे के समीप है। मुर्शी यहाँ रहते हुए नगर के जीवन से

बिलकुल पृथक् है और उनकी भेंट केवल उन लोगों से हो सकती है, जिनके पास समय और पेट्रोल है या जिन्हें उनसे मिलने की राजनैतिक आवश्यकता है।

मैंने उन्हें कुछ खिन्न और परेशान पाया ; उन्होंने कहा कि लायकअली ने उनके साथ हुई भेंट की एक बिलकुल झूठी रिपोर्ट दी है, जिसके कारण उन पर से उनका विश्वास बिलकुल उठ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि मोइन और लायकअली के बीच की स्थिति बड़ी अस्पष्ट है। यद्यपि वे दोनों साले-बहनोई हैं पर उन दोनों में मतभेद है। जहाँ तक निजाम पर प्रभाव का प्रश्न है, लायकअली का तारा इस समय बुलन्द है।

मुश्री ने कहा कि निजाम उत्तरदायी शासन या 'सब-प्रवेश' के सबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना चाहते। परन्तु वह मेरे इस विचार से सहमत है कि राजनैतिक स्थिति की बागडोर निजाम के ही हाथों में है।

मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरी यात्रा व्यक्तिगत तथा अनौपचारिक है और मैं प्रधान मंत्री तथा वी पी मेनन को पूर्ण सहमति से आया हूँ।

वह कल ब्रगलोर वापस जाने के बारे में बिलकुल प्रसन्न दिखलाई पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अब यहाँ रहना पसन्द नहीं करती और सरकार के साथ उनका सबंध इतना बिगड़ गया है कि कोई सार्क हो बाकी नहीं रह गया।

हैदराबाद, रविवार, १६ मई १९४८

दिन भर काम में बहुत व्यस्त रहा। बातचीत से जरा भी फुरसत न मिली। मैंने मीर लायकअली से कहा कि मैं कासिम रिजवी से खानगी तोर पर मिलना पसन्द करूँगा बशर्ते कि इस भेंट के बारे में कोई प्रचार न हो और यह समझ लिया जाय कि मैं केवल उन्हीं लोगों से मिल रहा हूँ जिनसे आप मुझे विशेष रूप से मिलाना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि वह निश्चित रूप से चाहते हैं कि मैं रिजवी से मिलूँ। उन्होंने कहा कि रिजवी मेरे दोरे पर खाना होने के पूर्व मुझ से भेंट करने आयगा। उन्होंने मुझे सलाह दी कि उसी वक्त मैं भी बातचीत में शामिल हो जाऊँ।

मैंने ऐसा ही किया। कुछ मिनटों की मामूली बातचीत के बाद प्रधान मंत्री मुझको रिजवी के साथ छोड़ कर चले गए। बातचीत की शुरुआत मैंने इस प्रकार की घटनाएँ जिस प्रकार करवट ले रही हैं उससे मुझे मायूसी हो रही है। उसने खट से उत्तर दिया कि वह तो जरा भी मायूस नहीं है। अगर है तो उन्मादपूर्ण। उसने मुझसे कहा कि मैं यह अच्छी तरह समझूँ कि उसका एकमात्र उद्देश्य मुसलमानों की रक्षा है और उसकी भारी वफादारी उन्हीं के प्रति है। मैंने उससे पूछा कि क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि कम्युनिस्ट रजाकारों से कह रहे हैं कि दोनों को



मिलकर सम्मिलित कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर रिजवी ने बहुत गरम हो कर जवाब दिया, “जब आप रजाकारो का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब मुझसे है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुसलमानों की हालत ऐसी है कि वे खुदबखुद बड़ी तेजी से कम्युनिस्ट बन रहे हैं। मैंने उन्हें (रिजवी ने ठीक निर्देश नहीं किया कि उनसे उसका क्या अभिप्राय था) चेतावनी दे दी है कि ऐसा होना संभव है।”

फिर उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि वह कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम करने को बिल्कुल तैयार है और इस दशा में उसने प्रारम्भिक कार्यवाही भी कर ली है। इस बात को बिल्कुल पक्का करने के लिए कि मैंने उसके विचारों को गलत रूप में नहीं समझा, मैंने कहा कि मेरा खयाल है कि कम्युनिस्टों द्वारा स्वयं निजाम को दी गई सीधी चुनौती रजाकारो के मार्ग में एक बाधा सिद्ध होगी। चुनौती से मेरा मतलब कम्युनिस्टों की वह चेतावनी है, जिसमें उन्होंने कहा है, “निजाम के साथ कोई वास्ता नहीं होगा।” मेरे इस कथन को सुनकर रिजवी एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर बोला कि यह कठिनाई वह भी सहस्र करता है। लेकिन बाद में जब मैंने फिर इस विषय की चर्चा की तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यदि मुसलमानों को हताश होने से बचाने के लिए कम्युनिस्ट ही एकमात्र साथी मित्र हुए तो सरकार तथा राजवंश दोनों ही उसके लिए गौण वस्तुएँ बन जायँगी। “यदि भारत हमें दो वर्ष तक चुपचाप स्वेच्छा से चलने दे तो मैं वचन देता हूँ कि एक ऐसी चीज का निर्माण कर दूँगा जिससे सब ईर्ष्या करने लगेंगे। हिन्दू अभी से रजाकारो में शामिल हो रहे हैं।” मैंने पूछा कि क्या राजनैतिक समझौते के बिना दो वर्ष बाद फिर वैसा ही सकट उत्पन्न नहीं हो सकता? इसका उसने समर्थन किया लेकिन साथ ही अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि भारतीय सभ दो वर्ष से अधिक नहीं टिकेगा।

उसने कहा कि समस्या के शांतिपूर्ण हल की उसे रस्ती भर भी उम्मीद नहीं। हिन्दुओं के प्रश्न पर चर्चा के समय उसकी बातों से स्पष्ट प्रकट हो गया कि उसका हृदय जातीय घृणा की भावना से सराबोर है। उसकी नजर में गांधीजी की मृत्यु उनके व्यवहार का प्रतीक है। उसने कहा कि हिन्दू सदा अपने देवताओं को महादेव बनाने के लिए उनको मार डालते हैं। मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या उसे यह ध्यान नहीं है कि कम्युनिस्टों के वर्तमान सगठन में हिन्दुओं की ही प्रधानता है। रिजवी ने उत्तर दिया कि यह बात सही है, लेकिन वे दूसरे दली की अपेक्षा कम साम्प्रदायिकतावादी हैं।

मैंने कहा कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि रिजवी ही राज्य में वास्तविक शक्तिसंपन्न व्यक्ति है, इसके बारे में उसकी क्या राय है? इस पर रिजवी ने उत्तर दिया, “आप मेरे बारे में इस प्रकार की निन्दात्मक बातों में विश्वास न करें कि मैं पड़्यत्रकारी हूँ और सरकारें गढ़ा करता हूँ। मैं तो एक अदना-सा शख्स हूँ। मैं

केवल मुसलमानों के हितों का रक्षक और उनका सेवक हूँ और उनके हितों की रक्षा में कोई कसर मैं उठा न रखूँगा। सरकार कभी-कभी मेरे विचार जानने के लिए मुझे बुलाती है और मैं बिलकुल स्पष्ट रूप में उन्हें व्यक्त कर देता हूँ।” उसने मुझ से कहा कि मुसलमानों को मोत से बचाने तथा मुसलमान स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करने के लिए वह अपनी जान न्योछावर करने को तैयार है। उसने कहा कि हैदराबाद के कांग्रेसी प्रतिनिधि मिट्टी के माधो हैं। फिर पहली बार मुसकराते हुए वह बोला, “हिन्दुओं की देख-रेख का भार मुझ पर छोड़ दीजिए।”

रिजवी पूरी तरह धर्मांध है। वह ऐसी आखों से घूरता है जो आप के चुभने लगती हैं। यदि उसके व्यक्तित्व पर बेहदापन और छत्र-कपट की तह नहीं होती तो उसकी नजर उसके दोस्तों और दुश्मनों के दिल ढहला देती है। यही कारण है कि जब वह जोर-जोर से बकवास करता है तो उसकी कलाई खुल जाती है और उसकी बातों को गम्भीर मानना कठिन हो जाता है। उसकी बकवास से यही लगता है कि उसकी नाटकीयता उसकी शक्ति से कहीं अधिक है। देखने में वह ठिगना और मोटा है। उसकी दाढ़ी की लम्बाई-चोड़ाई विचाल है और मिर पर तुर्की टोपी को वह ऐसे बाँके ढग से पहनता है कि धूर्तता टपकती है। तेज कदमों में बाहर जाते समय वह चाली चैपलिन और किसी छोटे पैगवर का प्रतिरूप जान पड़ता था।

हैदराबाद, सोमवार, १७ मई, १९४८

आज रात को आठ बजे प्रधान मंत्री से मेरी आखिरी बातचीत हुई। मैंने लायकअली से कहा कि मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि निजाम इसलिए तो दिल्ली जाने से नहीं डरते कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति कोई खतरा लगता है। लायकअली ने बताया कि हो सकता है कि ऐसी आशंका निजाम के मन में रही हो, लेकिन मुख्य और निर्णयात्मक कारण यह था कि यदि वह दिल्ली जाते तो रियासत में इस बारे में बड़ी गलतफ़हमी फैल जाती। मैंने लायकअली को बताया कि ब्रिटेन के विरोधी दल के समर्थन पर यहाँ जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें स्पष्ट ही भ्रम निहित है। मैंने कहा कि यह भारी भ्रम साबित होगा। ब्रिटिश लोक सभा में हैदराबाद अगर दलीय प्रश्न बन भी जायगा तो भी उसमें रियासत की कोई भलाई नहीं होगी। लायकअली ने कहा कि वह मेरी इन बातों से सहमत है। वह एश्ली के बड़े प्रशंसक हैं और नहीं चाहते कि हैदराबाद कहीं भी दलीय वाद-विवाद का विषय बने।

जब मैं जर्नल यारजग के पुत्र और स्वयंसेवक पुत्रों के नायक सुबह वानावरण में भोजन कर चुका तो जर्नल ने सुबह, जो उसी दिन दोपहर को जा गए थे, मुझसे मिलने की उच्छा प्रार्थना की और मैं रात के ११ बजे उनके मकान पर गया। उन्होंने

बताया कि वह निजाम से एकान्त में मिले थे। निजाम फिर बहुत गर्म हो रहे थे। जईन ने कहा, 'लेकिन, वह तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं।' निजाम वैधानिक प्रभुसत्ता के प्रश्न पर टस-से-मस होने को तैयार नहीं है। किन्तु, जईन ने उन्हें बताया कि एक ऐसी नई सरकार बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है, जिसका आधार मौजूदा सरकार की अपेक्षा अधिक विस्तृत हो। उन्होंने मुझे ऐसा आभास दिया कि निजाम और लायकअली आखिर ऐसा करने के लिए राजी हो गए हैं। निजाम ने मेरे दौरे की चर्चा भी उठाई थी और यह कहा कि उन्होंने बिना किसी हिचक के जो-कुछ भी उनके मन में था, मुझसे कह दिया। निजाम को विश्वास है कि माउन्टबेटन के खुद आने की अब भी दस प्रतिशत सम्भावना है और जईन से पूछा कि उनका क्या खयाल है। जईन ने बताया कि यह बात कुछ हद तक इसपर निर्भर करती है कि मैं कैसी रिपोर्ट भेजता हूँ। तब निजाम ने मेरे बारे में प्रश्न पूछने शुरू किये—मैं कौन हूँ, मेरी नीति क्या है, आदि।

जईन का खयाल है कि अगर वैधानिक प्रभुसत्ता की मांग को मान लिया जाय तो समस्या का हल सम्भव है। उन्होंने तो इतना तक कहा कि ऐसा होने पर फिर भारत सभ में 'प्रवेश' शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। निजाम ने जईन से दो-एक दिन बाद कुछ और बातचीत करने के लिए कहा है और वह मगल व बुध को, जब निजाम से बातें करेंगे तो इसे स्वीकार कराने की कोशिश करेंगे, बशर्त कि वह केवल तीन विषयों तक सीमित रहे। जईन ने बताया कि वह अल इद्रस से, जो कि रजाकारों को फौजी सहायता देते बताये जाते हैं, साफ बात करने की सोच रहे हैं। यह चीज दिल्ली में काफी 'चैनी' का कारण बनी हुई है।

हैदराबाद—नई दिल्ली, मंगलवार, १८ मई १९४८

दिल्ली लौटते ही मैं सीधा वी पी मेनन से मिलने गया। अपने हैदराबाद के सिरदर्द के अलावा उनपर रियासतों के विलीनीकरण की नीति का भी पूरा-पूरा दायित्व है और वह काम के बोझ से बुरी तरह दबे हुए हैं। उनकी साफ राय है कि मेरी यात्रा उपयोगी रही है। लेकिन वह हैदराबाद विधान सभा की प्रभुसत्ता के प्रश्न पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। मेरा अनुमान है कि मेरी गैर-मौजूदगी में हैदराबाद की ओर उनका रुख कड़ा हो गया है। लेकिन मैंने उन्हें कल जईन के लौटने तक इस विषय में कोई राय कायम न करने के लिए तो राजी कर ही लिया। वी पी ने आखिरी शर्तों की बात छेड़ी, लेकिन मैं शारारिक और दिमागी थकावट की ऐसी सीमा पर पहुँच चुका था कि मेरे लिए उनकी बात समझना मुश्किल हो रहा था।

: २६ :

## विदाई के दिन

नई दिल्ली, गुरुवार २०, मई १९४८

कल सारी दुनिया से नाता तोड़ कर मेने अपना सारा दिन रिपोर्ट पूरी करने की जी तोड़ कोशिश में लगाया। मैं चाहता हूँ कि मेरे शिमला पहुँचने के एक दिन पूर्व ही यह रिपोर्ट माउन्टबेटन के हाथ में पहुँच जाय।

आज शाम मेरी नेहरू के साथ एक घंटे तक बातचीत हुई। मेने अपने नतीजों के बारे में उनसे चर्चा की। उनका मत है कि शायद निजाम मुझे डराने के लिए जानबूझ कर नाराजी का अभिनय कर रहे थे। चूँकि वह किसी नये दल के साथ चर्चा करने से इन्कार कर रहे थे इसलिए उनका गोलमोल बातें करना समझा जा सकता है। वह इस बात में मुझसे सहमत है कि रजाकारों के असली जन्मदाता दीनयारजंग में रजाकारों के भग किये जाने की प्रतिक्रियाओं का सामना करने का वृत्त है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि हैदराबाद का इतिहास कभी गौरवपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने हमेशा बल के आगे घुटने टेके हैं। मुराठों के सामने उनका ढेर हो जाना इसका उदाहरण है।

नेहरू महसूस करते हैं कि निजाम अपनी दौलत और व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में सचमुच चिंतित हो सकते हैं। इनके विषय में वह आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मध-प्रवेश के द्वारा वह भारतीयविमान हैदराबाद पर लादना नहीं चाहते। अतिरिक्त विषयों पर अलग से समझौता किया जा सकता है। और न वह हैदराबाद की सेना को ही हड़प कर जाना चाहते हैं।

निजाम के धार्मिक-विचारों की चर्चा करते हुए नेहरू ने कहा कि मेरे साथ बातचीत के दौरान मैं उनका मोहर्म्म की चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस घटना की यादगार है जब मुसलमान जाति शिया और सुन्नी फिरकी में बंट गई थी। हैदराबादी मुसलमान सुन्नी है लेकिन निजाम के बारे में अनुमान किया जाता है कि वह छिपे तौर से शिया है।

मैंने कहा मुझे आशा है कि मेरे हैदराबाद के दोरे को जो प्रकाशन मिला उससे वह अधिक परेशान नहीं हुए होंगे और यह सफाई दी कि इसका मुख्य कारण मुन्गी के कर्मचारी-मंडल का उत्साह था। मैंने अपनी तरफ से उसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की थी। (मुझे पता चला था कि मन्त्रि-मंडल के एक-दो सदस्यों ने इस बारे में कुछ आलोचना की थी, लेकिन नेहरू या पटेल ने कुछ नहीं कहा था)

और वे इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं थे)। नेहरू ने आज फिर कहा कि उसकी कोई बात नहीं और मेरे दोरे के महत्त्व पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।

नेहरू ने कहा कि निजाम का रख उनकी समझ में नहीं आता क्योंकि वह नहीं समझते कि निजाम किसी प्रकार की वीरतापूर्ण भूमिका खेलने के लिए बने हैं।

कुछ देर तक यह अनिश्चित रहा कि जईन और मेनन आपस में मिलेंगे या नहीं, लेकिन बाद में जईन रात को ९ बजे मेनन के घर पहुँचे और मैं भी कुछ देर बाद उनमें शामिल हो गया। सीमावर्ती तनाव को देखते हुए मेनन का यह दृढ़ मत है कि वर्तमान अनिश्चितता को चलते नहीं रहने दिया जा सकता। एक-दो प्रस्तावित कार्य-क्रमों पर विचार करने और उनके ठुकराए जाने के बाद बैठकों का एक पेचीदा सिलसिला तैयार किया गया, जिसके अनुसार मीर लायकअली २२ तारीख को दिल्ली बुलाये जायेंगे, नेहरू और मेनन पटेल से मिलने के लिए मसूरी जायेंगे और बातचीत के दौरान में फंसले का मौका आने पर, कोई दृढ़ निश्चय करने से पहले, माउन्टबेटन को भी आमंत्रित कर लिया जायगा।

बातचीत कुछ असम्बद्ध और अनावश्यक रूप से लम्बी होने पर भी स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण थी। सीमावर्ती कांडों और सरदार के विचारों को मद्दे नजर रखते हुए स्थिति की गम्भीरता महसूस की गई। किसी भी मुख्य विचाराधीन विषय पर जईन ने निजाम के रख का कोई मकेत नहीं मिलने दिया। लेकिन मेनन ने उन्हें आश्वासन दिया कि सध-प्रवेश तीन विषयों तक ही सीमित रहेगा—अन्य विषय अलग चर्चा का विषय होंगे। जैसे हैदराबाद की सेना का स्वरूप और निजाम के वैधानिक अधिकार। (अन्तिम मामला सबसे पेचीदा वैधानिक और राजनैतिक प्रश्न है, जिस पर हमें सावधानी से तयारी करनी होगी।) लायकअली की स्थिति और सरकार के पुनर्निर्माण के प्रश्न पर भी विचार किया गया। जईन ने कहा कि लायकअली के लिए यह कठिन होगा कि खुद छोड़कर शेष सारे मंत्रिमंडल को भग कर दे और फिर उसकी रचना करे। लेकिन इस प्रश्न पर आगामी बैठक में खुल कर चर्चा की जायगी।

इस सभावना पर भी विचार किया गया कि जईन स्वयं सरकार में शामिल हों। जईन ने कहा कि वह खुद प्रधान मंत्री न होकर किसी दूसरे के मंत्रिमंडल में कार्य करना अधिक पसंद करेंगे। लेकिन वह सहयोग देने को तैयार है बशर्ते की नियुक्ति सीधी निजाम की ओर से हो न कि भारत सरकार के दबाव के फलस्वरूप।

जईन यह महसूस करते हैं कि इन सब विषयों पर मेनन के प्रस्ताव पहले की अपेक्षा अब अधिक रुचिकर हैं। किन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ भारत के दृष्टिकोण में कोई बनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी मेनन ने जईन के प्रति अपनी सराहना और समझौते की अपनी इच्छा को बड़ी भावुकता और हार्दिकता से व्यक्त किया है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच मौजूद सद्भावना उत्साह कटाने वाली

है। स्थिति का अधिकांश दारोमदार अब मसूरी में पटेल के साथ होने वाली मुलाकात पर और इस बात पर निर्भर करता है कि इस बैठक से मेनन को खुद फर्मला करने की कितनी आजादी मिलती है। मेनन यह मुठभेड़ आसान नहीं समझते हैं।

वी पी. ओर जर्डन दोनों ने मेरी हैदराबाद-यात्रा को उपयोगी बतलाने की सहृदयता दिखाई।

नई दिल्ली, मंगलवार, २५ मई १९४८

गिमला में छठीम घंटे विताने के बाद मैं रविवार को सबेरे वरनोन के साथ वहां से चल पड़ा। यात्रा करते-करते मैं ऊब गया हूँ। पिछले सप्ताह मैंने जो दौड़ धूप की वह रचनात्मक और सम्बद्ध चिंतन को सीधी चुनौती थी। माउन्टवेटन के अगाऊ दस्तों के रूप में हम दिल्ली के 'भाड़' में लौट आये हैं। पिछले चौबीस घंटे उन्होंने पटियाला में बिताये। उनके यहां पहुंचने पर हम उन्हें यह बताने की स्थिति में थे कि मीर लायकअली, जो रविवार को ही यहां आ गए थे बड़ी गलत भावना लेकर आये थे। वह वास्तविकता से इतनी दूर थे कि सकट अब टल गया है। इसलिए आज माउन्टवेटन ने लायकअली से बहुत मायापन्ची की। मेरे खयाल में अपने मिशन के दौरान में माउन्टवेटन ने जो विभिन्न लोगों से मुलाकातें की हैं, यह उन सबसे लंबी थी और ५ घंटे तक चली।

इस मुलाकात, और मेरे हैदराबाद दौरे, की पृष्ठभूमि यह थी कि सीमावर्ती मुठभेड़ों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद की सीमा के पास भारतीय सेनाओं का काफी बड़ी सख्या में जमाव हो गया है। अंतिम और सबसे गंभीर घटना गंगापुर रेलगाड़ी की थी, जिसमें दो गैर-मुसलमान लापता और घायलों की सख्या भी काफी थी। इस घटना से भारतीय जनमत बहुत उत्तेजित हो उठा था। मेरे हैदराबाद जाने से दो दिन पहले सुरक्षा-समिति की एक बैठक में यह निश्चय किया गया था कि फौजी तैयारियां अवश्य चलती रहनी चाहिए। लेकिन आक्रमण करने के लिए सेना को दस दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होगा। नेहरू से माउन्टवेटन को जो आश्वासन प्राप्त हुए थे उनसे उन्हें तसल्ली हो गई कि बहुत बड़ा सकट पैदा हुए बिना, जैसे हिन्दुओं का कत्लेआम, आक्रमण नहीं किया जायगा। वह अब निश्चित हो गए हैं कि उनके भारत छोड़ने से पहले या शायद उससे भी बाद तक, वर्पा के आरम्भ से पूर्व ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जायगा।

इस तरह शांतिपूर्वक समझौता कराने के लिए बहुत थोड़ा ही समय शेष रह गया था। अतः बहुत सख्त कदम उठा कर लायकअली की आखें खोलनी थी कि खतरा कितना निकट है और उन्हें समझा देना था कि अब चालवाजी से काम लेना उनके और उनके राज्य के लिए भारी खतरा सिद्ध होगा। मैंने माउन्टवेटन को गिमले में बता दिया था कि मुझे तो मीर लायकअली का रुख 'बुद्धिमान मूर्ख'

के समान लगता है—सारे गलत काम करने के लिए वह सारे सही तर्क जुटा सकते हैं।

माउन्टबेटन ने बातचीत के आरम्भ में ही बिना किसी लाग-लपेट के लायकअली के सामने उन सम्भावित घटनाओं का चित्र रखा जो कोई समझौता न होने पर, और हैदराबाद में हिन्दुओं की खून-खराबी होने पर होगी। यदि उनके भारत से चले जाने के कुछ सप्ताह बाद भारत सैनिक हस्तक्षेप का निश्चय करे तो हैदराबाद की फौज क्या कर लेगी? लायकअली ने कहा कि वह फौजी स्थिति को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन वह सध-प्रवेश को सर्व-प्रभुसत्ता की अपेक्षा दसगुना बदतर मानते हैं। उन्होंने सफाई दी कि व्यक्तिगत रूप से वह तो जनतंत्रीय व्यवस्था के पक्ष में हैं, लेकिन हैदराबाद में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का विरोध वह केवल इसलिए करते हैं कि बिना किसी शक के वह सध-प्रवेश का कारण बनेंगे। जब बी पी कमरे में दाखिल हुए तो तीनों केन्द्रीय विषयों के बारे में लायकअली ने पांच या दस वर्ष के लिए एक दीर्घकालीन समझौते का सुझाव सामने रखा।

नई दिल्ली, बुधवार, २६ मई १९४८

मेनन और लायकअली के बीच एकान्त वार्ता बहुत रात तक चलती रही। मेनन ने ममीदे तैयार करने और हल खोज निकालने की अपनी विलक्षण शक्ति का उपयोग करके “समझौते के मुख्य मुद्दों” की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली थी। उसको दो भागों में विभाजित किया गया था। मुख्य मुद्दे कुल ११ हैं। पहले भाग में हैदराबाद और भारत के बुनियादी सत्रयों की व्याख्या थी और दूसरे भाग में प्रथम भाग को कार्यान्वित करने के लिए अन्तरिम व्यवस्था का उल्लेख। ‘मुख्य मुद्दों की सूची’ से लायकअली के इस अनुरोध की रक्षा हो गई थी कि सध-प्रवेश के अलावा तीसरा विकल्प और जनमत-संग्रह का सुझाव भी वह निजाम के सामने पेश करना चाहते हैं। इस तीसरे विकल्प का सवाल वैसे अब कोई मतलब नहीं रखता।

माउन्टबेटन की खुद यह दृढ़ राय थी कि जनमत संग्रह सबसे अच्छा हल रहेगा क्योंकि “समझौते के मुख्य मुद्दों” की सूची से विस्तार के बारे में लम्बी और थकाने वाली सौदेबाजी का एक और दरवाजा खुल जायगा। लायकअली की व्यक्तिगत राय भी ऐसी ही मालूम देती थी क्योंकि उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत-संग्रह से “दोनों पक्षों की बात रह जायगी।” भारतीय क्षेत्रों में जनमत-संग्रह का समर्थन किया जा रहा था, विशेषतः पटेल की ओर से, जिनका आशीर्वाद अनिवार्य था। साथ ही यह मान लिया गया था कि उससे अपने आप सध-प्रवेश नहीं हो जायगा।

नई दिल्ली, शनिवार, २९ मई १९४८

हैदराबाद की परेशान करने वाली चर्चाओं का यह सब में नाजुक दौर है। बी पी, मसूरी जाकर पटेल से मिल आये थे और उनका रचनात्मक और कड़े शब्दों वाला सन्देश साथ लाये थे। पटेल ने फिर जनमत-संग्रह का सुझाव दोहराया था। जहाँ तक 'समझौते' के मुख्य मुद्दों का प्रश्न था, उन्होंने पहले भाग में वर्णित बुनियादी सम्बन्ध तो बिना किसी फेरबदल के स्वीकार कर लिये थे। किन्तु वह दूसरे भाग में दी गई अन्तरिम-व्यवस्था को इस प्रकार मजबूत करना चाहते थे जिसमें नियंत्रण का ज्यादा भार गैर-मुसलमानों के हाथ में रहे। पटेल के सन्देश का अन्तिम भाग स्वयं उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर लायक-अली काम की बात करना चाहते हैं तो उन्हें निजाम से पूरे अधिकार लेकर यहाँ आना चाहिए। उन्होंने लिखा था, "ऐसे व्यक्ति से चर्चा करने से क्या फायदा जिसे हर बार आदेश प्राप्त करने के लिए वापिस लौटना पड़ता है।"

वह चाहते हैं कि चौबीस घंटे की मोहलत देते हुए एक तार भेजा जाय। इसमें लिखा जाय कि यदि लायकअली इस अवधि के भीतर पूरे अधिकार और बुनियादी चीजों पर सहमति सहित यहाँ नहीं आ सकते तो भारत सरकार यह निष्कर्ष निकालेगी कि हैदराबाद-चर्चाएँ जारी रखने के लिए उत्सुक नहीं हैं—केवल समय गवाना चाहता है। उनके आखिरी शब्द थे "एक सप्ताह के अन्दर फैसला करो।" नेहरू ने लायकअली के प्रति गहरा अविश्वास प्रगट किया था। उनकी हलचलों के बारे में प्राप्त खुफिया जानकारी से पता चलता था कि हमारा सामना बहुत ही चाल-बाज व्यक्ति से है। लेकिन उनके या निजाम के उत्तर को अब ज्यादा रोक नहीं जा सकता।

आशा की बात केवल यह थी कि माकटन ने फिर भारत आने का फैसला किया था। माउन्टबेटन ने इस समाचार के प्रति अपनी हार्दिक खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके आने तक वह स्थिति को सभाले रखने की कोशिश करेंगे।

लेकिन माकटन ३ जून के पहले भारत आने वाले नहीं थे। और इसी दिन मैं अपने परिवार के साथ समुद्री रास्ते से घर जाने के लिए बम्बई से प्रस्थान करूँगा।

आज शाम सरकारी भवन में फे और मुझे विदाई देने के लिए एक दावत दी गई। वैसे हम जा तो मंगलवार को सवेरे रहे हैं, लेकिन माउन्टबेटन-दम्पति को फिर समय नहीं मिलेगा, और दावत में शरीक होने के लिए वह उत्सुक हैं। दावत में विलकुल पारिवारिक वातावरण था। मुझे दुःख है कि आखिरी पटाक्षेप होने के पहले ही मैं भारत छोड़ रहा था।

वाद में माउन्टबेटन ने मुझे एक चादी का सिगरेट-केस भेंट किया जिस पर उन्होंने बड़ी उदारता से अपना सन्देश भी खुदवा दिया था। विश्वास, प्रशंसा और



दोस्ती के इन प्रतीको ने मुझे विभोर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार मैं अपने इस सौभाग्य को मानता हूँ कि कि एक महान् मिशन पर मुझे एक महान् व्यक्ति की सेवा करने का अवसर मिला।

नई दिल्ली, रविवार, ३० मई १९४८

आज शाम हम एक स्वागत समारोह में शामिल हुए, जिसका आयोजन मेनन ने दिल्ली जीमखाना क्लब में किया था। दिल्ली का करीब-करीब हर खास व्यक्ति वहाँ दिखाई दे रहा था। माउन्टबेटन-दम्पति को आगामी तीन सप्ताहों में जो अनेक विदाई-भोज दिये जायेंगे, उनमें यह सब से पहला है। इस भीड़भाड़ में एक सदेश-वाहक निजाम के तीन पत्र लाया, जिनको पढ़ने में मेजबान, प्रमुख अतिथि और प्रधान-मंत्री तीनों रम गए। भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों के अधिकांश प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। ज्योंही माउन्टबेटन, नेहरू और मेनन एक कोने में जाकर खड़े हुए और चिन्ता पूर्ण धीमे स्वरों में बातचीत करने लगे तो दूर से ताड़ने वाले इन प्रसवालों को यह समझने देर नहीं लगी कि कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल समाचार आया है।

सरसरी नजर से देखने पर लगता था कि माउन्टबेटन के तत्वावधान में समझौते की आशाओं पर पानी फिर गया है। पहले पत्र में, “समझौते के मुख्य मुद्दों” पर निजाम की वस यह प्रतिक्रिया है कि वह माकटन के आगमन की प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दूसरे पत्र में इस समझदारी भरे सुझाव पर निजाम ने “दो टुक नहीं” लिख दी थी कि वह एक नये और अधिक समर्थनीय प्रधान मंत्री की नियुक्ति पर विचार करे। ध्यान देने की बात थी कि खुद लायक-अली ने कहा था कि यदि इस सुझाव से सद्भावना बढ़ाने में मदद मिलती हो तो वह खुद यह सुझाव रखने को तैयार है। उनके सुझाव में कितनी ईमानदारी थी, वह ही जाने। तीसरा पत्र फिर से एक निमंत्रण मात्र है, माउन्टबेटन को हैदराबाद बुलाने के लिए। यह निमंत्रण भी सौहार्द अथवा शिष्टाचार से शून्य था।

माउन्टबेटन ने निश्चय किया—जो मेरे विचार में बुद्धिमान्नीपूर्ण था—कि केवल पहले पत्र का उत्तर दिया जाय जिसमें और अधिक विलम्ब पर खेद प्रकट करते हुए यह आशा प्रकट की जाय कि लायकअली जब अगली बार दिल्ली आवें तो उन्हें समझौता करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

निजाम के इन शोचनीय नकारात्मक पत्रों के अतिरिक्त लायकअली ने मामले को और तूल दे दिया था। उनकी माउन्टबेटन, नेहरू तथा मेनन से २६ तारीख को जो बातें हुई थी, उनकी वरनोन द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के ठीक होने से उन्होंने इकार कर दिया था और कहा था कि वह कभी इस बात पर राजी नहीं हुए कि तीन केन्द्रीय विषयों पर भारत वैधानिक अधिकारों के अतिक्रमण की घोषणा कर सकेगा।

लेकिन जो भी लोग उस समय कमरे में उपस्थित थे, उनको पूरा विश्वास है कि लायकअली इस बात पर राजी हो गए थे। यह पत्र नेहरू की इस चेतावनी की पुष्टि करता था कि लायकअली भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है और उनका एक मात्र उद्देश्य टालमटोल करना था। माकटन का हस्तक्षेप प्रतिपल भारी महत्व ग्रहण करता जा रहा था।

मौजूदा तनाव के बावजूद जईन यारजग हैदराबाद भवन में पार्टिया देकर शांति और विश्वास का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। जाने से पहले हमारा प्रायः अन्तिम कार्यक्रम उनके तथा उनके परिवार और सगी-साथियों के साथ भोजन करना था। भोजन के बाद जब हम बागीचे में बैठे थे तो हैदराबादी महिलाओं में से एक ने शाइस्ता गुस्तगू करते हुए 'यथास्थिति समझौते', सध-प्रवेश के निर्देश-पत्रों तथा प्रभुसत्ता—से तुच्छ मामलों को ठिकाने लगा दिया। इन महिलाओं ने आह भर कर कहा, "दिल्ली अब पहले वाली दिल्ली नहीं रही। अब मुगल बादशाह नहीं रहे।"

एम. वी. केलडोनियो, गुरुवार, ३ जून १९४८

जब मैं यह लिख रहा हूँ, मैं भारत से इंग्लैंड जाने वाले 'एम वी केलडोनियो' नामक जहाज के राजसी कमरे में बैठा हूँ। हम सब पाच हैं—फे, मैं और मेरी पत्नी तथा दो छोटे बच्चे। मंगलवार सुबह हम बंबई के लिए रवाना हुए थे, जो ८०० मील और २६ घंटे की यात्रा है।

आज सवेरे मैंने माकटन से साता क्रुज के हवाई अड्डे पर मुलाकात की। वह एक खास हवाई जहाज से यहाँ पहुँचे हैं।

जहाज पर सवार होने से पहले मैंने आखिरी सरकारी कर्तव्य के नाते माउन्टबेटन को तार द्वारा सूचित किया। जब मैं माकटन से मिला तो वह स्पष्टतया सदिग्ध और निराश थे, और वह इस बात से बेखबर थे कि घटनाओं को अनुकूलता-पूर्वक वहाँ ले जाने में उनकी सलाह क्या महत्व रखती है। मैंने राजनैतिक तनाव की वास्तविकता और समय-तत्त्व की अनिवार्यता पर बल दिया है और मैं कह सकता हूँ कि माकटन मेरी मुलाकात के बाद अधिक आशावान नजर आते थे।

आज दोपहर बाद जब जहाज समुद्र-तट से रवाना हुआ तो मुझे लग रहा है कि मैं दबा-दबा जा रहा हूँ। निश्चय ही अत्यधिक व्यस्तता के बाद यह एकाएक वेकाम हो जाना ही इसका कारण था। ज्योंही हमने अरब सागर में प्रवेश किया, बंबई की दूरस्थ वस्तियाँ टिमटिमाती नजर आ रही थी, सब ओर अनंत शान्ति थी। लेकिन हमें चेतावनी दी गई कि भारी तूफान का सामना होनेवाला है।

लन्दन, बुधवार, २३ जून १९४८

बीस दिन की समुद्री यात्रा के बाद हम कल लिवरपूल पहुंचे। वम्बई से डेढ़ सौ मील चलने पर हमारी नौफान से टक्कर हुई, जिसने अदन तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। माउन्टबेटन और उनके दल के नार्थाल्ट हवाई अड्डे पर उतरने के समय में वहां पहुंच गया। इतनी ही यात्रा में उन्हें हवाई जहाज से केवल अडतालीस घंटे लगे थे।

उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर एडिनबरा के ड्यूक और एटली दोनों मौजूद थे। इससे उनके आगमन का महत्व असाधारण बन गया। इसके पहले शायद ही किसी और वाइसराय अथवा गवर्नर-जनरल ने अपने स्वागत के लिए एक शाही ड्यूक और प्रधान मंत्री को उनकी वापसी पर स्वागत के लिए खड़े पाया होगा। अन्य मंत्री लोग, ऊंचे और वरिष्ठ अधिकारी, बी बी सी न्यूज रील और समाचार पत्रों के प्रतिनिधि तथा फोटोग्राफर भी बड़ी संख्या में वहां उपस्थित थे। भारत के नये युद्धपोत "दिल्ली" के सौ नाविकों ने उन्हें सलामी दी।

एटली को उपस्थिति बिल्कुल मौजू थी, क्योंकि भारत में सत्ताहस्तांतरण प्रधान मंत्रीपद का सबसे ऐतिहासिक निर्णय था। उसके स्वरूप और अमल का भारी उत्तरदायित्व हमेशा उन्हीं के कंधों पर रहा इसलिए इतिहास मालों और मिन्टो, माटेयू और चेम्सफोर्ड को भाति एटली और माउन्टबेटन के नाम भी साथ लिया करेगा।

लन्दन, सोमवार, २८ जून १९४८

हैदराबाद वार्तालाप भग हो गया है। इसका केवल सक्षिप्त समाचार जहाज के रेडियो पर सुना था। इसके साथ ही माउन्टबेटन के विदाई पत्रों समाचार भी सुने थे। माउन्टबेटन के विदा होने के समय पर १५ अगस्त के समान ही हार्दिक-उत्साह प्रगट किया गया था। कई दृष्टियों से तो यह हार्दिक-विदाई उससे कहीं अधिक उल्लेखनीय थी, क्योंकि अब तो माउन्टबेटन के प्रति यह व्यक्तिगत कृतज्ञता की भावनाओं की मात्र अभिव्यक्ति थी।

अब से माउन्टबेटन-दल लौटा है, मेरे रोनी और वरतोन के साथ लंबी चर्चाएँ की हैं और इधर बीच एक या दो बार स्वतः माउन्टबेटन से भी बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त अपनी विदाई के समय तक उन्होंने अनेक सूचनाएँ एकत्र की थी। इन सब आचारों से पता चलता है कि माकटन के साथ मेरी मुलाकात के बाद काँग्रेस-नाक्रम समये में इस प्रकार रहा।

माकटन हैदराबाद में तीन दिन रुके और लायकअली के साथ दिल्ली आ गए। पहले तो वार्तालाप में बहुत गरमा-गरमी रही और कई बार लगा कि बातचीत का सिलसिला हमेशा के लिए टूट जायगा। नेहरू ने लायकअली से मिलने से इंकार

कर दिया और माकटन ने लदन लौट जाने की धमकी दी। एक बार तो माउन्टबटन ने नेहरू को फोन पर यह कह उस दिन का सकट टाल दिया कि उन्हें पक्का विश्वास है कि वह सतोषजनक हल खोज लेगे, जबकि तथ्य यह था कि उनके सामने ऐसा कोई हल था ही नहीं। लेकिन ज्यो-त्यो बातचीत को जारी रखा गया। नेहरू ने ८ जून को एक भाषण दिया, जो सहायक सिद्ध हुआ। अपने भाषण में उन्होंने अपने आलोचकों को इस बात का उत्तर दिया कि भारतीय फौजों ने अबतक हैदराबाद में क्यों प्रवेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब भी कभी बल का प्रयोग हुआ है, उससे निराकरण के बजाय अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

माकटन का ख्याल था कि परिस्थिति पर काबू पाने के लिए दीर्घकालीन जनमत-संग्रह से कुछ बढ़कर होना चाहिए। अपनी रण-शैली से पटेल अब भी बिना शर्त-संघ-प्रवेश चाहते थे। उनका कहना था कि भारतीय पक्ष की ओर से अब और हल पेश नहीं किये जाने चाहिये। माकटन को यह मान्य था और उसने दो दस्तावेज उपस्थित किये—१९४९ के आरम्भ में उत्तरदायी सरकार जारी करने तथा विधानसभा स्थापित करने का फरमान, और वर्तमान सरकार का तात्कालिक पुनर्निर्माण। दूसरा दस्तावेज पूरी तरह से वी पी मेनन के समझौते की शर्तों का प्रथम भाग था। लायकअली ने यह कह कर एक बार फिर चाल चली कि वह निजाम के साथ सलाह करने जाना चाहते हैं। ९ जून को दिल्ली में यह अफवाह उड़ी कि हैदराबाद में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधि आया हुआ है, लेकिन लायकअली ने कसम खा कर इससे इंकार किया और तय पाया कि वह सलाह-मशविरे के लिए हैदराबाद जाय।

१२ जून को माकटन ने सूचना दी कि वैज्ञानिक अतिक्रमण और विधान-सभा के निर्माण-संबन्धी दो मामलों के सिवा सब तजवीजों पर प्रबन्ध-परिपक्व की मार्फत निजाम से नजर डलवा ली गई है। इसे पहले तो दिल्ली में माउन्टबटन, माकटन और नेहरू के बीच मसूरी में बातचीत में अधिक कठिनाई पैदा हुई और उसके बाद मसूरी में पटेल के साथ एक मुलाकात में और माउन्टबटन की मौजूदगी में मन्त्रि-मंडल की अधिकांश बैठकों में भी इसका सामना करना पड़ा। लेकिन इन तजवीजों को निजाम द्वारा सशोषित रूप से इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि असंबली के निर्माण में साम्यता का कोई सीधा उल्लेख न हो, और उसकी जगह हैदराबाद में “मुख्य राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श के साथ” इन शब्दों को रखा जाय।

१३ जून को माकटन ने लायकअली से बहुत जोर दे कर कहा कि इस बार वह पूर्ण-निर्णायक अधिकारों के साथ आवें, लेकिन अपनी निर्णायक इच्छा का उपयोग करने में इस बार भी वह परिपक्व और स्वतंत्र निजाम द्वारा वक्रे थे। १४ जून को लायकअली ने “समझौता-शीर्षकों” में चार नये सशोषण करने के लिए कहा। वे ये थे—पहला, भारत सरकार हैदराबाद से प्रार्थना करेगी कि वह भारत में प्रचलित

व्यवस्था के अनुरूप ही एक कानून स्वीकार करे और वह खास तौर पर हैदराबाद के लिए न हो, दूसरा, हैदराबाद को आठ हजार अनियमित सैनिक रखने की मंजूरी दी जाय, तीसरा, रजाकारो का धीरे-धीरे अंत किया जायगा, एकाएक नहीं, चौथा, जिस सकट-अवस्था के अधीन भारत हैदराबाद में सेनाएं रखना चाहता है उसकी गवर्नमेंट एवं इंडिया एक्ट में व्याख्या की जाय। माउन्टबेटन का ख्याल था कि भारत सरकार इन अतिरिक्त मामलों पर विचार नहीं करेगी, लेकिन जब नेहरू भी मानने को तैयार हो गए तो उन्हें बेहद खुशी और आश्चर्य हुआ।

१५ जून को माउन्टबेटन ने हैदराबाद प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इस अप्रत्याशित सफलता की सूचना दी। इस पर लायकअली ने तत्काल दो नये मामले उपस्थित कर दिये। वह चाहते थे कि आर्थिक और तट-कर सबंधी स्वतंत्रता के ऐलानों को भी शामिल कर लिया जाय। भारत सरकार एक बार पुनः सहानुभूति-पूर्वक विचार करने को सहमत हो गई और उसने तजवीज भी की कि एक नत्थो-पत्र में इस विषय पर बल दिया जा सकता है। माउन्टबेटन ने कहा कि इस मामले पर नेहरू इस हद तक बढ गए कि वह नत्थो-पत्र में हैदराबाद के आर्थिक विकास में संयुक्त-सहकारिता की शर्त को भी शामिल कर देंगे। साथ जाहिर था कि लायकअली उनके इस आशय को नहीं समझे और उन्होंने इस शर्त को तत्काल निकाल देने के लिए कहा। लेकिन जब माकटन ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि हैदराबाद के लिए इस रियायत को दरगुजर करना अत्यधिक मूर्खता होगी, और माउन्टबेटन ने भी स्पष्ट किया कि अबतक हमेशा ही इसके साथ पूर्ण सब-प्रवेश की शर्त रही है तो लायकअली ने अपनी मांग को वापिस ले लिया। इस प्रकार सद्भावना की यह एक और मिसाल पेश की गई। लेकिन, जैसा कि माउन्टबेटन ने कहा है, इस समय पर लायकअली की यह मूर्खता क्रोध उत्पन्न करने वाली घटना थी।

लायकअली आखिरी दस्तावेज और सब संशोधनों को लेकर हैदराबाद रवाना हो गए। माकटन ने जोर देकर उनसे कहा कि या तो पूरी तरह मंजूर करो अथवा पूरी तरह इकार। उसी शाम को ७-३० बजे तक उत्तर की प्रतीक्षा की गई, लेकिन, आखिर ९-४० पर यह जवाब मिला कि निजाम अपनी मन्त्रि-परिषद् की सलाह के बिना कोई अंतिम निर्णय करने में असमर्थ है। व्यावहारिक रूप में यह आगामी दिन तक संभव नहीं था। फलतः इस विलंब को दिल्ली ने मंजूर कर लिया।

सोलह को दोपहर के समय माउन्टबेटन और माकटन को सूचना मिली कि चार नये प्रश्नों के आधार पर निजाम को सिफारिश की गई है कि वह इन तजवीजों को स्वीकार न करे। इन आधारों को माउन्टबेटन और यहा तक कि माकटन ने भी अत्यधिक अन्यायपूर्ण और बेहूदा बताया। उपरांत निश्चय हुआ कि माकटन रात ही को हैदराबाद जाय।

उनका सब से बड़ा एतराज विधान-सभा स्थापित करने सम्बन्धी फरमान

कि एक उप-पैरे में से "इस आधार पर, जिस पर मैं वाद में विचार करूंगा" शब्दों को निकाल देने के बारे में था। लेकिन उनका प्रतिनिधि मंडल इन शब्दों को निकालने की मजूरी पहले ही दे चुका था, इसलिए इस मामले को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता था। एक दूसरा एतराज यह था कि वह नृत्यी-पत्र के निर्णय द्वारा आर्थिक समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं (और भारत ने तो बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही यह रियायत पेश की थी)। अब वह इसे मूल-समझौते में शामिल कराना चाहते थे।

सत्रह को दोपहर के वक्त माकटन ने फोन में "वन अत" यही शब्द कहे। उसी शाम को निजाम ने बिल्कुल एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया और इससे पहले उसका उल्लेख कभी नहीं किया गया था। यह प्रश्न सकट काल में फोजें तैनात करने के भारतीय अधिकार के बारे में था। उन्होंने बातचीत को जागी रखने के लिए भी कहा। इधर नेहरू और बी. पी. मोहन माकटन के इतजार में थे। उनके आ जाने पर एक प्रेस-काफ़ेस की गई, जिसमें निजाम को दी हुई शर्तें प्रकट कर दी गईं।

इतना सब होने पर भी नेहरू ने वचन दिया कि वह स्वीकृति के लिए इस समझौते को खुला छोड़ते हैं और समय की पावरी नहीं लगाते। माकटन ने माउन्ट-बेटन को बताया कि लायकअली के इस व्यवहार से तो उन्हें बहुत ही निराशा हुई है कि निजाम तक के मुलाकात करने के पहले उसने रिजवी के साथ तीन घंटे बातचीत की। माकटन ने हेदरावाद की कथित नाकेबंदी के विषय में भी एक अनीपचारिक प्रेस-काफ़ेस में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि केन्द्रीय सरकार और किंगी भी प्रांतीय शासन ने इसे लागू नहीं किया, बल्कि छोटे दर्जे के अफसरों की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का ही यह परिणाम है।

माकटन के बातचीत-सम्बन्धी महान् चातुर्य को समझने की योग्यता होती तो परिणाम अनुकूल हो सकता था।

अपने पद-काल के आखिरी दो सप्ताहों में हैदराबाद की लंबी बातचीत और उसके दबाव के कारण माउन्टबेटन के लिए यह असम्भव हो गया कि वह काश्मीर-विषयक मध्यस्थता का कोई अंतिम यत्न कर सके। मार्च में उन्होंने दोनों प्रधान-मंत्रियों का समझौता कराया था कि वे लगभग प्रतिमास मिला करेंगे। लेकिन दो मास से ऐसा कोई यत्न नहीं हुआ। माउन्टबेटन ने नेहरू को सुझाव दिया कि वह लियाकत को दिल्ली में मिलने के लिए लिखे, जिससे लियाकत माउन्टबेटन को भारत छोड़ने से पूर्व विदाई-नमस्कार कर सके। लेकिन इस कोशिश को पहले तो हैदराबाद के कारण स्थगित करना पड़ा और उसके बाद लियाकत की बीमारी के कारण।

विभिन्न हलों पर विस्तार में बातचीत करने की सारी पृष्ठभूमितैयार हो चुकी थी। यद्यपि भारतीय मंत्रि-मंडल नियमित पाकिस्तानी सेना के काश्मीर-युद्ध में भाग लेने के प्रति अत्यंत कठोर था, तथापि समझौते के लिए काफी गुंजाइश थी। जब नेहरू ने पाकिस्तानी सेना के युद्ध में भाग लेने के प्रमाण भेजे, तो लियाकत ने साफ तौर पर इसका प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा के भय पर ही जोर दिया। उन्होंने लिखा, "ज्यो-ज्यो भारतीय फौजें उत्तर-पश्चिमी सीमान्त पर पहुंचती जाती हैं, कबाइलियों को सीधा खतरा महसूस होने लगा है।" माउन्टबेटन की राय है कि दोनों मुख्य व्यक्तियों का इस खास मौके पर परस्पर न मिल सकना राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यन्त अभाग्यपूर्ण था।

लेकिन भारतीय जनता के हृदय पर माउन्टबेटन ने जो निश्चित विजय प्राप्त की थी, उसके मुकाबिले निजाम और काश्मीर की असफलताएँ तो आकस्मिक-सी जान पड़ती थी। भारत में माउन्टबेटन का आखिरी दिन, जैसा कि मुझे सबकी जबानों मालूम हुआ है, कल्पनातीत विजय का था। अत्यधिक बल के साथ माउन्टबेटन दल यह मान गया था कि भारत के लोग और सरकार ने उनके मिशन के आशय और उनके यत्नों की सचाई को स्वीकार कर लिया है और वे उन्हें मित्रों तथा आजाद करने वालों के रूप में विदाई दे रहे हैं।

पहला विदाई-अभिनंदन-पत्र दिल्ली म्युनिसिपैलिटी की ओर से दिया गया था। यह मान-पुत्र पाने के लिए वह पुरानी दिल्ली के शाही मार्ग चादनी चौक से होकर निकले थे। चादनी चौक में ठसाठस भीड़ थी। १९११ में जब लार्ड हार्डिज की हत्या की चेष्टा की गई थी, तब से लेकर कोई भी वाइसराय इस मार्ग से नहीं निकला था। गांधी-ग्राउंड तक उनके चारों ओर भीड़ का समुद्र था, जो जय-जयों के तौर पर गूंज रही थी और उन्हें फूल मालाएँ पहना रही थी। गांधीग्राउंड में लगभग ढाई लाख आदमी जमा थे और ढाई लाख की ओर भीड़ उसमें दाखिल होने की चेष्टा

कर रही थी ।

महान शाही भोजों में सबसे आखिरी इस बार मन्नि-मडल की ओर से शाम को दिया गया था । इस अवसर पर नेहरू ने चिरस्मरणीय शब्दों में माउन्टबेटन-परिवार को हार्दिक श्रद्धाजलि भेंट की । उन्होंने कहा “श्रीमान्, बहुत ऊँची ख्याति के साथ आप यहाँ आये थे, लेकिन भारत में कइयों की ख्याति का लोप हो गया । आप यहाँ महान् कठिनाई और सकट के काल में रहे और इतने पर भी आपकी ख्याति का लोप नहीं हुआ । यह एक आश्चर्यजनक शक्ति का परिचायक है ।”

लेडी माउन्टबेटन के विषय में आगे उन्होंने कहा, “आपके हाथ में जादू है । जहाँ कहीं भी आप गई, आपने सान्त्वना प्रदान की, आपने आशा और उत्साह उत्पन्न किया । इसलिए, इसमें क्या आश्चर्य है कि भारत के लोग आपसे प्रेम करें और आपको भी अपने में से ही एक समझे तथा आप के जाने पर उन्हें दुःख का अनुभव हो ।”

चार घंटे पूर्व दिल्ली की सामान्य जनता द्वारा मित्रता और प्रेम के आश्चर्य-जनक प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए नेहरू ने कहा, “मैं नहीं कह सकता कि लार्ड और लेडी माउन्टबेटन को उस अवसर पर कैसा लगा होगा, लेकिन इन विशाल प्रदर्शनों का आदी होते हुए भी मैं तो अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ । मुझे इस बात की हैरानी है कि एक अंगरेज और एक अंग्रेज-महिला किस प्रकार भारत में इस थोड़े से काल में इतने ज्यादा लोक-प्रिय बन गए । निश्चय ही यह एक ऐसा काल है, जिसमें किसी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुःख और विनाश का भी यह काल था । आपको अनेक उपहार और भेंट प्राप्त होगी, लेकिन लोगों के प्रेम और आत्मीयता से बढ़ कर वास्तविक या मूल्यवान् क्या हो सकता है ?”

१. माउन्टबेटन-दर्पण ने भारत में अपने १५ मास के आवास में अत्यधिक व्यस्त कार्य-कलापों के बावजूद सरकारी भवन में सदृच्छा और मैत्री-भावना की वृद्धि की दृष्टि से जो भोज दिये उनका विवरण इस प्रकार है: दिन के भोजन पर उन्होंने ७६०५, रात्रि-भोज पर ८३१३ और चाय-पान आदि के लिए २५२८ व्यक्तियों को आमंत्रित किया ।



## परिशिष्ट

: १ :

ब्रिटिश सरकार की जिस घोषणा के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो उपनिवेशों को सत्ता-हस्तांतरण की गई, वह सामान्यतया '३ जून की योजना' के नाम से प्रख्यात है। इस घोषणा का मूल पाठ निम्न है

### ब्रिटिश-सरकार का वक्तव्य

नई दिल्ली, मंगलवार, ३ जून १९४७

#### प्रस्तावना

१ २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वह जून १९४८ तक भारत में ब्रिटिश-सत्ता को भारतीयों के हाथों सौंप देना चाहती है। ब्रिटिश सरकार को आशा थी कि १६ मई १९४६ की मन्नि-मंडल मिशन-योजना को सफल बनाने में मुख्य दलों के लिए सहयोग करना और भारत के लिए ऐसा विधान तैयार करना संभव होगा, जो सब संबंधित दलों को मान्य हो। यह आशा पूर्ण नहीं हुई।

२ मदरास, बंबई, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मध्य प्रांत और बरार, आसाम, उड़ीसा और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा और कुर्ग के प्रतिनिधियों की बहु-संख्या नया संविधान बनाने की दिशा में पहले ही पर्याप्त प्रगति कर चुकी है। दूसरी ओर मुस्लिम लीगो दल ने, जिसमें बंगाल, पंजाब, सिंध तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों की बहुसंख्या शामिल है, विधान-सभा में भाग न लेने का फैसला किया है।

३ ब्रिटिश-सरकार की सदा यह इच्छा रही है कि सत्ता-हस्तांतरण स्वतः भारतीयों की इच्छानुसार ही हो। भारतीय राजनैतिक दलों में परस्पर समझौता करने की दिशा में यह कार्य अत्यन्त सुगम हो जाता। फलतः, ऐसे किसी समझौते की अनुपस्थिति में भारतीयों की इच्छाओं का निश्चय करने का काम ब्रिटिश-सरकार पर आ पड़ा है। भारत के राजनैतिक नेताओं के साथ पूर्ण विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के लिए नीचे दी हुई योजना को अपनाने का फैसला किया

है। ब्रिटिश सरकार यह साफ जाहिर कर देना चाहती है कि वह भारत के लिए भी किसी भी प्रकार का सविधान बनाने की इच्छा नहीं रखती, क्योंकि यह तो स्वतः भारतीयों का ही मामला है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत योजना में संयुक्त भारत के लिए विभिन्न संप्रदायों के बीच वार्तालाप में बाधा बनने वाली भी कोई बात नहीं है।

### निर्णायक प्रश्न

४ ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा नहीं है कि वर्तमान विधान-सभा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। नीचे लिखे कुछ प्रातों के लिए अब व्यवस्था कर दी गई है, और ब्रिटिश सरकार को विश्वास है कि इस घोषणा के फलस्वरूप उन प्रातों के मुस्लिम-लीगो प्रतिनिधि भी इसके कार्य में अपना उचित योग-प्रदान करेंगे, जिनके प्रतिनिधियों की बहुसंख्या पहले से ही उसमें भाग ले रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस विधान-सभा द्वारा जो भी सविधान तैयार किया जायगा वह देश के उन भागों पर लागू नहीं हो सकता, जो उसे स्वीकार करने के इच्छुक न हों। ब्रिटिश सरकार इस बात से सतुष्ट है कि जो विधि नीचे दी गई है, उसमें उन क्षेत्रों के लोगों की यह इच्छा जानने की सर्वोत्तम व्यावहारिक विधि निहित है कि उनका सविधान।

(अ) वर्तमान विधान-सभा में वने, या

(ब) उन इलाकों के प्रतिनिधियों की नई और अलग विधान सभा में, जिन्होंने वर्तमान विधान-सभा में भाग न लेने का निर्णय किया है।

जब यह हो चुकेगा तो यह निश्चय करना संभव हो जायगा कि किस अधिकारी या अधिकारियों को सत्ता-हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

### बंगाल और पंजाब

५ फलतः, पंजाब और बंगाल की प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रत्येक को (यूरोपीय सदस्यों को छोड़ कर) दो भागों में बैठने के लिए कहा जायगा—एक वह, जिसमें मुस्लिम-बहुल-जिलों का प्रतिनिधित्व होगा और दूसरे, जिसमें शेष प्रांत का। जिलों की जन-संख्या का निश्चय करने के लिए १९४१ की जनगणना के आकड़ों को अधिकृत माना जायगा। इन दोनों प्रांतों के मुस्लिम-बहुल जिले इस घोषणा के अन्त में दिये गए हैं।

६ प्रत्येक व्यवस्थापिका सभा के दो भागों के सदस्यों को अलग-अलग बैठकों में इस मतदान का अधिकार होगा कि उस प्रांत का विभाजन किया जाय या नहीं। यदि दोनों में से कोई भी भाग विभाजन का समर्थन करता है तो विभाजन होगा और तदनुसार प्रवृत्त किये जायंगे।

७ विभाजन के प्रश्न का निर्णय होने से पहले, प्रत्येक भाग के प्रतिनिधियों

को अग्रिम रूप में मालूम होना चाहिए कि दोनों भाग यदि अतत संयुक्त रहने का ही निर्णय करते हैं तो समग्र रूप में वह प्रांत किस विधान-सभा में शामिल होगा। इसलिए, यदि दोनों व्यवस्थापिका सभाओं का कोई भी सदस्य यह जानना चाहेगा, तो व्यवस्थापिका सभा के सब सदस्यों (यूरोपियनों के सिवा) की बैठक होगी और उसमें इस प्रश्न का निर्णय किया जायगा कि इन दोनों भागों के संयुक्त बने रहने के निर्णय की दशा में वह प्रांत समग्र रूप में किस विधान-सभा में शामिल होगा।

८ विभाजन का निर्णय हो जाने की अवस्था में व्यवस्थापिका सभा का प्रत्येक भाग अपने प्रतिनिधित्व के हल्कों की ओर से उक्त पैरा ४ में दिये विकल्पों में से किसी एक को ग्रहण करने का निर्णय करेगा।

९ विभाजन के प्रश्न का निर्णय करने के तात्कालिक मुद्दे के लिए बंगाल और पंजाब की व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य मुस्लिम-बहुल जिलों (अन्त में लिखे अनुसार) और गैर-मुस्लिम-बहुल जिलों के अनुसार दो भागों में बैठेंगे। यह विधि तो केवल नितान्त अस्थायी स्वरूप की प्रारम्भिक कार्यवाही है, क्योंकि यह तो साफ जाहिर है कि इन प्रांतों के आखिरी विभाजन के लिए सीमा-संबंधी प्रश्नों की विस्तृत खोज करनी आवश्यक होगी, और, जैसे ही दोनों में किसी भी प्रांत के विभाजन का निर्णय हो जायगा, गवर्नर-जनरल एक सीमा-आयोग की स्थापना करेंगे, जिसकी सदस्यता और अधिकार-क्षेत्र का निश्चय संबंधित लोगों के परामर्श से किया जायगा। उसे मुस्लिमों और गैर-मुस्लिमों के आसपास के बहुल इलाकों का निश्चय करने के आधार पर पंजाब के दो भागों की सीमा-रेखाएं बनाने का आदेश दिया जायगा। उसे अन्य तत्वों को भी दृष्टि में रखने की हिदायत दी जायगी। इसी तरह की हिदायतें बंगाल सीमा-आयोग को भी दी जायगी। जब तक सीमा-आयोग की सूचना सक्रिय रूप में लागू नहीं हो जाती, तब तक परिशिष्ट में लिखित अस्थायी सीमाओं का प्रयोग किया जायगा।

### सिंध

१० सिंध की व्यवस्थापिका सभा भी यूरोपीय सदस्यों के सिवां उक्त पैरा ४ के विकल्पों के आधार पर अपने विशिष्ट अधिवेशन में अपना निजी निर्णय करेगी।

### उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रांत

११ उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत की स्थिति सबसे अलग है। इस प्रांत के तीन प्रतिनिधियों में से दो पहले से ही मौजूदा विधान-सभा में भाग ले रहे हैं। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति तथा अन्य विचारों को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यदि सारा या पंजाब का कोई भाग मौजूदा विधान-सभा में शामिल न होना निश्चय करता है, तो उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत को अपनी स्थिति पर पुनः

विचार करने का अवसर देना आवश्यक होगा। ऐसी अवस्था में उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत की मौजूदा व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचकों का जन-मत संग्रह होगा, जो पैरा ४ विकल्पों में से जिसे ग्रहण करना चाहते हैं, चुनेंगे। यह जनमत-संग्रह प्रांतीय सरकार के परामर्श के साथ गवर्नर-जनरल की देख-रेख में होगा।

### ब्रिटिश-बलूचिस्तान

१२ ब्रिटिश-बलूचिस्तान ने एक सदस्य चुना है, लेकिन वह मौजूदा विधान-सभा में शामिल नहीं हुआ। इसकी भौगोलिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए, इस प्रांत को भी अपनी स्थिति पर पुनः विचार करने और यह चुनने का अवसर दिया जायगा कि वह पैरा ४ के विकल्पों में किसे ग्रहण करना चाहता है। यह किस प्रकार समुचित ढंग से किया जा सकता है, इस बारे में गवर्नर-जनरल विचार कर रहे हैं।

### आसाम

१३ यद्यपि आसाम प्रबल रूप में गैर-मुस्लिम प्रांत है, तथापि सिल्हट का जिला, जो बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, प्रबल रूप में मुस्लिम है। यह मांग की गई है कि बंगाल का विभाजन होने की दशा में सिल्हट को बंगाल के मुस्लिम-भाग में शामिल किया जाय। तदनुसार यह फैसला किया गया है कि यदि बंगाल का विभाजन हो तो आसाम की प्रांतीय सरकार की सलाह से गवर्नर-जनरल की देख-रेख में सिल्हट जिले में इस आशय से जन-मत-संग्रह किया जायगा कि सिल्हट का जिला आसाम प्रांत का भाग बना रहे या पूर्वी बंगाल के नए प्रांत में शामिल कर लिया जाय, वशतः कि वह प्रांत उसे शामिल करने के लिए सहमत हो, यदि जनमत-संग्रह का परिणाम पूर्वी-बंगाल में शामिल होने के पक्ष में हो, तो पंजाब और बंगाल जैसा ही सीमा-आयोग बनाया जायगा, जो सिल्हट जिले के मुस्लिम-बहुल इलाकों और आसपास के जिलों के निकटस्थ मुस्लिम-बहुल इलाकों की सीमा-रेखा नियत करेगा। इसके बाद उन्हें पूर्वी बंगाल के हवाले कर दिया जायगा। शेष आसाम प्रांत मौजूदा विधान-सभा की कार्यवाही में भाग लेता रहेगा।

### विधान-सभाओं का प्रतिनिधित्व

१४ यदि बंगाल और पंजाब के विभाजन का निर्णय हो जाता है तो १६ मई १९४६ की मंत्रि-मंडलीय योजना में निहित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक दस लाख जनसंख्या पीछे एक प्रतिनिधि चुनने के लिए नए चुनाव करने आवश्यक होंगे। इसी तरह के चुनाव सिल्हट में भी करने होंगे, अगर वह पूर्वी बंगाल में शामिल होने का निर्णय करता है। प्रत्येक इलाके में प्रतिनिधियों की संख्या इस प्रकार होगी।

## भारत-विभाजन की कहानी



प्रांत	सामान्य	मुस्लिम	सिख	योग
सिलहट जिला	१	२	—	३
पश्चिमी बंगाल	१५	४	—	१९
पूर्वी बंगाल	१२	२९	—	४१
पश्चिमी पंजाब	३	१२	२	१७
पूर्वी पंजाब	६	४	२	१२

१५ विभिन्न इलाको के प्रतिनिधि प्रदत्त आदेशो के अनुसार या तो मौजूदा-विधान-सभा में शामिल होंगे या नई विधान-सभा बनायेंगे ।

### प्रशासनिक मामले

१६ यदि किसी विभाजन का निर्णय हो जायगा तो प्रशासनिक नतीजों पर यथाशीघ्र वार्तालाप आरंभ किया जायगा ।

(अ) यह वार्तालाप यथाक्रम उत्तराधिकारी शक्तियों के प्रतिनिधियों के बीच सुरक्षा, अर्थ और संचरण सहित उन सब विषयों के बारे में होगा, जो वर्तमान में केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं ।

(ब) सत्ता-हस्तांतरण से उत्पन्न मामलों के विषय में सधियों के लिए विभिन्न उत्तराधिकारियों और ब्रिटिश सरकार के बीच वार्तालाप होगा ।

(स) जिन प्रांतों का विभाजन होगा, उनकी संपत्तियों और देनदारियों, पुलिस और अन्य नौकरियों, हाइकोर्टों, प्रांतीय सरकारी संस्थाओं जैसे सभी प्रांतीय विषयों के प्रशासनिक मामलों पर वार्तालाप होगा ।

### उत्तर-पश्चिमी सीमान्त के कबीले

१७ भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत के कबीलों के साथ समुचित उत्तराधिकार शक्तियां समझौते करेंगी ।

### रियासते

१८ ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उक्त निर्णयों की घोषणा का सबंध केवल ब्रिटिश भारत के साथ है और भारतीय रियासतों के प्रति उसकी नीति १२ मई १९४६ की मंत्रि-मंडलीय घोषणा में निहित है, जिसमें कोई फर-बदल नहीं किया गया है ।

### गतिशीलता की आवश्यकता

१९ उत्तराधिकारी शक्तियों को सत्ता ग्रहण करने के लिए तैयारी का समय मिल सके, इसके लिए अत्यावश्यक है कि ऊपर लिखी हुई सब विधियों को यथाशीघ्र

पूरा कर लिया जाय। देरी से बचने के लिए विभिन्न प्रांत या प्रांतों के भाग इस योजना की शर्तों के अनुरूप यथासंभव स्वतंत्रता-पूर्वक भी कार्य करेंगे। माजुदा विधान-सभा और नई विधान सभा (यदि बनी) अपने-अपने इलाकों के लिए विधान बनाने का कार्य करती रहेगी।

### तात्कालिक सत्ता-हस्तांतरण

२० प्रमुख राजनैतिक दलों ने बारबार इस बात पर जोर दिया है कि जितना भी जल्दी संभव हो, भारत में सत्ता-हस्तांतरण हो जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार इस विचार के साथ पूर्ण सहानुभूति रखती है और वह जून १९४८ तक या उससे भी पहले स्वतंत्र भारतीय सरकार या सरकारें बना कर सत्ता-हस्तांतरण कर देने की इच्छुक है। इस घोषणा के फलस्वरूप जो निर्णय होंग उसके अनुसार औपनिवेशिक स्तर के आधार पर एक या दो उत्तराधिकारी शक्तियों को सत्ता-हस्तांतरण करने के लिए वह मौजूदा अधिवेशन में एक विधान भी पेश करना चाहती है। भारतीय विधान सभाओं को समयान्तर यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश-राष्ट्र-मंडल में रहना चाहते हैं या नहीं।

१९४१ की जनगणना के अनुसार पंजाब और बंगाल के मुस्लिम-बहुल जिले:

#### १ पंजाब

लाहौर डिवीजन—गुजरावाला, गुरुदामपुर, लाहौर, शेखूपुरा, स्यालकोट।

रावलपिंडी डिवीजन—अटक, गुजरात, जेहलम, मियावाली, रावलपिंडी, शाहपुर।

मुल्तान डिवीजन—डेरगाजीखा, झग, लायलपुर, मिन्टगुमरी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़।

#### २. बंगाल

चटगाव डिवीजन—चटगाव, नोआखाली, तिपरा।

ढाका डिवीजन—बकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मैमनसिंह।

प्रैसीडेंसी डिवीजन—जैस्मोर, मुर्शिदाबाद, नदिया।

राजाशाही डिवीजन—बोगरा, दीनाजपुर, मालदा, पबना, राजाशाही, रंगपुर।

## प्रमुख व्यक्तियों के परिचय

भारत-विभाजन और सत्ता-हस्तांतरण की इस लम्बी कहानी में लगभग २५ से अधिक व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हुआ है। हिन्दी के पाठकों के लाभ के लिए इनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है

**अब्दुल्ला, शेख :** काश्मीर के प्रतिनिधि राष्ट्रीय दल 'नेशनल काफ़ेस' के तत्कालीन नेता, काश्मीर के भारत में शामिल होने पर तत्कालीन प्रधान-मंत्री।

**अमृतकौर, राजकुमारी :** महात्मा गांधी की सचिव, भारत सरकार की भूतपूर्व स्वास्थ्य-मंत्री।

**अली, मोर लायक :** नवम्बर १९४७ से निजाम हैदराबाद की परिषद् के प्रधान अर्सकिन क्रम, लैफ्टीनेंट कर्नल वी एफ : वाइसराय और भारत के गवर्नर जनरल के काफ़ेस-सचिव।

**आचिल्लेक, फ़ोर्ड मार्शल सर क्लाड :** १५ अगस्त तक भारत में कमांडर इन-चीफ, ३० नवम्बर १९४७ तक भारतीय सेनाओं के विभाजन की देखरेख के लिए सुप्रीम कमांडर।

**आयंगर, गोपालस्वामी :** (स्व०) भारत-सरकार के मंत्री, जनवरी १९४८ में संयुक्त-राष्ट्र-संघ में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता।

**इस्मे, लार्ड :** वाइसराय के स्टाफ, और दिसम्बर १९४७ तक भारत के गवर्नर जनरल के स्टाफ के मुखिया।

**एबेल, जी ई बी. (बाद में सर जार्ज) :** वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी।

**कृपालानी, आचार्य जे. बी. :** कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान।

**छत्तारी, नवाब :** मई १९४७ से नवम्बर १९४७ तक निजाम हैदराबाद की परिषद् के प्रधान।

**जिन्ना, मुहम्मद अली :** (कायदे-आजम) (स्व०) मुस्लिम लीग के प्रधान, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर-जनरल।

**जैनकिन्स, सर इवान :** १५ अगस्त १९४७ तक पंजाब के गवर्नर।

**त्रिवेदी, सर चन्द्रलाल :** उड़ीसा के गवर्नर, १५ अगस्त १९४७ से पूर्वी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर।

**देवदास गांधी :** 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रबन्ध-मपादक, महात्माजी के सुपुत्र





## भारत-विभाजन की कहानी

सैन्य के कमांडर, सितम्बर से दिसम्बर १९४७ तक भारत के गवर्नर-जनरल के सैनिक सकट-कालीन मंडल के नेता ।

लाकहार्ट, लफ्टिनेंट-जनरल सर राव. : जून से १५ अगस्त १९४७ तक उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के गवर्नर, १५ अगस्त १९४७ से जनवरी १९४८ तक भारत उपनिवेश की सेना के कमांडर-इन-चीफ ।

लियाकत अली खा : (स्व०) मुस्लिम लीग के प्रधान मंत्री, अंतरिम सरकार में अर्थ सदस्य, पाकिस्तान उपनिवेश के प्रधान मंत्री, उपरांत मारे गए ।

स्काट, आई डा. वाइसराय के डिप्टी सcretरी ।

# अनुक्रमणिका

## अध्याय . १

पृ ७, गुप्त बात को प्रकट किया, पृ ७, वेवल के पद-काल का अंत, पृ ८, नये वाइसराय की खोज और सर्वसम्मत फैसला, पृ ८, वाइसरायपद के लिए माउन्टबेटन की स्वीकृति, पृ ९, ब्रिटिश राज्य के अंत की नीति, पृ १०, नये वाइसराय का नया कर्मचारी-मंडल ।

## अध्याय २

१०, लार्ड टैम्पलवुड का लार्ड-सभा में भारत मन्त्री योजना पर निदाप्रस्ताव, ११, लार्ड सैमुअल द्वारा समर्थन, ११, लार्ड हेलीफेक्स द्वारा मध्य-मार्ग, १२, निदा-प्रस्ताव वापस, १२, कामन्स सभा में वहस, १२, क्रिप्स द्वारा मन्त्रि-मंडल-मिशन-योजना का समर्थन; १३, लार्ड हैण्डरसन द्वारा समय-मर्यादा की निदा, १३-१४ भारत मन्त्री योजना पर चर्चिल द्वारा विप-वमन, १४, १५ एटली का विरोधी दल को उत्तर, १७, १८, नये वाइसराय को एटली-सरकार का आदेश, १८ माउन्टबेटन की विरोधी दल के सदस्यों से मुलाकातें ।

## अध्याय ३

२०-२१, नये वाइसराय माउन्टबेटन भारत में, २२, शपथ-विधि और समारोह, २२-२३, नेहरू और लियाकत से भेट, २५, लियाकत की गका, २७, सरदार पटेल के साथ भेट, २७-२८, राजाओं से मुलाकातों के विवरण ।

## अध्याय ४

२९-३०-३१, गांधीजी से भेट, ३४-३५, जिन्ना के साथ बातचीत; ३५, मन्त्रिमंडल-योजना जीवित, ३६, "घुन लगा पाकिस्तान", ३८, "गाति-अपील", ३९, माउन्टबेटन-योजना का मसविदा, ३९, वाइसराय भवन में गवर्नर-काफेस ।

## अध्याय ५

४०, योजना पर गवर्नरों के विचार, ४२, सीमा-आयोग की स्थापना की आवश्यकता, ४२-४३, पंजाब-विभाजन के विषय में बलदेवसिंह और गिख-नेताओं से भेट, ४५, सर्व-सत्ता-मपन्न-स्वतन्त्र गण-तन्त्र, ४५, अन्तिम चर्चा के लिए १९ मई ।

## अध्याय . ६

४६, माउन्टबेटन पेशावर में, ४६-४७ ममलमानों का प्रदर्शन, ४७-४८, सीमा-प्राप्तीय नेताओं से भेट, ५१, 'बटे-फटे और घुन लगे पाकिस्तान' पर जिन्ना, ५१, डा राजेन्द्रप्रसाद द्वारा लीग के 'लाहौर-प्रस्ताव' का उल्लेख, ५१, डा राजेन्द्रप्रसाद की महानता ।

## भारत-विभाजन की कहानी

७

५३-५३, माउन्टबेटन के विचारों के विषय में शका, ५३—५७, शिमला में नेताओं से भेंट, ५४, गांधी-जिन्ना का वक्तव्य, ५६, निराशा और घबराहट, ५७, औपनिवेशिक स्वराज्य और सत्ता-हस्तांतरण।

अध्याय ८

५८, माउन्टबेटन को लंदन से बुलावा, ५८, राजनैतिक दलों के नेताओं की बैठक, ५९, बैठक में भारत-विभाजन सहित आठ विषयों पर विचार, ५९, माउन्टबेटन लंदन रवाना, ९०, जिन्ना की गलियारे की मांग, ९०, पार्लियामेंट में 'भारतीय स्वतन्त्रता बिल', ६०-६१, गलियारे की मांग पर प्रतिक्रिया, ६१-६२, कलकत्ता की अशांत स्थिति, ६२, गांधीजी के संयुक्त-भारत पर भाषण, ६३, 'विभाजन अवश्यम्भावी'।

अध्याय ९

६३-६४, राजनैतिक दलों की बैठक—विभाजन-निर्णय, ६४, 'तुरत सत्ता हस्तांतरण', ६५, 'सहमति' और 'स्वीकृति', ६७—६९, विभाजन-निर्णय की राजनैतिक-नेताओं द्वारा स्वीकृति, ७१-७२, 'विभाजन-स्वीकृति' पर दलीय-नेताओं के रेडियो पर भाषण, ७२, प्रेस-काफ़ेस में सौ प्रश्न।

अध्याय १०

७६, अंतरिम सरकार सबंधी सकट, ७७-७८, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत में जनमत-संग्रह; ७८, पंजाब व्यवस्थापिका सभा में पंजाब के विभाजन का निर्णय; ७८-७९, रियासती विभाग की स्थापना, ७९, काश्मीर-नरेश की टालमटोल-नीति, ७९, बंगाल-विभाजन का निर्णय, ८०, सीमा-आयोग सबंधी निर्णय और रेडक्लिफ, ८०, विभाजन-कौंसिल, सेना का बंटवारा, ८१, संयुक्त सुरक्षा परिपद, ८२, १५ अगस्त से आचिन्लेक सर्वोच्च-सेनापति, ८२, १ अप्रैल, १९४८ सेनाबंटवारे की अन्तिम तिथि, ८२, अमृतसर-लाहौर में व्यापक हिंसा के समाचार।

अध्याय ११

८२, "भारतीय स्वाधीनता विधेयक", ८३, १५ अगस्त से जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल; ८५, १५ अगस्त से माउन्टबेटन भारत के गवर्नर-जनरल, ८५-८८, चर्चिल की सहमति।

अध्याय १२

८७, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पर शाही-स्वीकृति, ८७, भारत और पाक दो अस्थायी सरकार, ८८, सत्ता-हस्तांतरण का कलेंडर, ८८-८९, रियासतों के सङ्घ-प्रवेश-पत्र हस्ताक्षर की योजना, ८९, सीमाफौज की स्थापना; ८९-९०, ब्रिटिश वाइसराय के रूप में भारतीय देशी नरेशों के साथ माउन्टबेटन की

आखिरी मुलाकात, ९४, सघ-प्रवेश-पत्र पर देशी राजाओं द्वारा हस्ताक्षर करने में सौच, ९६, कैपवेल की गांधीजी से भेट, ९८, सघ-प्रवेश सवधी समस्याएँ, ९९, सिख-नेताओं की तोड़-फोड़ नीति, १०२-१०३, सीमा-आयोग का निर्णय तैयार और उसकी प्रकाशन-तिथि पर विचार ।

अध्याय . १३

१०३—११३ भारत और पाकिस्तान में स्वाधीनता समारोह ।

अध्याय . १४

११४, सीमा-आयोग का निर्णय प्रकाशित, ११६, हैदराबाद के विषय में चिन्ता, माकटन की निराशा, ११७, नवाब छतारी का त्यागपत्र, ११७, 'सघ-प्रवेश-पत्र' बनाम "मैत्री-संधि", ११८, सीमा-फौज को भग करने का फैसला ।

अध्याय : १५

११९, सकटापन्न परिस्थितियाँ, ११९, दिल्ली में हंगामा, १२०, गांधीजी का चमत्कार, १२१, दिल्ली बेकाबू, १२२, निजाम की झिझक ।

अध्याय १६

१२४, भारत और पाकिस्तान में अशांति, १२५-१२८, जूनागढ़ की पाकिस्तान में प्रवेश की योजना, १२८, भारतीय फौज जूनागढ़ की सीमा पर नात ।

अध्याय १७

१२९, विस्थापितों के काफिले, १२९-१३०, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण; १३१, काश्मीर की सौदेबाजी के लिए जूनागढ़, १३१, सरदार पटेल का क्रोध; १३२, भारत आने वालों के मार्ग में पाक द्वारा बाधाएँ ।

अध्याय १८

१३३, काश्मीर में भारतीय सेनाएँ, १३३, काश्मीर द्वारा सघ-प्रवेश-पत्र पर हस्ताक्षर, १३६, शेख अब्दुल्ला काश्मीर के प्रधान मंत्री, १३७, जिन्ना की पाकिस्तानी सेनाओं को काश्मीर में भेजने की आज्ञा, १३७, ग्रेसी का इकार; १३७, जिन्ना को आचिन्लेक की सलाह, १३८, काश्मीर-सकट की हैदराबाद पर प्रतिक्रिया, १४०, जूनागढ़ में जन-मत-संग्रह का सिद्धान्त, १४०-१४१, लाहौर में माउन्टबेटन-जिन्ना मुलाकात, १४१, काश्मीर में जन-मत-संग्रह का प्रश्न, १४४, हैदराबाद के साथ 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर का सुझाव, निजाम परिषद् की स्वीकृति और निजाम की मौखिक स्वीकृति, १४५, हैदराबाद में विरोधी प्रदर्शन, माकटन, छतारी और अहमद ने इस्तीफे दिये, १४७, जूनागढ़ भारत में शामिल, १४८, राजगोपालाचारी स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल ।

अध्याय : १९

१४९, हैदराबाद द्वारा 'यथास्थिति समझौते' पर हस्ताक्षर; १५२, काश्मीर-

## भारत विभाजन की कहानी

समस्या पर नेहरू-लियाकत भेट, १५४, पचपन करोड रु का प्रश्न, १५५-१५६, भारत का काश्मीर प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र-संघ में भेजने का निर्णय ।

अध्याय २०

१५७, माउन्टबेटन की कथित 'गुप्त योजना', १५८, संयुक्त राष्ट्र संघ में काश्मीर-प्रश्न लेकर जाने वाला प्रतिनिधि मंडल, १५९, छोटे राज्यों का विलयीकरण, १६०, गांधीजी का आमरण-उपवास, सांप्रदायिक मेल के लिए महाप्रयास; १६३, गांधीजी की मात शर्तें ।

अध्याय २१

१६४, "गांधी को मरने दो", १६४, आमरण-उपवास की समाप्ति; १६४ प्रार्थना-सभा में बम-विस्फोट, १६४, गांधीजी की हत्या, १६७-१६९, शव-यात्रा का जलूस और दाह-क्रिया, १७०-१७१, गांधीजी की मृत्यु पर श्रद्धांजलियां ।

अध्याय २२

१७१, महात्माजी की अस्थियों का विसर्जन ।

अध्याय २३

१७२-१७३, 'यथास्थिति समझौता' भग, १७३, हैदराबाद द्वारा पाकिस्तान को २० करोड रु० का ऋण, १७७, हैदराबाद में भारतीय एजेंट-जनरल के एम-मुशी, १७८, रजाकारों की सरगर्मियां, १७८, माकटन लदन रवाना ।

अध्याय २४

१७९, संयुक्त राष्ट्र-संघ में पाक-प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यारोप, १८०, काश्मीर सवधी चीनी-योजना, १८१, निजाम को समझौता-भग की चेतावनी, १८२, हैदराबाद शस्त्र-दिवस, १८२, रिजवी का वक्तव्य, १८४, निजामके लिए चार सूत्र ।

अध्याय २५

१८५, चार सूत्री योजना को रद्द करने का फरमान, १८६, 'संघ-प्रवेश, या युद्ध', १८७-१८८, कच्छ-राज्यों का विलीनीकरण, सिख-राज्यों का एकीकरण, राजपूताने के राजाओं का संघीकरण, १८९, निजाम के पास विशेष 'दूत' भेजने की योजना, १९०, 'दूत' की रवानगी ।

अध्याय २६

१९२, निजाम से 'दूत' की भेट, १९३, निजाम का विपरीत रुख ।

अध्याय २७

२०१, हैदराबाद-सीमा पर उत्पात; २०२, हैदराबाद के साथ 'समझौते के मुख्य मुद्दे', २०५, मुख्य मुद्दों पर निजाम की प्रतिक्रिया; २०५, माकटन फिर हैदराबाद में, २०५-२०९, माउन्टबेटन की हैदराबाद के साथ समझौते की अन्तिम चेष्टाएं, माउन्टबेटन लदन के लिए रवाना, समझौतावार्ता भग ।

